रजिस्ट्री सं. डी० (डी.एन.)-73 REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 8, 1985/ज्येष्ठ 18, 1907
No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 8, 1985/JYAISTHA 18, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 1985

सूचना

का.आ. 2486.—नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री ईश्वर दत्त शर्मा, एडवोकेट, 5547, न्यू चन्द्रावल, सब्जी मंडी, दिल्ली-7 ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए किया जा रहा है कि उसे दिल्ली व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्त पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं० 5(12)/85-न्या०]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 20th May, 1985

NOTICE

S.O. 2486.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ishwar Datt Sharma, Advocate, 5547, New Chandrawal, Subzi Mandi, Delhi 11007 for appointment as a Notary to practise in Delhi.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(12)/85-Judl.]

नई दिल्ली 24 मई, 1985

सूचना

का. आ. 2487:-नोटरीज नियम, 1956 के नियम 6क अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रामकृष्ण सत्य एडवोकेट अलवर, राजस्थान ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक

आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे अलवर (जिला) व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए।

[सं. 5 (13)/85-न्या.]
एस० गुप्तु०, सक्षम प्राधिकारी

New Delhi, the 24th May, 1985

NOTICE

S.O. 2487.—Notice is hereby given by the Competent Authority in pursuance of rule 6 of the Notaries Rules, 1956, that application has been made to the said Authority, under rule 4 of the said Rules, by Shri Ram Krishan Satya, Advocate, Alwar, (Rajasthan) for appointment as a Notary to practise in Alwar District.

2. Any objection to the appointment of the said person as a Notary may be submitted in writing to the undersigned within fourteen days of the publication of this Notice.

[No. F. 5(13)[85-Judl.]
S. GOOPTU, Competent Authority.

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

शुद्धि-पत्र

का० आ० 2488 :—भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग की अधिसूचना –

(1) सं० का० आ० 71(अ) तारीख 31 जनवरी 1985 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड (ii) तारीख 31 जनवरी 1985 में प्रकाशित हुई है की घोषणा में, राजपत्र के पृष्ठ सं० 2 पर निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम और पता के बाद "जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (ई) द्वारा खड़े किए गये हैं" शब्द अंत: स्थापित किए जाएगें ;

(2) सं० का०आ० 108(अ) तारीख 11 फरवरी 1985 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 3 उपखंड (II) तारीख 11 फरवरी 1985 में प्रकाशित हुई है की घोषणा में राजपत्र के पृष्ठ सं० 2 पर निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम और पता के बाद " जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (ई) द्वारा खड़े किए गये है" शब्द अंत: स्थापित किए जाएगें ;

(3) सं० का० आ० 187(अ) तारीख 12 मार्च 1985 जो भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ij) तारीख 12 मार्च 1985 में प्रकाशित हुई है कि:—

(i) घोषणा (1) में राजपत्र के पृष्ठ सं० 1 पर निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम और पता के बाद " जो भारत की कम्यनिस्ट पार्टी (मार्कसवादी) द्वारा खड़े किए गये हैं " शब्द अत: स्थापित किए जाएगें; और

(ii) घोषणा (2) में राजपत्र के पृष्ठ सं०. 1 पर निर्वाचित अभ्यर्थी के नाम और पता कें बाद "जो भारत की कम्युनिष्ट पार्टी (मार्कसवादी) द्वारा खड़े किए गये हैं" शब्द अंत: स्थापित किए जाएगे ।

[फ० सं० 13(1)/85–वि० ii]
एच० सी० सुमन अवर सचिव

(Legislative Department)

New Delhi, the 31st May, 1985

CORRIGENDA

S.O. 2488.—In the Ministry of Law and Justice, Legislative Department's notification,—

(1) S.O. No. 71(E), dated 31st January, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 31st January, 1985 at page 3,—

(i) in the declaration, after the name and address of the elected candidate, the words, "sponsored by Indian National Congress (I)" shall be inserted; and

(ii) in the concluding line of the said declaration, the words, "having become vacant" shall be omitted.

(2) S.O. No. 108(E), dated 11th February, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 11th February, 1985, at page 3,—

(i) in the declaration, after the name and address of the elected candidate, the words, "sponsored by Indian National Congress (I)" shall be inserted; and

(ii) in the concluding line of the said declaration, the words, "having become vacant" shall be omitted.

(3) S.O. No. 187(E), dated the 12th March, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 12th March, 1985, at page 2,—

(i) in declaration (1), after the name and address of the elected candidate, the words, "sponsored by Communist Party of India (Marxist)" shall be inserted; and

(ii) in declaration (2), after the name and address of the elected candidate, the words," sponsored by Communist Party of India (Marxist)" shall be inserted.

[F. No. 13(1)/85-Leg. II]
H. C. SUMAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1985

(आयकर)

का आ 2489—इस कार्यालय की दिनांक 12 मार्च, 82 की अधिसूचना सं 4514 (फा सं. 203/295/80-आ. क. नि.-II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि जगदाले साईंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, बंगलौर, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त फाउंडेशन अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त फाउंडेशन अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्था अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग नई दिल्ली को दरख्वास्त देगा। अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी।

संस्था

"जगदाले साईंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन, सपांगी टैंक रोड, बंगलौर।

यह अधिसूचना 7-2-1985 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6199/फा.स 203/45/85-आ.क.नि. II]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th April, 1985

(Income Tax)

S.O. 2489.—In continuation of this Office Notification No.4514 (F.No.203/295/80-ITA.II) dated the 12th March, 1982, in is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (thirty five/one/two) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Jagdale Scientific Research Foundation, Bangalore will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Foundation will furnish annual reurns of its scientific research activities of the Prescribed Authority for every financial years in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Foundation will submit to the prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Application received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Jagdale Scientific Research Foundation, Sampangi Tank Road, Bangalore".

This notification is effective for a period from 7-2-1985 to 31-3-1988.

[No. 6199/F. No. 203/45/85-ITA. II]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1985

(आयकर)

का.आ. 2490 —इस के सिलसिले मे, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम के 6 के साथ पठित आयकर अधिनिम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञानो के क्षेत्र में संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात :—

(1) यह कि सूर स्मारक मण्डल, कमला नगर, आगरा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों को पृथक लेखा रखेगा।

(2) यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रिया-कलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध मे प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

(3) यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

(4) यह कि उक्त संस्था अनुमोदन की समाप्ति के तीन मास पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगी। अनुमोदन की समाप्ति के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र को रद्द किया जासकता है।

संस्था

'सूर स्मारक मण्डल, कमला नगर, आगरा"

यह अधिसूचना दिनांक 16-2-1985 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6302 (फा.सं. 203/216/84-आ.क. नि-I]

New Delhi, the 23rd April, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2490.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purpose or clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five|one|three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Sur Smarak Mandali, Kamla Nagar, Agra will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its asses liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Applications received after the date of expiry of approval are libable be rejected.

INSTITUTION

"Sur Smark Mandal, Kamla Nagar, Agra".

This Notification is effective for a period from 16-2-1985 to 31-3-1986.

[No. 6202|F.No. 203|216|84-ITA.II]

का०आ० 2491.—इस कार्यालय की दिनांक 22 अगस्त, 1979 की अधिसूचना सं. 2976 (फा. सं. 203/65/79-आ. क. नि.-11 के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानो के क्षेत्र में संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि कृष्णामूर्ति फाउण्डेशन इंडिया, मद्रास वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उस के द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिकों अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापो की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररुप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजो में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के तीन मास पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्र को रद्द किया जा सकता है।

संस्था

"कृष्णामूर्ती फाउण्डेशन इंडिया, वसन्त विहार, मद्रास 600028"

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1982 31-12-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[स. 6203 (फा. स. 203/59/85-आ. क. नि. II)]

S.O. 2491.—In continuation of this office Notification No. 2976 (F. No. 203|65|79-ITA. II) the dated the 22nd August, 1979, it is hereby notified to general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-sect on (1) of Section 35 (Thirty five|One|Three) of the Income-ax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

(i) That the Krishnamurti Foundation India, Madras will maintain a separte account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institution will submit to the Proscribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institution will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Application received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Krishnamurti Foundation India, Vasant Vihar, Madras-600028".

This Noification is effective for a period from 1-4-1982 to 31-12-1985.

[No. 6203 (F. No. 203|59|85-ITA.II)]

का. आ. 2492.—इस कार्यालय की दिनांक 9 अक्तूबर, 1978 की अधिसूचना सं. 2541 (फा. सं. 203/110/78-आ. क. नि.-II के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संस्था" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि रिसर्च एंड डाक्युमेंटेशन सेंटर इन सोशल वैल्फेयर एंड डिवलेपमेंट, बम्बई वैज्ञानिक अनुसधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के तीन मास पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय नई दिल्ली को और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति के बाद प्राप्त प्रार्थनापत्र को रद्द किया जा सकता है।

संस्था

"रिसर्च एंड डाक्युमेंटेशन सेंटर इन सोशल वैल्फेयर एंड डिवलेपमेंट, दादाभाई नारोजी रोड, बम्बई

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1981 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6204 (फा. सं. 203/164/84-आ.क.नि. II)]

S.O. 2492.—In continuation of this Office Notification No. 2541 (F. No. 203|110|78-ITA II) dated the 9th October, 1978, it is hereby notified for general informat on that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/One/Three) of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:—

(i) That the Research and Documentation Central in in Social Welfare and Development, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet show ng ist assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 3 months in advance be-fore the expiry of the approval for further extension. Application received after the date of expiry if approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Research and Documentation Centre In Social Walfare and Development, Dadabhai Naroji Road. Bombay.

This Notification is effective for a period from 1-4-1981 to 31-3-1987

[No. 6204(F. No. 203|164|84-ITA.II)]

का. आ. 2493.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि लाल चन्द एग्रो रिसर्च इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्थान अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संस्थान अनुमोदन की समाप्ति के तीन मास पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को और अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति के बाद प्राप्त प्रार्थना पत्र को रद्द किया जा सकता है।

संस्था

'लाल चन्द एग्रो रिसर्च इन्स्टिट्यूट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली"

यह अधिसूचना दिनांक 16-2-1985 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6205 (फा. स. 203/173/84-आ. क. नि. II]

S.O. 2493.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 (Thirty five/one/two) of the Income tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions :—

i) That the Lal Chand Agro Research Institute, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

iii) That the said Institute will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets and liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

(iv) That the said Institute will apply to Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval for further extension. Application received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

"Lal Chand Agro Research Institute, Greater Kailash-II, New Delhi".

This Notification is effective for a period from 16-2-1985 to 31-3-1986.

[No. 6205 (F. No. 203/173/84-ITA. II)]

नई दिल्ली, 8 मई, 1985

का०आ० 2494.—इस कार्यालय की दिनांक 29-6-1983 की अधिसूचना सं० 5299(फा०सं० 203/31/78-आ०क० नि०II के सिलसिले में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य

प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है अर्थात्:—

1. यह कि पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, रायगढ़ उड़ीसा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2. यह कि उक्त संस्थान अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट उड़ीसा अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तिया, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

संस्था

पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, रायगढ़ उड़ीसा

यह अधिसूचना 1-4-1984 से 31-3-1985 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं० 6217 (फ़ा० सं० 203/119/84-आ०क०नि० II]

S.O. 2494.—In continuation of this office Notification No. 5299 (F. NO. 203|31|78-I T A. II) dated 29-6-83, it is hereby notiffied for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science and Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the purposes of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:—

(i) That the Pulp and Paper Research Institute, Raigada, Orissa will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institute will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the Pulp and Paper Research Institute, Raigada, Orissa will submit to the prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Pulp and Paper Research Institute, Raigada, Orissa. This notification is effective for a period of one year from 1-4-1984 to 31-3-1985.

[No. 6217 (F. No. 203/119/84-ITA-II)]

नई दिल्ली, 13 मई, 1985

(आयकर)

का. आ. 2495:—इस कार्यालय की दिनांक 25-3-1981 की अधिसूचना सं. 203/227/80 आ. क. नि.-II के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (II) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों के क्षेत्र में "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात:—

1. यह कि एस्पी कृषि अनुसंधान और विकास फ़ाउंडेशन वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक लेखा रहेगा।

2 यह कि उक्त संगम अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल, तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संगम अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगा।

4. यह कि उक्त संगम अनुमोदन की समाप्ति के 3 महीने पहले समयावधि बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई नई दिल्ली को आवेदन करेगा। अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा

संस्था

"एस्पी कृषि, अनुसंधान और विकास फ़ाउंडेशन, बी. जे. पटेल क्रस रोड न.-1, मलाड, बम्बई-400064

यह अधिसूचना 1-4-1984 से 31-12-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

[सं. 6219 (फ़ा. सं. 203/10/85-आ. क. नि.II]

गिरीश दवे, अवर सचिव

New Delhi, the 13th May, 1985

INCOME-TAX

S.O. 2495.—In continuation of this office Notification No. 3972 (F. NO. 203|227|80-ITA. II) dated 23-5-1981, it is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:—

(i) That the Aspee Agricultural Research & Development Foundation will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Association will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Association will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissiooner of Income-tax.

(iv) That the said Association will apply to C.B.D.T., Ministry of Finance, Deptt. of Revenue, New Delhi 3 months in advance before the expiry of the approval, for further extension. Application received after the date of expiry of approval are liable to be rejected.

INSTITUTION

Aspee Agricultural Research & Development Foundation B.J. Patel Cross Road, No. 1, Malad, Bombay-400064

This notification is effective for a period from 1-4-1984 to 31-12-1985.

[No. 6219 (F. No. 203/70/85-ITA. II]

GIRISH DAVE, Under Secy.

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

(आयकर)

का. आ. 2496.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री धर्म शास्ता उत्सवं ट्रस्ट" करणधाकर—निर्धारण वर्ष 1984–85 से 1985–87 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं. 6211 (फा.सं. 97/48/85–आ.क. नि.–1)]

आर. के. तिवारी, अवर सचिव

New Delhi, the 1st May, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 2496.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby Notifies, "Sree Dharma Sastha Utsavam Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1984-85 to 1986-87.

[No. 6211 F. No. 197/48/85-IT (AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 मई, 1985

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 2497—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा केवल बारह करोड़ रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों "आई. डी. बी. आई. ऋण 12.00 करोड़ रुपये (1985 प्रथम श्रृंखला" के रूप में जारी किए जाने वाले बन्ध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं 22/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/15/85-वि.क.]

New Delhi, the 15th May, 1985

ORDER

STAMPS

S.O. 2497.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes "IDBI Loan Rs. 12.00 Crores (1985)-1st Series" of the value of rupees Twelve crores only to be issued by the National Small Industries Corporation Ltd. are chargeable under the said Act.

[No. 22|85-Stamps-F. No. 33|15|85-ST]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 2498.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा केवल चालीस करोड़ बासठ लाख रुपए के मूल्य के ऋण पत्रों (ग्यारहवीं श्रृंखला) के रूप में जारी किए जाने वाले बंध पत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है।

[सं. 23/85 स्टाम्प-फा. सं. 33/17/85-वि. क.]

ORDER

STAMPS

S.O. 2498.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of debentures (Eleventh Series) of the value of rupees forty fourt crores and sixty two lakhs only to be issued by the Rural Electrifications Corporation Ltd., New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 23|85-Stamps-F. No. 33|17|85-ST]

नई दिल्ली 18 मई 1985

आदेश

स्टाम्प

का आ 499—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त शुल्क को माफ करती है जो आवास तथा शहरी विकास कारपोरेशन लि नई दिल्ली द्वारा केवल बीस करोड़ पचास लाख रुपये के "9 प्रतिशत ऋणपत्र 2000 XXII श्रृंखला" के रूप मे वर्णित बंधपत्रों के स्वरूप मे जारी किए जाने वाले प्रबंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभारी है।

[स 24/85–स्टाम्प–फा स 33/14/85–बि क]

भगवान दास, अवर सचिव

New Delhi, the 18th May, 1985

ORDER

STAMPS

S O 2499—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty, with which th bonds in the nature of debentures described as "9 00 per cent Debentures 2000-XXII Series" to the value of rupees Twenty crores and fifty lakhs only to be issued by the Housing and Urban Development Corporation Ltd, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No 24|85-Stamp-F No 33|14|85 ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy

नई दिल्ली, 6 मई 1985

प्रधान कार्यालय सस्थापन

का आ 2500—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 (1963 का सख्याक 54) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री सी के टिक्कू जो पिछले दिनो राजस्व विभाग मे सयुक्त सचिव (विदेश कर प्रभार) के रूप मे तैनात थे, 29 अप्रैल 1985 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा स ए–19011/15/83–प्रशा 1]

जे एम त्रेहन, अवर सचिव

New Delhi, the 6th May, 1985

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S O 2500—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963(No 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri C K Tikku an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) and formerly posted as Joint Secretary (F T D) in the Department of Revenue as Memebr of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 29th April, 1985.

[F No A 19011|15|83 Ad I]

J M TREHAN, Under Secy

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1984

का. आ. 2501 —सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की उस अधिसूचना को जो सख्या का. आ. 1903, दिनांक 31 मई, 1984 का भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड-3, उप खण्ड (ii), पृष्ठ 1768 पर दिनाक 16 जून, 1984 को प्रकाशित हुई थी, रद्द करती है।

[स एफ 1/27/(1)/83-काईन]

FINENCE MINISTRY

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 24th May, 1985

S O 2501—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906) the Central Government hereby cancels the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No S O 1903 dated the 31st May, 1984. published in the Gazette of India, part II Section 3, sub-section (ii), page 1768, dated the 16th June, 1984.

[No. F. 1|27|(i)|83-Coin]

का. आ. 2502 —सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 21 की उप-धारा (1) और धारा 7 के साथ पठित, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की उस अधिसूचना को जो संख्या का. आ 1904, दिनाक 31 मई, 1984 को भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii), पृष्ठ 1769 पर दिनाक 16 जून 1984 को प्रकाशित हुई थी, रद्द करती है।

[संख्या एफ 1/27 (II) 83-काईन]

सी. जी. पथरोज, अवर सचिव

S O 2502—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21, read with section 7, of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby cancels the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S O 1904, dated the 31st May, 1984, published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-Section (ii), page 1769, dated the 16th June, 1984.

[No. F.1|27|(ii)|83-Coin]

C. G PATHROSE, Under Secy

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली 23 मई, 1985

शुद्धि-पत्र

का आ 2503 —भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II खंड 3 उपखंड (ii) मे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग) की दिनांक 14 नवम्बर, 1984 की अधिसूचना का. आ. सख्या 837(अ) के अंग्रेजी पाठ की तीसरी और चौथी पंक्ति में "6th day of November, 1984 के स्थान पर "16th day of November, 1984 पढ़ा जाये।

[संख्या एफ. 2/7/84-बी. ओ.-1]

एस. एस. हसूरकर, निदेशक

(Banking Division)

New Delhi, the 23rd May, 1985

CORRIGENDUM

S.O 2503—In the English version of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) (Banking Division) No. S O 837(E), dated the 14th November, 1984, published at

page 2 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), in lines 3 and 4 for "6th day of November, 1984" read "16th day of November, 1984".

[No. F. 2/7/84-BO I]
S. S. HASURKAR, Director

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 1985

का आ 2504 केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) की धारा 21 की उप-धारा (2) के अनुसरण मे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर 10, 11 और 12 जून, 1985 को उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले और 10,11 और 12 जून, 1998 को परिपक्व होने वाले बाडो पर देय ब्याज की दर को एतद्द्वारा 9 75% (नौ दशमलव पचहत्तर प्रतिशत) वार्षिक निर्धारित करती है।

[फा स. 6 (7) आई एफ I / 85]
के. पी० पांडियन, अवर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 29th May, 1985

S.O. 2504.—In pursuance of Sub-section 2 of Section 21 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 (15 of 1948), the Central Government, on the recommendation of the Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of India, hereby fixes 9.75% (nine and three quarters) per annum as the rate of interest payable on the bonds to be issued by the said Corporation on 10th, 11th and 12th June, 1985 and maturing on 10th, 11th and 12th June, 1998.

[F. No. 6(7)|IFI|85]
K. P PANDIAN, Under Secy.

समाहर्तालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर

अधिसूचना स० सी ई आर/आर-5/1/85

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नागपुर, 18 मई, 1985

का. आ 2505 अधिसूचना स सी ई आर/आर-5/1/84 दिनांक 7-1-1984 निम्नलिखित अनुसार सशोधित की जाती है। कथित अधिसूचना के अनुबध मे —

1 क्रम सख्या 48 विलुप्त की जाएगी।

2 प्रविष्टि क्रम स 73 एव 84 मे नीचे लिखे अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

क्र स	के उ शु नियम	प्रत्यायोजित शक्तियों का स्वरूप	अधिकारी जिसे प्रत्यायोजित की गई	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	173 एल तथा 173 एम	(i) माल के संग्रहण मे छूट देने की शक्ति	अपर समाहर्ता	—
		(ii) माल की वापसी की अवधि बढ़ाने की शक्ति	अपर समाहर्ता	—
		(iii) समाहर्ता की अन्य शक्तिया	सहायक समाहर्ता	
84	192	(i) स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति	परिहार अधिसूचना मे दर्शाए अधिकारी अन्यथा सहायक समाहर्ता	
		(ii) अनुज्ञप्ति जारी करने तथा बधपत्र राशि एव प्रतिभूति निर्धारित करने की अधिकार	अनुज्ञप्ति अधिकारी	

[सी सं 4(16) 8-22/180-के. उ. शु. (भाग I]
कश्मीरा सिंह, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE
NOTIFICATION NO. CER|R-5|1|85
CENTRAL EXCISE

S.O. 2505 Notification No. CER/R-5/1/84 dated 7/1/84 shall be amended as under

1. In Annexure to the said notification

1. Sr. No. 48 shall be omitted.

2. For Sr. No. 73 and 84 of the Annexure the following shall be substituted.

1	2	3	4	5
73	173-L & 173-M	(i) Power to relax storage of goods	Additional Collector.	..
		(ii) Power to extend the period for return of goods	—do—	..
		(iii) Collector's other powers.	Assistent Collector	
84	192	(i) Power to grant permission.	Officer mentioned in remission notification, otherwise Assistant Collector.	..
		(ii) Power to issue licence and fixing of bond amount and security.	Licensing Authority.	..

[C. No. IV (16) 8-22/80/CX/Pt. I]
KASHMIRA SINGH, COLLECTOR

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मई, 1985

का० आ० 2506 --केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 सू उप-नियम (4) के अनुसरण मे दि ब्रिटिश इडिया कारपोरेशन लि , कानपुर को, जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[फाइल स. ई-11011/12/76-हिंदी]

उमेश प्रसाद सिंह, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 25th May, 1985

S.O. 2506.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the The British India Corporation Limited, Kanpur, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[F. No. E-11011/12/76-Hindi]

U. P. SINGH, Director

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 मई, 1985

आदेश

का. आ. 2507—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स, को, अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची 1 की मद 3 के साथ पठित खंड 2 (ङ) के प्रयोजनों के लिए अखबारी कागज का उत्पादन करने वाली मिल के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फाइल संख्या 5 (2)/81—कागज]

जी० सुन्दरम, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 28th May, 1985

ORDER

S.O. 2507.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby specifies Tamil Nadu Newsprint and Papers as a Mill producing newsprint for purposes of clause 2(e) read with item 3 of Schedule I of the Newsprint Control Order, 1962.

[F. No. 5(2)/81-Paper]

G. SUNDARAM, Under Secy.

परमाणु ऊर्जा मंत्रालय

बम्बई, 2 मई, 1985

का०आ० 2508·--केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40वाँ की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तारीख 24-5-1983 के का. आ. सख्या 1228 मे निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् --

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तम्भ (2) मे की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी .

"ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना, परमाण ऊर्जा विभाग, जिला सूरत, गुजरात के स्वामित्व के या उसके प्रशासनिक नियत्रणाधीन परिसर"

[स. 13/32/84- एस एस एस]

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Bombay, the 2nd May, 1985

S.O. 2508.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India, Department of Atomic Energy S.O. No. 1228 dated 24-5-1983 namely :—

In the table to the said notification, in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted :

'Premises belonging to or under the Administrative Control of Kakrapar Atomic Power Project, Department of Atomic Energy, District Surat, Gujarat'.

[No. 13/32/84-SSS]

का आ 2509·--केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40वाँ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत, सरकार के (परमाणु ऊर्जा विभाग के तारीख 22-3-1983 के) का. आ. संख्या 1227 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, स्तम्भ (2) में की गई प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी·

"आंध्र प्रदेश के रंगा रेड्डी जिले में परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वामित्व के या उसके प्रशासनिक नियत्रणाधीन परिसर"

[सं. 13/32/84- एस एस एस]

S.O. 2509.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India, Department of Atomic Energy S.O. No. 1227 dated 22nd March, 1983 namely :

In the Table to the said notification, in column (2) for the entry, the following entry shall be substituted :

'Premises belonging to or under the Administrative control of the Department of Atomic Energy in Renga Ready District of Andhra Pradesh'.

[No. 13/32/84-SSS]

का आ 2510:—केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40वाँ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी को, जो कि सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समान पद का अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त करती है।

उक्त अधिकारी उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परिसरों के सबध में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में, उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करेगे, और उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अन्तर्गत संपदा अधिकारियों मे अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सार्वजनिक परिसर
(1)	(2)
प्रधान, कार्मिक वर्ग, इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, चरलापल्ली, हैदराबाद 500762 के स्वामित्व के या उस कारपोरेशन के लिए पट्टे पर लिए गए वे परिसर जो बम्बई, महाराष्ट्र तथा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राज्य में उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं।

[सं. 13/32/84-एस एस एस]
एस. पी. सिंह, उप सचिव

S.O. 2510—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of a Gazetted Officer of the Government, to be the Estate Officer for the purposes of the said Act.

The said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officers by or under the said act within the local limits of his jurisdiction, in respect of the public premises specified in column (2) of the said table.

TABLE

Designation of the officer	Public Premises
(1)	(2)
Head Personnel Group Electronics Corporation of India Limited.	Premises belonging to or taken on lease for the Electronics Corporation of India Ltd., Industrial Development Area Cherlapally Hyderabad-500762 and which are under its administrative control in Bombay, Maharashtra and in Hyderabad, Andhra Pradesh State.

[No. 13/32/84–SSS]
S.P. SINGH, Dy. Secy.

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 1985

का. आ. 2511 —भारतीय चिकित्सा परिषद् नियम, 1957 के नियम 2 के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री वी. गोपाल कृष्णन नायर उप-सचिव, स्वास्थ्य विभाग, केरल सरकार, को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत केरल राज्य में भारतीय चिकित्सा परिषद् के सदस्य का निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या वी-11013/6/85-एम. ई. (पी)]
चन्द्रभान, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 20th May, 1985

S.O. 2511.—In pursuance of clause (d) of rule 2 of the Medical Council Rules, 1957, the Central Govt. hereby appoints Shri. V. Gopalakrishnan Nair, Deputy Secretary, Health Deptt. Government of Kerala, as Returning Officer for the conduct of election of a member to the Medical Council of India under clause (c) of sub-section (1) of sec. 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) in the State of Kerala.

[No. V-11013|6|85-ME(P)]
CHANDERBHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 1985

का० आ० 2512:—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सचिव श्री आनन्द स्वरूप को, श्रीमती सरला ग्रेवाल जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का एक सदस्य मनोनीत करती है और भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 6 जुलाई, 1983 को अधिसूचना संख्या का आ. 2959 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"श्री आनन्द स्वरूप सचिव, शिक्षा मंत्रालय	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

[सं. को. 16011/1/85-एम.ई. (पी. जी.)]
पी० आर० दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

New Delhi, 23rd May, 1985

S.O. 2512—In pursuance of clause (d) of section 4 read with sub-section (3) of section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri Anand Sarup, Secretary, Ministry of Education, to be a member of the All-India Institute of Medical Sciences, *vice* Smt. Serla Grewal resigned, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. S.O. 2959, dated the 6th July, 1983, namely :—

In the said notification, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

"1. Shri Anand Sarup, Secretary, Ministry of Education	— Representative of the Ministry of Education "

[No. V. 16011/1/85-ME(PG)
P. R. DASGUPTA, Jt. Secy.

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 17 मई, 1985

का० आ० 2513—केन्द्रीय सरकार पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 जिसका 30 जुलाई 1982 तक संशोधन

किया गया है, की धारा 5 की उपधारा (1) (i) के उपबन्धों के अंतर्गत, एतद्द्वारा निम्नलिखित संसद (लोकसभा) सदस्यों को तत्काल से तथा आगामी आदेशों तक भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद करती है :

संसद सदस्य का नाम

1. श्री पी. चिदाम्बरम
तामिलनाडु हाऊस,
नयी दिल्ली ।

2. श्री मानवेन्द्र सिंह,
506, एक्स्टर्नल एफेयर्स होस्टल,
नयी दिल्ली ।

3. श्री प्रकाश चन्द्र,
107, नार्थ एवेन्यु,
नयी दिल्ली-110001,

4. श्री सी. जंगा रेड्डी,
127-129, साउथ एवेन्यु,
नयी दिल्ली-110011.

[संख्या 14-6/85-एल. डी. I]
के. जी. कृष्णमूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 17th May, 1985

S.O. 2513.—Under provision of Sub-section (1)(i) of Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, as amended upto 30th July, 1982, the Central Government hereby nominate the following Members of Parliament (Lok Sabha) to be members of Animal Welfare Board of India with immediate effect and until further orders :—

Name of Member of Parliament

1. Shri P. Chidambaram,
Tamil Nadu House,
New Delhi.

2. Shri Manvendra Singh,
506, External Affairs Hostel,
New Delhi.

3. Shri Prakash Chandra,
107, North Avenue,
New Delhi-110001.

4. Shri C. Janga Reddy,
127-129, South Avenue,
New Delhi-110011.

[No 14-6/85-LD.I]
K. G. KRISHNAMOORTHY, Dy. Secy.

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

का. आ. 2514—व्यापार और पण्य वस्त चिह्न नियम, 1959 के नियम 157 के उप नियम (2) के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त नियम, 175 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार व्यापार चिह्नों के एजेन्टों के रजिस्टर में अंकित करने के लिए नीचे दिखाये गये परिवर्तन करती है :—

व्यापार चिन्हों के एजेंट का नाम	व्यावसाय के मुख्य स्थान का पता
श्री एम. आर. लक्ष्मी नारायन राव	दि आल इण्डिया ट्रेड मार्क्स एजेंसी, 367, 8वां क्रास, प्रथम ब्लाक, जयनगर, बंगलौर ।

[फा. सं. 29/1/आई/टी/टी एम/84]
पी. एन. कौल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 27th May, 1985

S.O.2514.—In pursuance of sub rule (2) of rule 157 of the Trade and Merchandise Marks Rules, 1959, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of the said rule 157, the Central Government has caused the following alterations to be made in the Register of Trade Marks Agent as shown below :—

Name of the Trade Marks Agent	Address of the Principal place of business
Shri M.R. Lakshmi Narayan Rao	The All India Trade Marks Agency, 367, 8th Cross, 1st Block, Jayanagar, Bangalore.

[F. No. 29/1/IT/TM/84]
P. N. KAUL, Economic Adviser

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

का. आ. 2515.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1910 का 9) की धारा 36 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान सुरक्षा महानिदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय पूरे भारत में खानों के लिए विद्युत निरीक्षक नियुक्त करती है :

1. श्री वी. रमण राव, उप निदेशक, खान सुरक्षा (विद्युत)
2. श्री जे. एन्थोनी " "
3. श्री आर. प्रसाद " "
4. श्री पी. मालवीय " "
5. श्री कहर सिंह " "
6. श्री डी. के. राय " "

[फाइल सं. 27/37/84-डेस्क (एस. ई.बी)]
जरनैल सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

(Department of Power)

New Delhi, the 27th May, 1985

S.O. 2515.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 36 of the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), the Central Government hereby appoints the undermentioned officers employed in the Directorate General of Mines Safety to be the Electrical Inspectors for mines under the said Act, in the whole of India except the State of Jammu & Kashmir :—

1. Shri V. Ramana Rao, Dy. Director of Mines Safety (Electrical)
2. Shri J. Anthony Dy. Director of Mines Safety (Electrical)
3. Shri R. Prasad, Dy. Director of Mines Safety (Electrical)
4. Shri O. P. Malviya, Dy. Director of Mines Safety (Electrical)
5. Shri Kehar Singh, Dy. Director of Mines Safety (Electrical)
6. Shri D. K. Roy, Dy. Director of Mines Safety (Electrical)

[File No. 27|32|84-D(SEB)]

JARNAIL SINGH, Dy. Secy.

पैट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली 29 मई 1985

का. आ. 2516.—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3900 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	लिया गया रकबा (एकड़ मे)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महराज गंज	मछरावा	मल्लपुर	1266	0-19-0	
				1267	0-5-15	
				1265	0-5-0	
				1264	0-3-10	
				201	0-3-0	
				202	0-13-10	
				206	0-1-10	
				207	0-16-0	
				183	0-11-0	
				179	0-11-15	
				175	0-0-15	
				177	0-5-0	
				176	0-11-5	
				154	0-4-10	
				153	0-2-0	
				152	0-7-10	
				371	0-16-0	
				386	0-3-0	
				370	0-12-5	
				368	0-6-6	
				401	0-3-15	
				367	0-2-15	
				366	0-1-10	
				396	0-4-5	
				365	0-6-15	
				400	0-2-15	
				399	0-14-0	
				397	0-1-15	
				398	0-5-10	
				401	0-1-15	
				416	1-0-0	
				415	0-2-15	
				417	0-8-10	
				411	0-16-0	
				694	1-0-10	
				698	0-2-15	
				708	0-3-15	
				707	0-5-10	
				706	0-2-0	
				709	0-0-3	
				699	0-4-0	
				705	0-5-0	
				704	0-7-0	
				710	0-7-0	
				715	1-0-0	
				711	0-1-0	
				714	0-10-10	
				713	0-11-18	
				1106	1-7-0	

1	2	3	4	5	6	7
				1108	0–0–6	
				1107	0–16–13	
				1105	0–13–0	
				1114	0–14–0	
				1104	0–1–10	
				1103	0–7–10	
				1102	0–8–0	
				1101	0–12–5	
				1062	0–2–5	
				1060	0–7–0	
				1061	0–1–17	
				1069	0–1–2	
				1068	0–14–0	
				1057	0–3–0	
				1056	0–7–10	
				1020	0–1–10	
				1021	0–1–4	
				1026	0–3–6	
				1027	0–1–0	
				1028	0–4–10	
				1029	0–5–14	
				1035	0–3–10	
				1036	0–13–10	
				1031	0–2–4	
				1055	0–4–10	
				1022	0–5–19	
				51	0–9–0	
				183	0–6–0	
				184	0–2–3	
				185	0–17–17	
				697	0–1–0	
				208	0–2–0	
				210	0–1–5	
				412	0–4–0	
				419	0–0–2	
				200	0–0–4	
				188	0–15–5	
				369	0–0–10	

[सं० O- 14016/240/84-ओपी]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 29th May, 1985

S.O. 2516.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3901 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Barielly–Jagdishpur–Pipeline Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	AREA Acquired (Acres)		Remarks
1	2	3	4	5	6		7
Rai-Barielly	Maharaj ganj	Bachh-rawan	Mal-pur	1266	0	19	0
				1267	0	5	15
				1265	0	5	0
				1264	0	3	10
				201	0	3	0
				202	0	13	10
				206	0	1	10
				207	0	16	0
				183	0	11	0
				179	0	11	15
				175	0	0	15
				177	0	5	0
				176	0	11	5
				154	0	4	10
				153	0	2	0
				152	0	7	10
				371	0	16	0
				386	0	3	0
				370	0	12	5
				368	0	6	6
				401	0	3	15
				367	0	2	15
				366	0	1	10
				396	0	4	5
				365	0	6	15
				400	0	2	15
				399	0	14	0
				397	0	1	15
				398	0	5	10
				401	0	1	15
				416	1	0	0
				415	0	2	15
				417	0	8	10
				411	0	16	0
				624	1	0	10
				698	0	2	15
				708	0	3	15
				707	0	5	10
				706	0	2	0
				709	0	0	3
				699	0	4	0
				705	0	5	0
				704	0	7	0
				710	0	7	0
				715	1	0	0
				711	0	1	3
				714	0	10	10
				713	0	14	18
				1106	1	7	0
				1108	0	0	6
				1107	0	16	13

1	2	3	4	5	6			7
				1105	0	13	0	
				1114	0	14	0	
				1104	0	1	10	
				1103	0	7	10	
				1102	0	8	0	
				1101	0	12	5	
				1062	0	2	5	
				1060	0	7	0	
				1061	0	1	17	
				1069	0	1	2	
				1068	0	14	0	
				1057	0	3	0	
				1056	0	7	10	
				1020	0	1	10	
				1021	0	1	4	
				1026	0	3	6	
				1027	0	1	0	
				1028	0	4	10	
				1029	0	5	14	
				1035	0	3	10	
				1036	0	13	10	
				1031	0	2	4	
				1055	0	4	10	
				1022	0	5	19	
				51	0	9	0	
				183	0	6	0	
				184	0	2	3	
				185	0	17	17	
				697	0	1	0	
				208	0	2	0	
				210	0	1	5	
				412	0	4	0	
				419	0	0	2	
				200	0	0	4	
				188	0	15	5	
				369	0	0	10	

[No. O-14016/240/84-GP]

का. आ. 2517 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3707 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं०	लिया गया रकबा-विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महराजगंज	मछरावा	पुनेन्द्री	1360	0-6-6	
				1361	0-17-5	
				1384	0-0-1	
				1385	0-16-10	
				1386	0-0-6	
				1389	0-1-10	
				1390	0-5-15	
				1391	0-3-3	
				1392	1-3-18	
				1393	0-1-16	
				1394	0-2-10	
				1395	0-14-6	
				1396	0-0-1	
				1436	0-1-10	
				1437	0-14-1	
				1443	0-0-1	
				1444	0-1-10	
				1448	0-7-16	
				1504	0-4-16	
				1504/3170	0-4-14	
				1505	0-17-10	
				1507	0-0-13	
				1508	0-7-4	
				1508/3171	0-4-12	
				1515	0-0-1	
				1517/3172	0-1-3	
				1551	0-1-8	
				1552	0-3-15	
				1553	0-2-5	
				1585	0-1-0	
				1593	0-1-13	
				1594	0-8-7	
				1595	0-0-15	
				1596	0-2-1	
				1598	0-12-1	
				1599	0-13-2	
				1600	0-0-1	

1	2	3	4	5	6	7
				1602	0-0-8	
				1632	0-0-1	
				1633	0-1-10	
				1634	0-9-14	
				1635	0-1-19	
				1638	0-4-5	
				1639	1-1-0	
				1640	0-0-14	
				1641	0-11-2	
				1642	0-0-1	
				1643	0-5-6	
				1645	0-0-1	
				2172	0-3-11	
				2230	0-1-14	
				2231	0-2-10	
				2232	0-4-0	
				2235	0-0-1	
				2236	0-00-1	
				2237	0-0-3	
				2238	0-0-5	
				2239	0-0-8	
				2240	0-0-12	
				2241	0-00-15	
				2242	0-0-1	
				2306	0-9-0	
				2307	0-0-15	
				2308	0-7-15	
				2311	0-00-16	
				2362	0-0-1	
				2363	1-1-10	
				2364	0-9-5	
				2365	0-1-7	
				2367	0-6-10	
				2368	0-2-15	
				2370	0-1-15	
				2371	0-2-15	
				2372	0-13-5	
				2376	1-4-10	
				2380	0-5-5	
				2381	0-15-2	
				2382	0-17-10	
				2393	0-13-10	
				2394	0-8-2	
				2395	0-6-10	
				2396	0-7-0	
				2397	0-5-15	
				2398	0-17-0	
				2402	0-13-00	
				2429	0-18-10	
				2430	0-0-0	
				2431	0-10-15	
				2432	0-1-5	
				2433	0-5-8	
				2434	0-1-0	
				2436	0-9-5	
				2437	0-1-0	
				2528	0-0-10	
				2530	0-00-1	
				2531	0-5-0	
				2532	0-1-10	
				2533	0-0-15	
				2534	0-0-10	
				2535	0-3-18	
				2536	0-0-15	
				2537	0-5-0	
				2539	0-1-12	
				2540	0-0-1	
				2448	1-17-5	
				2577	0-0-17	

[सं. O-14016/164/84-जीपी]

S.O. 2517.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3707 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule apprended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired			Remarks
1	2	3	4	5	6			7
Rae-Bareli	Mahar-Ganji	Bach-rawan	Thalendi	1360	0	6	6	
				1361	0	17	5	
				1384	0	0	1	
				1385	0	16	10	
				1386	0	0	6	
				1389	0	1	10	
				1390	0	5	15	
				1391	0	3	3	
				1392	1	3	18	
				1393	0	1	16	
				1394	0	2	10	
				1395	0	14	6	
				1396	0	0	1	
				1436	0	1	10	

1	2	3	4	5	6		7
				1437	0	14	1
				1443	0	0	1
				1444	0	1	10
				1448	0	7	16
				1504	0	4	16
				1504/			
				3170	0	4	14
				1505	0	17	10
				1507	0	0	13
				1508	0	7	4
				1508/			
				3171	0	4	12
				1515	0	0	1
				1517/			
				3172	0	1	3
				1551	0	1	8
				1552	0	3	15
				1553	0	2	5
				1585	0	1	0
				1593	0	1	13
				1594	0	8	7
				1595	0	0	15
				1596	0	2	1
				1598	0	12	1
				1599	0	13	2
				1600	0	0	1
				1602	0	0	8
				1632	0	0	1
				1633	0	1	10
				1634	0	9	14
				1635	0	1	19
				1638	0	4	5
				1639	1	1	0
				1640	0	0	14
				1641	0	11	2
				1642	0	0	1
				1643	0	5	6
				1645	0	0	1
				2172	0	3	14
				2230	0	4	14
				2231	0	2	10
				2232	0	4	0
				2235	0	0	1
				2236	0	0	1
				2237	0	0	3
				2238	0	0	5
				2239	0	0	8
				2240	0	0	12
				2241	0	0	15
				2242	0	0	1
				2396	0	9	0
				2307	0	0	15
				2308	0	7	15
				2311	0	0	16
				2362	0	0	1
				2363	1	1	10
				2364	0	9	5
				2365	0	1	7
				2367	0	6	10
				2368	0	2	15
				2370	0	1	15
				2371	0	2	15
				2372	0	13	5
				2376	1	4	10
				2380	0	5	5
				2381	0	15	2
				2382	0	17	10
				2393	0	13	10
				2394	0	8	2
				2395	0	6	10
				2396	0	7	0
				2397	0	5	15
				2398	0	17	0
				2402	0	13	0
				2429	0	18	10
				2430	0	0	0
				2431	0	10	15
				2432	0	1	5
				2433	0	5	8
				2434	0	1	0
				2436	0	9	5
				2437	0	1	0
				2528	0	0	10
				2530	0	0	1
				2531	0	5	0
				2532	0	1	10
				2533	0	0	15
				2534	0	0	10
				2535	0	3	18
				2536	0	0	15
				2537	0	5	0
				2539	0	1	12
				2540	0	0	1
				2448	1	17	5
				2377	0	0	17

[No. O-14016/164/84-GP]

का. आ. 2518.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3900 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी

बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	बछरावां	बछरावां	1671	0-1-4	
				1885एम	0-13-4	
				1886एम	0-18-12	
				4497एम	0-1-0	
				4496	0-1-8	
				4502	0-0-12	
				4503	0-1-0	
				4504एम	0-2-10	
				4512एम	0-4-0	
				4513एम	0-5-3	
				4514एम	0-7-12	
				4515	0-0-18	
				4516	0-12-14	
				4519एम	1-6-8	
				4541एम	0-9-9	
				4543	0-0-5	
				4544	0-1-10	
				4545एम	0-19-4	
				4546एम	0-18-14	
				4596एम	0-1-10	
				4597	0-4-0	
				4549	0-6-12	
				4645	0-2-10	
				4646	0-2-0	
				4647	0-1-10	
				4649	0-5-10	
				4650	0-1-10	
				4651	0-2-10	
				4654	0-2-0	
				4655	0-0-10	
				4656	0-3-0	
				4658	0-1-0	
				4659	0-1-15	
				4660	0-0-10	
				4661	0-2-10	
				4662	0-0-15	
				4665	0-4-5	
				4663	0-1-5	
				4666	0-7-10	
				4667	0-1-0	
				4673	1-1-10	
				4674	0-2-10	
				4675	0-1-14	
				4928	0-10-10	
				4929	0-5-10	
				4930	1-1-10	
				4931	0-0-10	
				4932	0-12-0	
				4933	0-1-10	
				4934	0-0-10	
				4938	0-1-10	
				4939	0-1-15	
				4947	0-1-5	
				4948	0-1-15	
				4950	0-2-10	
				4951	0-2-0	
				4952	0-1-10	
				4953	0-2-10	
				4955	0-4-0	
				4956	0-2-10	
				4957	0-1-0	
				4959	0-2-10	
				4968	1-10-10	

[सं. O-14016/238/84-जीपी]

S.O. 2518.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 3900 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira–Bareilly–Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Para-gana	Village	Plot No.	Area Acquired			Re-marks
1	2	3	4	5	6			7
Rai-bareli	Maha-rajganj	Bach-chrawa	Bach-chrawa	1671	0	1	4	
				1885M	0	13	4	
				1886M	0	18	12	
				4497M	0	1	0	
				4496	0	1	8	
				4502	0	0	12	
				4503	0	1	0	
				4504M	0	2	10	
				4512M	0	4	0	
				4513M	0	5	3	
				4514M	0	7	12	

1	2	3	4	5	6	7
				4515 0	0	18
				4516 0	12	14
				4519M 1	6	8
				4541M 0	9	9
				4543 0	0	5
				4544 0	1	10
				4545M 0	19	4
				4546M 0	18	14
				4596M 0	1	10
				4597 0	4	0
				4549 0	6	12
				4645 0	2	10
				4646 0	2	0
				4647 0	1	10
				4649 0	5	10
				4650 0	1	10
				4651 0	2	10
				4654 0	2	0
				4655 0	0	10
				4656 0	3	0
				4658 0	1	0
				4659 0	1	15
				4660 0	0	10
				4661 0	2	10
				4662 0	0	15
				4665 0	4	5
				4663 0	1	5
				4666 0	7	10
				4667 0	1	0
				4673 1	1	10
				4674 0	2	10
				4675 0	1	14
				4928 0	10	10
				4929 0	5	10
				4930 1	1	10
				4931 0	0	10
				4932 0	12	0
				4933 0	1	10
				4934 0	0	10
				4938 0	1	10
				4939 0	1	15
				4947 0	1	5
				4948 0	1	15
				4950 0	2	10
				4951 0	2	0
				4952 0	1	10
				4953 0	2	10
				4955 0	4	0
				4956 0	2	10
				4957 0	1	0
				4959 0	2	10
				4968 1	10	10

[No. O-14016/238/84-GP]

का आ. 2519.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात-	अकबरपुर-	अकबरपुर-	हसनापुर	381	1-5-0	
				384	1-8-0	
				386	0-1-8	
				385	1-19-0	
				887	0-0-17	
				381	0-19-0	
				392	0-2-10	
				565	0-15-10	
				559	1-0-0	
				566	1-4-0	
				457	0-1-17	
				567	0-0-17	
				564	0-3-8	
				574	0-1-4	
				582	0-11-0	
				583	0-13-6	
				581	0-0-17	
				579	2-0-0	
				580	0-5-17	
				762	4-9-15	
				761	4-12-13	
				759	0-6-2	
				758	1-13-17	
				753मि	2-5-3	
				753मि	1-0-0	
				753मि	1-5-0	
				753मि	1-0-0	
				753मि	0-10-0	

[सं. O-14016/191/84-जीपी]

S.O. 2519.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3799 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) ofo the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Schedule

Hajira Bariclly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Required	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kan-pur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Hasna-pur	381	1-5-0	
				384	1-8-0	
				386	0-1-8	
				385	1-19-0	
				387	0-0-17	
				381	0-19-0	
				392	0-2-10	
				565	0-15-10	
				559	1-0-0	
				566	1-4-0	
				457	0-1-17	
				567	0-0-17	
				564	0-3-8	
				574	0-1-4	
				582	0-11-0	
				583	0-13-6	
				581	0-0-17	
				579	2-0-0	
				580	0-5-17	
				762	4-9-15	
				761	4-12-13	
				759	0-6-2	
				758	1-13-17	
				753Min	2-5-3	
				753Min	1-0-0	
				753Min	1-5-0	
				753Min	1-0-0	
				753Min	0-10-0	

[No. O-14016/191/84-GP]

का.आ. 2520.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4080 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली-	महराजगंज-	बछरावां-	मनोहार कटरा			
				749	0-12-0	
				193	0-3-0	
				196	0-1-0	
				191	0-0-17	
				190	0-0-15	
				189	0-6-0	
				201	0-1-0	
				200	0-0-10	
				204	0-12-0	
				205	0-0-10	
				206	0-12-0	
				207	0-1-0	
				208	0-2-0	
				210	0-7-0	
				194	0-10-0	
				195/2	0-10-0	
				195/1	0-3-0	
				160	0-9-12	
				157	0-10-10	
				155	0-1-0	
				156	0-5-0	

1	2	3	4	5	6	7
				155	0-8-8	
				153	0-0-15	
				154	0-3-0	
				151	0-1-0	
				150	0-0-10	
				251	0-1-0	
				230	0-4-0	
				739	0-13-17	
				236	0-3-12	
				719	0-8-8	
				720	0-10-16	
				238	0-9-7	
				717/1	0-3-10	
				717/3	0-9-0	
				529/1	0-8-0	
				529/2	0-8-1	
				528	0-5-9	
				532	0-16-16	
				533	0-2-5	
				550	0-3-12	
				551	0-9-12	
				552	0-1-0	
				553	0-5-0	
				548	0-1-16	
				549	0-1-0	
				560	0-2-0	
				561	0-9-12	
				565	0-3-0	
				566	0-4-0	
				567	0-1-0	
				572	0-19-4	
				573	1-0-0	
				574	0-0-10	
				577	0-1-0	
				578	0-4-0	
				579	0-2-0	
				580	0-19-4	
				581	0-1-0	
				582	0-2-0	
				597	0-4-1	
				596	0-2-0	
				594	0-5-0	
				636	0-9-0	
				637	0-1-0	
				638	0-3-0	
				635	0-19-4	
				598	0-2-0	
				925	0-1-0	
				639	0-1-0	
				923	0-2-0	
				922	0-11-0	
				929	0-11-4	
				928	0-10-4	
				927	0-9-0	
				932	1-9-8	
				934	0-8-0	
				935	0-5-0	
				531	0-10-0	
				543	0-0-15	

[स. O-14016/319/84-जीपी]

S.O. 2520.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 4080 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Schedule

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rai Barielly	Maharaj ganj	Bachh-rawan	Manohar Katra	749	0-12-0	
				193	0-3-0	
				196	0-1-0	
				191	0-0-17	
				190	0-0-15	
				189	0-6-0	
				201	0-1-0	
				200	0-0-10	
				204	0-12-0	
				205	0-0-10	
				206	0-12-0	
				207	0-1-0	
				208	0-2-0	
				210	0-7-0	
				194	0-10-0	
				195/2	0-10-0	
				195/1	0-3-0	
				160	0-9-12	
				157	0-10-10	
				158	0-1-0	
				156	0-5-0	
				155	0-8-8	
				153	0-0-15	
				154	0-3-0	
				151	0-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				150	0-0-10	
				251	0-1-0	
				230	0-4-0	
				239	0-13-17	
				236	0-3-12	
				719	0-8-8	
				720	0-10-16	
				238	0-9-7	
				717/1	0-3-10	
				717/3	0-9-0	
				529/1	0-8-0	
				529/2	0-8-1	
				528	0-5-9	
				532	0-16-16	
				533	0-2-5	
				550	0-3-12	
				551	0-9-12	
				552	0-1-0	
				553	0-5-0	
				548	0-1-16	
				549	0-1-0	
				560	0-2-0	
				561	0-9-12	
				565	0-3-0	
				566	0-4-0	
				567	0-1-0	
				572	0-19-4	
				573	1-0-0	
				574	0-0-10	
				577	0-1-0	
				578	0-4-0	
				579	0-2-0	
				580	0-19-4	
				581	0-1-0	
				582	0-2-0	
				597	0-4-1	
				595/2	0-8-14	
				595/1	0-5-0	
				596	0-2-0	
				594	0-5-0	
				636	0-9-0	
				637	0-1-0	
				638	0-3-0	
				635	0-19-4	
				598	0-2-0	
				925	0-1-0	
				639	0-1-0	
				923	0-2-0	
				922	0-11-0	
				929	0-11-4	
				928	0-10-4	
				927	0-9-0	
				923	1-9-8	
				934	0-8-0	
				935	0-5-0	
				531	0-10-0	
				543	0-0-15	

[No. O-14016/319/84-GP]

का. आ. 2521.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4078 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्रामका नाम	लिया गया रकबा-विवरण		
1	2	3	4	5	6	7
राय बरेली	महराजगंज	सेमरौता	सिरसा	1	1-9-0	
				10	0-13-3	
				12	0-5-2	
				15	1-4-10	
				11	0-12-10	
				16	0-0-5	

[सं० O-14016/3/317/84-जीपी]

S.O. 2521.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4078 dated 1-12-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rae Bareli	Mohar Ganj	Sam-rauta	Sisra	1	1-9-0	
				10	0-13-3	
				12	0-5-2	
				15	1-4-10	
				11	0-12-10	
				16	0-0-5	

[No. O-14016/317/84-GP]

का. आ. 2522.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4019 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा नं.	लिया गया रकबा (एकड़ में)	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महराजगंज	हरदोई	पारा खुर्द	30	0-5-0	
				31	0-12-0	
				33	0-5-12	
				34	0-11-10	
				35	0-1-10	
				40	0-4-0	
				41	0-1-0	
				52	0-11-17	
				53	0-2-0	
				54	0-5-17	
				55	0-8-0	
				61	0-7-12	
				82	1-0-10	
				84	0-19-0	
				85	0-0-10	
				86	0-0-10	
				112	0-7-0	
				115	0-7-0	
				117	0-0-10	
				118	0-10-0	
				119	1-3-10	
				122	0-0-10	
				132	1-0-16	
				134	1-4-0	
				241	0-4-0	
				298	1-7-0	
				299	1-13-0	
				300	0-0-10	
				301	0-2-0	
				442	0-2-10	
				448	0-2-0	
				449	1-9-0	
				450	0-7-0	
				451	0-7-0	
				453	0-11-0	
				454	0-11-12	
				479	0-2-2	
				480	0-11-10	
				482	0-12-0	
				483	0-11-10	
				484	0-2-5	
				485	0-2-0	
				526	0-4-0	
				527	0-0-10	
				534	0-0-3	
				535	0-1-0	
				536	0-1-8	
				537	0-15-0	
				542	0-13-0	

1	2	3	4	5	6	7
				546	1-15-0	
				547	0-1-10	
				550	0-5-10	
				591	1-0-10	
				592	0-9-0	
				601	0-7-4	
				619	0-0-10	
				620	0-13-6	
				622	1-1-0	
				626	0-5-0	
				599	0-10-0	
				32	0-1-10	
				49	0-1-15	
				237	0-5-0	
				305	0-0-10	
				444	0-0-5	
				481	0-5-0	
				486	1-0-10	
				487	0-0-15	
				543	0-8-0	
				545	1-18-0	
				593	0-2-5	
				597	0-7-0	
				600	0-14-0	
				604	0-0-10	
				625	0-2-10	
				56	0-7-12	
				131	0-11-0	

[सं. O-14016/318/84-जी. पी]

S.O. 2522.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 4019 dated 1-12-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rae Barielly	Maharaj ganj	Hardoi	Para khurd	30	0-5-0	
				31	0-12-0	
				33	0-5-12	
				34	0-11-10	
				35	0-1-10	
				40	0-4-0	
				41	0-1-0	
				52	0-11-17	
				53	0-2-0	
				54	0-5-17	
				55	0-8-0	
				61	0-7-12	
				82	1-0-10	
				84	0-19-0	
				85	0-0-10	
				86	0-0-10	
				112	0-7-0	
				115	0-7-0	
				117	0-0-10	
				118	0-10-0	
				119	1-3-10	
				122	0-0-10	
				132	1-0-16	
				134	1-4-0	
				241	0-4-0	
				298	1-7-0	
				299	1-13-0	
				300	0-0-10	
				301	0-2-0	
				442	0-2-0	
				448	0-2-0	
				449	1-9-0	
				450	0-7-0	
				451	0-7-0	
				453	0-11-0	
				454	0-11-12	
				479	0-2-2	
				480	0-11-10	
				482	0-12-0	
				483	0-11-10	
				484	0-2-5	
				485	0-2-0	
				526	0-4-0	
				527	0-0-10	
				534	0-0-3	
				535	0-1-0	
				536	0-1-8	
				337	0-15-0	
				542	0-13-0	
				546	1-15-0	
				547	0-1-10	
				550	0-5-10	
				591	1-0-10	
				592	0-9-0	
				601	0-7-4	
				619	0-0-10	
				620	0-13-6	
				622	1-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				626	0-5-0	
				599	0-10-0	
				32	0-1-10	
				49	0-1-15	
				237	0-5-0	
				305	0-0-10	
				444	0-0-5	
				481	0-5-0	
				486	1-0-10	
				487	0-0-15	
				543	0-8-0	
				545	1-18-0	
				593	0-2-5	
				597	0-7-0	
				600	0-14-0	
				604	0-0-10	
				625	0-2-10	
				56	0-7-12	
				131	0-11-0	

[No. O-14016/318/84-GP]

का. आ. 2523.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4074 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आसीन	आलौन	आलौन	रोमई	194	1-08	
			मुस्तकिल	214	0-30	
				215	0-10	
				216	0-10	
				217	0-60	
				225	0-36	
				226	0-40	
				228	0-43	
				232	0-10	
				233	0-20	
				406	0-39	
				440/2	0-10	
				483	0-39	
				213	0-10	
				503	0-10	
				506	0-40	
				508	0-74	
				509	0-08	
				520	0-02	
				521	0-42	
				528	0-03	
				527	0-45	
				526	0-40	
				555	0-08	
				556	0-35	
				557	0-28	
				558	0-12	
				550	0-28	
				551	0-06	
				565/1	0-10	
				596/1	0-08	
				615	0-05	
				616	0-48	
				617	0-70	
				624	0-44	
				632	0-48	
				634	0-04	
				635	0-10	
				636	0-13	
				647	0-03	
				648	0-72	
				649	0-80	
				746	0-30	
				747	0-40	
				748	0-24	
				752	0-28	
				753	0-30	
				755	0-01	
				756	0-02	
				757	0-11	
				760	0-23	

1	2	3	4	5	6	7
				761	0-02	
				762	0-20	
				766	0-01	
				764	0-53	
				765	0-36	
				645	0-01	
				758	0-16	
				560	0-05	

[F. No. O-14046/313/84-GP]

S.O. 2523.—Whereas by notificatioon of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S.O. 4074 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acqrired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remark
1	2	3		5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Romai Mustkit	193	1-08	
				214	0-30	
				215	0-10	
				216	0-10	
				217	0-60	
				225	0-36	
				226	0-40	
				228	0-43	
				232	0-10	
				233	0-20	
				406	0-39	
				440/2	0-10	
				483	0-39	
				213	0-10	
				503	0-10	
				506	0-40	
				508	0-74	
				509	0-08	
				520	0-02	
				521	0-42	
				528	0-03	
				527	0-45	
				526	0-40	
				555	0-08	
				556	0-35	
				557	0-28	
				558	0-12	
				550	0-28	
				551	0-06	
				565/1	0-10	
				596/1	0-08	
				615	0-05	
				616	0-48	
				617	0-70	
				624	0-44	
				632	0-48	
				634	0-04	
				635	0-10	
				636	0-13	
				647	0-03	
				648	0-70	
				649	0-80	
				746	0-30	
				747	0-40	
				748	0-24	
				752	0-28	
				753	0-30	
				755	0-01	
				756	0-02	
				757	0-11	
				760	0-23	
				761	0-02	
				762	0-20	
				766	0-01	
				764	0-53	
				765	0-36	
				645	0-01	
				758	0-16	
				560	0-05	

[No. O-14016/313/84-GP]

का. आ. 2524.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4069 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप-लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे

विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा--बरेली--जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

1	2	3	4	5	6
जालौन	कौंच	कौंच	रैपुरा	22	0-03
				23	0-26
				24	0-04
				30	0-01
				38	0-12

[सं O 14016/308/84-जी पी]

S.O. 2524.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4069 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline From Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres
Jalaun	Konch	Konch	Repura	22	0–03
				23	0–26
				24	0–04
				30	0–01
				38	0–12

[No. O-14016/308/84-GP]

का. आ. 2525.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4539 व तारीख 10-12-84 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य. गुजरात जिला पंचमहल तालुका हालोल

गांव		सर्वे नं०	हैक्टेयर	आर	सेन्टियर
1	2	3	4	5	6
मुलतान पुरा		60	0	18	00
		63	0	18	00
		64	0	21	00
		65	0	42	00
		66	0	25	00
		67	0	04	00
		95	0	25	00
		19	0	37	00
		20	0	14	00
		13	0	08	00
		12	0	00	48
		24	0	52	00

[सं O--14016/441/84--जी पी०]

S.O. 2525.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O 4539 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat, District: Panchmahal, Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Sultanpura	60	0	18	00
	63	0	18	00
	64	0	21	00
	65	0	42	00
	66	0	25	00
	67	0	04	00
	95	0	25	00
	19	0	37	00
	20	0	14	00
	13	0	08	00
	12	0	00	48
	24	0	52	00

[No. O-14016/441/84-GP]

का. आ. 2526.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4493 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात, जिला पंचमहल, तालुका : लिमखेड़ा

गांव	सर्वे नं.	हैक्टर	आरे	सेन्ट आर
खेरीया	92/प.	1	52	49
	154/प	0	36	00
	151	0	43	51
	150	0	49	57

[सं. O-14016/381/84-जीपी]

S.O. 2526.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4493 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat, District : Panchmahal, Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Kheria	92/P	1	52	49
	154/P	0	36	00
	151	0	43	51
	150	0	49	57

[No. O-14016/381/84-GP]

का. आ. 2527.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 122 तारीख 2-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार

ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हैक्टर	आर	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
खांगेला	460	0	33	05
	465	01	01	65
	469	0	09	50
	466	01	43	80
	468	0	30	65
	467	0	20	00
	29	0	54	10
	31	0	38	50
	12/3	0	17	55
	12/2	0	17	68
	12/1	0	40	95
	11/1	0	04	95
	34/2	0	02	88
	10/6	0	40	20
	10/7	0	00	30
	9	0	41	85
	8	0	13	40
	135	0	57	40
	137	0	12	40
	140/1	0	13	40
	140/2	0	33	60
	142/3	0	07	75
	141/1	0	05	70
	146/1	0	31	25
खांगेला-जारी	146/2	0	21	00
	147/1	0	60	40
	152	0	00	50
	126	0	10	00
	153	0	11	90
	154/1	0	18	00
	124/1	0	16	30
	124/2	0	18	70
	117	0	81	90
	106/1	2	00	00
	107	0	12	00

[सं. O—14016/515/84—जी.पी.]

S.O. 2527.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 122 dated 2-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat, District : Panchmahal, Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Khangela	460	0	33	05
	465	01	01	65
	469	0	09	50
	466	01	43	80
	468	0	30	65
	467	0	20	00
	29	0	54	10
	31	0	38	50
	12/3	0	17	55
	12/2	0	17	68
	12/1	0	40	95
	11/1	0	04	95
	34/2	0	02	88
	10/6	0	40	20

1	2	3	4	5
Khangela—Contd.	10/7	0	00	30
	9	0	41	85
	8	0	13	40
	135	0	57	40
	137	0	12	40
	140/1	0	13	40
	140/2	0	33	60
	142/3	0	07	75
	141/1	0	05	70
	146/1	0	31	25
	146/2	0	21	00
	147/1	0	60	40
	152	0	00	50
	126	0	10	10
	153	0	11	90
	154/1	0	18	00
	154/1	0	16	30
	124/2	0	18	70
	117	0	81	90
	106/1	2	00	00
	107	0	12	00

[No. O-14016/515/84-GP]

का. आ. 2528.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4561 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों का बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य—गुजरात, जिला पंचमहाल तालुका—कोहवे

गांव	सर्वे नं.	हैक्टयर	आर	सेन्टीआर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बावका	138	0	24	00
	126/1	0	09	00
	109/ए	0	24	00
	127/2+5	0	02	00
	127/1/ए	0	04	00
	127/2/1	0	07	00
	127/2/8	0	10	00
	130/1/3	0	32	00
	130/2/सी	0	22	00
	130/1/ए	0	14	00
	130/1/बी	0	15	00
	130/2	0	14	00
	131	0	41	00
	133/1	0	16	00
	133/2	0	38	00
	134	0	87	00
	136	0	49	00
	174/ए/पी	0	20	23
	174/पी	0	67	00
	174/ए	0	60	77
	174/ए/पी	0	48	00
	174/ए	0	23	00
	174/ए/पी	0	20	00
	193/पी	1	45	00
	193/पी	1	12	00
	193/पी	0	86	00
	175	0	05	00
	176/1	0	50	00
	176/2	0	12	00

[सं. O—14016/464/84-जीपी]

S.O. 2528.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O 4561 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdisphpur

State : Gujarat, District : Panchamahal, Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Bavaka	138	0	24	00
	126/1	0	09	00
	109/A	0	24	00
	127/2+5	0	02	00
	127/1/A	0	04	00
	127/2/1	0	07	00
	127/2/8	0	10	00
	130/1/3	0	32	00
	130/2/C	0	22	00
	130/1/A	0	14	00
	130/1/B	0	15	00
	130/2	0	14	00
	131	0	41	00
	133/1	0	16	00
	133/2	0	38	00
	134	0	87	00
	136	0	49	00
	174/A/P	0	20	23
	174/P	0	67	00
	174/A	0	60	77
	174/A/P	0	48	00
	174/A	0	23	00
	174/A/P	0	20	00
	193/P	1	45	00
	193/P	1	12	00
	193/P	0	86	00
	175	0	05	00
	176/1	0	50	00
	176/2	0	12	00

[No. O-14016/464/84-GP]

का. आ. 2529.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ० सं. 4544 तारीख 10-2-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात, जिला—पंचमहाल, तालुका—दहोद

गांव	सर्वे नं	हैक्टर	आर	सेन्टीआर
जालत	129	0	32	00
	130	0	32	90
	124	0	67	40
	125	0	18	20
	120	0	77	90
	128	0	02	00

[सं. O-14016/446/84-जीपी]

S.O. 2529.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1544 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat, District : Panchamahal, Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Jalat	129	0	32	00
	130	0	32	90
	124	0	67	40
	125	0	18	20
	120	0	77	90
	128	0	06	00

[No. O-14016/446/84-GP]

का. आ. 2530:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3782 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजीरा—बरेली—जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	किया गया रकबा एकड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (7)
जालौन	जालौन	जालौन	हसनपुर	3	0–03
				5	0–49
				6	0–19
				7	0–01
				10	0–04
				11	0–01
				12	0–63
				13	0–86
				14	0–02
				24	0–01
				28	0–03

[सं. O–14016/173/84—जीपी]

S.O. 2530.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 3782 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Hasan-pur	3	0–03
				5	0–49
				6	0–19
				7	0–01
				10	0–04
				11	0–01
				12	0–63
				13	0–86
				14	0–02
				24	0–01
				28	0–03

[No. O-14016/173/84-GP]

का. आ. 2531:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3896 तारीख 10-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार

एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया जाना रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
जालौन	जालौन	जालौन	तातार-पुर	83	0–19
				84	0–01
				85	0–03
				99	0–27
				100	0–21
				101	0–24
				102	0–24
				103	0–27
				104	0–39
				105	0–21
				106	0–01
				109	0–24
				110	0–01
				121	0–54
				128	0–01
				124	0–48
				125	0–01
				128	0–69
				134	0–01
				139	0–12
				140	0–78
				141	0–01
				142	0–18
				143	0–16
				145	0–01
				151	0–15
				152	0–19
				153	0–19
				154	0–15
				158	0–01

[सं. O-14016/183/84-जी. पी.]

S.O. 2531.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3896 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Tatarpur	83	0–19
				84	0–01
				85	0–03
				99	0–27
				100	0–21
				101	0–24
				102	0–24
				103	0–27
				104	0–39
				105	0–21
				106	0–01
				109	0–24
				110	0–01
				121	0–54
				122	0–01
				124	0–48
				125	0–01
				128	0–69
				134	0–01
				139	0–12
				140	0–78
				141	0–01
				142	0–18
				143	0–16
				145	0–01
				151	0–15
				152	0–19
				153	0–19
				154	0–15
				158	0–01

[No. O-14016/183/84-GP]

का. आ. 2532.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3460 तारीख 16-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार

ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	किया गया रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6
जालौन	जालौन	जालौन	इटवा	183/1	0-05
			कनार	184	0-04
				211	0-65
				212	0-58
				210	0-04
				209	1-20
				208	0-04
				250	0-39
				251	0-02
				256	1-00
				257	0-01
				260	0-48
				261	0-03
				262	0-27
				263	0-42
				264	0-63
				266	0-18
				268/1	0-24
				281	0-74
				313	0-12

[सं. O-14016/30/84-जी० पी०]

S.O. 2532.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3460 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

Dist.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	area in acres
1	2	3	4	5	6
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Itawa	183/1	0-05
			Kanar	184	0-04
				211	0-65
				212	0-58
				210	0-04
				209	1-20
				208	0-04
				250	0-39
				251	0-02
				256	1-00
				257	0-02
				260	0-48
				261	0-03
				262	0-27
				263	0-42
				264	0-63
				266	0-18
				268/1	0-24
				281	0-74
				313	0-12

[No. O-14016/30/84-GP]

का. आ. 2533:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3392 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	टिप्पण
1	2	1	4	5	6	7
जालौर	जालौर	जालौर	कुतलूपुर	1	0–06	
				2	0–30	
				3	0–30	
				4	0–67	
				5	0–01	
				19	0–06	
				20	1–82	
				22	0–03	

[सं. O-14016/184/84जी० पी० 84]

S.O. 2533.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3792 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule apperded to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Kutlu Pur	1	0-06	
				2	0-30	
				3	0-30	
				4	0-67	
				5	0-01	
				19	0-06	
				20	1-82	
				22	0-03	

[No. O-14016/184/84-GP]

का. आ. 2534.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1526 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अत : अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर राज. पाईप लाईन तक बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
श्यामपुरा	3242	0	05	25
	340	0	10	80
	333	0	15	75
	332	0	40	15
	330	0	06	21
	327	0	32	22
	322	0	43	68
	150/2	0	16	08
	229	0	07	92
	150/1	0	35	70
	154	0	42	00
	158	0	32	06
	156	0	00	72
	157	0	28	32
	181	0	11	40
	182	0	13	80
	185	5	00	64
	184	0	16	61
	183	0	02	45
	186	0	13	50
	187	0	17	70
	188	0	14	10
	205	0	08	10
	191	0	02	25
	204	0	29	55
	192	0	53	55
	203	0	11	40
	172	0	07	10
	100	0	18	20
	104	0	02	60
	321	0	12	60
	329	0	02	70
	98	0	02	10
	99	0	00	30

[सं. O-14016/193/85-जी. पी.]

S.O. 2534.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1526 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Shyampura	342	0	05	25
	340	0	10	80
	333	0	15	75
	332	0	48	15
	330	0	06	21
	327	0	32	22
	322	0	43	68
	150/2	0	16	08
	229	0	07	92
	150/1	0	35	70
	154	0	42	00
	158	0	33	06
	156	0	00	72
	157	0	28	32
	181	0	11	40
	182	0	13	80
	185	0	00	64
	184	0	16	61
	183	0	03	45
	186	0	13	50
	187	0	17	70
	188	0	14	10
	205	0	08	10
	191	0	02	25
	204	0	29	55
	192	0	53	55
	203	0	11	40
	172	0	07	10
	100	0	18	20
	104	0	02	60
	321	0	12	60
	339	0	02	70
	98	0	02	10
	99	0	00	30

[No. O-14016/193/85-GP]

का. आ. 2535.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1525 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान · जिला कोटा तहसील · मागरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
"कुश्या"	10	0	01	34
	8	0	14	41
	9	0	01	08
	7	9	01	77
	5	0	06	00
	4	0	00	30

[सं. O-14016/192/85-जी. पी.]

S.O. 2535.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1525 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to S w.i Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Kushya	10	0	01	34
	8	0	14	41
	9	0	01	08
	7	0	01	77
	5	0	06	00
	4	0	00	30

[No. O-14016/192/85-GP]

का. आ. 2536:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1528 तारीख 29-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त नियम की धारा 6 की उपधारा, (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि., में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य : राजस्थान जिला : कोटा तहसील : मांगरोल

गांव	खसरा न	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
"चन्द्राहेडी"	139	0	05	94
	138	0	18	84
	137	1	22	28
	103	0	10	84
	104	0	33	60
	72	0	10	50
	74	0	42	35
	73	0	01	45
	47	0	00	12
	48	0	48	90
	39	0	87	00
	40	0	59	40
	17	0	57	84
	18	0	00	96
	16	0	41	34
	21	0	09	60
	14	0	02	30
	10	0	09	14
	11	0	01	76
	7	0	05	42
	6	0	04	40
	12	0	18	28
	15	0	00	36
	105	0	00	80
	8	0	03	00

[सं. O-14016/195/85-जी.पी.]

S.O. 2536.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1528 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Chandrahedi	139	0	05	94
	138	0	18	84
	137	1	22	28
	103	0	10	84
	104	0	33	60
	72	0	10	50
	74	0	42	35
	73	0	01	45
	47	0	00	12
	48	0	48	90
	39	0	87	00
	40	0	59	40
	17	0	57	84
	18	0	00	96
	16	0	41	34
	21	0	09	60
	14	0	02	30
	10	0	09	14
	11	0	01	76
	7	0	05	42
	6	0	04	40
	12	0	18	28
	15	0	00	36
	105	0	00	80
	8	0	03	00

[No. O-14016/195/85-GP]

का. आ. 2537.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का० आ. सं. 3942 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

ग्राम : उदयमाल तहसील : झाबुआ जिला-झाबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स मे)
1	2	3
1.	8	0.632
2.	9	0.097
3.	11	0.121
4.	12	0.364
5.	15	0.008
6	24	0.097
7.	25	0.607
8	28	0.032
9.	29	0.040
10.	30	0.251
11.	33	0.227
12.	45	0.040
13.	फारेस्ट वन वि.	0.809
	योग:—कुल क्षेत्रफल	3.325

[सं. O-14016/285/85–जी पी.]

S.O. 2537.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3942 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Udaymal Tehsil : Zabua Distt : Zabua

SCHEDULE

Sl. No	Survey No,	Area to be Acquired For R.O.U. in Hectare
1.	8	0.632
2.	9	0.097
3.	11	0.121
4.	12	0.364
5.	15	0.008
6.	24	0.097
7.	25	0.607
8.	28	0.032
9.	29	0.040
10.	30	0.251
11.	33	0.227
12.	45	0.040
13.	Forest Department	0.809
	Total Area	3.325

[No. O-14016/285/85-GP]

का०आ० 2538:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1521 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि., में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
1	2	3	4	5
"अयाना"	121	0	13	68
	128/1563	0	18	90
	128	0	08	40
	130	0	35	35
	129	0	01	60
	131	0	41	35
	132	0	16	20
	126	0	10	70
	147	0	07	40
	148	0	10	50
	125	0	02	40
	149	0	08	61
	146	0	04	50
	145	0	52	39
	151	0	00	20
	152	0	31	90

[सं. O-14016/188/85-जी. पी.]

S.O. 2538.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1521 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acqu're the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of th's declaration in the Gas Authority of India Ltd. from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj) State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Ayana	121	0	13	68
	128/1563	0	18	90
	128	0	08	40
	130	0	35	35
	129	0	01	60
	131	0	41	35
	132	0	16	20
	126	0	10	80
	147	0	07	40
	148	0	10	50
	125	0	02	40
	149	0	08	61
	146	0	04	50
	145	0	52	39
	151	0	00	20
	152	0	31	90

[No. O—14016/188/85-GP]

का. आ. 2539 : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4123 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्रा. का नाम	लिया गया खसरा नं०	रकबा	विवरण
1	2	2	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबरपुर	अकबरपुर	मुखलिसपुर	51	0—0—4	
				54	0—11—0	
				55	0—1—0	
				68	0—0—05	
				69	0—0—4	

1	2	3	4	5	6	7
				74	0–1–10	
				83	0–13–5	
				84	0–10–10	
				88	1–2–5	
				90	1–1–12	
				113	0–9–0	
				114	1–1–0	
				115	0–0–4	
				116	0–11–5	
				117	0–11–0	
				118	0–19–0	
				119	0–11–0	
				141	0–0–5	
				151	0–11–0	
				152	0–9–10	
				153	0–0–10	
				154	1–18–0	
				180	0–10–0	
				179	0–5–0	
				176	0–0–1	
				177	0–0–1	
				181	0–11–0	
				175	0–4–15	
				174	0–18–0	
				173	0–11–10	
				172	3–11–0	
				171	0–1–15	
				197	2–19–10	
				108	0–5–0	
				200	0–0–5	
				201	0–0–2	
				202	1–7–4	
				203	1–13–0	
				229	1–6–0	
				232	0–3–10	
				233	0–10–0	

[स O-14016/344/84-जी पी]

S.O. 2539.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4123 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Barielly Jagdeshpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Mukhlis-pur	51	0–0–4	
				54	0–11–0	
				55	0 1–0	
				68	0–0–5	
				69	0–0–4	
				74	0–1–10	
				83	0–13–5	
				84	0–10–10	
				88	1–2–5	
				90	1–1–12	
				113	0–9–0	
				114	1–1–0	
				115	0 0–4	
				116	0–11–5	
				117	0–11–0	
				118	0–19–0	
				119	0–11–0	
				141	0–0–5	
				151	0–11–0	
				152	0–9–10	
				153	0–0–10	
				154	0–18–0	
				180	0–10–0	
				179	0–5–0	
				176	0–0–11	
				177	0–0–1	
				181	0–11–0	
				175	0–4–15	
				174	1–18–0	
				173	0–11–10	
				172	3–11–0	
				171	0–1–15	
				197	2–19–10	
				188	0–5–0	
				200	0–0–5	
				201	0–0–2	
				202	1–7–4	
				203	1–13–0	
				229	1–6–0	
				232	0–3–10	
				233	0–10–0	

[No. O-14016/344/84-PG]

का. आ. 2540.—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. तारीख 3787/27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इसअधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
आलौन	कोंच	कोंच	कल्याण-पुर	5	0–49	
				6	0–01	
				8	0–01	
				9	0–06	
				20	0–26	
				21	0–68	
				23	0–42	
				52	0–01	
				54	0–32	
				56	0–01	

[सं. O-14016/178/84-जी. पी]

S.O. 2540.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3787 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

SCHEDULE

Gas Pipe Line from Hajira-Bareilly- Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
alaun	Konch	Konch	Kalyan-pur	5	0–49	
				6	0–01	
				8	0–01	
				9	0–06	
				20	0–26	
				21	0–68	
				23	0–42	
				52	0–01	
				54	0–32	
				56	0–01	

[No. O-14016/178/84-GP]

का. आ. 2541:—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3800 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट सं.	क्षेत्रफल बि. वि. बि. वि.
1	2	3	4	5	6
कानपुर देहात	अकबर-पुर	अकबर-पुर	तिगाई	1366	0–0–10
				1367	0–15–15
				1368	0–13–10
				1369	0–4–15
				1371	0–0–15
				1363	0–0–15
				1373	0–1–10
				1377	0–10–0
				1379	0–19–10
				1380	0–2–0
				1356	0–0–8
				1375	0–11–0
				1376	0–15–0
				1384	0–0–15
				1348	0–1–10
				1419	0–3–10
				1418	0–10–0
				1417	1–10–0
				1414	0–3–10
				1416	0–0–15
				1427	0–0–15
				1415	0–7–15
				1412	0–8–0
				1411	0–9–0
				1410	1–4–0
				1451	0–5–10
				1397	0–1–10
				1454	0–0–15
				1396	1–4–0
				1394	0–0–15
				1395	1–0–0
				1393	2–2–0
				1458	0–0–15
				1459	0–4–0
				827	0–8–5
				802	0–0–13
				807	1–12–0
				808	0–0–15
				809	0–0–10
				810	0–14–6
				811	0–3–0
				812मि	1–5–0

[सं० O-14016/192/84-जीपी)]

S.O. 2541.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3800 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira- Barielly- Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired B.V.V.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Tigai	1366	0–0–10	
				1367	0–15–15	
				1368	0–13–10	
				1369	0–4–15	
				1371	0–0–15	
				1363	0–0–15	
				1373	0–1–10	
				1377	0–10–0	
				1379	0–19–10	
				1380	0–2–0	
				1356	0–0–8	
				1375	0–11–0	
				1376	0–15–0	
				1384	0–0–15	
				1348	0–1–10	
				1419	0–3–10	
				1418	0–10–0	
				1417	1–10–0	
				1414	0–3–10	
				1416	0–0–15	
				1427	0–0–15	
				1415	0–7–15	
				1412	0–8–0	
				1411	0–9–0	
				1410	1–4–0	
				1451	0–5–10	
				1397	0–1–10	
				1454	0–0–15	
				1396	1–4–0	
				1394	0–0–15	
				1395	1–0–0	

1	2	3	4	5	6	7
				1393	2-2-0	
				1458	0-0-15	
				1459	0-4-0	
				827	0-8-5	
				802	0-0-13	
				807	1-12-0	
				808	0-0-15	
				809	0-0-10	
				810	0-14-5	
				811	0-3-0	
				812 मि	1-5-0	

[No. O-14016/192/84-GP]

का.आ. 2542 :—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3798 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा – बरेली– जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लाट नं०	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबर पुर	अकबर पुर	रायपुर कुकहर	13	0-7-0	
				302	0-6-0	
				303	1-2-0	
				304	0-7-10	
				314	0-5-0	
				315	1-8-10	
				316	0-10-0	
				318	0-0-10	
				319	0-0-10	
				323	1-14-0	
				324	1-2-0	
				325	0-5-0	
				326	0-1-0	
				327	0-0-10	
				328	0-1-0	
				329	0-10-0	
				335	0-0-10	
				336	0-1-10	
				350	0-19-0	
				351	2-13-0	
				354	0-7-0	
				410	0-6-0	
				411 मि	0-8-0	
				411 मि	0-6-0	
				412 मि	0-6-0	
				412 मि	0-6-0	
				413	0-5-0	
				414	0-2-0	
				415	0-11-10	
				423	0-1-10	
				428	0-9-0	
				429	0-2-10	
				430	0-8-0	
				434	0-4-10	

[सं. O-14016/190/84-जी पी]

S.O. 2542.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3798 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilley Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargara	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Raipur Kukhat	13	0-7-0	
				302	0-6-0	
				303	1-2-0	
				304	0-7-10	
				314	0-5-0	
				315	1-8-10	
				316	0 10-0	
				318	0-0-10	
				319	0-0-10	
				323	1-14-0	
				324	1-2-0	
				325	0-5-0	
				326	0-1-0	
				327	0-0-10	
				328	0-1-0	
				329	0-10-0	
				335	0-0-10	
				336	0-1-10	
				350	0-19-0	
				351	2-13-0	
				354	0-7-0	
				410	0-6-0	
				411min	0-8-0	
				411min	0-6-0	
				412min	0-6-0	
				412min	0-6-0	
				413	0-5-0	
				414	0-2-0	
				415	0-11-10	
				423	0-1-10	
				428	0-9-0	
				429	0-2-10	
				430	0-8-0	
				434	0-4-10	

[No. O-14016/190/84-GP]

का. आ. 2543:—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 3784/27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	मिहौना	238	0-03	
				240	0-15	
				268	0-27	
				269	0-15	
				272	0-02	
				273	0-45	
				274	0-39	
				279	0-02	
				267	0-17	
				266	0-13	
				265	0-18	
				241	0-20	
				264	0-07	
				242	0-21	
				263	0-01	
				243	0-64	
				244	0-04	
				245	0-01	
				246	0-13	
				256	0-08	
				249	0-08	
				253	0-52	
				254	0-06	
				259	0-41	
				314	0-05	
				313	0-75	
				315	0-03	
				308	0-02	
				348	0-57	
				349	0-69	
				352	0-07	
				391	0-10	
				408	0-18	

1	2	3	4	5	6	7
जालौन-(जारी)				410	0-15	
				420	0-06	
				467	0-52	
				466	0-36	
				465	0-01	
				464	0-75	
				461	0-01	
				460	0-02	
				456	1-35	
				458	0-02	
				472	1-00	
				483	0-03	
				489	0-03	
				499	1-02	
				493	0-04	

[सं. O-14016/ 175/84-जी पी]

S.O. 2543.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3784 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, **submitted report to** the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Mihauna	238	0-03	
				240	0-15	
				268	0-27	
				269	0-15	
				272	0-02	
				273	0-45	
				274	0-39	
				279	0-02	
				267	0-17	
				266	0-13	

1	2	3	4	5	6	7
Jalaun-(Contd.)				265	0-18	
				241	0-20	
				264	0-07	
				242	0-21	
				263	0-01	
				243	0-64	
				244	0-04	
				245	0-01	
				246	0-13	
				256	0-08	
				249	0-08	
				255	0-52	
				254	0-06	
				259	0-41	
				314	0-05	
				313	0-75	
				315	0-03	
				308	0-02	
				348	0-57	
				349	0-69	
				352	0-07	
				394	0-10	
				408	0-18	
				410	0-15	
				420	0-06	
				467	0-52	
				466	0-36	
				465	0-01	
				464	0-75	
				461	0-01	
				460	0-02	
				456	1-35	
				458	0-02	
				472	1-00	
				483	0-03	
				489	0-03	
				499	1-02	
				493	0-04	

[No. O—14026/175/84-GP]

का. आ. 2544:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4403 तारीख 3-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	बोहरा	181	0–43	
				185	0–06	
				187	0–10	
				188	0–97	
				191	0–02	
				192	0–60	
				193	0–94	
				195	0–02	
				198	2–16	
				209	0–02	
				211	0–61	
				212	1–26	
				231, 232	0–15	
				233	0–03	
				235	1–35	
				236	0–15	

[सं. O–14016/433/84–जी पी]

S.O. 2544.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4403 dated 3-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe Line From Hajira-Barailly-Jagdishpur Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Bohara	181	0–43	
				185	0–06	
				187	0–10	
				188	0–97	
				191	0–02	
				192	0–60	
				193	0–94	
				195	0–02	
				198	2–16	
				209	0–02	
				211	0–61	
				212	1–26	
				231, 232	0–15	
				233	0–03	
				235	1–35	
				236	0–15	

[No. O-14016/433/84-GP]

का. आ. 2545 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4541 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य–गुजरात जिला–पंचमहल तालुका– हालोल

गाव	सर्वे नं०.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
जाम्बुडी	93	0	58	00
	84	0	62	00
	90	0	09	00
	87/पी	0	17	00
	87/पी	0	27	00
	17	0	01	00
	26	0	61	00
	27	0	22	00
	25	0	00	20
	28	0	29	00
	24	0	01	00
	29	0	37	00
	30	0	19	00
	31	0	28	00
	32	0	35	00
	34	0	08	00
	33	0	29	00
	59	0	19	00
	58	0	33	00

[सं.-O 14016/443/84-जी पी]

S.O. 2545.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4541 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur
State : Gujarat District : Panchamahal Taluka : Halo

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Jambudi	93	0	58	00
	84	0	62	00
	90	0	09	00
	87/P	0	17	00
	87/P	0	27	00
	17	0	01	00
	26	0	61	00
	27	0	22	00
	25	0	00	20
	28	0	29	00
	24	0	01	00
	29	0	37	00
	30	0	19	00
	31	0	28	00
	32	0	35	00
	34	0	08	00
	33	0	29	00
	59	0	19	00
	58	0	33	00

[No. O-14016/443/84-GP]

का.आ. 2546 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3759 तारीख 6-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य– गुजरात जिला एवं तालुका–भरुच

गांव	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	मेन्टीयर
1	2	3	4	5
तवरा	444/1	0	17	85
	444/2	0	12	45
	444/4	0	11	70
	444/5	0	02	10
	443/6	0	19	85
	443/7	0	20	40
	443/8	0	21	90
	441	0	12	45
	442/2	0	01	62
	442/3	0	30	60
	439/1-2	0	16	20
	439/3	0	17	13
	438/1	0	22	69
	438/2	0	05	17
	365	0	00	45
	437	0	01	10
	386/1	0	12	15
	386/2	0	25	75
	367/1	0	04	40
	367/3	0	04	00
	345/2+3	0	13	05
	345/4	0	30	60
	346	0	02	40
	347	0	13	65
	337/1	0	18	05
	337/2	0	09	45
	337/4+5	0	25	80
	338/2	0	25	50
	328/3	0	18	00
	339/1	0	01	92
	339/2	0	17	12
	340/1	0	29	82
	327/1	0	23	10
	328	0	18	60
	271/6	0	09	21
	271/7	0	11	50
	272/2	0	15	75
	272/1	0	16	35
	271/4	0	37	94
	273/2+3	0	00	35
	274/2	0	12	45
	274/3	0	13	35
	274/4	0	05	50
	275	0	17	10
	279	0	02	79
	259/1	0	01	19
	259/3	0	39	30
	154	0	06	45
1	2	3	4	5
तवरा-(जारी)	258/1	0	01	10
	258/2	0	22	05
	258/3	0	16	80
	258/4	0	15	45
	184	0	03	15
	187/2	0	26	10
	187/1	0	18	00
	187/4	0	24	45
	253/1+2	0	04	50
	253/3	0	13	05
	190/1	0	31	34
	190/2	0	04	50
	191	0	15	45
	192/1	0	17	10
	193	0	17	40
	194	0	20	95
	196	0	00	25
	106/1	0	13	65
	109/2	0	00	25
	109/3	0	32	00
	109/4	0	16	50
	105/1	0	26	80
	105/2	0	04	70
	131	0	38	53
	133	0	05	33
	134	0	38	50
	136	0	04	70
	50/1	0	04	40
	50/2	0	06	11
	50/3+4	0	10	95
	51/1	0	26	43
	108/1	0	13	35
	111/3	0	32	70
	111/5	0	04	50
	112/1+2+3+4	0	16	05
	112/5	0	28	65
	113/2	0	01	02
	कार्ट ट्रैक	0	17	12
	50/5	0	07	25

[सं. O–14016/119/84–ओ पी]

S.O. 2546.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3759 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipe line from Hajira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Tavara	444/1	0	17	85
	444/2	0	12	45
	444/4	0	11	70
	444/5	0	02	10
	443/6	0	19	85
	443/7	0	20	40
	443/8	0	21	90
	441	0	12	45
	442/2	0	01	62
	442/3	0	30	60
	439/1-2	0	16	20
	439/3	0	17	13
	438/1	0	22	69
	438/2	0	05	17
	365	0	00	45
	437	0	01	10
	386/1	0	12	15
	386/2	0	25	75
	367/1	0	04	40
	367/3	0	04	00
	345/2+3	0	13	05
	345/4	0	30	60
	346	0	02	40
	347	0	13	65
	337/1	0	18	05
	337/2	0	09	45
	337/4+5	0	25	30
	338/2	0	25	50
	338/3	0	18	00
	339/1	0	01	92
	339/2	0	17	12
	340/1	0	29	82
	327/1	0	23	10
	328	0	18	60
	271/6	0	09	21
	271/7	0	11	50
	272/2	0	15	75
	272/1	0	16	35
	273/4	0	37	94
	273/2+3	0	00	35
	274/2	0	12	45
	274/3	0	13	35
	274/4	0	05	50
	275	0	17	10
	279	0	02	79
	259/1	0	01	19
	259/3	0	39	30
	154	0	06	45
	258/1	0	01	10
	258/2	0	22	05
	258/3	0	16	80
	258/4	0	15	45
	184	0	03	15
Tavara (Contd.)	187/2	0	26	10
	187/1	0	18	00
	187/4	0	24	45
	253/1+2	0	04	50
	253/3	0	13	05
	190/1	0	21	34
	190/2	0	04	50
	191	0	15	45
	192/1	0	17	10
	193	0	17	40
	194	0	20	95
	196	0	00	25
	106/1	0	13	65
	109/2	0	00	25
	109/3	0	32	00
	109/4	0	16	50
	105/1	0	26	80
	105/2	0	04	70
	131	0	38	52
	133	0	05	33
	134	0	38	50
	136	0	04	70
	50/1	0	04	40
	50/2	0	06	11
	50/3+4	0	10	95
	51/1	0	26	43
	108/1	0	13	35
	111/3	0	32	70
	111/5	0	04	50
	112/1+2+3+4	0	16	05
	112/5	0	28	65
	113/2	0	01	02
	Cart Track	0	17	12
	50/5	0	07	25

[No. O-14016/119/84.-GP]

का.आ. 2547:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4072 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा – बरेली– जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ मे	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोच	कोच	बिरौरा	8	1–90	
				11	0–05	
				13	0–04	
				29	0–09	
				36	0–85	
				39	0–03	
				40	0–02	
				42	1–52	
				43	0–60	

[सं. O–14016/311/84-जी पी]

S.O. 2547.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4072 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in, the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Biraura	8	1–90	
				11	0–05	
				13	0–04	
				29	0–09	
				36	0–85	
				39	0–03	
				40	0–02	
				42	1–52	
				43	0–60	

[No. O-14016 311/84-GP]

का. आ. 2548.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं: 1529 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे अतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाईमाधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य – राजस्थान जिला– कोटा तहसील – मागरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
श्रीनाल चक "बी"	83	0	84	10
	83/94	0	01	00
	81/93	0	17	31
	82	0	04	00
	69	0	13	20
	67	0	00	40
	70/92	0	22	20
	70	0	36	30
	47	0	72	00

48	0	13	50
27/87	0	49	06
25	0	01	04
24	0	41	10
21	0	26	40
20	0	25	28
6	0	30	60
7	0	19	80
8	0	30	30
9	0	04	00
10	0	02	00
12	0	07	50
19	0	00	42
65	0	09	00
68	0	09	00

[सं. O-14016/196/85-जी पी]

S.O. 2548.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1529 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Srinal Chak B	83	0	84	19
	83/94	0	01	00
	81/93	0	17	31
	82	0	04	00
	69	0	13	20
	67	0	00	40
	70/92	0	22	20
	70	0	36	30
	47	0	72	00
	48	0	13	50
	27/87	0	49	06
	25	0	01	04
	24	0	41	10
	21	0	26	40
	20	0	26	28
	6	0	30	60
	7	0	19	80
	8	0	30	30
	9	0	04	00
	10	0	02	00
	12	0	07	50
	19	0	00	42
	65	0	09	00
	68	0	09	00

[No. O—14016/196/85-GP]

का. आ. 2549:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ने पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं 1523 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य – राजस्थान जिला – कोटा तहसील – पीपल्दा

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
"कांकरा"	120	0	02	40
	128	0	46	20

(सं. O-14016/190/85- जी पी]

S.O. 2549.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1523 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi are
Kankara	120	0	02	40
	128	0	46	20

[No. O—14016/190/85-GP]

का. आ. 2550 यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1517 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजनों के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख में निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्था जिला कोटा तहसील पीपल्दा

गाव	खसरा न	हेक्टर	आर	सेंटीआर
श्रीपुरा	130	0	18	15
	137	0	08	55
	241/135	0	03	00
	131	0	01	95
	134	0	13	50
	135	0	26	48
	152	0	17	34
	151	0	25	80
	154	0	13	80
	155	0	59	10
	156	0	17	10
	161	0	39	45
	162	0	05	25
	171	0	45	90
	174	0	34	20
	172	0	50	70
	159	0	14	70
	129	0	02	40
	133	0	03	90

[म O-14016/184/85-जी पी]

S O 2550.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O. 1517 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bij pur (M.P. to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan -District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Centi-are
Shri Bura	130	0	18	15
	137	0	08	55
	241/133	0	03	00
	131	0	04	95
	134	0	13	50
	135	0	26	48
	152	0	17	3 4
	151	0	25	80
	154	0	13	80
	155	0	59	10
	156	0	17	10
	161	0	39	45
	162	0	05	25
	171	0	45	90
	174	0	34	20
	172	0	50	25
	159	0	14	70
	150	0	00	06
	129	0	02	40
	133	0	03	90

[No. O—14016/184/85-GP]

का. आ. 2551:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1 62 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1522 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—कोटा तहसील—पीपल्दा

गाव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
"रघनाथपुरा"	36	0	78	30
	39	0	06	00
	38	0	09	30
	37	0	02	22

[सं. O-14016/189/85-जी पी]

S.O. 2551.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1522 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P. to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hect-are	Are	Conti are
Raghunathpura	36	0	78	30
	39	0	06	00
	38	0	09	30
	37	0	02	22

[No. O—14016/189/85-GP]

का. आ. 2552 यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1530 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार

ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनें बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख में निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—कोटा तहसील—मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सीटीआर
श्रीनालचक (अ)	90	0	06	90
	89	0	12	30
	87	0	06	76
	88	0	08	32
	83	0	47	08
	84	0	47	64

[सं O-1406/197/85-जी पी]

S.O. 2552.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1530 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan —District : Kota —Tehsil Mangrol

Village	Surve No.	Hectare	Are	Centiare
Srinal Chak A	90	0	06	90
	89	0	12	30
	87	0	06	76
	88	0	08	32
	83	0	47	08
	84	0	47	64

[No. O-14016/197/85- GP]

का. आ. 2553: यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 602 तारीख 23-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने का प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैसप्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—देव गढबारीया

गांव	सर्वे न.	हेक्टयर	आर	सेंटीयर
1	2	3	4	5
रिछवानी	114/5	0	27	00
	114/6	0	05	00
	कोटर	0	16	00
	234	0	20	00
	233	0	21	00
	317	0	11	00
	294	0	34	00
	126/पी	0	97	00
	115/पी	0	12	00
	116/पी	05	05	00
	316 पी	0	20	00
	116/1	0	16	00
	117	0	11	00
	120	0	32	00
	121	0	21	00
	122	0	27	00
	127	2	34	00
	124	5	87	00
	कोटर	0	90	00
	148	0	04	00
	147/1	0	16	00
	147/2	0	08	00
	146	0	05	00
	189	0	07	00
	191/3	0	02	00
	191/2	0	16	00
	191/1	0	09	00
	193/1	0	03	00
	194/2	0	28	00
	194/1	0	25	00
	195	0	16	00
	196/पी	0	49	00
	210	0	16	00
	180	0	30	00
	179	0	34	00
	178	0	27	00
	175/1पी	0	44	00
	159/1	0	26	00

[स. O-1401 /47/ 5-जीपी]

S.O. 2553.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 5 2 dated 23-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipelne ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat, District : Panchmahal, Taluka : Devgadhbariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Richawan'	114/5	0	27	00
	114/6	0	05	00
	Kotar	0	16	00
	234	0	20	00
	233	0	21	00
	317	0	11	00
	294	0	34	00
	126/P	0	97	00
	115/1/P	0	12	00
	116/P	0	05	00
	116/P	0	20	00
	316/1	0	16	00
	117	0	11	00
	120	0	32	00
	121	0	21	00
	122	0	27	00
	127	2	34	00
	134	0	87	00
	Kotar	0	90	00
	148	0	04	00
	147/1	0	16	00
	147/2	0	08	00
	146	0	05	00
	189	0	07	00
	191/3	0	02	00
	191/2	0	16	00
	191/.	0	09	00
	193/1	0	03	00
	194/2	0	28	00
	194/1	0	25	00
	195	0	16	00
	196/P	0	49	00
	210	0	16	00
	180	0	30	00
	179	0	34	00
	178	0	27	00
	175/1/P	0	44	00
	159/1	0	26	00

[No. O-14016/47/85-G P]

का. आ. 2554.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम) 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 1518 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख मे निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला— कोटा तहसील—पीपल्दा

गांव	खसरा न	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
"प्रेमपुरा'	8	0	08	40
	10	0	40	24
	9	0	33	60
	107	0	13	95
	133	0	64	31
	131	0	37	50
	121	0	00	16
	132	0	33	11
	130	0	02	89
	128	1	04	39
	126	0	06	24
	127	0	29	46
	179	0	04	86
	223	0	06	24
	224	0	33	06
	593/179	0	00	24
1	2	3	4	5
	225	0	35	12
	227	0	23	18
	228	1	77	17
	214	0	30	90
	210	0	03	45
	422	0	05	18
	229	0	09	60
	411	1	53	45
	416	0	50	70
	415	0	24	00
	417	0	40	50
	420	0	60	15
	421	0	27	37
	433	0	53	40
	572	0	15	60
	423	0	17	70
	424	0	12	12
	425	0	00	10
	226	0	04	10
	212	0	00	28
	545	0	29	40
	544	0	22	80

[स. O-14016/185/85-जीपी]

S.O 2554.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1518 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Prempura	8	0	08	40
	10	0	40	24
	9	0	33	60
	160	0	13	95
	133	0	64	31

1	2	3	4	5
	131	0	37	50
	121	0	00	16
	132	0	33	11
	130	0	02	89
	128	1	04	39
	126	0	06	24
	127	0	29	46
	179	0	04	86
	223	0	06	24
	224	0	33	06
	593/179	0	00	24
	225	0	35	12
	227	0	23	18
	228	1	77	17
	214	0	30	90
	210	0	03	45
	422	0	05	18
	229	0	09	60
	411	1	53	45
	416	0	50	70
	415	0	24	00
	417	0	40	50
	420	0	60	15
	421	0	27	37
	433	0	53	40
	572	0	1..	60
	423	0	17	70
	424	0	12	12
	425	0	00	10
	226	0	04	10
	212	0	00	28
	545	0	29	40
	544	0	22	80

[No. O-14016/185/85-G P]

का. आ. 2555.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1534 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—कोटा तहसील—मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
"चनपुरिया'	144	0	09	00
	228	0	09	60
	145/2	0	39	60
	145/1	0	24	00
	145/3	0	23	40
	146	0	38	40
	147	0	26	40
	176	0	27	15
	178	0	26	52
	174	0	21	16
	173	0	10	07
	172	0	03	30
	167	0	29	70
	168	0	10	80
	166	0	29	10
	165	0	26	40
	163	0	34	50
	194	0	57	00
	195	0	02	10
	207	0	06	22
	196	0	11	10
	205	0	45	08
	204	0	45	60
	198	0	41	90
	199	0	01	00
	75	0	02	00
	76	0	02	09
	74	0	07	26
	73	0	05	20

[सं. O-14013/201/85-जीपी]

S.O. 2555.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1534 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition or Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from the date of the publication of this decalaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M P) to Sawai Madhopur (Raj)

State Rajasthan —District Kota —Tehsil Mangrol

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
Chainpuria	144	0	09	00
	228	0	09	60
	165/2	0	39	60
	145/1	0	24	00
	145/3	0	23	40
	146	0	38	40
	147	0	26	40
	176	0	27	15
	178	0	26	52
	174	0	21	16
	173	0	10	07
	172	0	03	30
	167	0	29	70
	168	0	10	80
	166	0	29	10
	165	0	26	40
	163	0	34	50
	194	0	57	00
	195	0	02	10
	207	0	06	22
	196	0	11	10
	205	0	45	08
	204	0	45	60
	198	0	41	90
	199	0	01	00
	75	0	02	00
	76	0	02	09
	74	0	07	26
	73	0	05	29

[No O-14016/201/85- GP]

का आ. 2556 —यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का आ स 1519 तारीख 29–3–85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो म उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—कोटा तहसील—पीपल्दा

गांव	खसरा न	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
"अयानी"	529	0	18	18
	530	0	03	90
	534	0	32	66
	533	0	40	20
	528	0	00	20
	531	0	39	30

[स O-14016/186l 85-जी पी)]

S O 2556 —Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 1519 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ,

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the

right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Ayani	529	0	18	18
	530	0	03	90
	534	0	32	66
	533	0	40	20
	528	0	00	20
	531	0	39	30

[No. O-14016/186/85-GP]

का. आ. 2557 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 1533 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला— कोटा तहसील—मांगरोल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेंटीआर
हिंगोनिया	221	0	32	10
	215	0	32	40
	217	1	00	79
	218	0	25	50
	190	0	00	28
	188	0	30	48
	46	0	00	10
	45	0	06	80
	44	0	09	60
	43	0	10	20

[सं. O-14016/200/85-जी पी]

S.O. 2557.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1533 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.,

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Hingonia	221	0	32	10
	215	0	32	40
	217	1	00	79
	218	0	25	50
	190	0	00	28
	188	0	30	48
	46	0	00	10
	45	0	06	80
	44	0	09	60
	43	0	10	20

[No. O-14016/200/85-GP]

का. आ. 2558.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसुचना का. आ. सं. 1532 तारीख 29–3–85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संग्लन अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य—राजस्थान जिला—कोटा तहसील—मांगरोल

गांव	खसरा न	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
"बोहत"	42	0	33	08
	49	0	65	62
	57	0	44	19
	50	0	04	76
	44	0	46	77
	45	0	00	06
	43	0	33	87
	41	0	05	56

[सं. O-14016/199/85-जी पी]

S.O. 2558.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1532 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)
State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Mangrol

Village	Survey No.	Hectare	Arc	Centiare
Bohat	42	0	33	08
	49	0	65	62
	57	0	44	19
	50	0	04	76
	44	0	46	77
	45	0	00	06
	43	0	33	87
	41	0	05	56

[No. O-14016/199/85-G P]

का. आ. 2559—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ सं. 1520 तारीख 29/3/85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों, को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्-द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म.प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल्दा

गांव	खसरा नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
श्योपुरा	102	0	41	40
	104	0	12	62
	108/203	0	31	86
	108	0	71	76
	108/221	0	00	16
	137	0	60	56
	136	0	53	92
	158	0	29	07
	159	0	77	85
	161	0	62	46
	160	0	15	60
	169	0	03	45
	170	0	73	65
	173	0	04	20
	172	0	83	75
	180	0	02	16
	166	0	06	70

[सं० O-14016/187/85-जी पी]

S.O. 2559.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1520 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan District : Kota Tehsil : Piplada

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centi-are
1	2	3	4	5
Shyopura	102	0	41	62
	104	0	12	62
	108/203	0	31	86
	108	0	71	76
	108/221	0	00	16
	137	0	60	56
	136	0	53	92
	158	0	29	07
	159	0	77	85
	161	0	62	46
	160	0	15	60
	169	0	03	46
	170	0	73	65
	173	0	04	20
	172	0	83	75
	180	0	02	16
	166	0	06	75

(No. O-14016/187/85-GP]

का. आ. 2560.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 1522 तारीख 29-2-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

बिजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील मागरोल

गांव	खसरा नं०	हेक्टर	आर	सेन्टी-आर
पाडलिया	19	0	06	30
	20	0	94	48
	51	0	14	70
	23	0	14	16
	22	1	05	28
	14	0	00	56
	11	0	34	50
	10	0	53	96
	7	0	12	00
	8	0	45	60
	5	0	33	00
	4	0	07	02
	-1	0	05	58
	12	0	00	04

[सं० O-14016/194/85-जी पी]

S O 2560—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S O 1527 dated 29-3-85 under sub section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ,

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ,

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

[No O 14016/194/85-G P]

SCHEDULE

Pipeline from Bijapur (M P) to Sawai Madhopur (Raj)

State Rajasthan District Kota Tehsil Mangbol

Village	Survey No	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Padliya	19	0	06	30
	20	0	94	48
	51	0	14	70
	23	0	14	16
	22	1	05	28
	14	0	00	56
	11	0	34	50
	10	0	53	96
	60	0	12	00
	8	0	45	60
	5	0	33	00
	4	0	07	02
	1	0	05	58
	12	0	00	04

[No O-14016/194/85-GP]

का आ 2561.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स 1531 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा।

अनुसूची

बिजयपुर (म प्र) से सवाई माधोपुर (राज) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील मांगरोल

गांव	खसरा न	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
महुआ	201	0	39	30
	194	0	75	06
	192	0	19	20
	191	0	33	50
	197/2	0	03	30
	193	0	00	04

[सं० O-14016/198/85-जी पी]

S.O. 2561.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O 1531 dated 29-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State Rajsthan District : Kota Tehsil Mangro

Village	Survey No.	Hectae	Are	Centiae
1	2	3	4	5
Mahuwa	201	0	39	30
	194	0	75	6
	192	0	19	20
	191	0	33	50
	197/2	0	03	30
	193	0	00	04

[No. O-14016/198/85-GP]

का.आ. 2562.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियमम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हजीरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	गाव	गारा संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबर पुर	अकबर पुर	फतेह-राजनाई	9	1-01-00	
				18	0-17-00	
				44	1-13-00	
				45	0-10-00	
				46	0-00-10	
				47	0-09-00	
				48	1-00-00	
				49	0-01-00	
				50	0-09-00	
				333	0-03-00	
				334	0-05-00	
				335	0-02-00	
				341	0-02-00	
				342	0-11-00	
				343	0-01-00	
				344	0-10-00	
				345	0-03-00	
				346	0-01-00	
				404	0-19-00	
				419	0-10-00	
				420	0-04-00	
				421	0-12-10	
				424	0-05-00	
				125	0-08-00	
				426	1-13-00	
				464	0-15-00	
				469	0-02-00	
				470	0-00-05	
				471	1-04-00	
				472	1-17-00	
				480	0-06-00	
				181	0-03-00	
				487	0-07-00	
				488	0-00-10	
				489	0-00-10	
				492	0-05-10	
				493	0-14-00	
				494	1-04-10	
				495	0-11-10	

5	6
496	0-17-10
497	0-15-00
430	0-00-05
340	0-01-00
435	0-00-10
479	0-00-05

[सं० O-14016/320/84 जीपी]

S.O. 2562.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4081 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification :

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Maira to Bareilly to Jagdishpur

Dis triet	Tehsil	Pargana	Village	Survey No.	Area B V.B.	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Fate-pur Rosh-nai	9	1-01-00	
				18	0-17-00	
				44	1-13-00	
				45	0-10-00	
				46	0-00-10	
				47	1-09-00	
				48	1-00-00	
				49	0-01-00	
				50	0-09-00	
				333	0-03-00	
				334	0-05-00	
				335	0-02-00	
				341	0-02-0	
				342	0-11-00	
				343	0-01-00	
				344	0-10-00	
				345	0-03-00	
				346	0-01-00	
				404	0-19-00	
				419	0-10-00	
				420	0-04-00	
				421	0-12-10	
				424	0 05-00	
				425	0-08-00	
				426	1-13-00	
				464	0-15-00	
				469	0-02-00	
				470	0-00-05	
				471	1-04-00	
				472	1-17-00	
				480	0-06-00	
				481	0-03-00	
				487	0-07-00	
				488	0-00-10	
				489	0-00-10	
				492	0-05-10	
				493	0-14-00	
				494	1-04-10	
				495	0-11-10	
				496	0-17-10	
				497	0-15-00	
				430	0-00-05	
				340	0-01-00	
				435	0-00-10	
				479	0-00-05	

[No. O-14016/320/84-G P]

का. आ. 2563.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3749 तारीख 30-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	किया गया विवरण रकबा एकड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	हिडोखरा	15	0–03	
				18	0–01	
				19	0–05	
				20	0–03	
				21	0–15	
				22	0–18	
				23	0–38	
				24	0–65	
				35	0–04	
				45	1–10	
				46	0–18	
				44	0–18	
				43	0–01	
				65	0–75	
				41	0–30	
				42	0–52	
				48	0–03	
				75	0–80	
				76	0–90	
				77	0–20	
				78	0–55	

[सं० O-14016/83/84-जीपी]

S.O. 2563.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3749 dated 30-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances,

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hazira Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres.	Remark
1	2		4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Hidokhra	15	0–03	
				18	0–01	
				19	0–05	
				20	0–03	
				21	0–05	
				22	0–18	
				23	0–38	
				24	0–65	
				35	0–04	
				45	1–10	
				46	0–18	
				44	0–18	
				43	0–01	
				65	0–75	
				41	0–30	
				42	0–52	
				48	0–03	
				75	0–80	
				76	0–90	
				77	0–20	
				78	0–55	

[No. O-14016/83/84-GP]

का. आ. 2564.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4102 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला-तहसील-परगना			ग्राम का नाम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महाराजगंज	सेमरौता	सेमरौता	14एम	0-9-0	
				90एम.	0-1-16	
				92एम	0-16-10	
				93एम	0-11-10	
				94एम	0-1-16	
				116एम	0-0-2	
				117एम	0-19-4	
				118एम	0-7-4	
				126एम	0-6-2	
				155एम	0-5-9	
				161एम	0-7-8	
				164एम	0-16-2	
				172एम	1-1-6	
				175एम	0-2-0	
				175/146	0-11-4	
				177एम	0-0-1	
				178एम	0-3-17	
				179एम	0-6-0	
				184एम	0-6-0	
				188एम	0-2-5	
				192एम	0-0-11	
				193एम	0-3-0	
				194एम	0-5-4	
				194एम	0-0-15	
				2151		
				196एम	0-0-1	
				197एम	0-9-11	
				198एम	0-5-6	
				199एम	0-0-2	
				201एम	0-4-6	
				210एम	0-11-5	
				219एम	0-0-10	
				13एम	0-0-5	
				17एम	0-0-5	
				23एम	1-6-3	
				96एम	0-4-10	
				97एम	0-0-6	
				98एम	0-0-12	
				119एम	0-1-2	
				156एम	0-0-18	
				157एम	0-0-2	
				163एम	0-0-7	
				165एम	0-1-2	
				173एम	0-1-10	
				176एम	0-3-0	
				185एम	0-4-0	
				189	0-2-0	
				190एम	0-2-0	
				202एम	0-1-0	
				211एम	0-0-13	
				212एम	0-4-12	
				227एम	0-1-5	

[सं. O 14016/4/84-जीपी]

S.O. 2564.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4102 dated 1.12.84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Barielly Jagdishpur Pipeline Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Bareilly	Maharajganj	Samrota	Semrota	14m	0-9-0	
				90m	0-1-16	
				92m	0-16-10	
				93m	0-11-10	
				94m	0-1-16	
				116m	0-0-2	
				117m	0-19-4	
				118m	0-7-4	
				126m	0-6-2	
				155m	0-5-9	
				161m	0-7-8	
				164m	0-16-2	
				172m	1-1-6	
				175m	0-[illegible]-0	
				175/146	0-11-4	
				177m	0-0-1	

178m.	0-3-17
179m.	0-6-0
180m.	0-6-0
188m.	0-2-5
192m	0-0-11
193m	0-3-0
194m.	0-5-4
194m.	0-0-15
215m.	
196m	0-0-1
197m.	0-9-11
198m.	0-5-6
199m.	0-0-2
201m.	0-4-5
210m.	0-11-5
219m.	0-0-10
13m.	0-0-8
17m.	0-0-5
23m.	1-6-3
96m.	0-4-10
97m.	0-0-6
98m.	0-0-12
119m.	0-1-2
156m.	0-0-18
157m.	0-0-2
163m.	0-0-7
165m.	0-1-2
173m.	0-1-10
176m.	0-3-0
185m.	0-4-0
189	0-2-0
190m.	0-2-0
202m.	0-1-0
211m.	0-0-13
212m.	0-4-12
227m.	0-1-5

[No. O-14016/4/84-GP]

का० आ० 2565.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारका (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ. सं० 4125 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्र. बी वि. बि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबर पुर	अकबर पुर	किमरखल	1286	0-15-3	
				1283	2-6-18	
				1288	0-0-13	
				1290	1-9-14	
				1277	0-0-13	
				1278	0-0-6	
				1275	0-8-15	
				1273	1-8-0	
				1279	0-1-7	
				1268	0-1-0	
				1272	0-3-17	
				1264	1-2-13	
				1256	1-18-9	
				1254	0-13-0	
				1255	0-9-9	
				1240	0-0-1	
				1241	0-0-2	
				224	1-7-0	
				221	0-0-6	
				220	0-0-13	
				219	2-1-0	
				116	0-8-0	
				217	0-0-12	
				218	0-1-13	
				117	1-13-15	
				208	0-1-7	
				205	0-18-0	
				206	0-6-0	
				124	0-16-0	
				165	0-6-0	
				163	0-5-0	
				167	0-4-0	
				170	0-7-0	
				171	0-3-0	

169	0–5–0
125	0–0–13
126	0–1–7
69	0–10–10
67	0–0–1
68	0–4–0
72	0–3–0
70	0–1–6
71	0–2–15
465	0–3–0
464	0–15–0
421	0–1–7
424	0–3–14
463	0–6–10
468	1–3–6
470	1–7–7
502	0–0–3
503	0–0–2
196	0–0–3
495	1–0–10
494	0–16–4
493	0–9–17
491	1–9–0
505	0–1–6
501	0–1–6
490	0–11–0
488	0–16–5
518	0–0–1
519	0–8–0
516	0–0–6
517	0–0–13
1243	1–11–0
1072	0–5–1
122	0–16–0
193	0–14–1
164	0–12–0
159	2–15–15
172	1–0–0
73	0–2–18
471	2–14–7
506	0–8–0
485	0–0–10
489	0–10–0
209	0–1–10

[म O–14016/347/81-जी पी]

S.O. 2565.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4125 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of Vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajha Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No	Acquired	Remar
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akber Pur	Akber Pur	Kisarwal	1286	0–15–3	
				1283	2–6–18	
				1288	0–0–13	
				1290	1–9–14	
				1277	0–0–13	
				1278	0–0–6	
				1275	0–8–15	
				1273	1–8–0	
				1279	0–1–7	
				1268	0–1–0	
				1272	0–3–17	
				1264	1–2–13	
				1256	1–18–9	
				1254	0–13–0	
				1255	0–9–9	
				1240	0–0–1	
				1241	0–0–2	
				224	1–7–0	
				221	0–0–6	
				220	0–0–13	
				219	2–1–0	
				116	0–8–0	
				217	0–0–12	
				218	0–1–13	
				117	1–13–15	
				208	0–1–7	
				205	0–18–0	
				206	0–6–0	
				124	0–16–0	
				165	0–6–0	
				163	0–5–0	
				167	0–4–0	
				170	0–7–0	
				171	0–3–0	
				169	0–5–0	
				125	0–0–13	
				126	0–1–7	
				69	0–10–10	
				67	0–0–1	
				68	0–4–0	
				72	0–3–0	
				70	0–1–6	
				71	0–2–15	
				465	0–3–0	
				464	0–15–0	
				421	0–1–7	

1	2	3	4	5	6	7
				424	0-0 14	
				463	0-6-10	
				468	1-3-6	
				470	1-7-7	
				502	0-0-3	
				503	0-0-2	
				496	0-0-3	
				495	1-0-10	
				494	0-16-4	
				493	0-9-17	
				491	1-9-0	
				505	0 1-6	
				504	0-1-6	
				490	0-11-0	
				488	0 16-5	
				518	0 0-1	
				519	0-8-0	
				516	0-0-6	
				517	0-0-13	
				1243	1-11-0	
				1072	0-5-1	
				122	0-16-0	
				193	0-14-1	
				164	0-12-0	
				159	2-15-15	
				172	1-0-0	
				73	0-2-18	
				471	2-14-7	
				506	0-8-0	
				485	0-0-10	
				489	0-10-0	
				209	0-1-10	

[No. O-14016/347/84-GP]

का०आ० 2566 —यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ. 4073/तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना के सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ?

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6 7
जालौन	जालौन	जालौन	कुरेपुरा कलार	174	0-02
				180	0-01
				181	2-66
				183	0-02
				184	0-90
				185	0-63
				187	0-06
				285	0-01
				287	0-27
				288	0-72
				274	0-21
				275	0-01
				266	0-06
				267	0-02
				272	0-24
				273	0-34
				271	0-02
				268	0-28
				263	0-03
				259	0-26
				255	0-51
				256	0-02
				248	1-47
				249	0-03
				1	0-09
				2	0-05
				231	0-72
				241	0-02
				242	0-60
				243	0-02
				244	0-54
				245	0-63
				246	0-30
				247	0-02
				282	0-01
				186	0-05

[सं. O-14016/312/84-जीपी]

S.O. 2566.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4073 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its

intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas he Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-secticon (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

					Area	Remark
Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired	
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Kure pura-Kanar	174	0-02	
				180	0-01	
				181	2-66	
				183	0-02	
				184	0-90	
				185	0-63	
				187	0-06	
				285	0-01	
				287	0-27	
				288	0-72	
				274	0-21	
				275	0-01	
				266	0-06	
				267	0-02	
				272	0-24	
				273	0-34	
				271	0-02	
				268	0-28	
				263	0-03	
				259	0-26	
				255	0-51	
				256	0-02	
				248	1-47	
				249	0-03	
				1	0-09	
				2	0-05	
				231	0-72	
				241	0-02	
				242	0-60	
				243	0-02	
				244	0-54	
				245	0-63	
				246	0-30	
				247	0-02	
				282	0-01	
				186	0-05	

[No. O-14016/312/84-GP]

का०आ० 2567.—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का०आ०स तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमिया के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम—लिया गया—रकबा		विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबर पुर	अकबर पुर	बुढ़िया	225	0-7-0	
				223	0-1-8	
				222	0-8-0	
				204	0-3-0	
				177	0-2-0	
				178	0-14-13	
				180	0-2-0	
				181	0-4-10	
				183	0-0-6	
				184	0-0-13	
				189	0-5-0	
				190	0-8-0	
				193	0-6-10	
				192	0-11-0	

1	2	3	4	5	6	7
				185	0-2-8	
				170	0-7-0	
				165	5-3-5	
				135	0-4-4	
				133	0-7-0	
				132	0-1-12	
				166	1-10-0	
				28	0-12-16	
				29	3-8-0	
				34	0-1-10	
				33	0-1-10	
				35	0-3-4	
				27	0-2-10	
				169	1-1-10	
				191	0-5-0	
				168	0-1-10	
				205	0-8-10	

[सं. O 14016/352/84-जीपी]

S.O. 2567.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4073 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas he Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-sectioon (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project.

Dist.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur	Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Bulhia-225	0-7-0	
				223	0-1-8	
				222	0-8-0	
				204	0-3-0	
				177	0-2-0	
				178	0-14-13	
				180	2-2-0	
				181	0-4-10	
				183	0-0-6	
				184	0-0-3	
				189	0-5-0	
				190	0-8-0	
				193	0-6-10	
				192	0-11-0	
				185	0-2-8	
				170	0-7-0	
				165	5-3-5	
				135	0-4-4	
				133	0-7-0	
				132	0-1-12	
				166	1-10-0	
				28	0-12-16	
				29	3-8-0	
				34	0-1-10	
				33	0-1-10	
				35	0-3-4	
				27	0-2-10	
				169	1-1-10	
				191	0-5-0	
				168	0-1-10	
				205	0-8-10	
				182	0-3-0	

[No. O-14016/352/84-GP]

का०आ० 2568.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं० 3706 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला–तहसील परगना–ग्राम का नाम				लिया गया रकबा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली-महाराजगज-सेमरौता-सयसपुर				567	0–9–0	
			हलौर	583	0–17–10	
				590	1–1–5	
				616	0–6–12	
				615	0–11–10	
				609	0–8–0	
				611	0–0–0	
				614	0–0–10	
				610	0–8–0	
				713	0–5–5	
				712	0–15–0	
				714	0–2–0	
				726	0–4–10	
				728	0–4–0	
				729	0–1–15	
				704	0–6–15	
				702	0–4–15	
				701	0–1–0	
				700	0–2–5	
				745	1–14–0	
				746	0–11–0	
				747	0–2–0	
				757	0–2–0	
				758	0–2–10	
				759	0–3–10	
				756	0–15–5	
				793	0–5–0	
				792	0–19–10	
				790	0–4–10	
				1008	0–15–0	
				1011	0–12–5	
				1013	0–12–0	
				1015	1–4–15	
				1466	0–1–15	
				1469	0–4–15	
				1468	1–5–0	
				1470	0–2–15	
				1486	0–1–10	
				1487	0–4–15	
				1491	1–14–10	
				1492	0–10–0	
				1493	0–5–10	
				1499	0–10–0	
				1500	0–6–0	
				1506	1–2–0	
				1125	0–2–0	
				1507	1–10–00	
				1508	0–15–0	
				1509	0–10–10	
				1510	1–6–10	
				1617	0–16–10	
				1618	0–5–10	
				1619	0–8–0	
				584	0–16–10	
				725	0–1–0	
				580	0–1–0	
				655	0–2–10	
				732	0–3–0	
				1488	0–1–5	
				1014	0–0–6	
				1512	0–6–6	
				727	0–0–15	
				1465	0–0–5	
				585	0–1–0	

[सं० 14016/163/84–जी.पी.]

S.O. 2568.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3706 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Gooovernment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Schedule

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pip line Project

Distt.	Tehsil	Parg-ana	Village	Plot No.	Area acquired.	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai-Baricily	Maha-raja-ganj.	Samro-da	Sams-pur Halor			
				567	0–9–0	
				583	0–17–10	
				590	1–1–5	
				616	0–6–12	
				615	0–11–10	
				609	0–8–0	
				611	0–0–0	
				614	0–0–10	
				610	0–8–0	
				713	0–5–5	

1	2	3	4	5	6	7
				712	0–15–0	
				714	0–2–0	
				726	0–4–10	
				728	0–4–0	
				729	0–1–15	
				704	0–6–15	
				702	0–4–15	
				701	0–1–0	
				700	0–2–5	
				745	1–14–0	
				746	0–11–0	
				747	0–2–0	
				757	0–2–0	
				758	0–2–10	
				759	0–3–10	
				756	0–15–5	
				793	0–5–0	
				792	0–19–10	
				790	0–4–10	
				1008	0–15–0	
				1011	0–12–15	
				1013	0–12–0	
				1015	1–4–15	
				1466	0–1–15	
				1469	0–4–15	
				1468	1–5–0	
				1470	0–2–15	
				1486	0–1–10	
				1487	0–4–15	
				1491	1–14–10	
				1492	0–10–0	
				1493	0–5–10	
				1499	0–10–0	
				1500	0–6–0	
				1506	1–2–0	
				1425	0–2–0	
				1507	1–10–00	
				1508	0–15–0	
				1509	0–10–0	
				1510	1–6–10	
				1617	0–16–10	
				1618	0–15–10	
				1619	0–8–0	
				584	0–16–10	
				725	0–1–0	
				580	0–1–0	
				655	0–2–10	
				732	0–3–0	
				1488	0–1–5	
				1014	0–0–6	
				1512	0–6–6	
				727	0–0–15	
				1465	0–0–5	
				585	0–1–0	

[No. O-14016|193|84-G.P.]

का०आ० 2569.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० सं० 3901 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप- लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय बरेली	बछरांवा	बछरावोमां	राजा मऊ	622	1–0–8	
				621	0–2–10	
				620	1–6–12	
				619	0–2–15	
				618	0–3–10	
				616	1–2–12	
				613	0–1–0	
				577	0–4–0	
				578	0–8–10	
				579	0–0–15	
				580	0–8–0	
				582	1–6–2	
				583	0–1–8	
				586	1–17–2	
				587	0–1–10	
				588	0–12–4	
				561	0–7–4	
				871	0–8–4	
				873	0–15–4	
				872	0–0–5	
				874	0–12–1	
				875	0–0–15	
				886	0–14–8	
				887	0–2–10	
				559	0–19–12	

1	2	3	4	5	6	7
				921	0-2-0	
				922	0-5-0	
				919	0-8-0	
				916	0-15-0	
				557	1-6-4	
				558	0-0-10	
				907	0-2-10	
				908	0-10-10	
				418	0-4-4	
				909	0-3-10	
				911	0-2-10	
				910	0-1-10	
				1119	0-8-8	
				1113	0-10-0	
				1122	1-15-11	
				1128	1-17-8	
				1110	0-6-0	
				1089	0-3-5	
				1090	0-12-0	
				1091	0-10-0	
				1088	0-1-0	
				1092	0-1-10	
				1317	0-17-0	
				1318	0-1-10	
				1319	0-0-10	
				1320	0-18-0	
				1321	0-11-8	
				1322	0-8-14	
				1323	0-1-0	
				1325	0-17-12	
				1324	0-1-10	
				1324/1467	0-0-10	
				1326	1-9-8	
				1392	1-15-0	
				1393	0-0-12	
				1394	1-1-16	
				923	0-2-0	
				554	0-0-15	

[सं. O-14016/239/84-जीपी]

S.O. 2569.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum. S. O. 3901 dated 24-11-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Gooverment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Dist.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rai Bareilly	Maharaj ganj	Balhn rameema	Raja mau	622	1-0-8	
				621	0-2-10	
				620	1-6-12	
				619	0-2-15	
				518	0-3-10	
				616	1-2-12	
				513	0-1-0	
				577	0-4-0	
				578	0-8-10	
				579	0-0-15	
				580	0-8-0	
				582	1-6-2	
				583	0-1-8	
				586	1-17-2	
				587	0-1-10	
				588	0-12-4	
				561	0-7-4	
				871	0-8-4	
				873	0-15-4	
				872	0-0-5	
				874	0-12-1	
				875	0-0-15	
				886	0-14-8	
				887	0-2-10	
				559	0-19-12	
				921	0-2-0	
				922	0-5-0	
				919	0-8-0	
				916	0-15-0	
				557	1-6-4	
				558	0-0-10	
				907	0-2-10	
				908	0-10-10	
				418	0-4-4	
				909	0-3-10	
				911	0-2-10	
				910	0-1-10	
				1119	0-8-8	
				1113	0-10-0	
				1122	1-15-11	
				1128	1-17-8	
				1110	0-6-0	
				1089	0-3-5	
				1090	0-12-0	
				1091	0-10-0	
				1088	0-1-0	
				1092	0-1-10	
				1317	0-17-0	
				1318	0-1-10	
				1319	0-0-10	
				1320	0-18-0	
				1321	0-11-8	
				1322	0-8-14	
				1323	0-1-0	
				1325	0-17-12	
				1324	0-1-10	
				1324/1467	0-0-10	
				1326	1-9-8	
				1392	1-15-0	
				1393	0-0-12	
				1394	1-1-16	
				923	0-2-0	
				554	0-0-15	

[No. O-14016/239/84-GP]

का०आ० 2570.:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 3906 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम डेवर तहसील आबुआ जिला—आबुआ राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची

अनु क्र. 1	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	71	0.121
2	94	0.462
3.	95/1	0.360
4.	99	0.120
5	101/1	0.485
6.	106/1	0.540
7.	107	0.024
8.	108/1	0.420
9.	114/1	0.270
10.	449	0.028
11.	450	0.004
12.	445/1	0.162
13.	448	0.016
14.	446/1	0.375
15	441/1	0.218
16.	442/1	0.161
17.	438/1	0.480
18.	440/1	0.690
19.	439	0.060
20.	259	0.120
21.	258	0.016
22.	260	0.567
23.	163	0.181
24.	170	0.081
25.	172/1	0.405
26.	174/1	0.210
27.	176/1	0.081
28.	231/1	0.324
29.	229/1	0.310
30.	228	0.219
31.	227	0.090
32	230	0.064
33.	232	0.040
34.	93	0.016
35.	257	0.032
36	446/2	0.024
37.	442/2	0.024
38.	441/2	0.030
39.	174/2	0.008
40.	233	0.016
41.	231/2	0.008
42.	444	0.020
43.	436/1	0.036
44.	437	0.043
45.	79/1	0.010
	योग — कुल क्षेत्र फल	7.971

[सं. O-14016/244/84-जी. पी.]

S.O. 2570.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3906 dated 24-11-84 under sub-section (I) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Gooverment directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Dhebar Tehsil Zabua Distt. Zabua

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area be to acquired for R.O.U. in Hectare
1.	71	0.121
2.	94	0.462
3.	95/1	0.360
4.	99	0.120
5.	101/1	0.485
6.	106/1	0.540
7.	107/	0 024
8.	108/1	0.420
9.	114/1	0.270
10.		
11.	449	0.028
12.	450	0.004
13.	445/1	0.162
14.	448	0.016
15.	446/1	0.375
16.	441/1	0.218
17.	442/1	0.161
18.	438/1	0.480
19.	440/1	0.690
20.	439	0.060
21.	259	0.120
22.	258	0.016
23.	260	0.567
24.	163	0.181
25.	170	0.081
26.	172/1	0.405
27.	174/1	174/1
28.	176/1	0.081
29.	231/1	0.324
30.	229/1	0.310
31.	228	0.219
32.	227	0.090
33.	230	0.064
34.	232	0.040
35.	93	0.016
36.	257	0.032
37.	446/2	0.024
38.	442/2	0.024
39.	441/2	0.030
40.	174/2	0.008
41.	233	0.016
42.	231/2	0.008
43.	444	0.020
44.	436/1	0.036
45.	437	0.043
46.	79/1	0.010
	Total Area	7.971

[No. O-1401/6/244/84-GP]

का० आ० सं० 2571.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3775 तारीख 17 11.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन

ग्राम गलोद मजरा तहसील बड़नगर जिला—उज्जैन राज्य (म.प्र.)

अनुसूची

क्रम	खसरा नं	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	16 18/2	1 050
2	1/2 12	0 100
3	11/1	0 605
4	11/2	0.300
5	42	0.790
6	43	0 070
7	74	0 010
8.	61	0.740
9	69	0 380
10	67/1	0.230
11	67/2	0.290
12.	94	0.950
13	18/1	0.160
14.	44	0.070
15	58	0.050
16	99	0.060
17	100	0 025
18	101	0.010
19	66/1	0.150
	कुल क्षेत्रफल	6.030

[सं. O-14016/111/84-जी. पी.]

S.O. 2571.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3775 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Jalod Sanjar Tehsil Badnagar Distt. Ujjain

SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired For R.O.U. in Hectare.
1.	16 18/2	1.050
2.	1/2 12	0.100
3.	11/1	0.605
4.	11/2	0.300
5.	42	0.790
6	43/2	0.070
7.	74	0.010
8.	61	0.740
9.	69	0.380
10.	67/1	0.230
11.	67/2	0.290
12.	94	0.950
13.	18/1	0.160
14	44	0.070
15.	58	0.050
16.	99	0.050
17.	100	0.025
18.	101	0.010
19.	66/1	0.150
Total Area		6.030

[No O-14016/144/84-GP]

का. आ 2572.— यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3704 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
राय बरेली	महराजगंज	बछरावाँ	बन्नावा	91	0-5-5	
				92	0-1-0	
				200	0-8-0	
				207	0-2-8	
				208	0-6-14	
				209	0-2-0	
				210	0-5-0	
				211	0-7-6	
				212	0-7-4	
				213	0-5-1	
				228	0-1-0	
				229	0-2-0	
				230	0-6-10	
				231	0-1-10	
				232	0-6-14	
				233	0-1-0	
				234	0-4-14	
				236	0-6-14	
				237	0-0-12	
				242	0-15-11	
				243	0-3-0	
				252	0-5-0	

1	2	3	4	5	6	7
				253	0-10-0	
				254	0-3-12	
				255	0-2-15	
				256	0-7-0	
				259	0-4-10	
				260	0-0-19	
				270	0-0-11	
				272	0-3-14	
				273	0-4-0	
				274	0-9-0	
				275	0-14-0	
				304	0-1-10	
				305	0-7-0	
				306	0-17-2	
				307	0-1-10	
				326	0-10-15	
				327	0-6-10	
				328	0-6-15	
				329	0-13-15	
				330	0-14-10	
				333	0-5-10	
				334	0-1-0	
				335	0-18-0	
				336	0-2-10	
				396	0-5-0	
				397	0-1-4	
				399	0-4-10	
				400	0-7-16	
				510	0-1-15	
				1448	2-17-12	
				1449	0-0-14	
				1450	0-2-8	
				1455	0-0-5	
				1456	0-2-0	
				1457	0-0-6	
				1458	0-3-0	
				1460	0-12-0	
				1467	0-11-6	
				1469	1-5-0	
				1470	0-4-4	
				1489	0-2-0	
				1720	2-8-0	
				1721	2-9-4	
				1723	0-3-3	
				1724	0-13-13	
				1725	0-1-6	
				1726	0-0-18	
				1727	0-10-10	
				1728	0-0-19	
				1733	0-1-16	
				1734	1-2-14	
				1735	0-4-0	
				1740	1-14-0	
				1742	0-7-5	
				1743	0-5-0	
				1790	0-18-12	
				398	0-0-15	
				417	0-1-0	
				418	0-0-15	
				1715	0-4-10	

[सं. ओ-14016/161/84-जी. पी.]

S.O. 2572.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3704 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rae Bareli	Maharaj Ganj	Bachhrawan	Bannauya	91	0-5-5	
				92	0-1-0	
				200	0-8-0	
				207	0-2-8	
				208	0-6-14	
				209	0-2-0	
				210	0-5-0	
				211	0-7-6	
				212	0-7-4	
				213	0-5-4	
				228	0-1-0	
				229	0-2-0	
				230	0-6-10	
				231	0-1-10	
				232	0-6-14	
				233	0-1-0	
				234	0-4-14	
				236	0-6-14	
				237	0-0-12	
				242	0-15-11	
				243	0-3-0	
				252	0-5-0	
				253	0-10-0	
				254	0-3-12	
				255	0-3-15	

1	2	3	4	5	6	7
				256	0–7–0	
				259	0–4–10	
				260	0–0–19	
				270	0–6–11	
				272	0–3–14	
				273	0–4–0	
				274	0–9–0	
				275	0–14–0	
				304	0–1–10	
				305	0–7–0	
				306	0–17–2	
				307	0–1–10	
				326	0–10–15	
				327	0–6–10	
				328	0–6–15	
				329	0–13–15	
				330	0–14–10	
				333	0–5–10	
				334	0–1–0	
				335	0–18–0	
				336	0–2–10	
				396	0–5–0	
				397	0–1–4	
				399	0–4–10	
				400	0–7–16	
				510	0–1–15	
				1448	2–17–12	
				1449	0–0–14	
				1470	0–2–8	
				1455	0–0–5	
				1456	0–2–0	
				1457	0–0–6	
				1458	0–3–0	
				1460	0–12–0	
				1467	0–11–6	
				1469	1–5–0	
				1470	0–4–4	
				1489	0–2–0	
				1720	2–8–0	
				1721	2–9–4	
				1723	0–3–3	
				1724	0–13–13	
				1725	0–1–6	
				1726	0–0–18	
				1727	0–10–10	
				1728	0–0–19	
				1733	0–1–16	
				1734	1–2–14	
				1735	0–4–0	
				1740	1–14–0	
				1742	0–7–5	
				1743	0–5–0	
				1790	0–18–12	
				398	0–0–15	
				417	0–1–0	
				418	0–0–15	
				1715	0–4–10	

[No. O-14016/161/84-GP]

का. आ. 2573.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4065 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लाट नम्बर	क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जलौन	काल	कोन	सुमरी	2	2-02	
				8	0-03	
				11	0-60	
				12	1-00	
				19	0-02	
				20	0-18	
				27	0-03	
				29	3-22	
				30/1	0-09	

[सं. ओ-11016/303/84-जी. पी.]

S.O 2573.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 4065 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jolaun	Konch	Konch	Ghamari	2	2-02	
				8	0-03	
				11	0-60	
				12	1-00	
				19	0-02	
				20	0-18	
				27	0-03	
				29	2-22	
				30/1	0-09	

[No. O-14016/303/84-GP]

का. आ. 2574— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 379 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया विवरण रकबा एकड़ में	
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	जमलापुर श्याम	67	0-69	
				68क	0-06	
				176	0-03	
				175	0-87	
				177	0-18	
				179	0-04	
				180	0-02	
				181	0-35	
				182	1-14	
				183	0-12	
				184	0-28	
				191	0-02	
				227	0-92	
				229	0-80	
				230	0-03	
				235	0-03	
				231	0-52	
				232	0-23	
				242	0-02	
				243	0-03	
				226	0-05	

[सं. ओ-14016/182/84जी. पी.]

S.O. 2574.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 3791 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpoose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

Schedule
Hijira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Jamal-pur Dhyan	67	0–69	
				68a	0–06	
				176	0–03	
				175	0–87	
				177	0–18	
				179	0–04	
				180	0–02	
				181	0–35	
				182	1–14	
				183	0–12	
				184	0–28	
				191	0–02	
				227	0–92	
				229	0–80	
				230	0–03	
				225	0–03	
				231	0–52	
				232	0–23	
				242	0–02	
				243	0–03	
				226	0–05	

[No O-14016/182/84-GP]

का. आ. 2575—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4127 तारीख 11-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची
हाजिरा-बरेला जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल बि-बि०बि०	विवरण
	अनुसूची					
कानपुर	देहात-अकबर पुर	अकबर पुर	बिसायक पुर	1186	1-07-00	
				1187	1-10-10	
				1215	0-11-00	
				1217	0-18-00	
				1219	0-06-10	
				1320	0-05-00	
				1221	0-03-00	
				1222	0-19-00	
				1223	0-17-00	
				1224	0-18-00	
				1225	0-12-00	
				1228	0-01-10	
				1269	1-08-00	
				1548	0-03-00	
				1549	0-03-00	
				1551	0-3-00	
				1552	1-08-00	
				1553	0-06-00	
				1554	0-08-00	
				1555	0-05-00	
				1572	0-01-00	
				1573	0-06-10	
				1574	0-09-00	
				1578	0-13-10	
				1579	0-04-10	
				1580	0-02-10	
				1581	1-01-00	
				1582	0-05-00	
				1590	0 01 00	
				1601	0-02-00	
				1602	0-01-10	
				1603	0-06-10	
				1604	1-03-00	
				1606	0-04-10	
				1607	0-17-00	
				1609	0-01-10	
				1615	0-00-10	
				1625	0-05-00	
				1758	0-10-00	
				1761	0-11-00	
				1762	0-15-00	
				1763	0-10-00	
				1765	0-02-10	
				1766	0-01-10	
				1767	0-16-00	
				1769	1-02-00	

1	2	3	4	5	6	7
				1771	1-02-00	
				1790	0-13-00	
				1792	1-12-00	
				1930	0-13-00	
				1944	0-13-00	
				1945	0-00-14	
				1946	0-15-00	
				1947	0-11-00	
				1948	0-17-00	
				1949	1-12-00	
				1950	0-07-00	
				1958	0-06-00	
				1960	2-02-00	
				1962	0-00-13	
				1963	0-02-14	
				1965	0-14-00	
				1980	0-06-00	
				2004	0-02-10	
				2006	0-09-00	
				2007	0-03-00	
				2009	0-18-00	
				2010	0-12-00	
				2011	1-10-00	
				1958	0-00-13	

[सं O-14016/349/84-जी. पी.]

S.O. 2575.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S. O. 4127 dated 11-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareily Jagdishpur Pipeline Project

Distt	Pergana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akber Pur	Akber Pur	Besaik-pur	1186	1-07-00	
				1187	1-10-10	
				1215	0-11-00	
				1217	0-18-00	
				1219	0-06-10	
				1220	0-05-00	
				1221	0-03-00	
				1222	0-19-00	
				1223	0-17-00	
				1224	0-18-00	
				1225	0-12-00	
				1228	0-01-00	
				1269	1-08-10	
				1548	0-0-300	
				1549	0-03-00	
				1551	0-03-00	
				1552	1-08-00	
				1553	0-06-00	
				1554	0-08-00	
				1555	0-05-00	
				1572	0-01-00	
				1573	0-06-10	
				1574	0-09-00	
				1578	0-13-10	
				1579	0-04-10	
				1580	0-02-00	
				1581	1-01-00	
				1582	0-05-00	
				1590	0-01-00	
				1601	0-02-00	
				1602	0-01-10	
				1603	0-06-10	
				1604	1-03-00	
				1606	0-04-10	
				1607	0-17-00	
				1609	0-01-10	
				1615	0-00-10	
				1625	0-05-00	
				1758	0-10-00	
				1761	0-11-00	
				1762	0-15-00	
				1763	0-10-00	
				1765	0-02-10	
				1766	0-01-10	
				1767	0-16-00	
				1769	1-02-00	
				1771	1-02-10	
				1790	0-13-00	
				1791	1-12-00	
				1930	0-13-00	
				1944	0-13-00	
				1945	0-00-14	
				1946	0-15-00	
				1947	0-11-00	
				1948	3-17-00	
				1949	1-12-00	
				1950	0-07-00	
				1958	0-06-00	
				1960	2-02-00	
				1962	0-00-13	
				1963	0-02-14	
				1965	0-14-00	
				1980	0-06-00	
				2004	0-02-10	
				2006	0-09-00	
				2007	0-03-00	
				2009	0-18-00	
				2010	1-10-00	
				2011	1-10-00	
				1958	0-00-13	

[No. O-14016/349/84-GP]

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

का०आ० 2576.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश मे हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन, के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगज लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं	क्षेत्रफल एकड़ डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
शाहजहाँपुर	काट	सदर	धनुवाखेड़ा	41	-- 18	
				42	-- 18	
				43	-- 84	
				44	— 35	
				47	— 42	
				52	— 02	
				53	-- 13	

[सं O-14016/354/85-जी. पी.]

New Delhi, the 30th May, 1985

S.O 2576.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd H B J Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U P

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

INDEX

Gas pipeline from, Hajira-Bareilly-Jagdish Pur-Project

District	Tehsil	Pargna	Village	Plot no	Area Acd Dismil	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Shahjahanpur	Sadar	Kat	Dhanuwakhada	41	— 18	
				42	— 18	
				43	— 84	
				44	— 35	
				47	— 42	
				52	— 02	
				53	— 13	

[No O-14016/354/85-G P]

का० आ० 2577.—यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित मे यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश मे हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अत. अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी-58/बी, अलीगज, लखनऊ-226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 [illegible]

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा--बरेली – जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
शाहजहाँ-	सदर	कट	बरनावा	87	--	30	
पुर				94	--	30	
				95	--	10	
				98	--	68	
				99	--	45	
				100	--	04	
				101	--	50	
				102	--	55	
				88	--	02	

[स. O-14016/355/85-जी. पी.]

S.O. 2577.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdispur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H. B. J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipeline from Hajira—Bareilly—Jabdishpur Project

Distriat	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	AREA Acd.	Dismil	Remark
1	2	3	4	5	6		7
Shahjahan-	Sadar	Kat	Barnawa	87	—	30	
pur				94	—	30	
				95	—	10	
				98	—	68	
				99	—	45	
				100	-	04	
				101	--	50	
				102	—	55	
				88	—	02	

[No. O-14016/355/85-G.P]

का० आ० 2578.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जमदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यत प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि०, बी/58 बी, अलीगंज लखनऊ-226020 यू०पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत हो ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
शाहजहाँ-	सदर	अमौर	जमौर	141	--	94	
पुर				142	—	16	
				143	—	42	

[स. O-14016/351/85-जी. पी.]

S.O. 2578.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdispur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipeline From Hajira—Bareilly Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	AREA Acd.	Dismil.	Remark
1	2	3	4	5	6		7
Shah-	Sadar	Jabhour	Jabhour	141	—	0.94	
jahanpur				142	—	16	
				143	—	42	

[No. O-14016/351/85-G.P.]

का० आ० 2579.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा–बरेली–जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकारी लि० बी–58/बी अलीगंज लखनऊ–226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

(अनुसूची)

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
शाहजहाँ-	कांट	सदर	जाजलपुर	220	--	18	
पुर				221	--	65	
				223	--	03	
				224	--	45	
				225	--	38	
				226	--	15	
				165	--	07	

[सं. O-14016/352/85-जी. पी.]

S.O. 2579.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipe line From Hajira—Bareilly—Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	AREA Acd.	Dismil.	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8
Shahjahan-	Sadar	Kat	Jajalpur	220	—	18	
pur				221	—	65	
				223	—	03	
				224		45	
				225	—	38	
				226	—	15	
				165	—	07	

[No. O-14016/352/85-G.P.]

का० आ० 2580.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम, 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि० बी–58/बी अलीगंज लखनऊ–226020 यू० पी० को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

(अनुसूची)

हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल बि.-बि.-बि.	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	गोरियासी-शाला	353	1-3-0	
				351	0-4-0	
				352	0-14-0	
				354	0-15-0	
				369	0-13-4	
				370	0-7-4	
				371	0-5-8	
				373	0-6-0	
				380	0-5-0	
				398	0-1-13	
				403	0-4-16	
				382	0-5-8	
				383	0-5-8	
				397	0-3-0	
				399	0-1-13	
				610	0-15-0	
				401	0-3-0	
				402	0-4-4	
				581	0-18-0	
				404	0-10-16	
				405	0-11-17	
				406	0-5-8	
				407	0-6-5	
				425	0-8-15	
				128	0-8-8	
				435	0-10-0	
				436	0-7-7	
				437	0-6-0	
				438	0-3-7	
				542	0-9-0	
				562	0-13-0	
				547	0-14-17	
				548	0-10-0	
				550	0-13-6	
				558	0-3-10	
				557	0-13-0	
				566 मिन	1-7-0	
				568	0-5-0	
				608	0-2-0	
				570	0-4-16	
				571	0-2-14	
				572	0-1-10	
				573	0-2-0	
				597	0-6-12	
				605	0-0-10	
				616	0-15-0	
				606	0-13-0	
				611	0-6-10	
				615	0-3-0	
				500	0-1-6	
				901	0-0-5	
				902	0-5-0	
				903	0-13-0	
				904	0-10-0	
				905	0-17-0	
				921	0-8-0	
				915	0-10-0	
				899	0-12-0	
				914	0-15-0	
				897	0-6-0	
				910	0-18-0	
				912	0-12-10	
				911	0-15-0	
				916	0-3-0	
				913	0-4-10	
				906	0-7-0	
				900	0-4-0	
				295	0-5-0	
				563	0-2-0	
				909	0-2-0	

[सं. O-14016/365/85-जी. पी.]

S.O. 2580.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Barellly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd, H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj, Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipe Line From Hajira-Barailly-Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Bigha. Biswa, Biswansi	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Goriya Shishala	353	1-3-0	
				351	0-4-0	
				352	0-14-0	
				354	0-15-0	
				369	0-13-4	
				370	0-7-4	
				371	0-5-8	

1	2	3	4	5	6	7
Hardoi—(co ntd.)				373	0-6-0	
				380	0-5-0	
				398	0-1-13	
				403	0-4-16	
				382	0-5-8	
				383	0-5-8	
				397	0-3-0	
				399	0-1-13	
				610	0-15-0	
				401	0-3-0	
				402	0-4-4	
				561	0-18-0	
				404	0-10-16	
				405	0-11-17	
				406	0-5-8	
				407	0-6-5	
				425	0-8-15	
				428	0-8-8	
				435	0-10-0	
				436	0-7-7	
				437	0-6-0	
				438	0-3-7	
				542	0-9-0	
				562	0-13-0	
				547	0-14-17	
				548	0-10-0	
				550	0-13-0	
				558	0-3-10	
				557	0-13-0	
				566mini	1-7-0	
				568	0-5-0	
				608	0-2-0	
				570	0-4-16	
				571	0-2-14	
				572	0-1-10	
				573	0-2-0	
				597	0-6-12	
				605	0-0-10	
				616	0-15-0	
				606	0-13-0	
				611	0-6-0	
				615	0-3-10	
				600	0-1-6	
				901	0-0-5	
				902	0-5-0	
				903	0-13-0	
				904	0-10-0	
				905	0-17-0	
				921	0-8-0	
				915	0-10-0	
				899	0-12-0	
				914	0-15-0	
				897	0-6-0	
				910	0-18-0	
				912	0-12-10	
				911	0-15-0	
				916	0-3-0	
				913	0-4-10	
				906	0-7-0	
				900	0-4-0	
				295	0-5-0	
				563	0-2-0	
				909	0-2-0	

[No. O-14016/365/85-GP]

का.आ. 2581.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	परगना	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण
					बी.-बि.बि.	
1	2	3	4	5	6	7
हरदोई	पछोहा	शाहाबाद	सकरौली	239	1-0-0	
				241	0-4-10	
				242	0-11-0	
				243	0-6-0	
				244	0-0-3	
				247	0-1-10	
				248	0-12-10	
				260	0-12-10	
				261	0-0-2	
				277	0-3-5	
				278	0-14-10	
				279	0-10-10	
				280	0-5-10	
				281	0-0-5	
				297	0-0-5	
				298	0-8-0	
				299	0-4-0	
				302	0-0-5	
				303	0-14-10	
				304	0-4-0	
				305	0-1-10	
				307	0-3-10	
				202	0-3-0	
				201	0-6-0	

1	2	3	4	5	6	7
हरदोई	पलोहा	शाहाबाद	सकरोली	200	0-2-0	
				199	0-7-5	
				198	0-5-10	
				177	0-8-15	
				176	0-0-3	
				181	0-2-10	
				182	0-0-4	
				179	0-3-0	
				178	0-3-10	
				174	0-6-0	
				173	0-7-0	
				169	0-8-10	
				170	0-6-0	
				411	0-0-3	
				410	0-10-0	
				409	0-3-0	
				408	0-9-10	
				407	0-0-10	
				406	0-12-0	
				405	0-2-15	
				436	0-5-0	
				467	0-6-0	
				468	0-15-10	
				469	0-9-0	
				470	0-4-0	

[सं. O 14016/364/85-जी. पी.]

S.O. 2581.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareily to Jagdispur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipe Line From Hajira-Bareilly-Jagdish pur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Bigha. Biswa Biswansi	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Sakrouli	239	1-0-0	
				241	0-4-10	
				242	0-11-0	
				243	0-6-0	
				244	0-0-3	
				247	0-1-10	
				248	0-12-10	
				260	0-12-10	
				261	0-0-2	
				277	0-3-5	
				278	0-14-10	
				279	0-10-10	
				280	0-5-10	
				281	0-0-5	
				297	0-0-5	
				298	0-8-0	
				299	0-4-0	
				302	0-0-5	
				303	0-14-10	
				304	0-4-0	
				305	0-1-10	
				307	0-3-10	
				202	0-3-0	
				201	0-6-0	
				200	0-2-0	
				199	0-7-5	
				198	0-5-10	
				177	0-8-5	
				176	0-0-3	
				181	0-2-10	
				182	0-0-4	
				179	0-3-0	
				178	0-3-10	
				174	0-6-0	
				173	0-7-0	
				169	0-8-10	
				170	0-6-0	
				411	0-0-3	
				410	0-10-0	
				409	0-3-0	
				408	0-9-10	
				407	0-0-10	
				406	0-12-0	
				405	0-2-15	
				436	0-5-0	
				467	0-6-0	
				468	0-15-10	
				469	0-9-0	
				470	0-4-0	

[No. O-14016/364/85-GP]

का. आ. 2582.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज-पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

गैस पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध मे भूमि अध्यापित करने का विवरण

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल बीघों मे बी.वि.वि.	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
हरदोई	शाहाबाद	पछोहा	नगला हुसैन	2	0-07-00	
				3	0-01-00	
				5	0-00-12	
				7	0-10-05	
				8	0-05-08	
				9	0-19-04	
				10	0-01-04	
				13	0-10-05	
				8	2-14-18	

[सं. O-14016/363/85-जी. पी.]

S.O. 2582.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Barellly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessarv to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area (Bigha)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
					B-B-B	
Hardoi	Shaha-bad	Pach-hoha	Nagla-husain	2	0-07-00	
				3	0-01-00	
				5	0-00-12	
				7	0-10-05	
				8	0-05-08	
				9	0-19-04	
				10	0-01-04	
				13	0-10-05	
				8	2-14-18	

का. आ. 2583.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश मे हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा बिस्वांसी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
हरदोई	शाहाबाद	पछोहा	भरखनी	1803	1- 15- 0	
				1802	0 13- 10	

1	2	3	4	5	6	7
				1797	0- 13- 0	
				1796	1- 10- 0	
				761	0- 7- 20	
				762	0- 15- 0	
				763	0- 15- 0	
				768	0- 9- 10	
				769	0- 6- 0	
				770	0- 11- 10	
				772	0- 10- 10	
				773	1- 3- 0	
				784	0- 17- 0	
				783	0- 0- 10	
				697	0- 5- 0	
				788	0- 0- 15	
				789	0- 0- 10	
				788	0- 13- 0	
				790	0- 15- 0	
				791	0- 10- 10	
				793	0- 1- 0	
				691	0- 18- 0	
				692	0- 0- 10	
				795	0- 0- 10	
				796	2- 2- 0	
				1745	0- 13- 0	
				1744	0- 17- 10	
				1743	0- 9- 0	
				800	0- 6- 0	
				1742	0- 0- 5	
				814	0- 9- 0	
				815	0- 5- 0	
				816	0- 12- 0	
				1810	0- 1- 10	
				949	0- 0- 5	
				909	0- 0- 10	
				817	0- 1- 10	
				813	0- 0- 10	
				837	1- 7- 10	
				836	0- 12- 0	
				835	0- 4- 0	
				839	0- 6- 0	
				833	0- 0- 8	
				865	2- 7- 10	
				864	0- 7- 10	
				867	0- 6- 0	
				868	0- 0- 10	
				881	0- 7- 0	
				882	0- 17- 0	
				916	0- 8- 10	
				893	0- 9- 10	
				894	1- 1- 0	
				895	0- 0- 2	
				911	0- 9- 0	
				896	0- 10- 0	
				906	0- 0- 10	
				907	0- 4- 15	
				905	0- 19- 5	
				904	0- 12- 0	
				900	0- 0- 5	
				902	0- 19- 5	
				901	0- 2- 0	
				897	0- 3- 0	
				704	0- 3- 10	
				705	0- 0- 5	
				1805	0- 0- 5	

[स. O-14016 / 362 / 85 /जी. पी.]

S.O. 2583.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58|B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipe Line From Hajira-Bareilly- Jagdish pur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Bigha. Biswa Biswansi	Remark
	2	3	4	5	6	7
Hardoi	Shahabad	Pachhoha	Bharkhani	1803	1-15-0	
				1802	0-13-10	
				1797	0-13-0	
				1796	1-10-0	
				761	0-7-10	
				762	0-15-0	
				763	0-15-0	
				768	0-9-10	
				769	0-6-0	
				770	0-11-10	
				772	0-10-10	
				773	1-3-0	
				784	0-17-0	
				783	0-0-10	
				697	0-5-0	
				787	0-0-15	
				789	0-0-10	
				788	0-130-	
				790	0-15-0	
				791	0-10-10	
				793	0-1-0	
				691	0-18-0	
				692	0-0-10	
				795	0-0-10	

1	2	3	4	5	6	7
हरदोई—(जारी)						
				796	2-2-0	
				1745	0-13-0	
				1744	0-17-10	
				1743	0-9-0	
				800	0-6-0	
				1742	0-0-5	
				814	0-9-0	
				815	0-5-0	
				816	0-12-0	
				1810	0-1-10	
				949	0-0-5	
				909	0-0-10	
				817	0-1-10	
				813	0-0-10	
				837	1-7-10	
				836	0-12-0	
				835	0-4-0	
				839	0-6-0	
				833	0-0-8	
				865	2-7-10	
				864	0-7-10	
				867	0-6-0	
				868	0-0-10	
				881	0-7-0	
				882	0-17-0	
				916	0-8-10	
				893	0-9-10	
				894	1-1-0	
				895	0-0-2	
				911	0-9-0	
				896	0-10-0	
				906	0-0-10	
				907	0-4-15	
				905	0-19-5	
				904	0-12-0	
				900	0-0-5	
				901	0-2-0	
				902	0-19-5	
				897	0-3-0	
				704	0-3-10	
				705	0-0-5	
				1805	0-0-5	

[No. O-14016/362/85-GP]

का. आ. 2584 .—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा बिस्वासी	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
हरदोई	शाहाबाद पछोहा	मामपरा	353	0-1-10	
			354	0-0-5	
			355	0-13-0	
			373	0-11-10	
			372	0-0-5	
			371	0-3-0	
			419	0-6-0	
			418	0-9-0	
			417	0-8-10	
			416	0-6-0	
			420	0-6-10	
			516	0-0-5	
			515	0-5-5	
			514	0-17-0	
			547	0-13-10	
			548	0-18-0	
			549	0-7-5	
			564	0-3-0	
			565	0-3-10	
			566	1-3-10	
			567	0-4-5	
			568	0-9-0	

[सं. O - 14016/361/85-जी. पी]

S.O 2584.—Whereas it appears to the Central Govoernment that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H B.J Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipe Line From Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project.

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Bigha, Biswa Biswansi	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Hardoi	Shaha-bad	Pach-hoha	Manpara	353	0-1-10	
				354	0-0-5	
				355	0-13-0	
				373	0-11-10	
				372	0-0-5	
				371	0-3-0	
				419	0-6-0	
				418	0-9-0	
				417	0-8-10	
				416	0-6-0	
				420	0-6-10	
				516	0-0-5	
				515	0-5-5	
				514	0-17-0	
				547	0-13-10	
				548	0-18-0	
				549	0-7-5	
				564	0-2-0	
				565	0-3-10	
				566	1-3-10	
				567	0-4-5	
				568	0-9-0	

[No. O-14016/361/85-GP]

का. आ. 2585.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट सं.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
शाहजहांपुर	सदर	कांट	रत्नापुर	54	--	04	

[स. O-14016/359/85-जी. पी.]

S.O. 2585.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira-Bariclly-Jagdish Pur Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargana	Villa	No.	Acd.	Dismil	mark
1	2	3	4	5	6	7	
Shahjahan-pur	Sadar	Kant	Ratna-pur	54	—	04	

[No. O-14016/359/85-GP]

का. आ. 2586.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
शाहजहां पुर	सदर	जमोर	खमरिया	98	—	21	
				99	—	06	
				100	—	22	
				101	—	58	
				103	—	15	
				124	—	34	
				125	—	70	
				126	—	07	
				167	—	55	
				182	—	34	
				183	—	06	
				187	—	17	
				188	—	15	
				189	—	14	
				190	—	52	
				191	—	01	
				208	—	03	
				216	—	14	
				217	—	25	
				219	—	03	
				223	—	18	
				224	—	06	
				226	—	21	
				229	—	42	
				230	—	03	
				231	1	56	
				225	—	16	
				118	—	66	
				232	—	24	
				233	—	20	
				234	—	02	
				121	—	01	
				122	—	03	
				288	—	02	

[सं. O-14016/360/85-जी. पी.]

S.O. 2586.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, **Gas Authority of India Ltd** H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipe Line From Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargna	Village	Plot No.	Area Acd.	Area Dismil	Re-mark
1	2	3	4	5	6		7
Shah-jahan-pur	Sadar	Jamour	Kham-ariya	98	—	21	
				99	—	06	
				100	—	22	
				101	—	58	
				103	—	15	
				124	—	34	
				125	—	70	
				126	—	07	
				167	—	55	
				182	—	34	
				183	—	06	
				187	—	17	
				188	—	15	
				189	—	14	
				190	—	52	
				191	—	01	
				208	—	03	
				216	—	14	
				217	—	25	
				219	—	03	
				233	—	18	
				224	—	06	
				226	—	21	
				229	—	42	
				230	—	03	
				231	—	56	
				225	—	16	
				118	—	66	
				232	—	24	
				233	—	20	
				234	—	02	
				121	—	01	
				122	—	03	
				288	—	02	

[No. O-14016/360/85-GP]

का. आ. 2587.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी अलीगंज लखनऊ-226020 य. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो य किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट सं.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल बिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
शाहजहाँ-	सदर	कांट	अलियापुर	2	--	83	
पुर				3	--	30	
				4	--	66	
				5	--	45	
				14	--	95	
				15	--	10	
				16	--	21	
				53	--	15	
				157	--	10	
				158	--	14	
				159	--	48	
				160	--	09	
				170	--	58	
				171	--	02	
				172	--	10	
				173	1	20	
				224	--	38	
				226	--	29	
				227	--	24	
				156	--	05	

[सं. O-14016/356/85-जी. पी.]

S.O. 2587.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargna	Village	Plot No.	Area Acd.	Area Dismil	Re mark
1	2	3	4	5	6		7
Shah-	Sadar	Kat	Aliya-	2	—	83	
jahan-			pur	3	—	30	
pur				4	—	66	
				5	—	45	
				14	—	95	
				15	—	10	
				16	—	21	
				53	—	15	
				157	—	10	
				158	—	14	
				159	—	48	
				160	—	09	
				170	—	58	
				171	—	02	
				172	—	10	
				173	1	20	
				224	—	38	
				226	—	29	
				227	—	24	
				156	—	06	

[No. O-14016/356/85-GP]

का. आ. 2588.—यत. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
शाहजहां-पुर	सदर	कांट	हसरामऊ	56	--	18	
				57	--	15	
				58	—	06	
				59	--	06	
				78	--	65	
				73	--	02	
				75	—	02	
				76	—	03	

[सं. O-14016/357/85-जी. पी.]

S.O. 2588.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aligaj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Gas Pipe Line From Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargna	Village	Plot No.	Area Acd.	Area Dismil.	Re-mark
1	2	3	4	5	6		7
Shah-jahan-pur	Sadar	Kat	Has-ramau	56	—	18	
				57	—	15	
				58	—	06	
				59	—	06	
				78	—	65	
				73	—	02	
				75	—	02	
				76	—	03	

[No O-14016/357/85-GP]

का. आ. 2589.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रयीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू. पी को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6		7
शाहजहां-पुर	सदर	जमौर	धरनीधरम	180	--	15	
				185	--	13	
				186	—	03	
				187	—	11	
				188	--	03	
				190	--	08	
				191	—	12	
				192	—	05	
				195	--	25	
				197	—	02	
				209	--	02	
				212	—	05	
				213	—	15	
				223	--	01	
				224	—	30	

1	2	3	4	5	6	7
				225	—	14
				226	—	30
				229	—	30
				230	—	38
				233	—	30

[सं. O-14016/366/85 जी. पी.]

S.O. 2589.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58/B. Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipe Line Project

District	Tehsil	Pargna	Village	Plot No.	Area Acd.	Area Dismil.	Remark
1	2	3	4	5	6		7
Shahjahanpur	Sadar	Jamour	Dharnidharampur	180	—	15	
				185	—	13	
				186	—	03	
				187	—	11	
				188	—	03	
				190	—	08	
				191	—	12	
				192	—	05	
				195	—	25	
				197	—	02	
				209	—	02	
				212	—	05	
				213	—	15	
				223	—	01	
				224	—	30	
				225	—	14	
				226	—	30	
				229	—	30	
				230	—	38	
				233	—	30	

[No. O-14016/366/85—GP]

का. आ. 2590.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू. पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट सं.	क्षेत्रफल एकड़	क्षेत्रफल डिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	
शाहजहांपुर	सदर	काट	महमदपुर अजमाबाद	249	—	06	

[सं. O-14016/358/85 जी पी]

S.O. 2590.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajra-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. J. Pipeline Project B-58/B. Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

INDEX

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipe Line Project

Disttict	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acd.	Area Dismil	Re-mark
1	2	3	4	5	6		7
Shah-jahan-pur	Sadar	Kant	Mahmad-pur	249	—	06	

[No. O-14016/358/85—GP]

का. आ. 2591.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हजीरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी अलीगंज लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्रामा	गाटा सं.	क्षेत्रफल एकड	क्षेत्रफल बिसमिल	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
शाहजहांपुर	सदर	काट	अख्त्यारपुर बघौरा	2	—	06	
				3	—	06	
				4	—	49	
				18	—	08	
				19	—	10	
				21	—	27	
				966/22	—	43	
				30	—	68	
				36	—	64	
				37	—	08	
				38	—	75	
				42	—	08	
				17	—	75	
				29	—	08	

[सं. O- 14016 / 353 / 85 - जी. पी.]

S.O. 2591.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly to Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now therefore, it exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. H. B. I. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Hazira-Barielly—Jagdishpur pipe line Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired area in (Bigha)	Re-mark
Shah-jahan-pur	Sadar	Kat	Akht-yarpur Bagh-oura	2	06	
				3	06	
				4	49	
				18	08	
				19	10	
				21	27	
				966/22	43	
				30	68	
				36	64	
				37	08	
				38	75	
				42	08	
				17	75	
				29	05	

[No. O-14016/353/85-G ']

का०आ० 2592.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० तारीख 4101/12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	करारा	286	0–28	
				285	0–03	
				284	1–33	
				283	0–26	
				282	0–40	
				281	0–03	
				280	1–55	
				276	0–07	
				274	0–74	
				271	0–08	
				199	0–63	
				197	0–03	
				196	0–50	
				195	1–38	
				182	0–60	
				183	0–80	
				180	0–03	
				179	0–01	
				176	0–58	
				177	0–67	
				178	1–28	
				80	0–03	
				64	0–01	
				63	0–13	
				62	0–30	
				61	0–20	
				59	1–25	
				53	0–60	
				53	0–06	
				52	2–30	
				25	0–30	
				24	0–06	
				13	0–64	
				15	0–12	
				14	0–95	
				297	0–10	
				60	0–01	

[सं. O–14016 / 3 / 84–जी. पी.]

S.O. 2592.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4101 dated 12-1184 under sub-section (1) of Sectin 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) A t, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby, declare, that the right of user in hte said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Romark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Karara	286	0–28	
				285	0–03	
				284	1–33	
				283	0–26	
				282	0–40	
				281	0–03	
				280	1–55	
				276	0–07	
				274	0–79	
				271	0–08	
				199	0–63	
				197	0–03	
				196	0–50	
				195	1–38	
				182	0–60	
				183	0–80	
				180	0–03	

1	2	3	4	5	6	7
				179	0–01	
				176	0–58	
				177	0–67	
				178	1–28	
				80	0–03	
				64	0–01	
				63	0–13	
				62	0–30	
				61	0–20	
				59	1–25	
				58	0–60	
				53	0–06	
				52	2–30	
				25	0–30	
				24	0–06	
				13	0–64	
				15	0–12	
				14	0–95	
				279	0–01	
				60	0–01	

[No. O-14016/3/84 GP]

का०आ० 2593.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० तारीख 4101/12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा--बरेली--जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट नं०	लिया गया रकबा	विवरण
झांसी	मोठ	मोठ	पिपरा	32/2	0–48	
				33	0–07	
				34/1	1–55	
				34/2	0–36	
				35	0–04	
				39	1–66	
				44	0–06	
				45	0–78	
				46	0–45	
				48	0–02	
				49	0–46	
				50	0–67	

[सं० O 14016/3/84--ग०प०]

S.O. 2593.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4101 dated 12-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Gram	Plot No.	Area (In Acre)	Remark
Jhansi	Moth	Moth	Pipara	32/2	0–48	
				33	0–07	
				34/1	1–55	
				34/2	0–36	
				35	0–04	
				39	1–66	
				44	0–06	
				45	0–78	
				46	0–45	
				48	0–02	
				49	0–46	
				50	0–67	

No. O—14016/3/84-GP/

का०आ० 2594—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०स० तारीख 4101/12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	बेलमा	120	0-05	
				121	0-70	
				122	0-01	
				123	0-02	
				124	1-38	
				132	0-90	
				133	0-08	
				134	0-18	
				135	0-40	
				436	0-15	
				437	0-05	
				438	1-14	
				439	0-66	
				440	0-02	
				450	0-53	
				451	0-06	
				154	2-32	
				455	0-06	
				456	0-24	
				723	0-02	
				724	0-08	
				725	0-35	
				726	0-06	
				727	0-15	
				750	0-27	
				794	0-80	
				795	0-88	
				796	0-01	
				799	1-52	
				800	0-45	
				801	0-06	
				822	0-36	
				838	0-05	
				[illegible]	0-02	
				138		
				850	0-29	
				851	0-12	
				852	0-08	
				856	0-05	
				858	0-10	
				857	0-04	
				940		
				858	0-03	
				866	0-13	
				867	1-12	
				866	0-02	
				944		
				868	0-32	
				880	0-66	
				872	0-22	
				873	0-02	
				875	1-00	

[सं० O-14016/3/84-जीपी०]

S.O. 2594.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification hereby acquired for laying the pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Belma	120	0-05	
				121	0-70	
				122	0-01	
				123	0-02	
				124	1-38	
				132	0-90	
				133	0-08	
				134	0-18	
				135	0-40	
				396	0-15	
				437	0-05	
				438	1-44	
				439	0-86	
				440	0-02	
				450	0-53	
				451	0-06	
				454	2-32	
				455	0-06	
				456	0-24	
				723	0-02	
				724	0-08	
				725	0-35	
				726	0-06	
				727	0-15	
				750	0-27	
				794	0-80	
				795	0-88	
				796	0-01	
				799	1-52	
				800	0-45	
				801	0-06	
				822	0-36	
				838	0-08	
				850	0-02	
				938	0-08	
				850	0-29	
				851	0-12	
				852	0-08	
				856	0-05	
				857	0-16	
				940	0-01	
				858	0-03	
				866	0-17	
				867	1-12	
				866	—	
				944	0-02	
				868	0-32	
				870	0-66	
				872	0-22	
				873	0-02	
				875	1-00	

[No. O—14016/3/84-GP]

का०आ० 2595.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० तारीख 12-11-84/1401 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
झांसी	मोठ	मोठ	लहावरा	622	2-16	
				625	0-04	
				627	0-78	
				634	0-22	
				637	0-08	
				656	1-05	
				662	0-03	
				658	0-04	
				661	0-02	
				659	1-24	
				660	1-60	
				686	0-01	
				687	2-28	
				695	0-04	
				696	0-48	
				694	1-07	

1	2	3	4	5	6	7
				698	0-10	
				685	0-05	
				688	0-08	
				693	0-01	
				652	0-19	

[F. O—14016/3/84—जी पी]

S.O. 2595.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Sections of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has, under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the secton 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquire for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe Line from Hajira Bareilly Jagdishpur Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Larawara	622	2-16	
				625	0-04	
				627	0-78	
				634	0-22	
				637	0-08	
				656	1-05	
				667	0-05	
				658	0-04	
				661	0-07	
				659	1-24	
				660	1-60	
				686	0-01	
				687	2-28	
				695	0-04	
				696	0-48	
				694	1-07	
				698	0-10	
				685	9-05	
				688	0-08	
				693	0-01	
				652	0-19	

[No. O—14016/3/84-GP]

का०आ० 2596-यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० तारीख 4101/12/11/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत. उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	चकभोर बेलमा	166	0-51	
				167	0-05	
				165	2-49	
				158	1-24	
				159	0-35	
				153	0-44	
				181	0-54	
				177	1-14	
				178	0-59	
				183 (ए और बी)	0-01/2	
				160	0-01 1/2	
				161	0-01 1/2	
				168	0-03	
				169	0-03	
				175	0-04 1/2	
				176	0-09	
				180	0-1 1/2	

[सं. O—14016/3/84—जी पी]

S.O. 2596.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd, free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe Line From Hajira Bareilly Jagdishpur Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Rrmark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Chaktor Belma	166	0–54	
				167	0–05	
				165	2–49	
				158	1–24	
				159	0–35	
				153	0–44	
				181	0–54	
				177	1–14	
				178	0–59	
				183 (A&B)	0-0–12	
				160	0–01-1/2	
				161	0–01-1/2	
				168	0–03	
				169	0–03	
				175	0–04-1/2	
				176	0–09	
				180	0–1-1/2	

[No. O—14016/3/84-GP]

का०आ० 2597—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० तारीख 4101/12/11/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	मई	201/2	0-11	
				201/3	0-35	
				201/8	0-50	
				201/9	0-27	
				209/2	0-54	
				210	0-04	
				213	0-27	
				214	1-08	
				220/3	0-16	
				220/4	1-44	
				221	0-04	
				224	0-51	
				225/3	0-48	
				226	0-07	
				240/3	2-28	
				240/4	1-90	
				227	0-11	
				241	0-60	
				231	0-09	
				207	0-76	

[सं O—14016/3/84—जी पी]

S.O. 2597.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said, Act the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of the power conferred by sub section (4) of that section the Central Government directs that right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Soi	201/2	0-11	
				201/3	0-35	
				201/8	0-50	
				201/9	0-27	
				209/2	0-54	
				210	0-04	
				213	0-27	
				214	1-08	
				220/3	0-16	
				220/4	1-44	
				221	0-04	
				224	0-51	
				225/3	0-48	
				226	0-07	
				240/3	2-28	
				240/4	1-90	
				227	0-11	
				241	0-60	
				234	0-09	
				207	0-76	

[No. O—14016/3/84-GP]

का०आ० 2598—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का०आ० स० त रीख 4101/12/11/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिदिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना स सलग्न अनुसूची मे विनिदिष्ट भूमियो मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गेस प्राधिकरण लि० मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झासी	मोठ	मोठ	चिरगवा खुर्द	16	0-75	
				17	0-02	
				18	1-75	
				20	0-45	
				21	0-02	
				23	0-52	
				24	0-04	
				25	0-85	
				28	0-01	
				30	0-02	
				244	0-10	
				245	1-20	
				247	0-02	
				249	0-80	
				250	1-25	
				252	0-50	
				253	0-03	
				254	0-07	
				255	0-03	
				258	1-20	
				275	0-03	
				277	0-90	
				284	0-02	
				285	0-90	
				289	0-75	
				290	1-52	
				291	0-20	
				295	0-02	
				296	0-08	
				297	1-30	

1	2	3	4	5	6	7
				298	0-20	
				340	1-02	
				345	0-90	
				348	0-02	
				350	0-05	
				351	0-88	
				352	0-03	
				353	1-03	

[सं. O—14016/3/84—जी पी]

S.O. 2598.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declarted its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, declared to acquired the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tahsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-marks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Chir-	16	0-75	
			gaon	17	0-02	
			Khurd	18	1-75	
				20	0-45	
				23	0-52	
				24	0-04	
				25	0-85	
				28	0-01	
				30	0-02	
				244	0-10	
				245	1-20	
				247	0-02	
				249	0-80	
				250	1-25	
				252	0-50	
				253	0-03	
				254	0-07	
				255	0-03	
				258	1-20	
				275	0-03	
				277	0-90	
				284	0-02	
				285	0-90	
				289	0-75	
				290	1-52	
				291	0-20	
				295	0-02	
				296	0-08	
				297	1-10	
				298	0-20	
				240	1-02	
				345	0-90	
				348	0-02	
				350	0-05	
				351	0-88	
				352	0-03	
				353	1-02	

[No. O-14016/3/84-GP]

का०आ० 2599.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० तारीख 4102/1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम		लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय-बरेली	महराज-गंज	इन्हौना	जगराज पुर	294	0–11–8	
				287 एम	0–3–12	
				292 एम	0–1–2	
				288 एम	0–18–0	
				285 एम	0–2–14	
				284 एम	0–7–16	
				281 एम	0–13–4	
				183 एम	0–7–4	
				176 एम	0–0–4	
				184 एम	0–2–2	
				175 एम	0–1–16	
				174 एम	0–3–12	
				173 एम	0–3–0	
				172 एम	0–0–6	
				170 एम	0–13–0	
				188 एम	0–4–0	
				160 एम	0–14–4	
				158 एम	0–10–16	
				155 एम	0–2–8	
				154 एम	0–3–12	
				152 एम	0–3–16	
				150 एम	0–4–0	
				151 एम	0–6–0	
				131 एम	0–6–0	
				130 एम	0–19–15	
				49 एम	0–0–1	
				129 एम	0–2–8	
				62 8 एम	0–12–12	
				164	0–0–14	
				62/1 एम	0–2–10	
				62/2 एम	0–10–10	
				62/4 एम	0–1–12	
				59 एम	0–3–0	
				60 एम	0–3–0	
				61 एम	0–4–15	
				70 एम	0–5–6	
				71 एम	0–5–0	
				46 एम	0–18–0	
				41 एम	0–19–8	
				40 एम	0–4–0	
				38 एम	0–10–0	
				37 एम	0–9–0	
				22 एम	0–0–2	
				24 एम	0–1–10	
				36 एम	0–4–0	
				25 एम	0–8–0	
				26 एम	0–3–8	
				27 एम	0–0–15	
				13 एम	0–3–5	
				14 एम	0–0–1	
				11 एम	1–0–0	
				10 एम	0–3–0	
				7 एम	0–2–16	
				57 एम	0–0–10	
				8 एम	0–15–0	
				19 एम	0–0–10	

[सं. O—14016/4/84—जी पी]

S.O. 2599.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further in exercise of power conferred by sub-sec-considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project,

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Bareilly	Maharaj ganj	Enhona	Jugrag-pur	294	0–11–8	
				287m.	0–3–12	
				-92m.	0–1–2	
				288m.	0–18–0	
				285m.	0–2–14	
				284m.	0–7–16	
				281m.	0–13–4	
				183m.	0–7–4	
				176m.	0–0–4	
				184m.	0–2–2	
				175m.	0–1–16	
				174m.	0–3–12	
				173m.	0–3–0	
				172m.	0–0–6	
				170m.	0–13–0	
				188m.	0–4–0	
				160m.	0 14–4	
				158m.	0–10–16	
				155m.	0–2–8	
				154m.	0–3–12	
				152m.	0–3–16	
				150m.	0–4–0	
				151m.	0–6–0	

1	2	3	4	5	6	7
				131m	0 6-0	
				130m	0–19–15	
				49m.	0–0–1	
				129m.	0–2–8	
				62/8m.	0–12–12	
				164	0–0–14	
				62/1m.	0–2–10	
				62/2m	0–10–10	
				62/4m	0–1–12	
				59m.	0–3–0	
				60m	0–3–0	
				61m.	0–4–15	
				70m.	0–5–6	
				71m.	0–5–0	
				46m.	0–18–0	
				41m.	0–19–0	
				40m.	0–4–0	
				38m.	1–10–0	
				37m.	0–9–0	
				22m.	0–0–2	
				24m.	0–1–10	
				36m.	0–4–0	
				25m.	0–8–0	
				26m.	0–3–8	
				27m.	0–0–15	
				13m.	0–3–5	
				14m.	0–0–1	
				11m.	1–0–0	
				10m	0–3–0	
				7m.	0–2–16	
				57m.	0–0–10	
				8m.	0–15–0	
				19m.	0–0–10	

[No. O-14016/4/84-GP]

का०आ० 2600.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं तारीख 4102/1/12/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय बरेली	महराज गंज	मऊरौला	कोटवा मोहम्मदा बाद	630 एम	0-10-0	
				631 एम	0-13-15	
				632 एम	0-9-12	
				633 एम	0-17-0	
				63 एम	0-9-0	
				635 एम	1-1-9	
				637 एम	0-0-3	
				638 एम	1-6-13	
				1083 एम	0-5-12	
				1684 एम	1-12-0	
				1096 एम	0-2-10	
				1089 एम	0-5-10	
				1115 एम	0-1-15	
				1118 एम	0-12-12	
				1119 एम	1-2-1	
				1123 एम	0-12-7	
				1126 एम	0-5-0	
				1159 एम	0-5-2	
				1160 एम	1-2-2	
				1162 एम	0-1-17	
				1163 एम	0-1-0	
				1199 एम	0-4-19	
				1200 एम	0-16-14	
				1201 एम	0-1-8	
				1202 एम	0-0-2	
				1245 एम	1-1-13	
				1251 एम	1-17-10	
				1255एम	0-11-2	
				1257 एम	0-16-16	
				1264 एम	1-14-6	
				1120 एम	0-0-12	
				1121 एम	0-2-8	
				1124 एम	0-2-0	
				1125 एम	0-1-8	
				1161 एम	0-2-2	
				1163 एम	0-0-16	
				1246 एम	0-2-2	
				1256 एम	0-15-15	

[सं O—14016/4/84—जी पी]

S.O. 2600.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4102 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declares its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	–	3		5	6	7
Rai Barielly	Maharaj ganj	Samrata	Kotwa-Moh-mdabad	630m.	0–10–0	
				631m.	0–13–15	
				632m.	0–9–12	
				633m.	0–17–0	
				634m.	0–9–0	
				635m.	1–1–9	
				637m.	0–0–3	
				638m.	1–6–13	
				1083m.	0–5–12	
				1084m.	1–12–0	
				1086m.	0–2–10	
				1089m.	0–5–10	
				1115m.	0–1–15	
				1118m.	0–12–12	
				1119m.	1–2–4	
				1123m.	0–12–7	
				1126m.	0–5–0	
				1159m.	0–5–2	
				1160m.	1–2–2	
				1162m.	0–1–17	
				1163m.	0–1–0	
				1199m.	0–4–19	
				1200m.	0–16–14	
				1201m.	0–1–8	
				1202m.	0–0–2	
				1245m.	1–1–13	
				1251m.	1–17–10	
				1255m.	0–11–2	
				1257m.	0–16–16	
				1264m.	1–14–6	
				1120m	0–0–12	
				1121m.	0–2–8	
				1124m.	0–2–0	
				1125m.	0–1–8	
				1161m	0–2–2	
				1163m.	0–0–16	
				1246m.	0–2–2	
				1256m.	0–15–15	

[No. O-14016/4/84-GP]

का०आ० 2600.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 4102 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना म संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महराजगंज	इन्हौना	फतेहपुर	111	0–0–5	
				154	0–1–0	
				155	0–9–0	
				156	1–11–0	
				157	0–1–0	
				158	0–0–3	
				170	0–0–15	
				171	0–1–15	
				172	0–6–0	
				173	0–0–15	
				174	0–5–0	
				175	0–2–0	
				176	0–3–8	
				177	1–17–0	
				179	0–7–0	
				233	0–1–0	

1	2	3	4	5	6	7
				234	0–1–5	
				235	1–1–5	
				236	1–0–0	
				287	0–5–0	
				238	0–1–10	
				242	0–1–10	
				244	0–0–5	
				476	0–0–10	
				478	1–10–0	
				485	0–18–0	
				487	ध–10–0	
				486	0–3–0	
				484	0–1–5	
				488	0–14–0	
				489	0–0–1	
				491	0–2–15	
				493	0–1–10	
				636	0–0–5	
				637	0–7–0	
				639	1–0–0	
				678	1–2–0	
				670	0–19–0	
				671	0–2–10	
				672	0–4–5	
				682	0–7–0	
				684	0–2–0	
				681	0–6–0	
				640	0–0–10	

[सं. O—14016/4/84—जी पां]

S.O. 2601.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4102 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Barielly	Maharajganj	Enhona	Fatehpur	111	0–0–5	
				154	0–1–0	
				155	0–9–0	
				156	1–11–0	
				157	0–12–0	
				158	0–0–3	
				170	0–0–15	
				171	0–1–15	
				172	0–6–0	
				173	0–0–15	
				174	0–5–0	
				175	0–2–0	
				176	0–3–8	
				177	1–17–0	
				179	0–7–0	
				233	0–1–0	
				234	0–1–15	
				235	1–1–0	
				236	1–0–0	
				287	0–5–0	
				238	0–1–10	
				242	0–1–10	
				244	0–0–5	
				476	0–0–10	
				478	1–10–0	
				485	0–18–0	
				487	0–10–0	
				486	0–3–0	
				484	0–1–5	
				488	0–14–0	
				489	0–0–1	
				491	0–2–15	
				493	0–1–10	
				636	0–0–5	
				637	0–7–0	
				639	1–0–0	
				678	1–2–0	
				670	0–19–0	
				671	0–2–10	
				672	0–4–5	
				682	0–7–0	
				684	0–2–0	
				681	0–6–0	
				640	0–0–10	

[No. O-14016/4/84-G.P.]

का०आ० 2602.— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०सं० 4102 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम		लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय बरेली	महराज-गंज	इन्हौना	रतयलिया मझार	211	0-6-0	
				212	0-6-0	
				213	0-1-10	
				228	0-4-0	
				229	1-10-0	
				230	0-1-4	
				233	0-3-0	
				234	1-5-0	
				235	0-2-0	
				236	0-2-0	
				237	0-1-15	
				238	0-7-0	
				239	0-0-5	
				888	0-1-0	
				247	0-1-0	
				254	0-0-15	
				258	0-0-2	
				259	0-11-0	
				260	1-2-0	
				389	0-7-0	
				800	0-1-15	
				676	0-5-10	
				801	0-12-0	
				802	0-5-0	
				807	0-1-0	
				808	0-9-0	
				809	0-4-0	
				819	0-5-0	
				820	0-10-0	
				827	0-0-3	
				828	0-0-2	
				829	0-0-13	
				830	0-3-0	
				831	0-9-0	
				832	0-2-0	
				833	0-7-0	
				836	0-0-4	
				835	0-0-1	
				840	0-8-0	
				841	0-0-2	
				844	0-3-0	
				848	0-2-10	
				846	0-7-0	
				850	0-5-0	
				851	0-8-0	
				867	1-19-10	
				890	0-1-0	
				891	0-15-0	
				892	0-0-15	
				893	0-6-0	
				915	0-4-0	
				1146	0-2-0	
				1147	0-2-0	
				1148	0-2-18	
				1149	0-1-0	
				1150	0-0-15	
				1151	1-18-10	
				1157	0-6-10	
				1158	0-11-0	
				1159	0-0-1	
				1160	0-15-0	
				1161	0-0-15	
				1162	0-3-0	
				1163	0-0-10	
				1183	0-1-15	
				1193	0-5-0	
				1194	0-8-0	
				1201	0-4-0	
				1202	0-0-9	
				1203	0-2-8	
				1209	0-10-0	
				1210	0-1-0	
				1211	0-4-10	
				1212	0-0-2	
				1272	0-5-0	
				1273	0-11-0	
				1278	0-5-0	
				1279	0-10-0	
				1280	0-10-0	
				1281	0-5-0	

[सं० O-11016/4/84—जी पी]

S.O. 2602.—WWhereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4102 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Barielly Jagdishxur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Barielly	Maharajganj	Enhona	Ratwalya Majhnar	211	0-6-0	
				212	0-6-0	
				213	0-1-10	
				228	0-4-0	
				229	1-10-0	
				230	0-1-4	
				233	0-3-0	
				234	1-5-0	
				235	0-2-0	
				236	0-2-0	
				237	0-1-15	
				238	0-7-0	
				239	0-0-5	
				888	0-1-0	
				247	0-1-0	
				254	0-0-15	
				258	0-0-2	
				259	0-11-0	
				260	1-2-0	
				389	0-7-0	
				800	0-1-15	
				676	0-5-10	
				801	0-12-0	
				802	0-5-0	
				807	0-4-0	
				808	0-9-0	
				809	0-4-0	
				819	0-5-0	
				820	0-10-0	
				827	0-0-3	
				828	0-0-2	
				829	0-0-13	
				830	0-3-0	
				831	0-9-0	
				832	0-2-0	
				833	0-7-0	
				836	0-0-4	
				838	0-0-1	
				840	0-8-0	
				841	0-0-2	
				844	0 3-0	
				848	0-2-10	
				846	0-7-0	
				850	0-5-0	
				851	0-8-0	
				867	1-19-10	
				890	0-1-0	
				891	0-15-0	
				892	0-0-15	
				893	0-6-0	
				915	0-4-0	
				1146	0-2-0	
				1147	0-2-0	
				1148	0-2-18	
				1149	0-1-0	
				1150	0-0-15	
				1151	1-18-10	
				1157	0-6-10	
				1158	0-11-0	
				1159	0-0-1	
				1160	0-15-0	
				1161	0-0-15	
				1162	0-3-0	
				1163	0-0-10	
				1183	0-1-15	
				1193	0-5-0	
				1194	0-8-0	
				1201	0-4-0	
				1202	0-0-9	
				1203	0-2-8	
				1209	0-10-0	
				1210	0-1-0	
				1211	0-4-10	
				1212	0-0-2	
				1272	0-5-0	
				1273	0-11-0	
				1278	0-5-0	
				1279	0-10-0	
				1280	0-10-0	
				1281	0-5-0	

[No O-14016/4/84-GP]

का.आ. 2603:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4102 तारीख 1/12/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
राय-बरेली	महाराज-गंज	इन्होना	दान्दू-पुर	417 एम	1-15-0	
				420 एम	0-4-0	
				416 एम	0-15-10	
				415 एम	0-4-18	
				414 एम	0-10-16	
				413 एम	0-7-0	
				412 एम	0-6-10	
				192 एम	0-1-10	
				213 एम	0-5-0	
				410 एम	0-0-10	
				408 एम	0-4-5	
				409 एम	0-1-0	
				214 एम	0-7-0	
				407 एम	0-0-2	
				215 एम	0-1-12	
				216 एम	0-3-15	
				217 एम	0-16-7	
				405 एम	0-0-2	
				21[illegible] एम	0-[illegible]-5	
				3[illegible] एम	0-17-0	
				3[illegible]	0-1-0	
				382	0-14-6	
				3[illegible]6	0-2-10	
				380	0-3-0	
				3[illegible]	0-1-0	
				2[illegible]	0-12-16	
				239	0-1-5	
				240	0-5-0	
				265 एम	0-15-0	
				263 एम	0-3-0	
				264 एम	0-2-5	

1	2	3	4	5	6	7
				258 एम	1-0-6	
				256 एम	0-1-10	
				257 एम	0-4-8	
				259 एम	0-1-10	
				277 एम	0-1-10	
				255 एम	0-3-8	
				254 एम	0-0-1	
				279 एम	0-1-10	
				278 एम	0-1-0	
				282 एम	0-0-2	
				283 एम	0-4-2	
				284 एम	0-1-8	
				285 एम	0-3-15	
				287 एम	0-1-0	
				292 एम	0-3-4	
				293 एम	0-8-0	
				294 एम	0-10-0	
				295	0-1-10	
				300 एम	0-4-0	
				302 एम	0-3-0	
				303 एम	0-10-5	

[सं. O—14016/4/84—जी पी]

S.O. 2603.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4102 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline:

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira Bariolly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired	Re-mark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Barielly	Maharaj-ganj	Enhona	Dandu-pur	417m.	1-15-0	
				420m.	0-4-0	
				416m.	0-15-10	
				415m.	0-4-18	
				414m.	0-10-16	

1	2	3	4	5	6	7
				413m.	0-7-0	
				412m.	0-6-10	
				192m.	0-1-10	
				313m.	0-5-0	
				410m.	0-0-10	
				408m.	0-4-5	
				409m.	0-4-0	
				214m.	0-7-0	
				407m.	0-0-2	
				215m.	0-1-12	
				216m.	0-3-15	
				217m.	0-16-7	
				405m.	0-0-2	
				218m.	0-2-5	
				383m.	0-17-0	
				384	0-1-0	
				382	0-14-6	
				386	0-2-16	
				380	0-3-0	
				381	0-1-0	
				238	0-12-16	
				239	0-1-5	
				240	0-5-0	
				265m	0-15-0	
				263m	0-3-0	
				264m	0-2-5	
				258m.	1-0-6	
				256m.	0-1-10	
				257m.	0-4-8	
				259m	0-1-10	
				277m	0-1-10	
				255m.	0-3-8	
				254m.	0-0-1	
				279m	0-1-10	
				278m.	0-1-0	
				282m.	0-0-2	
				283m.	0-4-2	
				284m.	0-1-8	
				285m	0-3-15	
				287m.	0-1-0	
				292m.	0-3-4	
				293m.	0-8-0	
				294m	0-10-0	
				295	0-1-10	
				300m.	0-4-0	
				302m	0-3-0	
				303m.	0-10-5	

[No. O-14016/4/84-GP]

का. आ. 2604.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4102 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
राय-बरेली	महराज-गंज	सेमरौता	खेमरवा	375 एम	0-0-3	
				377 एम	0-13-8	
				378 एम	1-13-16	
				379 एम	0-1-4	
				403 एम	0-6-8	
				404 एम	0-7-2	
				405 एम	0-9-12	
				469 एम	1-16-14	
				481 एम	1-5-1	
				487 एम	0-3-12	
				499 एम	0-7-14	
				501 एम	0-6-10	
				502 एम	0-7-12	
				503 एम	0-1-4	
				506 एम	0-19-4	
				525 एम	0-0-1	
				526 एम	1-7-10	
				527 एम	0-16-18	
				528 एम	0-0-12	
				652 एम	1-0-17	
				654 एम	0-3-3	
				673 एम	1-5-6	
				679 एम	0-8-8	
				680 एम	0-13-1	
				681 एम	0-12-0	
				682 एम	0-1-16	
				683 एम	1-3-3	
				685 एम	0-1-4	
				779 एम	0-2-8	
				781 एम	0-9-0	

1	2	3	4	5	6	7
				782 एम	0-15-18	
				781 एम	0-6-6	
				858 एम	2-1-8	
				376 एम	0-0-1	
				486 एम	0-1-4	
				629 एम	0-1-4	
				488 एम	0-1-13	
				653 एम	0-3-0	
				674 एम	0-2-0	
				780 एम	0-1-10	
				848 एम	0-0-5	
				859 एम	0-7-1	
				860 एम	0-6-3	
				861 एम	0-9-12	
				862 एम	0-6-18	
				863 एम	0-10-16	
				864 एम	0-9-12	
				883 एम	0-10-10	
				469 एम	0-0-18	
				957		
				530 एम	0-0-6	

[स O—14016/4/84—जी पी]

S.O. 2604.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4102 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Barielly	Maharajgang	Samrota	Khekharva	375m.	0-0-3	
				377m.	0-14-8	
				378m.	0-13-16	
				379m.	0-1-4	
				403m.	0-6-8	
				404m.	0-7-2	
				405m.	0-9-12	
				469m.	1-15-14	
				481m.	1-5-4	
				487m.	0-3-12	
				499m	0-7-14	
				501m.	0-6-10	
				502m.	0-7-12	
				503m	0-1-4	
				506m.	0-19-4	
				525m.	0-0-1	
				526m.	1-7-10	
				527m.	0-16-18	
				528m.	0-0-12	
				652m.	1-0-17	
				654m.	0-3-3	
				675m	1-5-6	
				679m	0-8-8	
				680m.	0-13-4	
				681m.	0-12-0	
				682m.	0-1-16	
				683m.	1-3-8	
				685m.	0-1-4	
				779m.	0-2-8	
				781m.	0-9-0	
				782m.	0-15-18	
				784m	0-6-6	
				858m.	2-1-8	
				376m.	0-0-1	
				486m	0-1-4	
				629m.	0-1-4	
				488m.	0-1-13	
				653m.	0-3-0	
				674m.	0-2-0	
				780m.	0-1-10	
				848m.	0-0-5	
				859m.	0-7-4	
				860m.	0-6-3	
				861m.	0-9-12	
				862m.	0-6-18	
				863m	0-10-16	
				864m.	0-9-12	
				883m.	0-10-10	
				469m.	0-0-18	
				957		
				530m.	0-0-6	

[No. O-14016/4/84-GP]

का. आ. 2605.—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 4102 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
राय-बरेली	महराज-गंज	इन्हौना	जिया-पुर	296एम	0-1-0	
				297एम	0-10-10	
				299एम	0-3-10	
				381एम	0-0-2	
				382एम	0-9-0	
				383एम	0-11-10	
				384एम	0-4-5	
				385एम	0-16-0	
				386एम	0-6-0	
				394एम	0-9-10	
				395एम	0-4-5	
				396एम	0-8-10	
				397एम	0-6-10	
				398एम	0-12-10	
				399एम	0-3-0	
				400एम	0-0-2	
				405एम	0-1-0	
				411एम	0-8-0	
				412एम	0-12-10	
				418एम	0-1-10	
				419एम	0-0-4	
				420एम	0-6-6	
				421एम	0-0-5	
				422एम	0-4-10	
				423एम	0-3-5	
				424एम	0-3-17	
				425एम	0-0-5	
				432एम	0-6-0	
				433एम	0-2-11	
				434एम	0-0-10	
				436एम	0-15-0	
				437एम	0-0-18	
				439एम	0-9-7	
				438एम	0-10-0	
				443एम	0-3-10	
				416एम	0-0-15	
				417एम	0-11-10	
				410एम	0-4-0	
				293एम	0-0-1	

[सं. O-14016/4/84-जी पी.]

S.O. 2605.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4102 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Rai Barielly	Maharaj-gang	Enhona	Jiyapur	296m.	0-1-0	
				297m.	0-10-10	
				299m.	0-3-10	
				381m.	0-0-2	
				382m.	0-9-0	
				383m.	0-11-10	
				384m.	0-4-5	
				385m.	0-16-0	
				386m.	0-6-0	
				394m.	0-9-10	
				395m.	0-4-5	
				396m	0-8-10	
				397m	0-6-10	
				398m	0-12-10	
				399m	0-3-0	
				400m.	0-0-2	
				405m	0-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				411m	0-8-0	
				412m	0-12-10	
				418m	0-1-10	
				419m	0-0-4	
				420m	0-6-6	
				421m	0-0-5	
				422m	0-4-10	
				423m	0-3-5	
				424m	0-3-17	
				425m	0-0-5	
				432m	0-6-0	
				433m	0-2-11	
				434m	0-0-10	
				436m	0-15-0	
				437m	0-0-18	
				439m	0-9-7	
				438m	0-10-0	
				443m	0-3-10	
				446m	0-0 15	
				447m	0-11-10	
				410m	0-4-0	
				293m	0-0 1	

[No O-14016/4/84 GP]

का आ 2606—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मत्रालय की अधिसूचना का आ स 4101 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमिया के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनो को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार का रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमिया मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि मे सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	माठ	माठ	पुलिया	132	1-92	
				133	0-06	
				130	0-02	
				123	0 16	
				124	0-02	
				125	0-01	
				126	1-14	
				129	0-03	
				127	0-01	
				128	1-31	
				149	0-02	
				203	0-12	
				202	0 49	
				201	0-0	
				200	0-02	
				157	1-00	
				156/2	0-10	
				159	0-05	
				158	0 32	
				160	1-25	
				161	0 02	
				162	0-2	
				163	0-39	
				71/3	0-18	
				59	0 01	
				57	0-04	
				55	0-51	
				59	1-40	
				49	0-01	
				18	0-0[illegible]	
				17	0-48	
				1[illegible]	0-84	
				[illegible]3	0-02	
				64	0-06	
				बी पथ	12-72	
				247	0-02	
				243	0-16	
				[illegible]19	0-06	
				[illegible]	0-[illegible]7	
				[illegible]31	0-45	
				27[illegible]	0-49	
				2[illegible]3	0-06	
				[illegible]01	0 1[illegible]	
				[illegible]00	0-23	
				[illegible]89	0-63	
				29[illegible]	0-02	
				[illegible]4	0-02	
				[illegible]96	0-0[illegible]	
				29[illegible]	0-42	

1	2	3	4	5	6	7
				276	0–02	
				275	0–86	
				371	0–12	
				387	0–02	
				388	0–06	
				393	0–29	
				373	0–64	
				375	0–02	
				374	1–27	
				376	0–02	
				377	0–02	
				378	0–04	
				292	0–13	
				274	0–01	
			योग :—		19–59	

[स. O-14016/3/84-जी पी]

S.O. 2606.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4102 dated 12-11-84 sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in India) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bariclly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Puhya	132	1-92	
				133	0–06	
				130	0–02	
				123	0–46	
				124	0-02	
				125	0 01	
				126	0–14	
				129	0–03	
				127	0–01	
				128	1–34	
				149	0–02	
				203	0–12	
				202	0–49	
				201	0–05	
				200	0–02	
				157	1–00	
				156/2	0–10	
				159	0–05	
				158	0–32	
				160	1–25	
				161	0–02	
				162	0–28	
				163	0–39	
				71/5	0–18	
				56	0–01	
				57	0–04	
				55	0–54	
				59	1–40	
				49	0–01	
				48	0–02	
				47	0–48	
				46	0–84	
				28	0–02	
				64	0–06	
				PF	12–72	
				247	0–02	
				248	0–16	
				249	0–06	
				283	0–37	
				281	0–45	
				279	0–39	
				288	0–06	
				291	0–42	
				290	0–23	
				289	0–68	
				293	0–02	
				294	0–02	
				296	0 05	
				295	0–42	
				276	0–02	
				275	0–86	
				371	0–12	
				387	0–02	
				388	0–06	
				393	0–29	
				373	0–64	
				375	0 02	
				374	1–27	
				376	0–02	
				377	0–02	
				370	0–04	
				292	0–13	
				274	0–01	
				Total	19–59	

[No. O-14016/3/84-GP]

का. आ. 2607.---यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 का (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 304 तारीख 26-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच० बी० जे० गैस पाईप लाइन प्राजेक्ट

ग्राम रमडी तहसील चम्बोरा जिला मना राज्य (म. प्र.)

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1	177/1/4	0 178
2	177/1/5	0 178
3	183	0 293
4	216/1/2	0 084
5	203	0 554
6	202	0 136
7	201	0 073
8	206	0 042
9	154	0 575
10	155	0 366
11	166/1/3	0 272
12	109	0 167
13	108	0 010
14	104	0.157
15	103	0 115
16	89/467	0.303
17	55	0 167
18	57	0 397
19	58	0.063
20	59	0.240
21	28	0.240
22	32/1	0.010
23	30	0 732
24	20/3	0 784
25	216/1/3	0 084
26	366	0.125
27	368	0 331
28	370	0 188
29	369/1	0.031
30	17	0 304
31	15/5	0 031
32	88	0.031
33	18	0 031
	योग कुल क्षेत्रफल --	7 294

[सं० O-14016/538/84-जी. पी.]

S.O 2607.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 304 dated 26-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication in this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Randi, Tehsil : Chachora Distt. : Guna, (M.P)

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	177/1/4	0.178
2.	177/1/5	0.178
3.	183	0.293
4.	216/1/2	0.084
5.	203	0.554
6.	202	0.136
7.	201	0.073
8.	206	0.042
9.	154	0.575
10.	155	0.366
11.	166/1/3	0.272
12.	109	0.167
13.	108	0.010
14.	104	0.157
15.	103	0.115
16.	89/467	0.303
17.	55	0.167
18.	57	0.397
19.	58	0.063
20.	59	0.240
21.	28	0.240
22	32/1	0.010
23.	30	0.732
24.	20/3	0.784
25.	216/1/3	0 084
26.	366	0.125
27.	368	0.334
28.	370	0.188
29.	369/1	0.031
30.	17	0.303
31.	15/2	0.031
32.	88	0.031
33.	18	0.031
	TOTAL AREA	7.294

[No. O—14016/538/84-G.P.]

का.आ. 2608.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 300 तारीख 26-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम तेश खुर्द तहसील चाचोड़ा जिला—गुना राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनुक्रम 1	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर्स में)
1	2	3
1.	37	0.073
2	35	0.548
3	34/1	0 281
4	34/2	0.428
5.	24	0.527
6	12	0.021
7	11	0 393
8	10	0 974
9	9	0.021
10	8	0.679
	योग —कुल क्षेत्रफल	3.945

[सं O-14016/534/84-जी. पी]

S.O 2608.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 300 dated 26-1-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT Distt. Guna
Village Nesh Khurd Tehsil Chachoda

SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	37	0.073
2.	35	0.548
3.	34/1	0.281
4.	34/2	0.428
5.	24	0.527
6.	12	0.021
7.	11	0.393
8.	10	0.974
9.	39	0.021
10.	8	0.679
	TOTAL AREA	3.945

[No. O-14016/534/84-G.P.]

का. आ. 2609:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 1524 तारीख 29-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख से निहित होगा ।

अनुसूची

विजयपुर (म. प्र.) से सवाई माधोपुर (राज.) तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य राजस्थान जिला कोटा तहसील पीपल

गांव	खसरा नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1	2	3	4	5
उम्मेदपुरा	107	0	30	00
	108	0	30	90
	109/134	0	07	80
	109	0	48	00
	110	0	17	70
	164	0	04	20
	169	0	13	20
	170	0	04	20
	171	0	07	20

[सं. O-14016/191/85-जी. पी.]

S.O. 2609.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 1524 dated 29 3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Bijaipur (M.P.) to Sawai Madhopur (Raj.)

State : Rajasthan	District : Kota		Teshil : Piplada	
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	
Ummedpura	107	0	30	00
	108	0	30	90
	109/134	0	07	80
	109	0	48	00
	110	0	17	70
	164	0	04	20
	169	0	13	20
	170	0	04	20
	171	0	07	20

[No. O-14016/191/85-G.P.]

का. आ. 2610:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ. सं. 3461 तारीख/16-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	क्षेत्रफल एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	रसूलपुर	1	0-03	
				19	0-27	
				20	0-10	
				21	0-03	
				160	0-03	
				164	0-16	
				165	0-93	
				166	0-03	
				167	0-03	
				173	0-18	
				174	0-10	
				175	0-10	
				176	0-49	
				151	1-15	
				152	1-02	
				147	0-03	
				146	0-57	
				229	0-03	
				230	0-03	
				242	0-31	
				243	0-33	
				244	0-03	
				249	0-69	
				250	0-03	
				259	0-64	
				260	0-57	
				261	0-03	
				264	0-83	
				289	0-03	
				290	0-05	

[सं. O-14016/31/84-जी. पी.]

S.O. 2610.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3461 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas pipe line from Hajira : Barcily : Jagdish pur Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun,	Jalaun,	Jalaun	Rasulpur	1	0-03	
				19	0-27	
				20	0-10	
				21	0-03	
				160	0-03	
				164	0-16	
				165	0-93	
				166	0-03	
				167	0-03	
				173	0-18	
				174	0-10	

1	2	3	4	5	6	7
				175	0–10	
				176	0–49	
				151	1–15	
				152	0–02	
				147	0–03	
				146	0–57	
				229	0–03	
				230	0–03	
				242	0–31	
				243	0–33	
				244	0–03	
				249	0–69	
				250	0–03	
				259	0–61	
				260	0–57	
				261	0–03	
				264	0–83	
				289	0–03	
				290	0–05	

[No. O-14016/31/84-G.P.]

का. आ. 2611:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3790 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. मे सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	प्लाट नं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	खेड़ा मुस्तकिल	139	0–23	
				140	0–30	
				142	0–41	
				143	0–45	
				172	0–22	
				173	0–22	
				175	0–67	
				176	0–06	
				132	0–06	

[सं. O-14016/181/84-जी. पी.]

S.O. 2611.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3790 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas pipe line from, Hajira-Bareilly : Jagdishpur Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun,	Jalaun	Jalaun	Khera Musta-kil	139	0–23	
				140	0–30	
				142	0–41	
				143	0–45	
				172	0–22	
				173	0–22	
				175	0–67	
				176	0–06	
				132	0–06	

[No. O-14016/181/84-G.P.]

का.आ. 2612:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3438 तारीख 16-10/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा करती घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमयों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	घिलौवा	19	0–03	
				30	0–42	
				31	0–42	
				32	0–20	
				33	0–03	
				34	0–11	
				35	0–08	
				39	0–02	
				43	0–60	
				44	0–70	
				45	0–01	
				49	0–02	
				51	0–36	
				53	0–02	
				54	0–78	
				55	0–80	
				56	0–45	
				172	0–02	
				173	0–21	
				174	1–03	
				176	0–03	
				168	0–03	
				164	0–02	
				165	0–15	

[स. O-14016/34/84-जी. पी.]

S.O. 2612.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3438 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira–Bareilly–Jagdishpur Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Ghilava	19	0–03	
				30	0–42	
				31	0–42	
				32	0–20	
				33	0–03	
				34	0–11	
				35	0–08	
				39	0–02	
				43	0–60	
				44	0–70	
				45	0–01	
				49	0–02	
				51	0–36	
				53	0–02	
				54	0–78	
				55	0–80	
				56	0–45	
				172	0–02	
				173	0–21	
				174	1–03	
				176	0–03	
				168	0–03	
				164	0–02	
				165	0–15	

[No. O-14016/34/84-G.P.]

का.आ. 2613.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4516 तारीख 3-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	बघावली	1	0–54	
			दिवारा	3	0–72	
				4/3	0–16	
				22/1	3–60	
				5	1–02	

[सं. O-14016/410/84-जी. पी.]

S.O. 2613.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4516 dated 3-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipeline from Hajira–Bareilly–Jagdishpur Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Bagha-	1	0–54	
			wali	4/3	0–16	
			Diwara	22/1	3–60	
				5	102	

[No. O—14016/410/84-G.P.]

का.आ. 2614.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 5703/17/11/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का आधिकार केन्द्रीय सरकार मे निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सभी बाधाओं से मुक्त रूप मे घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा स.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
रायबरेली	महराज-गंज	इन्हौना	मनभरिया	1515	0–4–0	
				1516	0–10–0	
				1570	0–2–0	
				1573	0–7–0	
				1574	1-5-0	
				1578	0–1–0	
				1579	0–13-0	
				1595	0–5–0	
				1647	0–0–2	
				1596	0–18–0	
				1646	0–4–0	
				1648	0–10–0	
				1649	0–0–10	
				1665	0–13–15	
				1667	0–7–0	
				1669	0–3–0	
				1670	0–8–0	
				1671	0–0–10	
				1674	0–5–0	
				1675	0–0–10	
				1683	0–9–10	
				1804	0–11–0	
				1805	0–0–2	
				1809	0–16–0	
				1810	0–1–10	
				1811	0–3–10	
				1861	0–3–0	
				1862	0–0–5	
				1863	0–1–15	
				1864	0–12–10	
				1865	0–2–0	
				1866	0–5–10	
				1867	0–3–10	
				1874	0–5–0	
				1875	0–1–5	
				1876	0–3–10	
				1880	0–9–10	
				1881	0–6–10	
				1882	0–2–0	
				1883	0–0–5	
				1917	0–11–0	
				1918	0–2–10	
				1919	0–3–0	
				1920	0–5–0	
				1921	0–2–0	
				2113	0–15–0	
				2114	0–7–0	
				2115	0–5–10	
				2117	0–1–0	
				2118	0–14–10	
				2119	0–9–10	
				2120	0–2–0	
				2126	0–0–5	
				2127	0–3–0	
				2162	0–13–0	
				2165	0–0–10	
				2406	0–3–0	
				2408	0–2–0	
				2442	0–2–10	
				2443	0–7–0	
				2444	0–4–0	
				2445	0–4–0	
				2446	0–15–0	
				2447	0–1–0	
				2453	0–2–0	
				2454	0–5–8	
				2455	0–4–10	
				2459	0–5–0	
				2460	0–3–0	
				2461	0–1–10	
				2471	0–10–0	
				2472	0–5–0	
				2473	0–0–10	
				2474	0–0–10	
				2475	0–2–10	
				2476	0–9–10	
				2477	0–19–00	
				2497	0–3–10	
				2533	0–5–10	
				2534	0–5–0	
				2539	0–15–0	
				2541	0–3–10	
				2545	0–18–0	
				2546	0–10–0	
				2586	0–16–0	
				2587	0–2–2	
				2588	0–4–10	
				2479	0–1–0	
				2480	0–6–0	
				1512	0–1–0	
				1513	0–5–0	
				1514	0–5–0	
				2407	0–1–0	

[सं ओ-14016/160/84-जी पी]

S.O. 2614.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3703 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention

to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication in this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira : Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rai-Barielly	Maha-rajganj	Enhona	Bon-baharya	1515	0–4–0	
				1516	0–10–0	
				1570	0–2–0	
				1573	0–7–0	
				1574	1–5–0	
				1578	0–1–0	
				1579	0–13–0	
				1595	0–5–0	
				1647	0–0–2	
				1596	0–18–0	
				1646	0–4–0	
				1648	0–10–0	
				1649	0–0–10	
				1665	0–13–15	
				1667	0–7–0	
				1669	0–3–0	
				1670	0–8–0	
				1671	0–0–10	
				1674	0–5–0	
				1675	0–0–10	
				1683	0–9–10	
				1804	0–11–0	
				1805	0–0–2	
				1809	0–16–0	
				1810	0–1–10	
				1811	0–3–10	
				1861	0–3–0	
				1862	0–0–5	
				1863	0–1–15	
				1864	0–12–10	
				1865	0–2–0	
				1866	0–5–10	
				1867	0–3–10	
				1874	0–5–0	
				1875	0–1–5	
				1876	0–3–10	
				1880	0–9–10	
				1881	0–6–10	
				1882	0–2–0	
				1883	0–0–5	
				1917	0–11–0	
				1918	0–2–10	
				1919	0–3–0	
				1920	0–5–0	
				1921	0–2–0	
				2113	0–15–0	
				2114	0–7–0	
				2115	0–5–10	
				2117	0–1–0	
				2118	0–14–10	
				2119	0–9–10	
				2120	0 2–0	
				2126	0–0–5	
				2127	0–3–0	
				2162	0–13–0	
				2165	0–0–10	
				2406	0–3–0	
				2408	0–2–9	
				2442	0–2–10	
				2443	0–7–0	
				2444	0–4–0	
				2445	0–4–0	
				2446	0–15–0	
				2447	0–1–0	
				2453	0–3–0	
				2454	0–5–8	
				2455	0–4–10	
				2459	0–5–0	
				2460	0–3–0	
				2461	0–1–10	
				2471	0–10–0	
				2472	0–5–0	
				2473	0–0–10	
				2474	0–0–10	
				2475	0–2–10	
				2476	0 9–10	
				2477	0–19–00	
				2497	0–3–10	
				2533	0–5–10	
				2534	0–5–0	
				2539	0–15–0	
				2544	0–3–10	
				2545	0–18–0	
				2546	0–10–0	
				2586	0–16–0	
				2587	0–2–2	
				2588	0–4–10	
				2479	0–1–0	
				2480	0–6–0	
				1512	0–1–0	
				1513	0–5–0	
				1514	0–5–0	
				2407	0–1–0	

[No. O—14016/160/84–G.P.]

का.आ. 2615—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4077/तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों मे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7
राय-बरेली	महराज-गंज	बछरावां	पहुंमाशा	166	0–0–10	
				167	0–7–15	
				168	0–7–15	
				241	0–7–15	
				143	0–11–0	
				246	0–8–5	
				247	0–7–15	
				248	1–9–10	
				249	0–11–10	
				250	0–10–15	
				251	0–9–0	
				268	0–4–15	
				275	0–13–10	
				277	0–4–10	
				278	0–4–5	
				286	0–1–0	
				288	0–8–10	
				289	0–5–0	
				290	0–8–15	
				331	0–9–10	
				334	0–1–5	
				315	0–0–10	
				336	0–8–15	
				443	0–1–15	
				347	0–8–0	
				348	0–8–10	
				350	0–0–5	
				357	0–1–0	
				358	0–2–0	
				359	0–3–5	
				360	0–4–15	
				361	0–7–5	
				362	0–4–5	
				374	0–3–0	
				375	0–2–15	
				376	0–7–10	
				388	0–0–5	
				394	0–4–10	
				396	0–10–0	
				397	0–1–0	
				398	0–7–5	
				399	0–15–15	
				400	0–5–0	
				416	0–1–10	
				418	0–9–10	
				458	0–8–0	
				459	0–2–5	
				460	0–0–5	
				461	0–2–5	
				462	0–18–10	
				463	0–13–10	
				464	0–1–10	
				465	0–1–5	
				470	0–1–5	
				471	0–1–10	
				472	0–0–15	
				489	0–12–0	
				496	0–5–10	
				497	0–8–10	
				501	0–2–5	
				585	0–14–0	
				586	0–2–0	
				342	0–0–15	
				169	0–0–10	
				389	0–1–0	
				582	0–0–15	
				291	0–1–12	
				584	0–2–0	
				242	0–0–15	
				244	0–4–0	
				269	0–14–0	
				287	0–4–5	
				485	0–1–15	

[सं. O-14016/316/84-जीपी]

S.O. 2615.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4077 dated 1-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances

SCHEDULE

Hajira : Barielly –Jagdishpur Pipe line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village No.	Plot No.	Area Acquired	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Rai-Barielly	Maha-rajganj	Bachhra-wana	Panna-sha,	166	0-0-10	
				167	0-7-15	
				168	0-7-15	
				241	0-7-15	
				143	0-11-0	
				246	0-8-5	
				247	0-7-15	
				248	1-9-10	
				249	0-11-10	
				250	0-10-15	
				251	0-9-0	
				268	0-4-15	
				275	0-13-10	
				277	0-4-10	
				278	0-4-5	
				286	0-1-0	
				288	0-8-10	
				289	0-5-0	
				290	0-8-15	
				331	0-9-10	
				334	0-1-5	
				335	0-0-10	
				336	0-8-15	
				343	0-1-15	
				347	0-8-0	
				348	0-8-10	
				350	0-0-5	
				357	0-1-0	
				358	0-2-0	
				359	0-3-5	
				360	0-4-15	
				361	0-7-5	
				362	0-4-5	
				374	0-3-0	
				375	0-2-15	
				376	0-7-10	
				388	0-0-5	
				394	0-4-10	
				396	0-10-0	
				397	0-1-0	
				398	0-7-5	
				399	0-15-15	
				400	0-5-0	
				416	0-1-10	
				418	0-9-10	
				458	0-8-0	
				459	0-2-5	
				460	0-0-5	
				461	0-2-5	
				462	0-18-10	
				463	0-13-10	
				464	0-1-10	
				465	0-1-5	
				470	0-1-5	
				471	0-1-10	
				472	0-0-15	
				489	0-12-0	
				496	0-5-10	
				497	0-8-10	
				501	0-2-5	
				585	0-14-0	
				586	0-2-10	
				342	0-0-15	
				169	0-0-10	
				389	0-1-0	
				582	0-0-15	
				291	0-1-12	
				584	0-2-0	
				242	0-0-15	
				244	0-4-0	
				269	0-14-0	
				287	0-4-5	
				485	0-1-5	

[No. O—14016/376/84-G P]

का. आ. सं. 2616.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण
कानपुर देहात	अकबर-पुर	अकबर-पुर	सहाय-हरपाली	369 0–4–0	
				370 0–7–0	
				368 0–8–0	
				374 1–0–0	
				373 1–6–0	
				383 0–2–12	
				473 1–7–0	
				474 0–0–6	
				477 0–13–0	
				470 0–15–0	
				478 0–0–13	
				479 0–0–6	
				464 0–16–18	
				462 1–6–0	
				481 0–0–6	
				487 0–0–13	
				509 1–0–16	
				507 0–10–0	
				506 0–2–0	
				603 1–5–0	
				602 0–11–0	
				599 0–0–6	
				598 0–0–13	
				593 1–1–0	
				592 0–0–6	
				590 0–2–0	
				588 0–0–10	
				591 0–0–10	
				589 1–18–0	
				587 0–11–0	
				583 0–3–0	
				510 1–5–0	
				472 0–2–0	

[सं. ओ–14016/193/84–जी.पी.]

S.O. 2616.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3802 dated 17-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification:

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government, vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Sarai-Harpali	369	0-4-0	
				370	0-7-0	
				368	0-8-0	
				374	1-0-0	
				373	1-6-0	
				383	0-2-12	
				473	1-7-0	
				474	0-0-6	
				477	0-13-0	
				470	0-15-0	
				478	0-0-13	
				479	0-0-6	
				464	0-16-18	
				462	1-6-0	
				481	0-0-6	
				487	0-0-13	
				509	1-0-16	
				507	0-10-0	
				506	0-2-0	
				603	1-5-0	
				602	0-11-0	
				599	0-0-6	
				598	0-0-13	
				593	1-1-0	
				592	0-0-6	
				590	0-2-0	
				588	0-0-10	
				591	0-0-10	
				589	1-18-0	
				587	0-11-0	
				583	0-3-0	
				510	1-5-0	
				472	0-2-0	

[No. O-14016/193/84-G.P.]

का.आ. 2617.—यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4523 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस

अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत:, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	बड़ा गांव भिक्खी	4	0-1-10	
				18	0-2-0	
				19	2-13-5	
				24	2-12-3	
				40	0-15-8	
				41	0-0-15	
				36	0-1-10	
				38	0-1-1	
				50	0-11-5	
				51	0-17-10	
				52	0-1-2	
				54	0-10-0	
				56	0-10-13	
				57	0-0-15	
				58	0-14-1	
				60	0-14-10	
				61	0-14-1	
				369	0-3-6	
				374	0-14-13	
				376	0-0-12	
				377	0-1-8	
				378	0-2-0	
				379	0-0-1	

[सं. O-14016/418/84-जी.पी.]

S.O. 2017.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4523 dated 22-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government, vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
Kanpur Dehat	Derapur	Derapur	Baragawn Bhikhi	4	0-1-10	
				18	0-2-0	
				19	2-13-5	
				24	2-12-3	
				40	0-15-8	
				41	0-0-15	
				36	0-1-10	
				38	0-1-1	
				50	0-11-5	
				51	0-17-10	
				52	0-1-2	
				54	0-10-0	
				56	0-10-13	
				57	0-0-15	
				58	0-14-1	
				60	0-14-10	
				61	0-14-1	
				369	0-3-6	
				374	0-14-13	
				376	0-0-12	
				377	0-1-8	
				378	0-2-0	
				379	0-0-1	

[No. O-14016/418/84-G.P.]

का.आ. 2618:—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4071, तारीख 12-11-1984 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः, केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया विस्तार रकबा (एकड़ में)
जालौन	कोंच	कोंच	तीतरा परसराम	1	0–02
				2	0–02
				13	1–47
				14	0–77
				15	0–51
				53	0–02
				58	0–05
				59	0–43
				60	1–05
				71	2–16
				72	1–18
				66	0–02
				54	0–05

[सं. O-14016/310/84-जी पी.]

S.O. 2618.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4071 dated 12-11-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired (Acre)	Remark
Jalaun	Konch	Konch	Titra Persh-ram	1	0-02	
				2	0-02	
				13	1-47	
				14	0-77	
				15	0-51	
				53	0-02	
				58	0-05	
				59	0-43	
				60	1-05	
				71	2-16	
				72	1-18	
				66	0-02	
				54	0-05	

[No. O-14016/310/84-GP]

का.आ. 2619.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4096 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों की बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लाट सं०	लिया गया रकबा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबर-पुर	अकबर-पुर	भिखना-पुर	362	1–2–0
				368	0–4–0
				369	2–8–0
				370	0–8–0
				371	0–7–2
				372	0–4–0
				373	0–11–18
				427	0–2–14
				424	0–1–5
				423	0–18–0
				425	1–15–0
				429	0–3–0
				419	0–15–0
				420	0–7–0
				458	0–8–0
				457	0–2–16
				464	0–0–1
				463	1–17–0
				462	0–10–10
				507	1–0–0
				466	0–2–8
				487	2–4–0
				490	0–6–0
				484	0–6–0
				486	0–2–8
				489	2–0–14
				767	0–2–15
				765	1–17–0
				763	0–2–8
				764	0–15–0
				753	0–2–0
				757	1–5–0
				755	0–17–0
				730	0–10–10
				728	0–0–10
				726	0–17–0
				725	1–18–0
				361	0–5–0
				432	0–0–10
				459	0–11–0
				456	0–0–2
				488	0–8–0
				460	0–0–13
				461	0–0–13

[सं. O–14016/346/84-जी.पी.]

S.O. 2619.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4096 dated 1-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Bhikh-napur	362	1-2-0	
				368	0-4-0	
				369	2-8-0	
				370	0-8-0	
				371	0-7-2	
				372	0-4-0	
				373	0-11-18	
				427	0-2-14	
				424	0-1-5	
				423	0-18-0	

1	2	3	4	5	6
				425	1-15-0
				429	0-3-0
				419	0-15-0
				420	0-7-0
				458	0-8-0
				457	0-2-16
				464	0-0-1
				463	1-17-0
				462	0-10-10
				507	1-0-0
				466	0-2-8
				487	2-4-0
				490	0-6-0
				484	0-6-0
				486	0-2-8
				489	2-0-14
				767	0-2-15
				765	1-17-0
				763	0-2-8
				764	0-15-0
				753	0-2-0
				757	1-5-0
				755	0-17-0
				730	0-10-10
				728	0-0-10
				726	0-17-0
				725	1-18-0
				361	0-5-0
				432	0-0-10
				439	0-11-0
				456	0-0-2
				488	0-8-0
				460	0-0-13
				461	0-0-13

[No. O-14016/346/84—G.P.]

का.आ. 2620:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा विवरण
1	2	3	4	5	6 7
कानपुर देहात	अकबर-पुर	अकबर-पुर	बिलहा-हार	38	0-1-0
				40	1-12-0
				42	1-12-0
				44	1-17-15
				45	0-4-5
				47	0-2-8
				48	0-11-7
				59	0-4-0
				60	0-7-5
				61	0-5-10
				62	0-17-0
				63	0-0-1
				66	0-0-5
				65	0-2-10
				71	0-10-5
				72	0-10-0
				73	1-1-10
				74	0-19-6
				75	0-1-1
				78	0-8-17
				79	0-0-4
				81	0-2-4
				90	2-0-0
				97	1-3-11
				98	0-0-8
				99	0-0-4
				100	0-14-0
				109	0-1-4
				133	1-13-0
				260	0-7-0
				262	1-2-0
				263	0-9-0
				264	1-13-0
				96	0-10-0
				89	0-1-10
				92	0-9-0
				93	0-4-0
				95	0-1-10

[सं. O-14016/351/84-जी.पी.]

S.O. 2620.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4127 dated 1-12-1984 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification:

Now therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Vilva-hai	38	0-4-0	
				40	1-12-0	
				42	1-12-0	
				44	1-17-15	
				45	0-4-5	
				47	0-2-8	
				48	0-11-7	
				59	0-4-0	
				60	0-7-5	
				61	0-5-10	
				62	0-17-0	
				63	0-0-1	
				66	0-0-5	
				65	0-2-10	
				71	0-10-5	
				72	0-10-0	
				73	1-1-10	
				74	0-19-6	
				75	0-1-1	
				78	0-8-17	
				79	0-0-4	
				81	0-2-4	
				90	2-0-0	
				97	1-3-11	
				98	0-0-8	
				99	0-0-4	
				100	0-14-0	
				109	0-1-4	
				133	1-13-0	
				260	0-7-0	
				262	1-2-0	
				263	0-9-0	
				264	1-13-0	
				96	0-10-0	
				89	0-1-10	
				92	0-9-0	
				93	0-4-0	
				95	0-1-10	

[No. O-14016/351/84-GP]

का.आ. 2621.—यत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4068 तारीख 12/11/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	8	7
जालौन	कोंच	कोंच	टोपार	61	0-02	
				64	0-39	
				65	0-52	
				67	0-08	
				68	0-02	
				71	1-05	
				73	0-01	
				76	1-02	
				157	0-02	
				153	1-47	
				154	0-80	
				162	0-01	
				167	1-20	
				168	0-02	
				66	0-13	

[सं O-14016/307/84-जी पी]

S.O. 2621.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O 4068 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdisphur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Konch	Konch	Topare	61	0-02	
				64	0-39	
				65	0-52	
				67	0-08	
				68	0-02	
				71	1-05	
				73	0-01	
				76	1-02	
				157	0-02	
				153	1-47	
				154	0-80	
				162	0-01	
				167	1-20	
				168	0-02	
				66	0-13	

[No. O-14016 307/84—G.P.]

का.आ. 2622.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4101 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	बेलमा कलां	117	0-17	
				118	0-33	
				119	0-84	
				120	0-03	
				121	0-04	
				131	1-80	
				132	0-44	
				133	0-05	
				144	0-10	
				145	0-07	
				146	0-09	
				289	0-68	
				290	0-09	
				292	1-08	
				294	0-03	
				295	1-40	
				296	0-02	
				297	0-27	
				301	0-03	
				311	0-91	
				342	1-15	
				343	0-68	
				351	0-06	
				352	0-03	
				354	0-46	
				355	0-68	
				356	0-64	
				357	0-04	
				358	0-90	
				359	0-22	

[सं. O-14016/3/84-जीपी]

S.O. 2622.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Belma-kalo	117	0-17	
				118	0-33	
				119	0-84	
				120	0-03	
				121	0-04	
				131	1-80	
				132	0-44	
				133	0-05	
				144	0-10	
				145	0-07	
				146	0-09	
				289	0-68	
				290	0-09	
				292	1-08	
				294	0-03	
				295	1-40	
				296	0-02	
				297	0-27	
				301	0-03	
				341	0-91	
				342	1-15	
				343	0-68	
				351	0-06	
				352	0-03	
				354	0-46	
				355	0-68	
				356	0-64	
				357	0-04	
				358	0-90	
				359	0-22	

[No. O-14016/3/84—GP]

229 GI/85—18

का.आ. 2623.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. स. 4101 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	पूल-गहना	73	0-38	
				75	0-06	
				76	0-06	
				77	1-41	
				79	0-04	
				80	0-05	
				81	1-12	
				82	0-30	
				97	0-03	
				98	0-06	
				99	0-01	
				100	0-90	

1	2	3	4	5	6	7
				101	1-25	
				102	0-06	
				103	0-14	
				292	0-03	
				319	0-88	
				219	0-18	
				285	1-20	
				320	0-05	
				282	1-10	
				283	0-13	
				176	0-17	
				166	0-02	
				165	2-10	
				164	1-20	
				183	5-05	
				182	0-03	
				181	1-55	
				184	0-88	
				185	0-23	
				187	0-08	
				200	0-03	
				253	0-35	
				145	0-04	
				228	0-20	
				229	0-23	
				225	0-02	
				226	1-80	
				231	0-03	
				232	5-05	
				238	0-01	
				236	0-35	
				233	0-07	
				235	1-70	
				234	0-10	
				146	0-03	

[सं. O-14016/3/84- जी. पी]

S.O. 2623.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Pulgohna	73	0-38	
				75	0-06	
				76	0-06	
				77	1-41	
				79	0-04	
				80	0-05	
				81	1-12	
				82	0-30	
				97	0-03	
				98	0-06	
				99	0-01	
				100	0-90	
				101	1-25	
				102	0-06	
				103	0-14	
				292	0-03	
				319	0-38	
				291	0-18	
				285	1-20	
				320	0-05	
				282	1-10	
				283	0-13	
				176	0-17	
				166	0-02	
				165	2-10	
				164	1-20	
				183	0-05	
				182	0-03	
				181	1-55	
				184	0-88	
				185	0-23	
				187	0-08	
				200	0-03	
				253	0-35	
				145	0-04	
				228	0-20	
				229	0-23	
				225	0-02	
				226	1-80	
				231	0-03	
				232	0-05	
				238	0-01	
				236	0-35	
				233	0-07	
				235	1-70	
				234	0-10	
				146	0-02	

[No. O-14016/3/84-G. P.]

का.आ. 2624.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 4101 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है। अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	बड़वदा	91	0–20	
				92	0–02	
				93	0–80	
				94	1–50	
				95	0–03	
				108	0–03	
				110	1–25	
				111	0–04	
				112	1–55	
				116	0–02	
				120	0–75	
				144	0–03	
				145	0–75	
				146	1–50	
				152	0–30	
				153	1–27	
				154	0–12	
				155	0–06	
				162	0–32	
				163	0–02	
				164	1–20	
				165	0–56	
				166	0–02	
				170	0–01	
				171	1–24	

[सं. ओ-14016/3/84/जी.पी.]

S.O. 2624.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area (In Acre)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Baravda	91	0–20	
				92	0–02	
				93	0–80	
				94	1–50	
				95	0–03	
				108	0–03	
				110	1–25	
				111	0–04	
				112	1–55	
				116	0–02	
				120	0–75	
				144	0–03	
				145	0–75	
				146	1–50	
				152	0–30	
				153	1–27	
				154	0–12	
				155	0–06	
				162	0–32	
				163	0–02	
				164	1–20	
				165	0–56	
				166	0–02	
				170	0–01	
				171	1–24	

का. आ. 2625 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4101 तारीख 12-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
झांसी	मोठ	मोठ	कुइंया	262	1–70	
				261	0–18	
				260	0–82	
				256	0–03	
				255	0–01	
				253	0–13	
				254	1–60	
				247	0–03	
				212	1–00	
				246	0–07	
				245	0–03	
				213	0–20	
				244	0–80	
				243	0–55	
				214	0–01	
				217	0–04	
				218	1–55	
				229	0–03	
				228	0–01	
				227	0–40	
				226	0–38	
				225	0–40	
				224	0–58	
				223	0–26	

[सं. O-14016/3/84-जी. पी.]

S.O. 2625.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4101 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-BareillyJa-gdishpur Pipeline Project

Dist.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jhansi	Moth	Moth	Kanyan	262	1–70	
				261	0–18	
				260	0–82	
				256	0–03	
				255	0–01	
				253	0–13	
				254	1–60	
				247	0–03	
				212	1–00	
				246	0–07	
				245	0–03	
				213	0–20	
				244	0–80	
				243	0–55	
				214	0–01	
				217	0–04	
				218	1–55	

1	2	3	3	5	6	7
				229	0-03	
				228	0-01	
				227	0-40	
				226	0-38	
				225	0-40	
				224	0-58	
				223	0-25	

[No. O-14016/3/84-GP]

का. आ 2626.:--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3789 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए, अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत. सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की उपधारा (6) उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली--जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	सीपुरा मुस्तिकिल	52	0-08	
				54	0-35	
				55	0-31	
				67	0-02	
				68	0-42	
				69	0-42	
				70	0-01	
				72	0-11	
				73	0-28	
				74	0-33	
				75	0-28	
				82	0-01	

[सं. O-14016/180/84-जी. पी.]

S.O. 2626.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3789 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Sipura Mustkil	53	0-08	
				54	0-35	
				55	0-31	
				67	0-02	
				68	0-42	
				69	0-42	
				70	0-01	
				72	0-11	
				73	0-28	
				74	0-33	
				75	0-28	
				82	0-01	

[No. O-14016/180/84-GP]

का. आ. 2627:--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4050 तारीख 12-11-84

द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी से उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	क्योलारी	429	0–02	
				428	1–73	
				424	0–01	
				423	0–70	
				421	0–01	
				413	1–43	
				412	0–03	
				419/1250	0–05	
				225	0–02	
				224	1–05	
				222	0–60	
				223	0–02	
				206	0–01	
				205	0–01	
				204	1–02	
				203	0–62	
				202	0–45	
				201	0–01	
				198	1–05	
				199	0–55	
				195	0–01	
				194	0–70	
				184	0–01	
				183	0–90	
				409	0–01	
				167	0–01	
				166	0–50	
				230	0–02	
				251	0–60	
				252	0–35	
				147	0–02	
				91	0–40	
				92	0–01	
				90	0–40	
				89	0–01	
				68	0–10	
				145	0–01	
				96	0–70	
				95	1–50	
				94	0–01	
				91	0–90	
				97	0–10	
				100	0–05	
				98	0–05	
				99	0–45	
				51	0–02	
				41	0–02	
				47	0–35	
				48	0–60	
				46	0–03	
				45	0–70	
				44	0–30	
				43	0–35	
				42	0–20	
				678	0–15	
				679	0–03	
				116	0–03	
				692	0–20	
				691	0–43	
				690	0–01	
				689	0–30	
				688	0–20	
				687	0–10	
				686	0–08	
				682	0–20	

[सं. O-14016/288/84-जी. पी.]

S.O. 2627.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4050 dated 12-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe Line From, Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Kouch	Konch	Quolari	429	0-02	
				428	1-73	
				424	0-01	
				423	0-70	
				421	0-01	
				413	1-43	
				412	0-02	
				419/1250	0-05	
				225	0-02	
				224	1-05	
				222	0-60	
				223	0-02	
				206	0-01	
				205	0-01	
				204	1-02	
				203	0-62	
				202	0-45	
				201	0-01	
				198	1-05	
				199	0-55	
				195	0-01	
				194	0-70	
				184	0-01	
				183	0-90	
				409	0-01	
				167	0-01	
				166	0-50	
				230	0-02	
				251	0-60	
				252	0-35	
				147	0-02	
				91	0-40	
				92	0-01	
				90	0-40	
				89	0-01	
				88	0-10	
				145	0-01	
				96	0-70	
				95	1-50	
				94	0-01	
				93	0-90	
				97	0-10	
				100	0-05	
				98	0-05	
				99	0-45	
				51	0-02	
				41	0-02	
				47	0-35	
				48	0-60	
				46	0-03	
				45	0-70	
				44	0-30	
				43	0-35	
				42	0-20	
				678	0-15	
				679	0-03	
				116	0-03	
				692	0-20	
				691	0-43	
				690	0-01	
				689	0-30	
				688	0-20	
				687	0-10	
				686	0-08	
				682	0-20	

[No. O-14016/288/84-GP]

का. आ. 2628:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3793 तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	जालौन	जालौन	मुहम्मदपुर	5	0—01	
				41	0—01	
				43	1—14	
				132	1—32	
				133	0—01	
				136	0—01	
				137क	0—15	
				138	0—01	
				149	0—30	
				150	0—08	
				151	0—07	
				154	0—34	
				158	0—01	
				148	0—09	
				153	0—02	

[सं O-14016/12/84 जी पी.]

S.O. 2628.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3793 dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the sadi Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe line from Hajira-Bareilly-Jagdishpur P?oject

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Moham-mad Pur	5	0–01	
				41	0–01	
				43	1–14	
				132	1–32	
				133	0–01	
				136	0–01	
				137क	0–15	
				138	0–01	
				149	0–30	
				150	0–08	
				151	0–07	
				154	0–34	
				158	0–01	
				148	0–09	
				153	0–02	

[No. O-14016/185/84 GP]

का. आ 2629 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

हाजिरा--बरेली--जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा स०	क्षेत्रफल बि. वि०वि०	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	अकबरपुर	अकबरपुर	गहौलिया	454	4- 09- 00	
				458	0- 14- 00	
				456	0- 00- 18	
				457	1- 03- 00	

1	2	3	4	5	6	7
				465	1- 03- 00	
				544	0- 01- 14	
				480	0- 03- 02	
				481	0- 15- 00	
				482	0- 12- 00	
				483	0- 11- 10	
				484	0- 07- 00	
				485	0- 00- 10	
				486	1- 06- 00	
				512	0- 01- 10	
				518	0- 01- 02	
				517	1- 18- 00	
				513	1- 16- 04	
				511	0- 11- 12	
				508	2- 03- 00	
				510	0- 02- 09	
				489	0- 03- 00	
				509	1- 12- 00	
				497	2- 07- 00	
				498	0- 12- 00	
				246	2- 00- 00	
				684	0- 03- 10	
				680	0- 00- 16	
				247	0- 00- 18	
				678	1- 00- 00	
				677	1- 00- 00	
				676	0- 11- 11	
				679	0- 17- 00	
				674	0- 11- 00	
				673	1- 00- 00	
				703	0- 01- 18	
				701	0- 04- 18	
				702	1- 04- 00	
				704	1- 19- 00	
				706	0- 07- 00	
				711	0- 15- 00	
				710	0- 02- 00	
				708	0- 16- 00	
				707	0- 02- 00	
				719	1- 11- 00	
				622	1- 10- 00	
				718	0- 04- 10	
				621	0- 07- 00	
				705	0- 00- 10	

[सं० O-14016/348/84 जी. पी.]

S.O. 2629.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4097 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the scheduled appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Pargana	Tehsil	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Gahaliya	454	4-09-11	
				458	0-14-00	
				456	0-00-18	
				457	1-03-00	
				465	1-03-00	
				544	0-01-14	
				480	0-03-02	
				481	0-15-00	
				482	0-12-00	
				483	0-11-10	
				484	0-07-10	
				485	0-00-10	
				486	1-06-00	
				512	0-01-10	
				518	0-01-10	
				517	1-18-00	
				513	1-16-04	
				511	0-01-12	
				508	2-03-00	
				510	0-02-09	
				489	0-03-00	
				509	1-12-00	
				497	2-07-00	
				498	0-12-00	
				246	2-00-00	
				684	0-03-10	
				680	0-00-16	
				247	0-00-18	
				678	1-00-00	
				677	1-00-00	
				676	0-11-11	
				679	0-17-00	
				674	0-11-00	
				673	1-00-00	
				703	0-01-18	
				701	0-04-18	
				702	1-04-00	
				704	1-19-00	
				706	0-07-00	
				711	0-15-00	
				710	0-02-00	
				708	0-16-00	
				707	0-02-00	
				719	1-11-00	
				622	1-10-00	
				718	0-04-10	
				621	0-07-00	
				705	0-00-10	

[No. O-14016/348/84 GP]

का. आ. 2630.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3437 तारीख 16-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया विवरण रकबा एकड़ में
1	2	3	4	5	6 7
जालौन	जालौन	जालौन	कर्तला-पुर	1	0-03
				2	0-37
				3	0-43
				4	0-60
				5	0-02
				11	0-02

[सं० O-14016/33/84 जी० पी०.]

S.O. 2630.—Whereas by notification of the Goernment of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3437 dated 16-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notificat on for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to th's notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the sadi Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the p'peline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe Line From Hajira-Bareilly-Jagdishpur Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in acres	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Kartala-pur	1	0-03	
				2	0-37	
				3	0-43	
				4	0-60	
				5	0-02	
				11	0-02	

[No. O-14016/33/84-G. P.]

का. आ. 2631:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4491 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहल तालुका—हालोल

गांव	661	0	10	00
	662	0	10	00
	603	0	01	00
	413	0	38	00
	412	0	37	00
	411	0	04	80
	410/2	0	36	30
	कोटर	0	16	50
	443	0	27	00
	444	0	20	00
	445	0	10	00
	518	0	26	00
	519	0	46	00
	कोटर	0	12	60
	532	0	11	00
	510	0	09	00
	531	0	03	00
	565	0	22	00
	712	0	12	00
	714+715	0	76	80

[सं० O-14016/379/84-जी. पी.]

S.O. 2631.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4491 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby required for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Hazira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Jalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Cen-tiare
Halol	661	0	10	00
	662	0	10	00
	603	0	01	00
	413	0	38	00
	412	0	37	00
	411	0	04	80
	410/2	0	36	30
	Kotar	0	16	50
	443	0	27	00
	444	0	20	00
	445	0	10	00
	518	0	26	00
	519	0	46	00
	Kotar	0	12	60
	532	0	11	00
	510	0	09	00
	531	0	03	00
	565	0	22	00
	712	0	12	00
	714+715	0	76	80

[No. O-14016/379/84 GP]

का. आ. 2632:— यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4559 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य-गुजरात जिला--पंचमहाल ताल्लुका--देवगढ़ बारिया

गांव	सर्वे नं	हेक्टर	आर	सेंटयर
1	2	3	4	5
[illegible]	893/पी	0	20	00
	892/पी	0	30	00
	887/पी	0	18	00
	889	0	25	00
	887/पी	0	05	00
	888	0	52	00
	881	1	46	00
	856	0	03	00
	857	0	46	00
	862/4	0	01	60
	880	0	41	00
	873	0	00	10
	872	0	65	00
	871	0	41	00
	870	0	32	00
	80/1/पी	3	00	00
	100	0	03	00
	101	0	13	00
	144	0	40	00
	134	0	02	00
	143	0	58	00
	142	0	38	00
	146/पी	0	06	00
	146/पी	0	10	00
	139/पी	0	15	00
	139/पी	0	13	00
	139/पी	0	03	00
	139/पी	0	14	00
	139/पी	0	05	00
	147/3	0	10	00
	147/2	0	14	00
	147/1	0	20	00
	167	0	26	00
	160	0	36	00
	159	0	20	00

[सं.O-14016/462/84-जी. पी.]

S.O. 2632.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4559 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the sadi Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline From Hazira-Breilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluk : Dovgadhbariya

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Gollav	893/P	0	20	00
	892/P	0	30	00
	887/P	0	18	00
	889	0	25	00
	887/P	0	05	00
	888	0	52	00
	881	1	46	00
	856	0	03	00
	857	0	46	00
	862/4	0	01	60
	880	0	41	00
	873	0	00	10
	872	0	65	00
	871	0	41	00
	870	0	32	00
	80/1/P	3	00	00
	100	0	03	00
	101	0	13	00
	144	0	40	00
	134	0	02	00
	143	0	58	00
	142	0	38	00
	146/P	0	06	00
	146/P	0	10	00
	139/P	0	15	00
	139/P	0	13	00
	139/P	0	03	00
	139/P	0	14	00
	139/P	0	05	00
	147/3	0	10	00
	147/2	0	14	00
	147/1	0	20	00
	167	0	26	00
	160	0	36	00
	159	0	20	00

[No. O-14016/462/84-GP]

का. आ. 2633.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय

की अधिसूचना सं. का. आ. 3462 तारीख 16-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
जालौन	कोंच	कोंच	खेड़ाबेड़ा	1	0-35	
				2	0-18	
				5	0-01	
				6	0-30	
				17	0-55	
				16	0-60	
				15	0-77	
				19	0-01	
				21	0-35	
				22	0-96	
				31	0-02	
				43	0-06	
				44	0-02	
				79	0-11	
				78	0-02	
				77	0-50	
				76/1	0-08	
				76/2	0-50	
				65	0-10	
				65/252	0-42	
				66	0-08	
				67	0-41	
				59	0-01	
				47	0-60	
				46	0-04	
				45	0-65	
				18	0-01	
				60	0-01	

[सं. O-14016/32/84-जीपी]

S.O. 2633.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3462 dated and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) 16!0-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines acquisition of right of User in Land Act. 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the sadi Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline :

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Gas Pipe line from Hajira Bareilly Jagdishpur Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	ares in acres	Remark
1	2	3	4	4	6	7
Jalaun	Konch	Konch,	Khera Bora	1	0-35	
				2	0-18	
				5	0-01	
				6	0-30	
				17	0-55	
				16	0-60	
				15	0-77	
				19	0-01	
				21	0-35	
				22	0-96	
				31	0-02	
				43	0-06	
				44	0-02	
				79	0-11	
				78	0-02	
				77	0-50	
				76/1	0-08	
				76/2	0-50	
				65	0-10	
				65/252	0-42	
				66	0-08	
				67	0-41	
				59	0-01	
				47	0-60	
				46	0-04	

	5	6	7
	45	0-65	
	18	0-01	
	60	0-01	

[No. O-14016/32/84-PG]

का. आ 2634 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. 4530 का. आ. तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा एकड़ में	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
कानपुर देहात	डेरापुर	डेरापुर	दुड़ौली	378	0-02-06	
				380	0-11-0	
				381	1-04-01	
				382	1-05-15	
				408	0-02-02	
				415	0-05-04	
				416	0-0-16	
				418	0-12-10	
				419	0-0-18	
				420	0-15-12	
				421	0-17-0	
				423	0-0-13	
				426	0-17-0	
				427	0-0-07	
				429	1-07-0	
				430	0-01-06	

[सं. 0-14016/425/84- जी पी.]

S.O. 2634.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4530 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report user in the lands specified in the schedule appended to to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the sadi Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDUL

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Kanpur Dehat	Dera-pur	Dera-pur	Durauli	378	0-02-06	
				380	0-11-0	
				381	1-04-01	
				382	1-05-15	
				408	0-02-02	
				415	0-05-04	
				416	0-0-16	
				418	0-12-10	
				419	0-0-80	
				420	0-15-12	
				421	0-17-0	
				423	0-0-13	
				426	0-17-0	
				427	0-0-07	
				429	1-07-0	
				430	0-01-06	

[No. O-14016/425/84-GP]

का. आ. 2635 :—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3785, तारीख 27-10-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	दिया गया विवरण रकबा एकड़ में
जालौन	जालौन	जालौन	बघावली मुस्तकिल	2	0-43
				5	0-55
				6	0-08
				9/1	0-81
				9/3	0-07
				9/2	0-12
				18/1	0-07
				18/2	0-06
				19	0-60
				20	0-47
				21	0-46
				23	0-45

[सं. O-14016/176/84-जी पी]

S.O. 2635.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3785, dated 27-10-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has, under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Jalaun	Jalaun	Jalaun	Baghwali Mustkil	2	0-43	
				5	0-55	
				6	0-08	
				9/1	0-81	
				9/3	0-07	
				9/2	0-12	
				18/1	0-07	
				18/2	0-06	
				19	0-60	
				20	0-47	
				21	0-46	
				23	0-45	

[No. O-14016/176/84-GP]

का. आ. 2636.—यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4098, तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब,अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों मे उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

हाजिरा–बरेली–जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट ।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लाट सं.	लिया गया रकबा
कानपुर देहात	अकबर पुर	अकबर पुर	भटियामऊ	125	2–10–1
				124	0–2–18
				118	0–19–3
				120	1–4–0
				123	0–0–3
				122	0–18–10
				136	1–6–0
				138	1–8–0
				139	0–2–0
				166	0–6–11
				157	0–0–13
				158	0–0–7
				171	1–1–0
				173	0–2–0
				172	0–4–18
				435	0–0–18
				384	1–12–0
				386	1–6–0
				387	0–1–6
				388	0–0–13
				553	0–8–14
				694	1–12–0
				591	0–14–5
				592	0–6–10
				593	1–2–8
				752	1–9–7
				754	0–1–10
				755	0–12–0
				751	0–11–0
				761	0–2–16
				760	0–11–1
				756	0–10–0
				449	2–10–0

[सं. O–14016/350/84–जी पी]

एम. एस. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 2636.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4098, dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has, under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall, instead of vesting in Central Government, vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

SCHEDULE

Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	Remark
Kanpur Dehat	Akbar-pur	Akbar-pur	Bhatya-mou	125	2–10–1	
				124	0–2–18	
				118	0–19–3	
				120	1–4–0	
				123	0–0–3	
				122	0–18–10	
				136	1–6–0	
				138	1–8–0	
				139	0–2–0	
				166	0–6–11	
				157	0–0–13	
				158	0–0–7	
				171	1–1–0	
				173	0–2–0	
				172	0–4–18	
				435	0–0–18	
				384	1–12–0	
				386	1–6–0	
				387	0–1–6	
				388	0–0–13	
				553	0–8–14	
				694	1–12–0	
				599	0–14–5	
				592	0–6–10	
				593	1–2–8	
				752	1–9–7	
				754	0–1–10	
				755	0–12–0	
				751	0–11–0	
				761	0–2–16	
				760	0–11–1	
				756	0–10–0	
				449	2–10–0	

[No. O-14016/350/84-GP]

M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 1985

का. आ. 2637 केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित कार्यालयों / सरकारी उपक्रम एककों, जिनके 80 प्रतिशत या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को उक्त उपनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है :--

1. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मध्य प्रदेश सर्किल कार्यालय, भोपाल।
2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का उत्तर प्रदेश सर्किल कार्यालय, लखनऊ।
3. भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय, गोआ।
4. हिन्दुस्तान जिंक लि. को जिंक स्मेल्टर देबारी, उदयपुर (राजस्थान)।
5. हिन्दुस्तान जिंक लि. का राजपुरा दरीबा, खान कम्पलैक्स (राज.)।
6. हिन्दुस्तान कापर लि. का खेतड़ी कापर कम्पलैक्स खेतड़ीनगर (राज.)।
7. हिन्दुस्तान कापर लि. का सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली
8. भारत एल्युमिनियम कंपनी का कोरबा प्रोजेक्ट कार्यालय, कोरबा, जिला बिलासपुर (म. प्र.)।

[स. ई.-11017/2/84 हि.]

दुर्गादास गुप्त, उप सचिव

MINISTRY OF STEEL, MINES & COAL

(Department of Mines)

New Delhi, the 24th May, 1985

S.O. 2637.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (use for Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following offices under the Ministry of Steel, Mines & Coal, Department of Mines, the 80 per cent or more staff whereof have acquired working knowledge of Hindi, for the purpose of the said sub-rule :--

1. Geological Survey of India, M.P. Circle, Bhopal.
2. Geological Survey of India, U.P. Circle, Lucknow.
3. Indian Bureau of Mines, Regional Office, Goa.
4. Hindustan Zinc Ltd. Zinc Smelter, Udaipur (Raj).
5. Hindustan Zinc Ltd., Rajpura-Dariba Complex (Raj).
6. Hindustan Copper Ltd, Khetri Copper Complex, Khetri Nagar (Raj)
7. Hindustan Copper Ltd., Liaison Office, New Delhi.
8. Bharat Aluminium Co. Ltd., Korba Project, Korba Distt. Bilaspur (M.P.).

[N. E-11017/2/84-Hindi]

DURGADAS GUPTA, Dy. Secy.

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 15 मई, 1985

(शुद्धि-पत्र)

का. आ. 2638 --भारत के राजपत्र तारीख 1 दिसंबर, 1984 के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 3680-3682 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय, (कोयला विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 4044, तारीख 13 नवम्बर, 1984 में :--

पृष्ठ 3681 पर--अनुसूची में।

1. "गोपालपुर ब्लाक आई की घाटी क्षेत्र" के स्थान पर "गोपालपुर ब्लाक, ईब घाटी एरिया, पढ़िए।
2. क्रम सं. साथ में अनुक्रम 1 में--
   "सरडोगा" के स्थान पर "सारडोगा" पढ़िए।
3. सीमा वर्णन में रेखा द×ध में "उत्तरी किनारे" के स्थान पर 'उत्तरी किनारे" पढ़िए

[सं. 43019/1/84/सी एल.सी एल]

(Department of Coal)

New Delhi, the 15th May, 1985

CORRIGENDUM

S.O. 2638.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O 4044 dated the 13th November, 1984 published at pages 3681 to 3682 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 1st December, 1984.—

At page 3681, in the Schedule under the column "District" against serial number 1. for "Sindargarh", read "Sundargarh".

[No. 43019/1/84-CL/CA]

(शुद्धि-पत्र)

का. आ. 2639 भारत के राजपत्र तारीख 1 दिसम्बर, 1984 के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ 3679-3680 पर प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का. आ. सं. 4043, तारीख 12 नवम्बर, 1984 में--

पृष्ठ 3679 पर अधिसूचना के अनुक्रम 2 में--

(1) "धारा 13 की उपधारा (1)" के स्थान पर "धारा 13 की उपधारा (7)" एवं "नागपुर -446001" के स्थान पर "नागपुर 440001" पढ़िए।

(2) अनुसूचि में--

(क) क्रम सं. स्तम्भ में अनुक्रम 1 में "जुनाविमुण्डा" के स्थान पर "जुनानीमुण्डा" पढ़िए।

(ख) क्रम सं. स्तम्भ में अनुक्रम 3 में "बाघराचक" के स्थान पर "बघराचका" पढ़िए।

(3) सबसे अंत में "(सं. 43019/4/84-सीएलसी.एल)" के स्थान पर ("सं. 43019/4/84 सी.एल-/सी.ए.)" पढ़िए।

[सं. 43019/4/84-सी.एल./सी.ए.]

CORRIGENDUM

S.O. 2639.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 4043, dated 12th November, 1984, published at pages 3679 to 3680 of the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii), dated 1st December, 1984 at page 3680,

1. In the Schedule, for "North-West Block of Orient Mines No. 4—" VIB Valley "read North West Block of Orient Mine No. 4, Ib Valley".
2. In Boundary Description in line G-H-I for "Village Chhuliberna" read "Village Chhualiberna".

[No. 43019|4|84-CL|CA]

का. आ. 2640.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 444 तारीख 28 जनवरी, 1984 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 11 फरवरी, 1984 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 182.73 हैक्टर (लगभग) या 451.54 एकड़ (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 160.48 हैक्टर (लगभग) या 396.54 एकड़ (लगभग) माप की भूमि का, सभी अधिकारों सहित जैसा कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण—1 : इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं. सी-1(ई)/111/जे आर/283/0684 तारीख 12-6-84 का निरीक्षण कलक्टर, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001 (महाराष्ट्र) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण—2 : पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध हैं :—

अर्जन के प्रति आपत्ति :

"8(1) किसी ऐसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आक्षेप कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण : इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी व्यक्ति की ओर से यह कहना आक्षेप नहीं माना जाएगा कि वह स्वयं किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जानी चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को स्वयं सुने जाने का या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आक्षेपों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों को इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिया जाता।"

टिप्पण—3 : केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची "क"

पदमापुर विस्तारण ब्लाक

वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकारी (राजस्व भूमि)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	तहसील और जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1.	किटाडी	11	चन्द्रपुर	9.87	भाग
2.	पदमापुर	11	,,	73.09	भाग
3.	दुर्गापुर	10	,,	5.48	भाग
4.	सिनहाला	11	,,	41.74	भाग

कुल क्षेत्र 130.18 हैक्टर (लगभग)
या 321.68 एकड़ (लगभग)

अनुसूची "क 1"

पदमापुर विस्तारण ब्लॉक

वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र

जिला चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)

सभी अधिकार (वन भूमि)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल सं.	तहसील और जिला	क्षेत्र हैक्टर में	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1.	किटाडी	11	चन्द्रपुर	3.50	भाग
2.	पदमापुर	11	,,	26.80	भाग

कुल क्षेत्र — 30.30 हैक्टर (लगभग)
74.86 एकड़ (लगभग)

कुल योग (क+क1)— 160.48 हैक्टर (लगभग)
या 396.54 एकड़ (लगभग)

ग्राम किटाडी में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

1, 2 (भाग), 13 (भाग), 14, 80 (भाग), 81 (भाग), 85/2 (भाग), 86 आबादी (भाग), 87 (भाग), 88/1, 88/2 और सड़क (भाग)

ग्राम पदमापुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

71/1, 71/2, 71/3 (भाग), 72, 73, 74, 75 (भाग), 76 (भाग), 77 (भाग), 124 (भाग), 125 (भाग), 126 (भाग), 127 से 129, 130 (भाग), 131 से 133, 134 (भाग), 135, 142 (भाग), 143/1 (भाग), 143/3 (भाग), 144 (भाग), 145 से 148, 149 (भाग)

150 से 153, 154 (भाग), 155, 156(भाग), 157, 158(भाग), 159(भाग), नाला (भाग), आबादी (भाग), और सड़क (भाग)

ग्राम दुर्गापुर में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

45(भाग), 46 (भाग), 70(भाग), 71, 72(भाग), 74(भाग), 75(भाग), 76 (भाग),

ग्राम सिनहाला में अर्जित किए जाने वाले प्लाट सं.

59(भाग, 62(भाग), 63, 64, 65/1, 65/2, 67 से 72, 73(भाग), 74 (भाग), 75 (भाग), 76 (भाग), 77, 78(भाग) 79 से 84, 85(भाग), 87(भाग), 88 (भाग), 90 (भाग'), 91(भाग), 92 (भाग), 93 (भाग), और नाला (भाग)।

सीमा वर्णन

क-ख रेखा, इरई नदी के पूर्वी किनारे से प्रारम्भ होती है और प्लाट सं. 13, 14, 2, 1 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ किटाडी ग्राम से होकर जाती है, सड़क पार करती है, प्लाट सं. 88/1 से होकर जाती है और फिर प्लाट स. 87, 85/2, 86 आबादी, 80,81 में से होकर जाती है और प्लाट स. 81 में बिन्दु "ख" पर मिलती है ।

ख-ग रेखा प्लाट स. 81, 80 में किटाडी ग्राम से होकर जाती है और पदमापुर ग्राम से होकर, सड़क पार करती है और फिर प्लाट स. 76, 77, 75 में होकर लोक निर्माण विभाग की चन्द्रपुर-तारोबा सड़क को पार करती है और फिर प्लाट सं. 149, 154, आबादी, 156 में से होकर जाती है और प्लाट स. 156 में बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा, प्लाट सं. 156 में पदमापुर ग्राम से होकर जाती है, सड़क पार करती है, प्लाट सं. 131 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ भागतः जाती है, फिर प्लाट सं. 130, 124, 158 में से होकर जाती है और मोटा घाट नाले के मध्य स्थल पर बिन्दु "घ" पर मिलती है ।

घ-ङ-च-छ-ज रेखा, मोटा घाट नाले के मध्य स्थल से प्लाट सं. 159, 125 में पदमापुर ग्राम में होकर जाती है और फिर सिनहाला ग्राम में प्लाट सं. 78, 85, 87, 88, 91, 90, 93, 92 में से होकर जाती है और फिर प्लाट स. 67, 65/1 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और प्लाट स. 62, 59 में से होकर जाती है, नाला पार करती है और फिर सिनहाला और दुर्गापुर ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ज" पर मिलती है ।

ज-झ रेखा, दुर्गापुर ग्राम में प्लाट स. 76, 75, 74, 72, 70, 46, 45 में से होकर जाती है और सिनहाला ग्राम में से होकर जाती है, नाला पार करती है और फिर प्लाट स. 73, 74, 75, 76 से में होकर जाती है और फिर पदमापुर ग्राम में प्लाट स. 126, 159 में से होकर जाती है, मोटा घाट नाला पार करके प्लाट सं. 158, 134, 143/3, 144, 143/1, 142 में से होकर जाती है और लोक निर्माण विभाग की चन्द्रपुर तारोबा सड़क की पूर्वी सीमा पर बिन्दु "झ" पर मिलती है।

झ-अ रेखा, लोक निर्माण विभाग की चन्द्रपुर-तारोबा सड़क की पूर्वी सीमा के साथ-साथ पदमापुर ग्राम में से होकर जाती है और बिन्दु "अ" पर मिलती है ।

अ-ट रेखा, पदमापुर ग्राम से होकर जाती है, लोक निर्माण विभाग की चन्द्रपुर तारोबा सड़क को पार करती है और फिर प्लाट सं. 3, 70, 69, 68, 67, 66, 65 गाओधान आबादी की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और प्लाट स. 61, 71/2 और 71/3 की सम्मिलित सीमा पर बिन्दु "ट" पर मिलती है ।

ट-ठ रेखा, पदमापुर ग्राम में प्लाट स. 71/2 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और फिर प्लाट स. 71/3 में से जाती है, सड़क पार करती है और प्लाट स. 80, 86 की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ किटाडी ग्राम में से होकर जाती है और बिन्दु "ठ" पर मिलती है।

ठ-ड रेखा, प्लाट स. 86 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ किटाडी ग्राम में में होकर जाती है, सड़क पार करती है, भागतः प्लाट स. 2 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और भागतः उसमें से होकर जाती है और फिर प्लाट सं. 13 में से होकर जाती है और इरई नदी के पूर्वी किनारे पर बिन्दु "ड" पर मिलती है ।

ड-क रेखा, इरई नदी के पूर्वी किनारे के साथ-साथ किटाडी ग्राम से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है ।

[सं. 43019/22/84-सी. ए.]

रामय सिंह, अवर सचिव,

S.O. 2640.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Coal S.O. No. 444 dated the 28th January, 1984 under sub-Section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) and published in the Gazette of India in Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 11th February, 1984, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 182.73 hectares (approximately) or 451.54 acres (approximately) of the lands in locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in part of the said land;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the Lands measuring 160.48 hectares (approximately) or 396.54 acres (approximately) in All Rights as described in the Schedule appended hereto.

Note—1 : The plans bearing No. C-1(E)III/JR/283-0684 dated 12-6-84 of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Collector, Chandrapur (Maharashtra) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Western Coalfields (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur—440001 (Maharashtra).

Note—2 : Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act, which provide as follows :

Objections to Acquisition :

"8(1)—Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

EXPLANATION :—

It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under su-bsection (1) shall be made to the Competent Authority in writing and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as he thinks necessary, either makes a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of Section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him for the decision of that Government.

(3) For the purpose of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act."

Note—3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta has been appointed by the Central Government as the Competent Authority under the Act."

SCHEDULE 'A'

PADMAPUR EXTENSION BLOCK

WARDHA VALLEY COALFIELD

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASHTRA)

ALL RIGHTS (REVENUE LAND)

Sl. No.	Name of village	P.C. No.	Tehsil & District	Area in hectares	Remarks
1.	Kitadi	11	Chandrapur	9.87	Part
2.	Padmapur	11	,,	73.09	Part
3.	Durgapur	10	,,	5.48	Part
4.	Sinhala	11	,,	41.74	Part
	Total Area :		130.18 hectares	(approximately)	
	OR		321 68 acres	(approximately)	

SCHEDULE 'A1'

PADMAPUR EXTENSION BLOCK

WARDHA VALLEY COALFIELD

DISTRICT CHANDRAPUR (MAHARASTHRA)

ALL RIGHTS (FOREST LAND)

Sl. No.	Name of village	P.C. No.	Tehsil & District	Area in hectares	Remarks
1.	Kitadi	11	Chandrapur	3 50	Part
2.	Padmapur	11	,,	26.80	Part
	Total Area :		30.30 hectares	(approximately)	
	OR	74.86	acres	(approximately)	
Grand Total (A+A1)=160.48 hectares				(approximately)	
	OR		390.54 acres	(approximately)	

Plot numbers to be acquired in village Kitadi :
1, 2 (Part), 13 (Part), 14, 80(Part), 81 (Part), 85/2 (Part), 86 Abadi (Part), 87 (Part), 88/1, 88/2 and Road (Part).

Plot numbers to be acquired in village Padmapur :
71/1, 71/2, 71/3 (Part), 72, 73, 74, 75 (Part), 76 (Part), 77 (Part), 124 (Part), 125 (Part), 126 (Part), 127 to 129, 130 (Part), 131 to 133, 134 (Part), 135, 142 (Part), 143/1 (Part), 143/3 (Part), 144 (Part), 145 to 148, 149 (Part), 150 to 153, 154 (Part), 155, 156 (Part), 157, 158 (Part), 159 (Part), Nallah (Part), Abadi (Part) and Road (Part)

Plot numbers to be acquired in village Durgapur :
45 (Part), 46 (Part), 70(Part), 71, 72 (Part), 74 (Part), 75 (Part), 76 (Part).

Plot numbers to be acquired in village Sinhala :
59 (Part), 62 (Part), 63 64, 65/1, 65/2, 67 to 72, 73 (Part), 74 (Part), 75 (Part), 76 (Part), 77, 78 (Part), 79 to 84 85 (Part), 87 (Part), 88 (Part), 90 (Part), 91 (Part), 92 (Part), 93 (Part), and Nallah (Part).

Boundary Description :

A–B : Line starts from eastern bank of Erai river and passes through village Kitadi along the northern boundary of plot numbers 13, 14 2, 1, crosses road, 88 1, then in plot numbers 87, 85/2, 86 Abadi, 80, 81 and meets in plot number 81 at point 'B'.

B–C : Line passes through village Kitadi in plot numbers 81, 80 and proceeds through village Padmapur, crosses road, then in plot numbers 76, 77, 75, Crosses Chandrapur-Taroba P.W.D. road and then in plot numbers 149, 154, Abadi, 156 and meets in plot number 156 at point 'C'.

C–D : Line passes through village Padmapur in plot number 156, corsses road, proceeds prtly along the northern b undary of plot number 131, then in plot numbers 130, 124, 158 and meets on the centre point of Motaghat Nallah at point 'D'.

D–E : Line passes through village Padmapur from the centre.

F–G : Point of Motaghat Nallah and in plot numbers 159.

H : 125, then proceeds through village Sinhala in plot numbers 78, 85, 87, 88, 91, 90, 93,92, then along the eastern boundary of plot numbers 67, 65/1 and in plot numbers 62, 59, crosses Nallah, then proceeds along the common boundary of villages Sinhala and Durgapur and meets at point 'H'

H–I : Line passes through village Durgapur in plot numbers 76, 75, 74, 72, 70, 46, 45 and proceed through village Sinhala, crosses nallah, then in plot numbers 73, 74, 75,76 and then through village Padmapur in plot numbers 126, 159, crosses Motaghat Nallah, 158, 134, 143/3, 144, 143/1, 142 and meets on the eastern boundary of Chandrapur-Taroba P.W.D. road at point 'I'.

I–J : Line passes through village Padmapur along the eastern boundary of Chandrapur-Taroba P.W.D. road and meets at point 'J'

J–K : Line passes through village Padmapur, crosses Chandrapur-Taroba P.W.D. road, then proceeds along the northern boundary of Gaothan Abadi plot numbers 3, 70, 69, 68, 67, 66, 65 and meets on the common boundary of plot numbers, 61, 71/2 and 71/3 at point 'K'.

K–L : Line passes through village Padmapur along the western boundary of plot number 71/2, then in plot number 71/3, crosses aroad and proceed through village Kitadi along the common boundar of plot numbers 80, 86 and meets at point 'L'.

L–M : Line passes through village Kitadi along the northern boundary of plot number 86, crosses road, then partly along and partly through northern boundary of plot number 2, then in plot number 13 and meets on the eastern bank of Erai River at point 'M'.

M–A : Line passes through village Kitai along the eastern bank of Erai river and meets at the starting point 'A'.

[No. 43019/22/84-CA]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली 26 अप्रैल 1985

(वाणिज्यिक नौवहन)

का आ 2641 —वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (नौवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का आ 2889 दिनांक 31 जुलाई, 1982 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार श्री बी के राव आई ए एस के स्थान पर श्री एन चक्रवर्ती को नौवहन महानिदेशक नियुक्त करती है।

[सं एम डब्ल्यू/1-एमडीएस (6)/85 एम ए]

पी वी राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th April, 1985

(MERCHANT SHIPPING)

S O 264 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and in supersession of Notification of the Government of India Ministry of Shipping and Transport (Shipping Wing) No S O 2889 dated 31st July, 1982, the Central Government hereby appoints Shri N Chakraborty as the Director General of Shipping vice Shri B K Rao, I A S

[No SW I MDS(6)|85-MA]

P V RAO, Jt Secy

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 25 मई, 1985

का. आ 2642—चापरमुख सिलघाट रेलवे लाइन और कटखाल लालाबाजार रेलवे लाइन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1982 की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे माली गाव को इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियों, इस अधिनियम की धारा 14, 15 और 16 के अन्तर्गत की शक्तियों को छोड़कर का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

भारत के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से।

ए एन बाचू, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi the 25th May, 1985

S O 2642 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Chaparmukh Silghat Railway Line and the Katakhal Lalabazar Railway Line (Nationalisation) Act 1982 the Central Government hereby authorises the Geneal Manager, North East Frontier Railway Maligaon to exercise all the powers under the Act which are exercisable by the Central Government excepting those under sections 14, 15 and 16 of the Act

A N WANCHOO, Secy Railway Board
for and on behalf of the President of India

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 1985

का आ 2643 —औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम (पंजाब क्षेत्र) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-1985 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 21st May, 1985

S O 2643 —In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, (Punjab Region) and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th May, 1985

BEFORE SHRI I P VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No I D 15 of 1984

PARTIES

Employers in relation to the management of Food Corporation of India

AND

Their Workmen

APPEARANCES

For the Employers —Sh B L Laroiya

For the Workmen —Sh P K Singla

INDUSTRY—Food Corporation of India STATE—Punjab

AWARD

Dated the 8th of May, 1985

The Central Govt, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act 1947, vide their Order No L—42011 (12)|83 D II (B)|D IV (B)|D (V) dated of 5th of May, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication —

> "Whether the management of FCI in relation to the Dist Manager FCI, Hoshiarpur in justified in refusing night duty allowance, for the night duty performed by its Class IV Employees ? If not, to what relief are the Class IV employees entitled and from which date ?"

2 The petitioner Union represents the Class IV employees of the Respdt Corporation posted at its various depots in Punjab including District Hoshiarpur It was complained that the Management was not paying Night Duty Allowance to them despite the fact that they were made to work at odd hours of the night and even the rules required such payment They, therefore raised a demand for the appropriate relief However the Management was found unresponsive despite the intervention of the A I C (C) and hence the Reference

3 The Management resisted the proceedings on the sole ground that there was no legitimacy in it

4. Keeping in view the comprehensive nature of the terms of reference, the parties were called upon to adduce evidence in support of their respective versions, without going through the drill of framing formal issues. Thus the petitioners' examined their General Secretary Sh. P. K. Singla whereas the Management produced their Dy. Manager (IR) D. V. S. Raju. Of course, the petitioners filed a few document also whose authenticity was not challenged from the opposite side.

5. On a careful consideration of the entire available data and hearing the parties, I am not inclined to sustain the petitioners' cause for the simple reason that on the showing of their own authorised representative Sh. Singla their primary engagement is under the watch and Ward staff, who operate round the clock in three different shifts. To be precise, they work for only 8 hours duration per day It is an entirely different thing that such shifts keep on rotating with the obvious result that nobody is permanently deployed in any particular shift.

6 Reliance was placed on the Circular Exh. W-2 dated 6-11-75 with the contention that after a long drawn out struggle with the Management they had succeeded in extracting assurance that all Class III and IV employees put on night duty would be paid Night Duty Allowance also. I am attain the petitioners' have tried to read too much in between the lines of the Circular because even a cursory scrutiny thereof would leave no manner of doubt that it benefits only such of the Class III & IV employees who are put on emergency duty in the Control room consecutively for more than six nights. In our case, under the weight of oath, in his cross-examination, Sh. Singla conceded that "the petitioners' do not perform duty in the Control room during the emergency for the simple reason that there is no control room."

7. In my considered opinion his admission on such a vital aspect of the issue takes the very wind out of the petitioners' sails because it clearly implies that there is neither any control room nor any occasion for them to be deputed there so as to invoke the philosophy of the aforesaid Circular Exb. W-2 otherwise too, in the very nature of things a watchman is often required to be on duty after the usual office hours, though in our case the petitioners are kept on rotation by the Management in differant shifts.

8. Be that as it may for the reasons recorded above for want of merit, I reject the petitioners demand and on sustaining the Management's action in declining them any Night Duty Allowance, return my Award accordingly.

Chandigarh.

8-5-1985.

I. P VASISHTH. Presiding Officer.

[No. L-42011 (12)|83 D.II (B)|D. IV (B)|D. V.]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 23 मई, 1985

का. आ 2644.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि की इडस्ट्री कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21-5-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd May, 1985

S.O. 2644. --In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Industry Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, and their workmen, which was received by the Central Goernment on the 21st May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT

Shri I. N. Sinha,

Presiding Officer.

Reference No. 45 of 1984

In the Matter of Industrial Disputes under Section 10(1) (d) of the I. D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Industrial Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited, and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar : INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 15th May, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012 (110)|84-D.III(A), dated the 30th July, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Industrial Colliery of M|s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Dhansar, Distt. Dhanbad in denying regularisation as Dumper Khalasi to Shri Hajrat Mia and in stopping him to work as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83 is justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled and from what date ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Hajrat Mia was originally appointed as Miner|Loader in Group VA in Industry Colliery of M/s. B.C.C. Ltd. The concerned workman possessed valid driving licence and as such he was directed by the management to work as Dumper Khalasi and he was assured that he would be promoted as Dumper Operator. In pursuance of the said direction of the management the concerned workman has been regularly working as Dumper Khalasi since January, 1983 and was getting the wages of Cat. II. He had put 240 days attendance as Dumper Khalasi and as such the management being satisfied with his performance regularised him as Dumper Khalasi in Cat. II with effect from 20-8-83. The concerned workma was getting underground allowance when he was work-

ing as Miner/Loader but the said underground allowance was stopped since the concerned workman started working as Dumper Khalasi. The concerned workman had accepted Cat. II wages in place of Group V wages seeing the future promotional avenues and the assurance of the management for further promotion as Dumper Operator. After sometime the concerned workman represented before the management for his proper categorisation. The maangement with an ulterior motive stopped the concerned workman from working as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83 illegally without giving any reason and notice under Section 9A of the Industrial Disputes Act. The action of the management in stopping him from work as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83 was illegal and against the principles of natural justice. The concerned workman is an active member of Bihar Colliery Kamgar Union and the local management is biased and prejudiced against the members of Bihar Colliery Kamgar Union and for that reason the workman was stopped to work as Dumper Khalasi with a motive to victimise him. The concerned workman and the union protested against the illegal and arbitrary action of the management but without any effect. Thereafter the union raised an industrial dispute before the ALC(C), Dhanbad for conciliation but the same ended in failure and thereafter the Government of India, Ministry of Labour referred the said dispute for adjudication by this Tribunal. The concerned workman is legally entitled to be regularised as Dumper Khalasi with effect from 20-8-83 with all consequential benefits.

The case of the management is that the concerned workman was employed as permanent miner/loader in Group VA and was paid on the piece rate basis according to the output given by him from time to time. The concerned workman by an application dated 14-3-83 and another application intimated the management that he has got valid licence for driving light vehicles and offered himself to work as Dumper Khalasi expressing his desire to accept the wages payable to the workmen employed as Dumper Khalasi and requested the management to employ him as Dumper Khalasi. The management were in need of temporary Dumper Khalasi and as such the concerned workman was allowed by Office order dated 20-8-83 to work as Dumper Khalasi with a condition that he shall be paid Cat. II wages. The concerned workman reported for duty and was allowed to work in the third shift as Dumper Khalasi from 21-8-83 for the first time after the said order was passed. The concerned workman worked as Dumper Khalasi in Cat. II till 12-11-83 for a period of less than 3 months only. He was neither appointed on probation nor he had even worked for 3 months as Cat. II Dumper Khalasi. The concerned workman had not been appointed in any permanent vacancy as Dumper Khalasi and as such he was reverted back to his original job of Miner. The concerned workman had neither completed 240 days attendance as Dumper Khalasi nor he was employed as Probationary Dumper Khalasi to fill in the post of permanent vacancy and as such he did not acquire any right to work as Dumper Khalasi and was rightly reverted back to his original job of Miner/loader with effect from 12-11-83 and there was no question of his regulaiton as Dumper Khalasi. The action of the management in stoping the concerned workman to work as Dumper Khalsi and reverting him back as Miner/loader is fully justified and he is not entitled to any relief. The management had never assured the concerned workman to promote him as Dumper Operator. He was allowed to work on his own request as Dumper Khalasi with effect from 21-8-83 but he, was never regularised as Dumper Khalasi with effect from 20-8-83. The management had no reason to victimise the concerned workman and the said allegation is false. Since the concerned workman was not appointed on probation to fill any permanent vacancy and was allowed to work as Dumper Khalasi on his request and as such he was reverted back to his old job when his services were no more required as Dumper Khalasi and in the circumstances there was no question of giving notice under Section 9A of the I.D. Act. On the above plea it has been submitted on behalf of the management that the Award be made in their favour.

Two questions arise for determination in this case in accordance with the schedule of the order of reference. The first point to be considered is whether the action of the management in denying regularisation as Dumper Khalasi to the concerned workman is justified and the other point for consideration is whether the action of the management in stopping the concerned workman to work as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83 is justified.

The management have examined three witnesses in support of their case and the workmen have examined one witness namely, the concerned workman Hajrat Mia in support of the case. The management have further produced some documents which have been marked Ext. M-1 to M-4. No document has been exhibited on behalf of the workmen.

Ext. M-1 dated 20-8-83 is an Office order under the signature of Shri A. K. Singh, Superintendent of Industry Colliery addressed to the concerned workman as Miner Industry Colliery. MW-1 A.K. Singh has stated that he is working as Superintendent of Industry Colliery and Office order dated 20-8-83 Ext. M-1 was issued by him allowing the concerned workman to work as Dumper Khalasi wth effect from 20-8-83. He has stated that before that the concerned workman was working as Miner/loader. According to him the concerned workman had applied for, working as Dumper Khalasi. It is the admitted case of the parties that the concerned workman was reverted back as Miner/loader with effect from 12-11-83 and since then the concerned workman is working as Miner/loader. MW-1 has stated that he had not assured the concerned workman that he would be employed permanently as Dumper Khalasi.

Ext. M-2 is a petition by the concerned workman dated 14-3-83 to the Superintendent of Industry Colliery for his appointment as Dumper Khalasi. It will appear from this petition that the concerned workman was working as Miner in Industry Colliery at the time when he had filed this petition before the management. It is stated in his petition before the management that he has come to know that some posts of Dumper Khalasi are lying vacant and he intends to work in that post of Dumper Khalasi. It is further stated that the concerned workman possessed driving licence for light vehicles and that

he knows the work of Khalasi. It is also stated that he is ready to accept the wages of the Cat. II of Khalasi if he is appointed as Dumper Khalasi. MW-2 N.K. Sinha was a senior personel Officer at Industry Colliery. He has stated that this petition Ext.M-2 bears his endorsement and that the concerned workman had put his LTI in his presence. The concerned workman WW-1 has stated in his cross-examination that he had filed a petition Ext.M-2 for giving him the job of Dumper Khalasi. He has also accepted in his evidence that he had stated in his petition Ext. M-2 that he will be working in the Category of Khalasi. It is, therefore, clearly admitted by the concerned workman that Ext.M-2 was filed by the concerned workman before the management for Dumper Khalasi and that he was ready to accept the wages of Cat. II if he was appointed as Dumper Khalasi. It will also appear from this petition that the concerned workman was not working as Dumper Khalasi prior to the filing of this petition Ext. M-2 dated 14-3-83. Ext.M-1 dated 20-8-83 shows that the management had favourably considered the petition of the concerned workman and thereafter permitted him to work as Dumper Khalasi in Cat.II Wages. In iew of the facts stated in Ext.M-2 it is clear that the concerned workman had not worked as a Dumper Khalasi since January, 1983 as stated by him in his evidence as WW-1. It is stated by WW-1 that he was regularised by the management as Dumper Khalasi on 20-8-83 but the Office order dated 20-8-83 does not show that the concerned workman was regularised from 20-8-83 but he was only permitted to work as Dumper Khalasi from 20-8-83. There is no other paper on the record to show that the concerned workman had worked as Dumper Khalasi prior to the Office order Ext.M-2 dated 20-8-83. I hold therefore that the concerned workman was allowed to work as Dumper Khalasi from 20-8-83 and that he had not worked as Dumper Khalasi prior to that date and as such it cannot be said that the concerned workman had worked earlier as Dumper Khalasi and was regularised as Dumper Khalasi from 20-8-83.

Admittedly, the concerned workman was stopped from working as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83 and thereafter he is working in his old job of Miner/loader. The concerned workman has not completed 24 days attendance in a year prior to his stoppage of his work as Dumper Khalasi as he had worked as Dumper Khalasi only for the period from 21-8-83 to 12-11-83. Ext. M-3 and M-4 are Bonus Registers of Industry Colliery which will also show that the concerned workman had not completed 240 days as Dumper Khalasi. As the concerned workman did not complete regular and continuous attendance of 240 days as a Dumper Khalasi, the demand of the concerned workman for his regularisation as Dumper Khalasi does not appear to be justified and this point referred to in the schedule of the order of reference has to be decided in favour of the management.

The next question to be determined is whether the management was justified in stopping the concerned workman to work as Dumper Khalasi with effect from 12-11-1983. The case of the management is that the concerned workman was temporarily appointed to work as Dumper Khalasi and that when his services were no more required he was reverted back to his old job of Miner/loader. For this purpose the most important document is the Office order dated 20-8-83 which is the order by which the concerned workman was allowed to work as Dumper Khalasi. On perusal of Ext. M-2 it will appear that there is no mention of the fact that the concerned workman was being appointed for a temporary period for any limited period as Dumper Khalasi and on reference to the petition of the concerned workman Ext. M-2 it will appear that there was some vacancies of Dumper Khalasi for which he had applied and had agreed to accept the wages of Cat. II and on those facts the concerned workman was appointed as Dumper Khalasi vide Ext. M-1. MW-1 in his cross-examination has stated that Miner/loader in Group VA are entitled for underground allowance and when the concerned workman was employed as Dumper Khalasi in Cat. II his underground allowance was stopped. He has stated that the concerned workman had not been engaged as Dumper Khalasi in place of sickness of any other Dumper Khalasi. He has further stated that the period for which the concerned workman was engaged as Dumper Khalasi was not stated in Ext-M-1. Thus from Ext.M-1 and the evidence of MW-1 it will appear that the concerned workman had not been appointed in a temporary vacancy. The point has further been elucidated in the evidence of MW-1. He has stated that there were four Dumpers in the mines on 20-8-83 and that on 1-1-84 there were four dumpers but only three were in use. He was unable to say, the number of permanent dumper Khalasi in Industry Colliery. MW-2 who is a Sr. Personnel Officer has stated that he does not remember if there were nine permanent Dumper Khalasi from August to November, 1983 in Industry Colliery and that out of them five were promoted as Dumper Operator in 1983 and that the concerned workman was posted in place of the promoted Dumper Operator. Thus there is no positive evidence adduced on behalf of the management to show that the concerned workman was not appointed in a permanent vacancy. The concered workman as WW-1 has given a positive evidence on this score. He has stated that in 1983 four dumper were being operated which was still in operation. He has further stated that all the four dumpers were being operated in all the three shifts and there were 12 dumper operators and 10 dumper Khalasies to do the job. According to him at present there are only seven dumper Khalasies and the shortage of dumper Khalasies is made up, by engaging the workmen from other places by the management. He has, also stated that one Dumper Khalasi always accompany the dumper operator. He has also stated that he was appointed in regular vacancy of a Dumper Khalasi. Thus the evidence of WW-1 positively shows that he was apointed as Dumper Khalasi in a permanent vacancy and I do not find any material on the record to show that the concerned workman was appointed as a Dumper Khalasi on temporary basis. Taking the entire evidence into consideration I hold that the concerned workman was appointed as Dumper Khalasi in a permanent vacancy.

Admittedly, no notice was given to the concerned workman when his work as Dumper Khalasi was stopped and he was asked to go back to work in his old job of Miner/loader. It will appear that the

concerned workman had gien his choice for being appointed as a Dumper Khalasi in Cat. II by giving up the job of Miner|loader where his total wages were more than what he was getting as Dumper Khalasi. Now after the management accepted his prayer and allowed him to work as Dumper Khalasi the service condition of the concerned workman had changed and by asking the concerned workman to go back as Miner|loader, from wages of piece rated workman in Group VA would be a complete change in his service conditions as he was working in a time rated job in Cat.II as Dumper Khalasi. It was imperative on the part of the management to give him notice under Section 9A of the I.D.Act as there was a complete change of the condition of service and on his being transferred as Miner/loader from the post of Dumper Khalasi Cat. II. The stoppage of work of the concerned workman as Dumper Khalasi from 12-11-83 and asking him to work as Miner|loader from that date was an illegal order as no employer who proposes to effect any change in the condition of service aplicable to any workman shall effect such change without giving the workman a notice in the prescribed manner of the nature of change proposed to be effected. The order of the management, therefore, stopping the concerned workman from, working as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83 and asking him to work as Miner| loader is not justified and the concerned workman is entitled to continue as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83.

In view of the discussion made above I hold that the action of the management of Industry Colliery of M|s. B.C.C.Ltd. in denying regularisation as Dumper Khalasi to the concerned workman Shri Hajrat Mia is Justified. I further hold that the action of the management of Industry Colliery of M|s. B.C.C.Ltd. in stopping the concerned workman Shri Hajrat Mia to work as Dumper Khalasi with effect from 12-11-83 is not justified, and the concerned workman is entitled to continue as Dumper Khalasi from 12-11-83. The management is further directed to pay the difference of wages, if any, which the concerned workman has received as Miner|loader and the wages of Cat.II which he was entitled to get from 12-11-83.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-20012(110/84-D.III (A)]

A.V.S.SARMA, Desk Officer

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 मई, 1985

का. आ 2645.:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-5-85 को प्राप्त हुआ था।

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 22nd May, 1985

S.O. 2645.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India, and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th May, 1985.

BEFORE SHRI O.P. SINGLA, RESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 208|77

In the matter of dipute between :

Shri D.L. Mazumdar s|o late Shri H. L. Majumdar, r/o F-46/2, Kotla Mubarakpur, New Delhi.

Versus

The Management of Central Bank of India, New Delhi.

APPEARANCES :

Shri S. S. Sethi for the Management.
Shri Tara Chand Gupta for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour on 16-12-77 vide Order No. L-12012|62|77-D.II.A. made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of the Central Bank of India, New Delhi in dismissing Sri D. L. Majumdar, Clerk at their Janpath Branch of the Bank w.e.f. 25-10-75 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Shri D.L. Majumdar joined as clerk in Central Bank of India on 10-3-47 as complaint was lodged with police by the Bank and he was suspended by order dated 17-6-71 after his arrest on 2-6-71 in the case under sections 409|420|467|468|471|477-A I.P.C. His suspensinon was pending completion of investigation in the case.

3. The challan was presented against the workman in the court of Metropolitan Magistrate only on 14th March, 75 and the case FIR/865/71 P.S. Parliament Street, New Delhi was pending before Shri Brijesh Kumar, M.M. New Delhi in November, 1963.

4. The Management did not start any disciplinary proceedings against the workman but dismissed him from service on 25-10-75 with dismissal order in the following terms :

"We regret that we are hereby compelled to intimate to you that you are hereby dismissed from the service.

You are aware that criminal trial is pending against you and during pendency thereof. We cannot take departmental action against you. As you are due to retire on and from 18-12-75. and as the criminal trial is not likely to be over and even if the same is over, your departmental enquiry cannot be over, we are left with no other alternative but to dismiss you from service with immediate effect.

Your dues as per law will be paid to you after deducting there from the amount embezzled by you. Since there is no amount payable to you, you are hereby requested to make payment of the balance amount of Rs. 1,34,431.64 to us on or before 25-11-75."

5. This action was taken by the Management because the workman was due to retire on and from 18-12-78 and the Management did not think it proper that workman whom it believed to be guilty of the offences mentioned above should retire in the ordinary course.

6. The workman raised an Industrial Dispute which has been referred to this Tribunal as indicated earlier. The first question that was raised is whether the Management can justify its action of dismissal before this Tribunal by giving him the chargesheet on the basis of the facts in the FIR already lodged against him on the basis of which criminal trial is pending in the Criminal court or whether the Management is precluded from doing so. The preliminary issue framed is in the following terms :

"Whether in case of criminal proceedings at the instance of Management pending, a departmental enquiry| enquiry by the Tribunal is admissible.

7. I have had the benefit of examining the written arguments filed by the parties.

8. The Management's case is that the Supreme Court in Kitz Theatres Private Ltd. Vs. its workmen, reported in 1962 II LLJ at page 498 ruled that in case of no enquiry or defective enquiry by the Management, the Management is entitled to lead evidence before the Tribunal and the whole issue is before the Tribunal for adjudication on the evidence to be led by the parties before the Tribunal. This position is said to be reiterated by the Supreme Court in later judgements in (i) M|s Bharat Sugar Mills Ltd. Vs. Sh. Jai Singh & Ors. 1961 II LLJ, page 644, (ii) Punjab National Bank Ltd. Vs. its workmen 1959 II LLJ, page 666, (iii) Workmen of Motipur Sugar Factory Pvt. Ltd. Vs. Motipur Sugar Factory, 1965 II LLJ, page 162, (iv) State Bank of India Vs. R.K. Jain & Ors. 1971 II LLJ, page 599, (v) Delhi Cloth & General Mills Ltd. Vs. Ludh Budh Singh, 1971-I-LLJ, page 180, and (vi) Workmen of Firestone Tyre & Rubber Co. Vs. The Management, 1973 I LLJ, page 278.

9. In respect of para 19.4 of the Bipartite Settlement dated 19-10-66 no enquiry could be held by the employer during the pendency of the criminal trial and employer could not hold enquiry that the Tribunal could not do so, the Management contention is that it is only the Management that was precluded from holding an enquiry during pendency of criminal trial and the bar did not apply to the Industrial Tribunal from discharging its functions when the dispute had been referred to it to examine the justifiability of the action of the Management. The Settlement was binding only on the parties and not on the Tribunal and even the findings of the Criminal court are not binding on this Tribunal.

10. In respect of the plea that since the employer did not hold enquiry during the period intervening between the date of expiry of one year from the filing of complaint with the police and the commencement of trial, the Management's case is that during that period there was temporary lifting of the bar in respect of departmental enquiry but the enquiry itself was totally impossible because of the documents in respect of the enquiry both of the bank and of the postal authorities were with the police who had collected them from the bank and the postal department during course of investigation and the Management could not hold the enquiry at all and under para 19.4 even if the enquiry is commenced it would have to be stopped from the commencement of criminal trial. In any case the Management view is that there is no bar whatsoever for the Tribunal to decide the matter on evidence before it.

11. In regard to the case cited by the workman Hindustan Steel Limited Workmen Vs. Hindustan Steel Ltd. and others reported in 1985 Current Labour Reports Vol. I page 193, the Management differentiated that case as one where standing Orders 32 was to be interpretted in the case of misconduct of an employee and was not a case dealing with the question whether the employer could justify dismissal by leading evidence for the first time before the Industrial Tribunal para 10 of the said judgment is referred to where the Supreme Court observed that there are two course of options first to permit the Management to hold the disciplinary enquiry and to come to its own decision and the second to remit the matter to the Labour Court to permit the Management to lead evidence to substaniate the charges if it was entitled to do so under law.

12. In my opinion the Management cannot lead evidence and issue the chargesheet to the workman before his Tribunal. The reasons are plain.

13. The Management had the right and opportunity to start enquiry by issuing chargesheet to the workman when the criminal trial did not start one year after the lodging of the report to the police. It was a default on the part of the Management and the Bipartite Settlement did not bar enquiry by the Management. The Management could refer to the Bipartite Settlement and its power to hold enquiry and could request the police to produce the relevant documents before it in the enquiry. There is no presumption that the police would not have produced the documents before the Enquiry Officer at the request by the bank-Management when the bank-Management was within its rights to hold the enquiry under Bipartite Settlement. However, if the bank was stalled in that enquiry by the police not co-operating by producing relevent documents before the Enquiry Officer at the request by the Management, a peculiar situation would have arisen and then in that event this Tribunal would certainly have allowed the Management to prove its case against the workman before this Tribunal.

14. What has been referred to this Tribunal is the justifiability of the action of the Management. The Management could take appropriate action by way of domestic enquiry during a period of three years from June, 72 to February, 75, but it failed to do so and the plea raised by it that the police would not have produced the documents before the Enquiry Officer is presumptuous and not factual. When such is the case, and the Management failed to hold enquiry in accordance with the Bipartite Settlement, it will be unfair for this Tribunal to hold enquiry against the workman when the criminal trial of the workman is also pending on the same charges.

15. The Delhi High Court in Civil Writ No. 1088 of 1969 decided on 12-11-70 in workmen of Indian Overseas Bank Vs. Indian Overseas Bank and another reported in 1973(1) LLJ. 316, through Hon'ble Mr. Justice Rajinder Sachar, has ruled that the Management need not first prosecute the workman or get him prosecuted when he appears to be guilty of an offence punishable under the I.P.C. Their interpretation of para 581(3) of Shastry Award is that the Management has the option to proceed against the employee either in a criminal court or departmentally, and the Management need not wait for his being put on trial or prosecuted within a period of one year of commission of the offence. Accordingly, the Management could have decided to take disciplinary action against the workman without reporting the matter to the police|Criminal court, but it failed to do so.

16. In the circumstances above, the action of the Management in dismissing the workman from service without enquiry is unjustified, and this Tribunal will not allow the Management to issue a charge-sheet and hold enquiry for the first time before this Tribunal. The action of the Management in dismissing the workman from service w.e.f. 25-10-75 in the cirucumstances of the case is neither legal nor justified. The workman is entitled to relief and he shall be deemed to have retired in the normal course on 18-12-75 and to advantages on that basis. This, however, is not to say that the workman will suffer no adverse consequences of conviction in the criminal court if any ensued in respect of his employment but so far as this Tribunal is concerned, it refuses to allow the Management to hold enquiry before this Tribunal and further holds that order of dismissal of the workman in question passed on 25-10-75 is illegal and unjustified, and the workman must be deemed to have retired on and from 18-12-75 ignoring the order of dismissal dated 25-10-75. The Award is made accordingly.

Further is is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer.

[No. L-12012|62|77-D.II(A)|Part I]

का. आ. 2646.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, बम्बई, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-5-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2646.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL

TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2|33 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Nagpur,

and

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employers : Shri A. E. Kulkarni, Officer M.M.G. Sc. II, Regional Office, State Bank of India, Nagpur.

For the workmen : Shri S. D. Phadke, President, SBI & S. B. Employees' Union, Nagpur.

Bombay, dated athe 1st May, 1985

AWARD PART I

Termination of services of the workman in question on the ground that he was negligent in driving the vehicle of the State Bank of India whereby it met with an accident and secondly on the ground that the workman was found driving the vehicle while under the influence of liquor is the subject matter of the present reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act (Order of reference number being L-12012|200|84-D. II(A) dated 12-3-17985). There was also an allegation that some unauthorised persons were allowed to travel by the vehicle.

2. The facts are not much in dispute. The incident is alleged to have occurred on 7-8-1981 as a result of which there was a complaint to the Police who taking congnizance of the said complaint lodged chargesheet against the workman after investigating the offence, in which criminal proceeding ultimately the workman was acquitted by the judicial Magistrate who heard the complaint. After this acquittal the State Bank of India authorities chargesheeted the workman appointed an enquiry officer who on going through the Police Statements, statements recorded during the criminal trial and relaying upon the certificate issued by the Medical Officer, without calling any witness for adducing evidence and without giving any opportunity to the workman to challenge the statements and the certificate, arrived at his own conclusion, held the workman guilty of the misconduct as alleged, on the strength of which finding the competent authority decided to terminate the services of the workman.

3. Certainly even after the acquittal of the workman the Bank was entitled to hold an enquiry. There is no doubt about it but once it was decided to hold fresh domestic enquiry, the Enquiry Officer could not have relied upon the statements recorded during the Police investigation or the statements recorded before the judicial magistrate and could not have held the workman guilty especially when on the strength of the very statements the judicial authority had come to the conclusion of not guilty. If the matter was to be probed into again it was necessary to cite the witnesses before the Enquiry Officer giving the workman opportunity to cross-examine them and the Medical Officer who issued the certificate and also give the workman an opportunity to adduce his evidence and then the Enquiry Officer could have differred from the final conclusions arrived at by the Judicial Magistrate, if in his opinion the circumstances and evidence before him warranted such conclusion. Without following such procedure a curious procedure has been followed and thereby deprived the workman of an opportunity to defend himself. In my view therefore in the light of these circumstances, the enquiry is vitiated, cannot be held to be valid and therefore must be ignored.

4. Although such is the decision since there is a request by the Bank to give them opportunity to establish the misconduct before the Tribunal, said opportunity has to be given and as such the matter is fixed for evidence which the Bank is desirous to adduce for bringing home the charge against the workman.

5. Since the enquiry is being set aside, having been found to be vitiated, the status quo ante at the time of discharge order will have to be restored namely that the workman who was placed under suspension shall be deemed to continue to be under suspension till final order in the present reference.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-12012|200|84-D. II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 23 मई, 1985

का. आ. 2647.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, देना बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, धनबाद, के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 21-5-85 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 23rd May, 1985.

S.O. 2647.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Dena Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 21st May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 87 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)-(d) of the I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Dena Bank, Patna and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri I. P. Singh, Advocate.
On behalf of the workmen—Shri T. K. Prasad and Shri V. N. Sahay, Advocates.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Banking

Dhanbad, the 14th May, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-12012|100|84-D.II A dated the 6th December, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Dena Bank, Calcutta in relation to their Bakhtiarpur Branch, Distt. Patna in dismissing from service Shri Ram Bali Singh, Cashier-cum-Clerk with effect from 21-12-1982 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Rambali Singh was appointed as a Clerk in Dena Bank on 8-10-68 and was posted at Bhawanipur Branch of Dena Bank at Calcutta. Subsequently he was transferred to Howrah Branch of the Bank and thereafter in November, 1971 he was transferred to Bakhtiarpur Branch of the Bank as Cashier-cum-Clerk till he was dismissed by the order dated 21-12-82. There was no complaint at any time in respect of his work or behaviour since his appointment. In recognition of his efficiency and good performance the concerned workman was allotted the work of a paying cashier in the year 1978 and for that job he was allowed special allowance of Rs. 120 per month. He was an active member of Dena Bank Employees Union, Bihar State affiliated to Bihar Provincial Bank Employees Association. In 1973 he was elected as Vice President of the Bihar State Dena Bank Employees Union and was being re-elected every year as Vice President till 1980. As Vice President he was voicing emphatically the grievances of the employees of the Bank before the superior authorities and due to his active participation in the union affairs the superior officers of the Bank did not like him and were on the look out for an opportunity to punish him. The union gave a call for work-to-rule in all the branches of Dena Bank including the Bakhtiarpur branch from 1-1-80 to 11-1-80 in order to get settlement of their industrial dispute implemented. Due to the efforts of the concerned workman the strike was a complete success. Seeing the successful organisation of the employees of the Bank at the instance of the concerned workman, the management of the Bank were finding out a pretext to implicate and punish him. The union under the Vice Presidentship of the concerned workman informed the higher authorities in writing about the mal practices and mismanagement in the matter of loans and advances by the then Bakhtiarpur Branch Manager of the Bank Shri P. S. Padmanavan and the accountant Shri Baradarajan. Therefter there was departmental enquiry against them. Shri Padmanavan was suspended on 4-1-80 and Shri Baradarajan charge sheeted on 31-7-80 on various allegations including the complaint of the concerned workman against them. Shri Baradarajan was dismissed from service in April, 1983.

On 4-1-1980 Shri V. Shankar Narain took over charge of Bakhtiarpur Branch of Dena Bank from Shri Padmanavan. After taking over charge on that day Shri Shankar Narain accompanied by Shri Baradarajan, Accountant came to take a stock of the cash at the counter of the concerned workman when the cash had already been opened and daily Bank transaction had started. Shri Shankar Narain did not find any irregularity and as such no irregularity was pointed out to the concerned workman. Thereafter Shri Shankar Narain with Shri Baradarajan went away to talk and came in a few minutes and at that time there was n oindication of any shortage in cash. However, a packet of Rs. 10,000 had been misplaced but was found immediately on the spot. No verbal or written allegation was levelled against the concerned workman in respect of the misplaced bundle of Rs. 10,000. He was not asked to explain any shortages and no memo was issued to him on 20-2-1980, the concerned workman had returned after a few days leave when he received an order not to perform the duties in the cash department. Eeven at that time there was no reference of any irregularity, shortage of cash defalcation, theft or attempt of theft. On 13-3-80 the Regional Manager, Calcutta issued a charge-sheet-cum-suspension order on the concerned workman alleging that on 4-1-80 an amount of Rs. 10 000 was found missing at the time of checking cash but after sometime it was found. The further allegation was that the concerned workman had attempted to commit theft and that his act was prejudicial to the interest of the Bank. The concerned workman submitted his explanation denying the allegations in the charge as false and fabricated and it was stated that the charges were levelled with a view to victimise him for his trade union activities. A domestic enquiry was conducted by Shri Kothari. The enquiry was being delayed and thereafter the concerned workman filed a Writ application CWJC 1691 of 1982 in the Hon'ble Patna High Court in which it was ordered on 7-5-82 that the domestic enquiry should be completed within two months failing which the suspension order would automatically stand vacated. The enquiry proceeding were not completed within 2 months of the order of the Hon'ble Court and thereafter the concerned workman was allowed to join his duties by a letter dated 29-7-82. The enquiry was held wherein some witnesses were examined. The enquiry Officer held the workman guilty of misconduct as alleged in the chargesheet by his report dated 30-9-82. A dismissal order dated 21-12-82 was served on the concerned workman under the signature of the Regional Manager. He filed an appeal before the AGM(P) against the order of his dismissal but the same was dismissed and his order of dismissal was confirmed. According to the concerned workman the management could not produce any dependable and direct evidence to establish that there was an attempt to steal or that any financial loss was caused or was likely to be caused by the conduct of the concerned workman. The findings are perverse being contrary to the oral and documentary evidence produced before the Enquiry Officer. There was no material establishing the charges against the concerned workman. The enquiry Officer did not explain the contradictions in the evidence of the management's witnesses which could go to show that the witnesses were all tutored The principles of natural justice were not observed in as much as the Enquiry Officer had restrained cross-examination of the management's witnesses by and on behalf of the concerned workman. The management had relied upon the witnesses who had got the benefits of wrongful advances by the Branch Manager and the Accountant of Bakhtiarpur Branch in respect of which the concerned workman as Vice President of the Union had made complaint. The dismissal of the concerned workman is a result of victimisation. On the above facts it is prayed on behalf of the workmen that an Award be passed declaring the order of the dismisal dated 23 6 82 as void and the concerned workman be reinstated with all benefits from the date of dismissal.

The case of the mangement is that the concerned workman Shri Ramballi Singh was duly chargesheeted for attempt to commit theft of Rs. 10,000 by unauthorisedly and surreptiously removing the said amount from the safe and doing acts prejudical to the interest of the Bank involving or likely to involve the Bank in serious financial loss. A domestic proceeding for the same was held in which the concerned workman and his co-worker participated and cross-examined given full opportunity to defend himself in the domestic management's witnesses and the concerned workman was found guilty of the charges and thereafter he was dismissed from service by the competent authority The order of dismissal was confirmed even in the appeal filed by the concerned workman before the appellate authority. The facts leading to the charge against the concerned workman is that on 4-1-80 Shri V Shankaranarain joined at Bakhtiarpur Branch of the Bank as Manager on deputation from Regional Office, Calcutta On his arrival he decided to check the entire cash. In course of checking he found shortage of Rs. 10,000 in the total cash. The concerned workman was the Cashier Incharge of all the Cash and was responsible for the shortage. The Branch Manager stopped all business transaction and with the help of Accountant and other staff made a thorough search of the office for the missing amount but was not found. It transpire that while the Branch Manager had gone to inform the superior authorities on phone or the upper floor of the Bank the concerned workman surreptitiously left the Bank premises and managed to induct into the Bank premises the missing amount. The concerned workman handed over the amount to the Bank cash Peon Shri Rabindra Bahadur Singh who stitched and stamped the bundle of the note at the instance of the concerned workman. Thereafter the concerned workman cleverly kept the said bundle of note under old ledgers. When the Branch Manager came down stairs, the concerned workman made a show of discovery of the missing amount from the old ledgers. The Branch Manager had already thoroughly searched the said place earlier from where the missing amount was later shown to be recovered by the concerned workman The Branch Manager made a report of the entire fact to

the Regional Manager, Calcutta who after considering the entire matter issued a charge sheet-cum suspension order dated 15-5-80. The charge-sheet was served on the concerned workman to which the concerned workman gave explanation. The explanation was found unsatisfactory and a departmental proceeding was started and the enquiry was conducted by Sari M. Kothari the then Astt. General Manager (O), Calcutta who was a competent authority on the panel of enquiry officers. The Enquiry Officer held enquiry according to the rules in which the concerned workman duly participated. The concerned workman was given full opportunity to defend himself and in fact he cross-examined all the management's witnesses and also adduced witnesses in his defence. After fully discussing the materials on record, the enquiry officer found the concerned workman guilty of the charges. The Regional Manager who is a disciplinary authority considered the enquiry report and the materials on the record and was satisfied about the guilt of the concerned workman and passed an order of his dismissal after giving an opportunity for personal hearing of the concerned workman. The concerned workman filed an appeal against the order of his dismissal before the appellate authority and after properly hearing the concerned workman the appellate authority confirmed the order of dismissal passed by the disciplinary authority. The findings is based on the oral and the documentary evidence produced before the Enquiry Officer and there was no question of victimisation or biasness from the side of the management. The second charge is connected with the first charge and as the first charge of committing the theft is proved, the second charge was also automatically proved because the said act of theft of money was prejudicial to the interest of the Bank involving in serious financial loss. The management's witnesses clearly stated the fact of theft of money committed by the concerned workman and there was no contradiction in the evidence of the management's witnesses. The paying cashier's allowance was withdrawn as the concerned workman was stopped from working as a Paying Cashier. On the above plea it has been submitted that an Award be passed that the action of the management in dismissing the concerned workman is justified.

The management had raised a preliminary point that as it is a case of dismissal based on domestic enquiry the question of fairness and propriety of the domestic enquiry should be first decided as a preliminary issue and in case the domestic enquiry was held to be improper and unfair an opportunity should be given to the management to prove their case by adducing direct evidence before the Tribunal. The said prayer was allowed. The preliminary issue was heard and decided by the order dated 25-3-85 wherein it was held that the Enquiry Proceeding against the concerned workman was fair and proper.

As it has been held that the Enquiry Proceeding was fair and proper it has now to be seen whether the materials before the Enquiry Officer were sufficient to establish the charge against the concerned workman.

It has been submitted on behalf of the concerned workman that the evidence led in the Enquiry Proceeding did not establish the charges against the concerned workman and because of the prejudice against the concerned workman for his trade union activities, he has been found guilty and dismissed from service.

I will deal with some of the salient features in the evidence of the witnesses to find out whether there was sufficient materials in the Enquiry Proceeding to establish the charges against the concerned workman and that the enquiry report was centrary to the evidence showing perversity. For this purpose I would refer to the domestic enquiry proceeding Ext. M-7. It will appear from the evidence of Shri P. S. Padmanavan MW-5 Branch Manager that on 4-1-80 Shri V. Shankarnarain took charge as Acting Manager of Bakhtiarpur Branch of Dena Bank. Shri Padmanavan has stated before the Enquiry Officer that as about 10 A.M. Shri Shankar Narain came to the Bakhtiarpur Branch on 4-1-80 and Shri Shankar Narain had asked him to handover the charge of Bakhtiarpur Branch and to verify the cash. Shri Padmanavan had already applied master key to the safe. He had asked Shri Shankernara'n to check the cash which was under the custody of the Cashier Rambali Singh (concerned workman). He has further stated that Shri Shankernarayan detected that one packet of Rs. 100 note was missing and on being searched inside the safe the said bundle of notes was not found. MW-5 Shri Padmanavan has stated that the banking transaction had already started when Shri Shankar Narain wanted to check the cash. MW-5 have further stated that in the evening of 3-1-80 he had closed the cash in joint custody with Rambali Singh and there was no shortage of cash when it was closed. He has stated that even on 4-1-80 when the cash was opened along with Shri Rambali Singh it was all intact. Thus it is clear that the said bundle of 100 rupee notes was in the safe on 3-1-80 and on 4-1-80 at the opening time. It will appear that thereafter Shri Rambali Singh took some cash from the safe for daily banking transaction and the safe was locked jointly. It appears therefore that Shri Rambali Singh had no occasion to take out surreptitiously the bundle of 100 rupee note from the safe. MW-5 in his further cross-examination has stated that after opening the cash and prior to the arrival of Shri Shankar Narain the concerned workman Shri Rambali Singh was inside the bank and nobody had seen him going out of the Bank. Thus Rambali Singh had not left the Bank premises after opening the cash and prior to the arrival of Shri Shankar Narain and as such he had no occasion to take the bundle of 100 rupee notes outside the banks premises. Admittedly, the bundle of 100 rupee note was found from the ledgers and registers kept around the safe area by Shri Rambali Singh.

The case of the management is that Shri Rambali Singh had removed the bundle of 100 rupee note outside the banking premises and when Shri Shankar Narain detected shortage of the bundle of 100 rupee note in the safe, Shankar Narain went upstairs is to phone the higher authorities and in the meantime Shri Rambali Sing went out of the Bank premises and came back with the bundle of notes and got it stitched and stamped and manoeurved to keep it under the registers and ledgers. In order to prove that Shri Rambali Singh had left the premises and had returned back soon with the bundle of note which was stitched and stamped and kept under the ledger and registers the management had adduced oral evidence in the enquiry. MW-1 Shri V. Shankar Narain who had taken the charge of Acting Manager on 4-1-80 and had checked the cash has stated that when he had located the shortage of Rs. 10,000 in the denomination of 100 rupee notes, he asked the watchman to close the gate of the Bank and went up stairs to contact the Regional Manager on telephone and informed him of the shortage and there after he came down and found that Rambali Singh was not in his seat and on enquiry he was informed by Shri Padmanavan that Shri Rambali Singh had gone out and that when he again went upstairs to telephone the Regional Office and came down stairs, he found Rambali Singh sitting in his seat in the cash counter, and that on seeing him Rambali Singh came out of the counter and started searching in and around the safe area by removing ledgers and registers and found a packet of 100 rupee note. Shri Shankar Narain had not himself seen Shri Rambali Singh either going out of the bank or returning back with the bundle of the notes. The evidence on this point is of MW-2 Prabhat Kumar, MW-3 Sachitanand Yajee and MW-4 Sailendra Kumar who all maintain account in the Bank and of MW-6 Rabindra Bahadur Singh, a subordinate staff of Baktiarpur Branch of Dena Bank. MW-2 had gone to deposit money in the Bank on 4-1-80 and was asked to go out as Banks gate was being closed for verification of the shortage of amount in the Bank by an Officer who had come from outside. When the gate was closed he was waiting outside the gate of the Bank and after two or 3 minutes he saw the cashier (Rambali Singh) coming out of the Bank's gate and going towards Bazar hurriedly and after sometime the cashier returned to the Bank premises and went inside and thereafter he learnt that the shortage of cash was found. MW-3 Sachitanand Yajee had also gone to deposit cash in his account in Dena Bank on 4-1-80 and when he was standing near the cash counter he was informed that the cash would not be accepted as one officer had come from Calcutta and was checking cash and when he was waiting in the Bank he saw the cashier Shri Rambali Singh going out 2 or 3 minutes after the gate was closed and returning back holding a bundle in his hand wrapped in a paper and he further saw that the bundle contain 100 rupee note which was handed over by the cashier to a subordinate on duty and the subordinate was asked to stitch the notes and thereafter the subordinate stitched the bundle and returned it to the cashier and the cashier put the said bundle below some registers and thereafter the cashier started telling that the money was located. It will appear from his evidence that PW-3 remained inside the Bank when the gate was

closed although all the other customers and outsiders were asked to go out of the bank at the time the gate was closed. MW-4 Sailendra Kumar had gone in the Bank on 4-1-80 in connection with bill transaction and he was told that the work will not be transacted as an officer has come from Calcutta for checking and at that time he learnt that there was a shortage of Rs. 10,000/- in cash and he was asked to leave the Bank's premises. He came out and was waiting near the window and saw the cashier coming out hurriedly from the bank and returning after sometime with one packet which the cashier gave to the cash peon asking him to stich and thereafter the cashier came out saying that the cash was located. MW-6 is Rabindra Bahadur Singh a subordinate working in Baktiarpur Branch of Dena Bank. He has stated that on 4-1-80 at about 10.15 A.M. Shri Shankar Narain came and checked the cashier and found a shortage of Rs. 10,000/- He has further stated that when Shri Shankar Narain went up stairs Shri Rambali Singh went outside and brought Rs. 10,000/- which was given to this witness and the witness stitched and stamped the notes on the slip with the date of 3-1-80 and returned it to Shri Rambali Singh. From his further evidence it will appear that the gate was closed at the time of checking and that the gate was opend after 2 minutes. He has stated that he saw Shri Rambali Singh going out and coming in the Bank but he did not see him bringing the cash and he further states that when Rambali Singh returned he gave him one bundle of notes of Rs. 10,000. Thus it will appear from the evidence of MW-6 that he had not seen any bundle of note being carried by Shri Rambali Singh when he entered the Bank and he saw notes only when it was handed over to him for stitching and stamping. The other two witnesses who were standing outside the bank have stated that they had seen Rambali Singh entering the Bank with a bundle of notes in the hand is not supported by MW-6 and as such the evidence of MW-3 and MW-4 is of very doubtful nature and in this circumstances it is difficult to believe their evidence on the point

Another very important evidence is that of MW-8 Shri Parash Nath Singh who had closed the gate of the Bank after shortage of the amount was detected by Shri Shankar Narain. He has stated that on the order of Shri Baradarajan he closed the door of the bank and thereafter Shri Shankar Narain and Shri Baradarajan went up stairs and when they came down they again checked the cash and he heard that the amount was located and thereafter Padmanavan told him to open the gate as money was located. MW-8 was the gate Keeper who does not say that the concerned workman had gone out and returned after the gate was closed and as such his evidence also does not support the evidence of the so called eye witnesses who had seen the concerned workman coming out of the bank and returning back with a bundle. There is no reason as to why this witness would not have supported the case of the management on this point if the concerned workman had gone out of the Bank's premises and returned when the gate of the bank was closed for checking of the cash.

MW-6 has stated that Rambali Singh had handed over the bundle of 100 rupee note to him which he stitched and stamped on the slip with the stamp dated 3-1-80. It has come in the evidence of the MW-5 that the transaction of the Bank had started at 10 A.M. on 4-1-80 and the date of stamp must have been changed from 3-1-80 to 4-1-80 when the transaction of the Bank started. The evidence of MW-6 that he had stamped the slip with a date of 3-1-80, therefore, does not appear to be convincing. It will appear that the bundle of 100 rupee note which was recovered from under the ledger of the Bank had not been produced before the Enquiry Officer so as to examine the truth of the evidence of MW-6. It appears to be admitted by MW-6 that the slip of 100 rupee note contain the stamp of 3-1-80. Had the bundle of note been restitched and new slip attached to it on 4-1-80 the slip should have stamp of 4-1-80. In this view of the matter the evidence of MW-6 that he had stitched and stamped the 100 rupee note on 4-1-80 giving the stamp of 3-1-80 on the slip is not convincing.

The evidence discussed above will show that the concerned workman had not gone outside the bank after the cash was taken out from the safe for the days transaction and before the arrival of Shri Shankar Narain and as such there was absolutely no possibility of removal of the bundle of 100 rupee notes from the Bank outside its premises. If the bundle was not removed during that time how can it be said that the concerned workman had removed the bundle of 100 rupee note which he subsequently brought when the shortage was detected and the gate was closed on the order of Shri Shankar Narain. This fact alone will show that the witnesses who have deposed that the concerned workman had gone outside the Bank's promises when the gate was closed and had returned back with the bundle of notes appears to be a complete myth by which it is being tried to implicate the concerned workman.

There is another important point which has remained unanswered by the management. Admittedly the concerned wokman had taken out some cash out of the safe for days transaction before the actual transaction of the Bank started. A very pertinent question was asked from MW-1 Shri Shankar Narain on behalf of the concerned workman. On being questioned as to how much rupees were inside the safe at the time of checking, Shri Shankar Narain could not say the amount which was actually in the safe of the amount which was taken out from the safe for days transaction on 4-1-80. As some amount had been taken out of the safe for days transacton, the amount of cash inside the safe must be less than the amount of cash which was in fact at the time the safe was opened by the Manager and the Cashier on 4-1-80. It appears from the evidence of MW-1 that the cash balance book is maintained by the Branch indicating the position of the cash inside the safe during the banking hours and the amount of cash taken out for days transaction, but the said cash balance book was not produced before the Enquiry Officer and as such it was not possible for MW-1 to say as to what was the amount which was taken out of the safe for days transaction on 4-1-80. This was an important question which was being repeatedly asked from Shri Shankar Narain on behalf of the concerned workman but the answer was evasive. A request was made on behalf of the concerned workman to produce the book dated 4-1-80 and it appears that the prosecuting Officer stated to the Enquiry Officer that one Shri M. S. Pathak has stated that there was no system of maintaining such a register during the relevent time. This answer was just to explain as to why the required register was not being produced and it still remain a mystry as to what was the amount of cash inside the safe and what was the amount of cash which was taken out of the safe for days transaction. As there is no evidence as to the amount which was taken out of the safe for days transaction on 4-1-80 there may be a possibility that the said bundle of 100 rupee note might have been taken for days transaction and had slipped under the ledger near and around the safe. Positively there is no evidence what I have stated above but in the circumstances of the evidence discussed above the possibility stated by me above cannot completely be ruled out.

One of the important question will naturally arise as to how the bundle of 100 rupee notes was found under the ledgers near and around the safe of the Bank. MW-1 has stated that after checking the cash he located a shortage of Rs. 10,000 in the denomination of 100 rupee note and thereafter he asked the Watchman to close the gate. A question was put to him in the cross examination made on behalf of the concerned workman as to whether the shortage of Rs. 10,000 was inside the safe or the shortage was located in the cash taken out for the days transaction in the counter to which he answered that the entire cash was brought to him to the counter and checked. It appears therefore that Shri Shankar Narain was sitting in the counter where the entire cash from the safe was brought by the concerned workman and the amount taken out by the cashier in the counter was checked. MW-1 has further stated that he himself did not take out the cash from the safe and that the cashier brought all the cash of various denominations kept inside the safe to the counter for checking while he himself was sitting inside the counter. DW-3 Lala Prasad is a Deftry in the Dena Bank. He has stated that formerly he was employed as subordinate and thereafter he was made a Daftry. He also worked in the cash department. It was asked from him as to how cash is brought out from the safe to which he has stated that the cash is put on register and then carred to cash counter and that only coins is kept in the box. It will thus appear that the cash is

brought from the safe keeping it on some registers on the counter and there may be possibility of some bundle slipping from the registers. It will appear from the evidence of MW-1 that all the cash was brought from the safe to the counter for checking and as such there was also a possibility of bundle of note slipping from register while the cash is brought from the safe to the counter. MW-1 has no doubt stated that the cash was short in the safe. But it has not been established as to the amount which had actually been taken out of the safe at the earlier hours for days transaction. It has also been said by MW-1 that he had searched all the places including the place from where the bundle of note was found and by this evidence he has tried to show that the bundle of notes was subsequently planted there by the concerned workman but there is no specific evidence that all the registers and ledgers had been removed from the place at the time of search from where subsequently the bundle of note was found. Thus taking all the evidence and circumstances of the case into consideration the possibility of the bundle of note slipping in the ledgers while the cash was being brought from the safe to the counter cannot be eliminated.

DW-2 Rohan Ram is a sweeper working in the Bakhtiarpur Branch of Dena Bank. He was on duty on the alleged date from 9.45 to 11.45 A.M. He was working on the ground floor when Shri Shankar Narain had come and checked the cash. He has stated that he had seen the gate of the bank closed when he was working and at that time Shri Shankar Narain and Baradarajan had gone up stairs to telephone. He has stated that Rambali Singh did not go out during the shortage was located. Thus his evidence is to the effect that the concerned workmen had not gone out of the Bank premises at the time of checking. No reason has been taken out from him in the cross-examination made on behalf of the management to show as to why he would depose falsely against the management. DW-3 Shri Lala Prasad was working as Daftry in Bakhtiarpur Branch of Dena Bank, who also said that Shri Rambali Singh was inside the Bank when alleged shortage was located and when the search was going on. He has also stated that the Bank's gate was closed. DW-4 Shri Rajendra Prasad Singh had transaction with Dena Bank at Bakhtiarpur. He has stated about the behaviour and good performance of the concerned workman in the Bank..

In view of the evidence discussed above it will appear that the findings of the Enquiry Officer that the charges have been estabishment against the concerned workman lacks evidence on the point that the concerned workman had removed the bundle of 100 rupee notes outside the premises of the Bank. The evidence adduced on behalf of the management that the concerned wokman had brought the bundle of note from outside the Bank's premise and had planted under the ledgers and registers near and around the safe has also not been establishment by the competent and reliable witnesses. In that view of the matter the finding lacks evidence regarding the establishment of the charge against the concerned workman and as such the finding appears to be preverse.

The concerned workman is the Vice President of Dena Bank Employees Association and in that capacity he must have taken up some disputes with the management causing irritation to the management. As such it is no wonder that the concerned workman has alone been picked up although the previous Branch Manager Shri Padmanavan may also be reponsible being in possession of the double key system of the safe.

The shortage took place on 4-1-80 and the chargesheet was submitted against the concerned workman on 13-3-80. In between this period there is nothing to show that any endorsement was made on any register of the Bank to show that there was shortage of Rs. 10,000/- on 4-1-80 and that the concerned workman was responsible for it. No explanation in writing was asked from the concerned workman prior to the receipt of the chargesheet.

In view of the discussion made above I hold that the action of the management of Dena Bank, Calcutta in dismissing from service the concerned workman Shri Rambali Singh Cashier-cum-clerk with effect from 21-12-82 is not justified and as such the concerned workman is reinstated with full back wages from the date of this dismissal with continuity of service and all consequential benefit accruing to him.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-12012/100/84-D. II(A)]

नई दिल्ली, 28 मई, 1985

का. आ. 2648.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-2-85 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 28th May, 1985

S.O. 2648.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd May 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 186 of 1983

In the matter of dispute between Shri Suresh Kumar Dwevidi C/o Shri Shishu Pal Singh, 119/205 Om Nagar, Darshan Purwa, Kanpur.

AND

The management of State Bank of India, (Law Department) Halwasiya Place, 24, Hazarat Ganj, Lucknow.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide its notification No. L-12012/178/82-D-II-A, dated 11th May, 1983 has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India Swarup Nagar, Branch, Kanpur in terminating the services of Shri Suresh Kumar Dwevidi, temporary messanger w.e.f. 1st September, 1981 is justified. If not, to what relief the workman concerned is entitled ?"

The case of the workman is that he was appointed as temporary messenger at Latouch Road Branch of the management State Bank of India on 27-11-78. He took charge of the permanent messenger which was lying vacant and he worked as temporary messenger till 13-4-79 and was confirmed w-e-f 14-4-79. The workman was never paid his salary and on his demand, he was told by the branch manager that the same would be payable to him after sanction from the Local Head Office. The workman concerned was paid conveyance allowance for the duties when he was asked to go out of the bank in connection with the work. In this way from November 78 till August 31st 1981 except for three months i.e. September October and November, when he was on leave. On 20-2-80 the workman was transferred to Swarup Nagar, Branch, Kanpur where he worked up to 31-8-81 and his services were terminated verbally w.e.f. 1-9-81 without assigning any reason and without giving him any termination letter. In this way the workman concerned worked with the management bank for three years when his services were done away without justifying any reason. That the act of the management bank in terminating the services of the workman is illegal and unjust. That the act of the management bank in terminating the services of the workman concerned is against the staff circular no.167/7 dated 8-9-76.

The management bank has contested the case of the work and raising the perliminary objection that Shri S. K. Dwevidi a so called workman is not workman as defined under sec. 2(s) of the I.D. Act. In as much as Shri Dwevidi had never been in the employment of the management bank of its Latouch Road Branch, Kanpur, or Swarup Nagar Branch, Kanpur and no employer and employee relationship existed between the bank and Shri S.K.Sharma so called workman, at any

time during the period alleged and as such it was not an industrial dispute.

On merit the bank management has alleged that the workman Shri Dwevidi somehow knew the then Branch Manager Shri R.S. Sharma and approached to help him in securing the job for him. The branch manager out of sympathy accommodated Shri Dwevidi by giving him casual work of carrying dak and for that he was paid conveyance which is nominal at the rate of Rs.3 or 4 per day in the name of conveyance allowance. That the work performed by the workman was only for an hour or so in a day. No appointment or termination letter was given to the workman nor was he required to attend office work nor paid any salary to the workman. When the branch manager Shri R.S. Sharma was transferred to Swarup Nager Branch on 20-2-80 Shri Dwevidi again approached him for similar favours and he was given similar favour of carrying dak etc. for which some amount was paid to him in the name of conveyance. The workman Sri Dwevidi was trying to encash the said circumstances by calling himself to be a bank employee during that period. It is further averred that no person could continue in service without any instruction for such a long time and without salary and the workman never demanded salary or wages for the service rendered. The management has denied all other averments of the workman except that the workman was issued dak/papers each day for which he was paid Rs.3 or 4 per day in the name of conveyance.

It is argued by the management representative that Sri Suresh Kumar was not an workman within the meaning of section 2(s) of the Industrial Dispute Act and no jural relationship of employer and employee was there and at the worst he was casual ad hoc and gratituous worker to whom no appointment letter was ever given, no salary was ever given and no termination letter was ever given to him. Only this such is admitted that he was given dak for which he was paid conveyance allowance.

It is further argued that the workman Shri Dwevidi whereever Shri Sharma bank manager was posted and that he did not work as other employees did work in the bank.

At the instruction of the workman the joint inspection report has been filed which shows that the workman was paid conveyance charges from 6-7-81 to 28-9-84 for carrying dak/bank clearing work and he was paid Rs. 3 for each side i.e. in all Rs. 6 per day. A solitary day he was paid Rs. 2 for going to Nawabganj, for office work, one day he was paid Rs. 5 and on the other day he was paid Rs. 4.80 paise for purchase of 12 reffile for official pens and in the same way he was paid Rs. 3.50.

The management has filed detailed statement of conveyance paid to Shri S.K.Dwevidi at Swarup Nager, Branch, Kanpur for the period 20-2-80 to 31-8-81. This shows that the workman was paid conveyance charges for going to Local Head Office for either delivering Dak or for going to clearing work and was normally paid conveyance charges for going and coming and on some occasion charges were paid three times. On one occasion he was paid Rs. 5/- for going to Post Office for delivery of registered letter of the bank. The workman has also filed the list of the working days prepared by him for the purposes of payments made to him either at Swarup Nager Branch or at Latouch Road Branch, Kanpur and the said paper is ext. W.1. It is almost the same as ext. W-1 and he was paid Rs. 5/- as casual labour from 30-11-78 to 19-4-79 and from 15-4-79 he was paid conveyance charges at the rate of Rs.5/- per day. From 18-6-79 to 7-7-79 he again worked as labour and was paid at the rate of Rs. 6/- per day. Thus barring for September. October and November 79 he almost worked regularly with the bank insatisfying him as casual labour or as messenger for taking dak for clearance.

The only question to be decided is whether was the work done by the workman a gratutious one or of ad hoc nature or of casual nature which did not make him a workman of the management concerned.

The workman has been defined under section 2(s) of the I.D. Act as allowing any person to employee in an industry to do any mannual, unskilled.....the work for which he was rewarded whether the terms of the employment be expressed or implied. It is common ground that regarding the employment working expressed except daily payment of conveyance charges. There is no doubt that the workman Shri S. K. Dwevidi was asked by the management to do the job almost daily i.e. taking of dak or clearance to L.H.O. or other places. The question is whether the payment made by the management to the workman was for hire or reward or simply actual conveyance charges. The word "in the name of conveyance" carrying in para 2 of the written statement and again in para 7 of the w.s. which is quite significant showing that the payments were not actually conveyance charges paid to the workman who had been doing all that work for one remuneration or he was being paid that amount for the services rendered though in the name of conveyance as alleged. Word in the name of conveyance shows that the payment were for the services rendered, though payments shown in the vouchers by way of conveyance. The workman was free to utilise the amount so regularly paid and not that he actually paid towards Rickshaw charges. Thus it was the way to remunerate a man for the services rendered i.e. doing the job or taking away dak or clearing work and paying in the name of conveyance.

Thus Shri S. K. Dwevidi though he might have been doing not full time work as other bank employee do but was employed to do the bank work for hire or reward in the name of conveyance and in this way he comes in the definition of the workman as defined under section 2(s) of the I.D. Act and the dispute raised by the management would be industrial dispute and in this way reference is competent.

It can not be denied looking to the chart filed by the parties Ext. W-1 and the joint inspection note that the workman worked in the bank almost continuously from 27th November, 1978 till 31st August, 1981 which would be more than 240 days for purposes of section 25F and this has not been disputed by the management. As the workman's services were done which amounts to retrenchment w.e.f. forenoon of 1st September, 1981 after a continuous service of more than one year and without payment of retrenchment compensation or notice pay as required under section 25F of the A.D. Act. Thus the termination/retrenchment is illegal and void ab initio.

I accordingly hold that the action of the management bank State Bank of India in terminating the services of Shri Suresh Kumar Dwevidi Messanger Swarup Nagar Branch, Kanpur, w.e.f. 1st September, 1981 is not justified and void ab initio.

The result is that the workman has to be reinstated in service with full back wages which he was getting at the time of his termination.

I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this award be sent to the Ministry of Labour for publication.

Dated : 10-5-1985.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No.L-12012/178/82-D.II(A)]

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

का०आ० 2649 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-5-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th May, 1985

S.O. 2649.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government

Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd May 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 52 of 1981

In the matter of dispute between :

Shri Sabbir Ahmad C/o Shri Harmangal Prasad 36/1, Kailash Mandir Kanpur.

AND

The Regional Manager, State Bank of India, Post Bag No. 1, Varanasi.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/75/80-D-II-A dated 1st April, 1981 has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India (Regional) Varanasi in terminating the services of Shri Sabbir Ahmad, temporary watchman with effect from 5th May, 1973 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

Sabbir Ahmad workman was initially appointed by Bhadohi Branch of the State Bank of India on 18th December, 1970 as a temporary godown watchman and his services were terminated on 5th May, 1973 by the branch manager Badohi after the workman had put in 783 days of service as ennumerated in annexure 'A' of the rejoinder At the time of termination on 5th May, 1973 the workman had put in 330 days of service during the preceding 12 calender months yet at the time of termination he was not given notice, notice pay or retrenchment compensation The termination of the workman having been brought about without following the mandatory provision of section 25F of the I.D Act and the termination is illegal void ab initio and the workman is entitled to be reinstated with full back wages. The management has raised objection that the claim is highly belated having been raised on 4th December, 1979 when the termination was effected on 5th May, 1973. It has been prayed that the claim of the workman may be rejected outright on this ground.

The management admits that the workman was initially appointed by Bhadohi Branch of S.B.I. Varanasi on 18th December, 1970 and was extended from time to time according to the requirement of the branch and ultimately his services were terminated on June, 1972 and the workman received his full and final payment of his own account. The workman never challenged the termination thereafter. Later workman commits to know that a godown watchman was required by the Bhadohi branch, the workman applied on 7th June, 1972 requesting the employment as godown watchman The management appointed the workman as temporary godown watchman at the godown of M/s Dass Carpet Limited Sambharia Bhadohi for specified period of two months from 7th June 1972 The workman thereafter continued to work as temporary godown watchman and his services were extended from time to time after expiry of two months. There were reports that the workman was frequently absent from the godown the Branch Manager visited the godown on 4th May 1973 and found the workman absent from his place of duty and even the keys of the godown were left with the employees of the said factory The branch manager after noticing the serious lapse on the part of the workman thereby exposing the bank to serious risk did not grant him further extension for the service and his services were consequently expired on 5th May, 1973 after noon and he was relieved from his duty The workman voluntarily vide his letter dated 14th May, 1973 admitted his lanses of remaining absent from his place of duty and requested to excuse him and reemployed in the bank The Branch Manager Bhadohi Branch decided not to allow him any further work and consequently he was not given any work having lost confidence in the workman According to the averments of the management, the termination brought about on 5th May, 1973 will not amount to retrenchment and section 25F of the I.D. Act is not attracted. Lastly they pleaded that the workman was gainfully employed If the tribunal comes to the conclusion that the termination is illegal.

In the rejoinder the workman has explained that after his termination on 5th May, 1973, the Letter dated 14th May, 1973 was obtained from him under threat, pressure and elurement. It is not disputed that the services of the workman were terminated on 5th May, 1973. It is further not disputed that the workman had completed more than 240 days of his temporary service counting backward from 5th May, 1973. It is further not disputed that no notice, pay, or retrenchment compensation was given to the workman The termination having been brought about as early as 5th May, 1973, it is true that the workman sat quite and raised demand as later 4th December, 1979 which letter is paper No 1 filed by the management on 22nd April, 1983. In this very letter the workman has given reason to have raised demand late. The reason is given in para 9 of that letter in the following words :

"that hundreds of employees of your bank who had worked for 240 days in 12 consequence months in subordinate cadre during the period rendered services were reemployed by the bank after the judgment in Sunder Mony Case by the Supreme Court and in this case you had also issued a circular on that point inviting the application from such cand dates."

The workman having worked as a temporary in the management bank for more than 240 days prior to 5th May, 1973 should have been paid notice pay and retrenchment compensation as required under section 25-F which was admittedly not done, and on that account the termination becomes void ab initio resulting re-instatement of the workman with full back wages.

It is argued that the termination was for lack of confidence in the workman. The original letter terminating the services of the workman his not been filed to decifer from its whether it is a reasoned order and is not the result of capriswhim of fancy reached on the ground of policy or experience. The letter dated 5th May, 1973 written by the then branch manager who terminated the services of the workman to the Secretary State Bank of India, Kanpur requesting for permission to recruit a temporary hand as godown watchman and stating the reasons that the workman's services had been despenced with from 5th May, 1973 as on his inspection on 4th May, 1973 he was found absent from duty. The Manager also found that the factory gate was opened and lock and key was lying in the varandah. He checked the stock kept in the godown and luckly he found the stock in order.

Termination on the ground of loss of confidence is also retrenchment and is not covered by any of the exception given in section 2(oo) of the I.D. Act. The termination could awarded the effect of the termination had the workman been chargesheeted for his latches and punished by way of deciplinary. Thus termination by way of loss of confidence is also covered under definition of retrenchment and attracts the provisions of section 25-F. As admittedly the provision of the section 25-F were not resorted too, the termination is illegal.

I, accordingly, hold that the action of the management of S.B.I. Varanasi Region in terminating the services of Shri Sabbir Ahmad Temporary Watchman from 5th May, 1973 is not justified. The termination being void ab initio, the workman is entitled to be reinstated with full back wages.

I, therefore, give my award accordingly.

Let six copies of this Award be sent to the Government for publication.

Dated : 10-5-1985.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/75/80-D. II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

का. आ. 2650:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22-5-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 31st May, 1985

S.O. 2650.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd May, 1985.

BEFORE SHRI R.B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 194 of 1984

In the matter of dispute between :

Mahatma Mishra, C|o Shri N. C. Pande, Authorised representative of the Workman-C-323, Guruteg Bahadur Nagar, Kaveli, Allahabad;

And

The Regional Manager, State Bank Of India, Region III, The Mall, Kanpur.

AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide its order dt. 19th July, 1934 and its No. L-12012|319|83-D-II-A, has referred the following dispute for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank Of India, Region III, The Mall, Kanpur, in relation to their Jhonstonganj Branch, Allahabad in terminating the services of Shri Mahatma Mishra, Ex-Massenger with effect from 4-9-82 and not considering him for further employment as provided under sec. 25-H of the ID Act, is justified? If not to what relief is the workman concerned entitled ?"

It is common ground that the workman was engaged as temporary employee of the management bank of its Jhonstonganj Branch, Allahabad on 31-5-82, and his services were terminated on the ground as no more required. It is further not disputed that the workman worked for a total 88 days with breaks. It is also not disputed that no appointment letter, termination letter or notice pay was given to the workman rather after his terination persons namely S|Shri Basudeo Harihar and Jai Ram were appointed for same or similar job and the workman was not called to work and thus the management bank has violated the provisions of 25G and 25H of the I.D. Act.

The management has raised a preliminary objection that no demand or claim was made before bringing the case hence there was no subsisting valid industrial dispute. In their rejoinder, the workman alleged that one Basudeo Misra on the same day i.e. 3-9-82 and continued till and beside Basudeo, Jairam Harihar and others were appointed after the termination of the workman. It is further argued that there was clear vacancy and he was not allowed to work after 3-9-82.

The workman has filed circular staff no. 163|64 paper no. 1 issued by the Personnel Department of the management bank, Head Office Lucknow, to all the branch managers and in its para (ii) direction was given in the following word i.e. that temporarily appointment were to be made for maximum period of 90 days in the case of sub staff and 180 days in case of temporary after obtaining suitable number of names from concerning employment exchange. In sub para (v) it is laid down "engagement of casual labour was required to be resorted to for work of casual nature only and they were not be engaged in members of subordinate staff."

On the preliminary point it has been argued by the representative for the workmen that the workman did sent notice dt. 7-6-83 requiring for the management to reinstate him in service with continuity and with entire back wages and allowances. This was itself a demand, moreover, the reference resulted after conciliations proceedings which after failure was referred to the govenment and the government in its wisdom finding it as industrial dispute referred for adjudication. Thus it cannot be said that there was no valid demand and that there was no subsisting valid industrial dispute.

On behalf of the management one Shri V.K. Mehrotra an officer of the management bank appeared in the witness box and admitted that the workman was engaged as temporary massenger. It may be mentioned here that the job of massenger is not of casual nature but is of permanent nature. According to him the date of employment of the workman is 3-5-82 and date of termination is 3-9-82. He has further admitted that no appointment or termination letter was given to the workman nor notice of termination was given to him. He has admitted that prior to the workman one Shri Rajendra Kumar was working there as temporary massenger and then one Ashok Kumar had worked as temporary massenger from 26-4-82 to 31-5-82. He has further admitted that one Basudeo was also appointed as temporary massenger for the period 30-9-82 to 30-11-82. When enquired about Jai Ram and Hari Ram he expressed his ignorance. The management witness has further stated that he is not able to tell if the workman was appointed through the employment exchange. He has further admitted that all the above temporary massenger were appointed on leave vacancy or casual requirement. In the end he admitted that in persuance of the instructions contained in circular letter the duration of the temporary workmen was restricted.

Th workman in his affidavit evidence stated that during his span of service i.e. from 31-5-82 to 3-9-82 no permanent massenger remained on leave continuously and that during his tenure of service Rajaram Suresh Chandra were appointed for period less than 90

days and after his termination Basudeo Jai Ram and Harihar were again appointed for less than 90 days. In the end he stated that since termination he is not gainfully employed anywhere else.

In cross-examination he has admitted that he was not employed on vacancy created by retirement of some one. He further stated on enquiry as to why his services were being terminated, he gave reply that there were others who were given change.

It is further admitted that when workmen was terminated on that very day, one Basudeo was apointed as temporary massenger who continued for another two months. This goes to show that the work of temporary massenger was there and the workman would have been continued but for the circular of the management bank referred earlier he had to be terminated before completion of 90 days of work. Thus the praciice of the management to terminate when work was there was unfair labour practice.

Further if it was necessary to terminate the workman then another workman Sri Basudeo should not have been appointed. Further as required in para 522 (v) of the Shastri Akard, the workman should have been given 14 days notice or notice pay but nothing was done and in the absence of compliance of this rule which has force of law, the termination of the workman would be illegal. The management did not comply with the provision of para 495 last para and para 522(5) of the Shastri Award.

In view of the facts mentioned above it can not be said that the workman was purely temporary against the temporary requirement of the management bank.

In Central Bank of India vs. Jammu & Kashmir 1968 LLJ page 646 J & K where in it was held that where no written order is served on the employee it is victimisation and unfair labour practice, and the court is competent to set aside the order and direct for reinstatement".

The Bipartite settlement, Shastri and Desai Award in which are in the nature of standing order.

In Whedia District Central Cooperative Bank vs. Bhargava Balwanti Vyas, 1984 II LLJ page 330 it was held that standing order bringing for terminating of employment by giving one months notice or notice pay was void and inaffective as the contention of standing order was not satisfied and in any case the workman would be deemed in continuing service entitle to order of reinstatement with full back wages."

Para 20.8 of Bipartie settlement lays down that a temporary workman may also be apointed to fill all permanent vacancy provided with such temporary appointment shall not exceed for a period of three month during which the bank shall make permanent arrangement for filling up the vacancy permanently.

The permanent vacancy is created by the death or retirement or transfer of a permanent employee or continuity of a permanent nature of work for a prolong period.

In the instant case before termination of Mahatma Mishra two other persons worked as temporary massenger and after his termination several others were also appointed to work as temporary massenger. Thus there was vacancy of permanent nature and has the workman allowed to be continued after 88 days he could have acquired the status of permanent massenger and it was on that count that his services were terminated two days before which was an unfair labour practice on the part of the management bank.

Thus in view of the discussion made above and the law discussed, I hold that the action of the management bank of the State Bank Of India in terminating the service of the workman concerned w.e.f. 4-9-83 which in reality and admittedly 3-9-82 and not considering him for further employment as provided under sec. 25H of the ID Act is illegal. The effect is that he will be reinstated in service full back wages.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer
[No. L-1012|319|85-D.II(A)]
N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 22 मई, 1985

का. आ. 2651.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम फैक्ट्री के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, बम्बई, के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 22nd May, 1985

S.O. 2651.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. I, Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom Factory and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY

Reference No. CGIT-2 of 1985

PARTIES :

Employers in relation to Tele-com Factory.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the employer—Mr. Masurkar, Advocate.

For the workmen—Mr. Wagh, Advocate.

INDUSTRY : Telecommunication STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 11th day of April, 1985

AWARD

This reference relates to the short question as to the justification of non-promotion of Shri Nerurkar as Planner Grade I in the Telecom Factory, Deonar, Bombay-400088.

2. The statement of claim is filed by the workman Nerurkar himself, though it appears that his cause was taken up at some stage by the union. The workman, Narurkar himself is also a party to the reference. Unfortunately, the statement of claim made by him done not disclose all the true and material facts which ought to have been disclosed. It seeks to convey an impression that Nerurkar was Planner Grade-II from the Method Section. As a matter of fact, he came from the planner section. In para 3 he says "two other employees junior to me in order of seniority whose names appears at Sr. Nos. 3 and 4 as per Trade Test.....were promoted overiding my claim with effect from 14-1-1975 as Pianner Grade-I in method section.' Some of the relevant memoranda issued in this connection and orders have also been filed on behalf of the workman. According to him, a new policy was introduced which directed in-shop seniority to be observed for promotions and not seniority in the passing of the test. This, he contended, is a change in the service conditions.

3. The correct picture and position, however, is revealed by the written statment filed by the employer. It points out that there are two shops, viz. planning and methods. Both of them have got planners Grades II and I. According to R. 2, as amended in 1959 promotions are to be given to

planners grade II, who pass the trade test in the same section. It is only if suitable candidates are not available, then others may be considered. The management pointed out that initially notice of the trade test and availability of promotions from methods section was notified on 28th of June, 1974. The management was then prevailed upon to amend that notice and a fresh notice was issued on 16-9-1974 inviting applications from the combined seniority list of both the shops, namely, Method section and Planning Section. Ultimately, it pointed out that the matter was referred after selection and appointment of planners at Sl. Nos. 3 and 4 who came from the Methods Section to the Director who pointed out that that was correct. Circumstance that Nerurkar topped the list in the trade test was not denied. It was pointed out that he belonged to the Planning Section and not Methods Section in which there were vacancies. In Methods Section in persons at Sl. Nos. 3 and 4 have also passed the trade test and were eligible to be promoted from among the planners from the Planning Section. 'No new promotional policy was introduced and there was no change in the service condition.

4. The documents produced in this case both by the workman and by the management, can now be examined, which will disclose the correct position. Appendix B to the written statement sets out the promotional avenues, it will be seen from entry at Sl. No. 6 thereof that planners Grade-II are promoted as planner Grade-I which is highly skilled category. Exhibit-B which is produced alongwith the written statement and is similar to W 2 produced by the workman contains Rule 2 which was later subsituted by another rule framed in the year 1959. The contention however, on behalf of the workmen is not right even if we are to consider the original Rule 2, as it says, Normally tests will be opened to workers of the same shop in which vacancy occurs. If no suitable candidates are available workers of allied trade from other shops may be allowed to appear." This clearly goes to show the preference for in-shop promotions. In other words, the rule indicates that tests would not be thrown open for persons outside even if eligible ordinarily and only in exeptional circumstance of non-availability of suitable candidates. It would follow therefore that the policy and principle was that promotions should be vertical and shop-wise.

5. The position is made quite clear by the amendment made on 2nd April, 1959 (Ex-C). There the existing Rules 2, 5 and 7 have since been revised. This has been approved by the P & T Board, Rule 2 now says, "if no suitable worker is available for promotion in accordance with the channel of promotion laid down, other workers will be eligible in the following order of priority :—

(i) Workers of similar trades and grade in other shops.

(ii) Workers of other trades, but in equivalent grades in all shops". It will thus be seen that the priority is firstly to workers in-shop and if no suitable worker in-shop is available for promotion, then of similar trade or grade in other shops and lastly workers of other trades in equivalent grade in all shops. What was therefore not very clear originally, was made perfectly clear by the amended rules.

76. The notice issued on 28-6-1974 was in accordance with the amended rule and also in accordance with the earlier policy and principle. It has invited applications for selection to planner Grade-I in the method section and the eligibility of applicants was "planners Grade-II attached to methods section". It is therefore, quite clear that the original notice for a applying eligibility tests for these promotions was restricted to methods section planners Grade-II only and not to others. The trouble has arisen only on account of the subsequent notice of 16-9-1974 which the management issued under union pressure.

7. This was however modified and another notice dated 16th September, 1974 was put on the notice board, which gave eligibility to everybody. It merely said "Planner Grade II having 5 years experience" and not only planners, Grade II in methods section. That clause obviously led to the present controversy. It seems to me however quite clear that though workman Nerurkar had stood first in the test, being from the Planning Section, he was not entitled to be considered in preference when suitable Planners Grade-II who have passed the tests were available in Methods Section Consequently, the management is justified in not promoting Nerurkar. On the contrary, it would have committed a breach of its own rules and violated them, if it had not done so. If the matter had been raised by Planners Grade-II who had passed the test in the Methods Section in a court it is clear that Nerurkar promotion had it been made would not have been sustainable.

8. The reference therefore has to be answered according. Award to that effect.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-40012(15)|84-D. II(B)]

का. आ 2652.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस, बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं 1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2652.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Overseas Communication Service, Bombay and their workman, which was received by the Central Government on the 13th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

Reference No. CGIT-23 of 1984

PARTIES :

Employers in relation to the Overseas Communication Service, Bombay;

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the employer—Mr. Masurkar, Advocate

For the workman—Mr. Samant, Advocate

INDUSTRY : Communications STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 26th day of March, 1985

AWARD

This is a reference in which facts which privide the background for the two questions referred to this Tribunal under order of reference dated 12-12-1984 which call for decision are not in dispute. The questions referred are as follows :—

(i) "Whether the workmen engaged by the Overseas Communication Service Bombay to the factory ceases (cease) to be industrial workers when they perform similar duties outside ? If not, to what relief are they estitled ?"

(i) "Whether overtime should be paid to workers engaged in the Factory of Overseas Communication Service, Bombay as per Factory Act which they perform as part of the duties outside the factory premises ?"

2. The claim in substance of the workmen, who are represented by the Overseas Communication Service Staf Union, is that work-shop workmen working on the fourth floor are also required to perform duties on the 5th floor 9th floor 11th floor, 14th floor and 16th floor. They ar also required to perform outdoor duties at the offices of th customers, who are granted leased telegraph channels. I may be mentioned that at the time of the hearing no refer ence was made to 14th and 16th floors, nor any claim pu

forward in that behalf, but a claim was put forward in respect of the work on the 7th floor required to be performed by these 4th floor workmen. The duties which are required to be performed by such workmen employed in the workshop on the fourth floor of the Videsh Sanchar Bhavan are set out in para 6. They are— (1) routines and maintenance of telegraph equipment, (2) fault attention of telegraph equipment in the building as well as at leased channels, (3) overhauls and partial overhaults of telegraph equipment, (4) Fabrication of all spare parts of telegraph equipment, and (5) working on milling, lathe, drilling machine, press and bench work. According to the union, workmen are governed by the Factories Act and workmen employed in the workshop on the 4th floor are treated as factory workmen. The workshop was also declared as a factory under the Factories Act. They say that they are entitled for payment of double overtime under Section 59 of Factory Act, even if they perform and whenever they perform duties sometimes outside the workshop. If that is so, the Overseas Communication Service department neglects and refuses to pay them and treat them as factory workers when working on floors other than 4th floor and at the customers or leased channels. They therefore pray that they should be granted overtime according to Section 59 of the Factories Act and not at the rate granted by the Overseas Communication Service. In para 10, they also added that considering the hazardous and strenuous duties performed by the employees in all kinds of climatic conditions they must be adequately compensated. I have no hesitation in saying that if this demand is to mean anything over and above the claim to be pad under the Factories Act, then it is outside the ambit of the terms of the reference.

3. In the written statement of the department, it sets out what is done in the workshop, which is registered as a factory under the Factories Act, namely the 4th floor premises. They say that this workshop is meant for "maintenance of Teleprinters, Receivers, Transmitters etc. belonging to the Employer" and "also attends to the repairs of the machines in case of breakdown and fabricates some minor spare parts of the various machines". In addition, there were leased channels given to the customers for their private use, and are located at the premises of the customers.

4. In case of any fault in these machines, the mechanics are sent for repairs of these machines located outside the workshop. There are also a few machines, according to it, installed on other floors of the Videsh Sanchar Bhavan, outside the factory premises and which are also attended to by the workmen, in case of faults and break-downs. The complement of the staff is 92 of which 73 are Senior Mechanical Assistants and Junior Mechanical Assistants, and nine are sub-staff.

5. It then says that out of this complement some 14 are utilised for shift duty "on floors of Videsh Sanchar Bhavan other than 4th floor". Place of work of these 14 persons is the instrument room on 5th floor and 11th floor. They are rotated in duty hours beginning from 0000 hours to 0700 hours, 0700 hours to 1400 hours, 1000 hours to 1700 hours 1400 hours to 2100 hours and 1700 hours to 2400 hours.

6. According to the department, workers working in the factory on 4th floor are paid for the overtime work at double the rates, in excess of 48 hrs. working in a week. Those attending to "Teleprinter Machines located on the premises of the customers and to machines located on other floors of Videsh Sanchar Bhavan" which are not factory premises, according to it, are not paid overtime at double the rate, but at the normal rate of overtime admissible accordingly, as prescribed by the Government. It denied that all the duties, which are mentioned by the union in its statement in para 6 which are preformed in the workshop are similarly performed on other floors or at customers' premises. According to it, teleprinter machines located in areas other than at workshop are neither overhauled nor any major repairs carried out to them, outside the factory, meaning thereby on the other floors of the building or at the customer's premises. According to it, such machines are brought back and replaced by good ones and are repaired at the workshop on the 4th floor.

7. It is the case of the employer that factory workers are entitled to payment of double overtime, according to Section 59 if and only when they do any work on overtime duty "within the precincts of the factory and not for workers working outside the factory" or factory premises. According to it, Section-70 of the Bombay Shops and Establishments Act, 1948 also dose not apply, since they have to work, according to it, not "in and in connection with the factory. Even if the work done by the factory is in connection with the factory, it is not, according to it 'in' factory. Therefore, they are, according to the department, outside the ambit of Section 70 of the Bombay Shops and Establishments Act.

8. The premises of the Overseas Communication Services Department were visited and my notes of inspection are kept at exhibit.

9. A few facts which may now be set out, which I have pointed out above, are not in dispute, are that on the fourth floor of the Overseas Communication Building, as has appeared in the evidence and also in my inspection report, a section of the area has a few machines which can be said to be general purpose machines in a general workshop, such as lathe, handpress, workshop bench, etc. In the machine section, various machines used by the OCS, namely, receivers teleprinters, transmitters, perforators, etc. are repaired and overhauled. Each section is being entrusted with the repairs to particular kinds of machines. A small area is also used for making minor spare parts. These are the ones which are very often required. The kinds of machinery which is used by the OCS is the computer peripheral equipment, such as disc mechanism and tape peripheries. The more sophisticated machinery such as VDU by other sections is attended to by other mechanics who are conversant with electronics on 7th 9th and 11th floors, for repair work. We are in the present case not concerned with these.

10. In this workshop, on the fourth floor, various kinds of machines either working on the 5th, 7th, 9th and 11th floors of the OCS building or at the customers premises, are for major repairs brought and repaired. They are also overhauled at the workshop and defects rectified in case of major defects. Other minor defects are rectified as also cleaning is carried out on the other floors or the customers' premises themselves. The workshop hours which consist of only one shift are between 9 a.m. to 5 p.m. The staff can also be sent out for rectification or attending to repairs and servicing or handling complaints of customers at their places So far as the other floors are concerned, staff drawn from the workshop establishment is permanently attached to these floors. They work in shifts, which are mentioned is Exhibit-C and they work round the clock. Since they are on duty all the time, in case of complaints received from the customers when the factory shift is not working that is, when they are received after 5 p.m. or before 9 a.m. then it is this staff which is drawn from the workshop, which is sent to serve the customers' requirements. Whether it is the staff drawn from the workshop or it is staff drawn from the other floors, if they attend a customer, they have to complete the work and return then only. If any day, they have to work more than their prescribed duty hours, the staff either in the workshop or in the other floors gets only overtime at the departmental rates prescribed, mentioned at Exhibit-B. They are admittedly, not the rates payable in accordance with Section 59 of the Factories Act. It is also an admitted position that the staff which is attached to the other floors from the workshop which is not only rotated, but is also periodically sent to the workshop and other set of employees drawn therefrom to work on the other floors. Though they work on the other floors of the OCS for longer duration, they are not permanently attached to that floor.

11. The crucial and controversial question, therefore, is whether the staff which is drawn from the workshop establishment and directed to work on the other floors and staff working on the fourth floor workshop or other floors directed to go and work at the premises of the customers of leased channels are entitled to overtime in according with Section 59 of the Factories Act. In this context, if we look to the terms of the reference once again, it would be seen that question No.1 in the schedule in not happily worked. We have already re-produced the terms of the reference. The dispute does not appear to be whether these workmen when they go out of the factory cease to be industrial workers, but what was presumably intended and what if the order of reference were to be meaningful and consistent should mean is not whether they cease to be industrial workers, but whether they cease to be factory workers. In other words, the first question in the schedule of reference

should read "whether the workmen engaged in the OCS Bombay in the factory cease to be factory workers when they perform similar duties outside."

12. I do not think that there is also any dispute between the parties or that it is possible to say that such factory workmen cease to be factory workers when they are sent out to perform duties which are similar, though not entirely same, outside the declared factory premises, namely, 4th floor, which is the workshop. In that view of the matter the first issue referred is really redundant. What is disputed and what is in controversy, and what is claimed is not the stating of such workmen, but their right to get overtime in accordance with the Factories Act. A Factory worker, does not bare aside his status or description, when he leaves the factory premises and works at some other place, on the same kind of work, which he is required or can be called upon to do within the factory premises. The principal controversy between the parties is not answered by the change in status. It is not because they leave the factory premises that they cease to be factory workers, if they carry out the same kind of work which they do in the factory and their right to the overtime under Section 59 does not depend upon merely their status as factory workers As I shall presently point out, it is really not enough to be factory worker to be entitled to claim double overtime under Section 59 of the Factories Act. In that view of the matter, it is clear to me that it is really the second issue which is referred, which is the most important and germane issue and the question must be germane to the controversy between the parties. That question, shortly stated, is whether these workmen, who are on the establishment of the fourth floor workshop of the Overseas Communication Service are entitled to overtime in accordance with the Factories Act, when they perform similar duties, not on the factory premises and technically in the factory, but outside. In other words, the question is when and whether workers borne on the workshop establishment of OCS, when they are doing similar kind of work at the customers' premises qualify for double payment of overtime under Section 59 of the Factories Act, and whether such workmen qualify similarly for payment of overtime at double the rate under Section 59 of the Factories Act, when they are doing the same kind of work on the other floors, namely, 5th, 7th, 9th, and 11th floors. It is these latter two questions which are the most important and fall for decision. Incidentally it may be mentioned that though in the claim statement 7th floor was not mentioned and 14th and 16th floors were mentioned, in the evidence there was no mention of 14th and 16th floors while there was mention of 7th floor. It is however, an admitted position that similar work which is carried out in the workshop is also carried out on 5th, 7th, 9th and 11th floor and the employees borne on the workshop establishment are attached to these floors for the time being.

13. The question, therefore, is purely and more or less, of application of relevant provisions of the Factories Act and finding out what is the applicable law on the point, on the established and admitted facts The established and admitted facts, which are relevant for our purpose, are (a) The concerned employees are borne on the workshop establishment. (b) the duties which they perform on the other floors and at customers premises are also similar in kind in some respects to the duties which they may be and they are required to perform at the workshop. Such duties being attending to minor faults and defects, minor repairs, cleaning and rectification of faults.

14. It is necessary firstly to refer to Section 59 of the Factories Act. That section reads "where a worker works in a factory for more than nine hours in any day of for more than forty-eight hours in any week, he shall be entitled to wages at twice the rate of ordinary wages." We are not concerned with the rest of the portion of Section 59. The key words, therefore, which have to be considered and which will determine the operation of Section 59, are that he must be a worker as defined under Factories Act and must work in a factory. If a person is found to be a worker and works in a factory, then there is no dispute between the parties and there can not be any dispute between the parties about his entitlement to overtime allowance under Section 59 of Factories Act. The main controversy therefore, centres upon the question whether the particular kind of work the concerned employee is doing on the other floors of the OCS, namely 5th, 7th, 9th and 11th, whether he is a factory worker working in the factory and similarly whether a worker when he is working at the customers premises doing the same kind of work which he is along and which he does or can be called upon to do in the workshop can be said to be working "in factory", I have bifurcated the two questions which operate slightly differently, primarily to concentrate and understand the principal question of controversy in the present case. If I may straightaway specify the controversy, then it is whether the workmen can be deemed to be factory workers when they are doing similar work a the customers premises and whether they can be deemed to be wroking in a factory when they work on the other floors of the OCS. Different circumstantial factors and evidence require the two aspects of the matter to be considered separately and differently.

15. We have, therefore, in order to provide an answer to the aforesaid questions refer to the definition of the expression 'manufacturing process' and given the circumstantial situation and place of work, whether the workman can be considered and treated and held to be "working in a factory". If it is found that he must, in the circumstances, be deemed to be working 'in a factory' then he will have to be held entitled to overtime in accordance with Section 59 of Factories Act. While it will have to be held that he is not entitled to such overtime, it is found that he is not working "in a factory".

16. In the context, Section 2(1) of the Factories Act defines a worker and says "worker" means a person employed, directly or by or through any agency (including a contractor) with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not] in any manufacturing process or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process, or in any other kind of work incidental to, or connected with, the manufacturing process, or the subject of the manufacturing process (but does not include any member of the argued forces of the Union)." It would be seen from the definition that it is not only a person employed in any manufacturing process, who is called a worker, but even a worker who does cleaning any part of a machinery used for manufacturing process will also be entitled to be described as a worker under the Factories Act. It is not even suggested for the OCS that these workmen can not be said to be cleaning any part of the machinery used for manufacturing process. Indeed, it is admitted and conceded that it is the most elementary part of their duty and they have to do repairs, attend to defects, carry out minor repairs, etc. That is undoubtedly the work "incidental or connected with the manufacturing process" and can be described also as "subject of manufacturing process".

17. The two crucial definitions and important ones for the purpose are the expressions "manufacturing process" and "factory". A factory is defined as "premises including the precincts thereof". There is a quantative limit in the form of number of workmen and qualitative limit which is also prescribed, but that is not a subject of contention or dispute here. On all the other floors, more than 10 workmen were working and the work done was being carried out with the aid of power. The principal contention of the OCS seems to be that while the workshop is a factory registered under the Factories Act and designated as such the very circumstances that 5th floors 7th, 9th and 11th floors are not so designated, must be held to exclude any claim under the Factories Act by the workmen. Similarly, it seems to be the contention that they can not also fall within the extended definition of the factory namely precincts, as they are neither, precints nor premices of the factory, so that persons working on the other floors or at the customers premises will automatically become workers not working in a factory. The principal ground of contention, therefore, is and seems to be that 5th, 7th, 9th and 11th floors as well as the customers premises are not factory within the meaning of the Factories Act, so that the workers working there can not be described as working "in a factory".

18. The question can not be answered by merely looking at the definition of the word "factory" before one refers to

the expression "manufacturing process" appearing in the body of its definition. The expression 'manufacturing process' has been defined under Section 2(k) as follows :—

"Manufacturing process" means any process for —

(i) making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal, or"

(ii) xxxxxxxxx

(iii) xxxxxxxxxx

(iv) (composing types of printing, printing by letter press, lithography phytogravare or other similar process or book binding) (or)"

(v) and

(vi) xxxxxxxx

19. We are concerned only with clauses (i) and (iv) of sub-section (k) of Section 2. Other parts of the sub-Section are not relevant. From what I have stated above and admitted, the workmen are at least concerned with repairing, when they are attending to work on the other floors and at the customers premises. They are also engaged in oiling and cleaning of machinery with a view to its use. Similarly, composing types for printing or printing by letter press or "other similar process" is also a manufactuing process.

20. Now, on the other floors of the OCS, there is undoubtedly "printing" by "other similar process" going on. It would be seen from my notes of inspection that there are teleprinters on the other floors and messages are not only received by transmitters, they are printed on reels of paper and go out of the machine. On the 9th and 11th floors, process is much more electronically controlled and operated. It is difficult to exclude that however from the compendious expression 'printing by other similar process." It embraces in the definition printing even by perforation, which is a means by which messages can be read and is as good as letter printing. The other floors therefore, can be said also to be engaged in a manufacturing process where printing "by other similar process" is going on. Repairing in connection with such machinery used for printing would also therefore be part of the manufacturing process, and persons engaged would be engaged in a kind of work "incidental to or connected with manufacturing process". It is, in the circumstances, difficult to think that on the other floors, no manufacturing process is going on or the concerned workmen who are borne on the workshop establishment are not workers working in a factory though they are working on the premises where a manufacturing process is going on. They will, therefore, have to be held to be factory workers within the meaning of the Factories Act and for purposes of Section 59 also working 'in a factory'. Persons working on the other floors therefore, who are subject matter of this reference must be held to be and considered, notwithstanding that no declaration or registration under the Factories Act, having been made with regard to these floors, held to be factory workers working in a factory under the Factories Act. Therefore, under Section 59 they are entitled to overtime at twice the rate of ordinary wages. The absence of declaration of other floors as factories is not a matter between the workmen and the management. If that contention were to be accepted, then by not registering the premises where a manufacturing process is going on, the employees can be denied the benefit under Section 59 of Factories Act. Factories Act is meant for regulation of premises and workmen engaged in a certain kind of activity. The declaration or registration is not a sinquo-non to be eligible for the benefits under the Factories Act.

21. This does not however, apply in the absence of any evidence whatsoever with regard to the activity which is going on at the customers' premises when such a factory worker is sent to the customers premises namely, to do some kind of work or similar kind of work which he may be called upon to do on the other floors or on the 4th floor. There is little evidence which would establish that any manufacturing process is going on at the customers premises or more than 10 persons are working there or were working there. Besides, it is not clear and not an admitted position whether the customers are entitled to transmit messages or the channels are only for receiving facilities. I have already referred to the definition of the word 'factory' and the essential requirement therein of a 'manufacturing process' being carried on there with the aid of power. Even if therefore, the leased equipment is repaired at the customers premises, so that it can be used, that itself would not satisfy the requirement of "a worker" "working in a factory" to attract Section 59. In the circumstances, though it must be held that employees borne on the 4th floor establishment of the workshop when engaged on other floors must be deemed to be factory workers working in a factory and entitled to overtime under Section 59 of Factories Act, the same can not be said when such workmen are sent out to the customers' premises for repairs, claiming or normal servicing.

22. What now remains is to refer to some of the decisions on the subject. In AIR (46) 1959 Allahabad page 794, though the complement of the rice mill workmen was only 7 and temporarily 3 persons were employed for repairing the compressor, that was held to satisfy the definitions under Section 2(k) and 2(m).

23. In AIR 1957 (MB) page 125, the view that a person engaged in receiving messages on a teleprinter and editing them into news items constituted a manufacturing process, was dissented and disapproved by the division bench of the Madhya Bharat High Court. There it was held that the employee whose duties were to get the messages recieved by the teleprinter and to cast them into news-items which does not constitute a manufacturing process, is not a factory worker. The High Court held, contrary to the finding of the Tribunal, that he can not be described as a factory worker. It may be seen that the person was not engaged in operating the teleprinter where messages are printed, but only concerned with receiving them and casting them into news-item.

24. Reference was made to the decision reported in 1959 II LLJ p. 397. In the present case also Section 70 of the Bombay Shops and Establishment Act was referred to. According to the employers, the workmen are not entitled to its benefits. In the view, which I have taken of what is going on other floors, it does not appear to me to be necessary to refer to Section 70 of the Shops and Establishments Act or to consider that decision.

25. The other two decisions reported in 1960 I LLJ page 270 and 1968 II LLJ page 74 also deal with the application of Section 70 extending the benefit of Factories Act in certain contingencies. It seems to me not necessary to elaborate and deal with these decisions, as they present merely another aspect of the matter. It cannot be disputed that these persons were working "in connection with the factory". The contention was that they were not "working in the factory". I have already dealt with that contention.

26. The result therefore, is that it must be held that the workmen working on other floors are entitled to be paid overtime in terms of Section 59 of the Factories Act, if they work overtime.

27. Award accordingly.

R. D. TULPULE, Presiding Officer

[No. L-40011(2)/83-D.II (B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

का०आ० 2653:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लि०, बैलमपाली के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 18 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th May, 1985

S.O. 2653.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited. Bellampalli and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th May, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, CENTRAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal.

Inustrial Dispute No. 11 of 1981

BETWEEN

Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Ltd., Bellampalli, Adilabad District.

APPEARANCES :

Sri D.S.R. Varma, Advocate—for the workmen.

Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate—for the Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-21011|6|81-D.IV B dated 10-6-1981 referred under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act for adjudication of the industrial dispute between the workmen and the management of Singareni Collieries Company Ltd. Bellampalli with the following issues :—

"Whether the decision of the management of M|s. Singareni Collieries Company Limited to deduct the wages of coal fillers of Somagundam-I Kalyankhani-I and Kalyankhani-II Inclines for going on strike in the month of April, 1981 is legal and justified ? If not to what relief are the workmen concerned are entitled ?"

2. After the notice served, both parties were present along with their Counsel Sri Saigal for the Management and Sri D.S.R. Varma for the workmen before the Tribunal. When the matter came up for enquiry Sri Varma filed a Memo dated 31-1-1985 stating that the Management had paid back the deducted wages for the period in question after the failure report of the conciliation is sent and therefore they are not pressing the matter for adjudication of the dispute stating that there is no necessity for this Tribunal to adjudicate the reference. Sri Saigal for the Management filed a counter stating that the Memo convey the different meaning than what is transpired. It is said for the period of strike when wages were deducted on the principle of "no work no pay" discussions took place and the Management paid the amount not on the ground that they are entitled for the same but as a temporary measure. It is maintained that there is no settlement of this issue as provided for under the I.D. Act. Therefore the counsel wanted that the matter should not be treated as closed. The counsel wanted that the Industrial Tribunal should hear the case on merits and report the award as required by law and the matter should not be treated as closed

3. The point for consideration now is whether the reference is to be adjudicated in the given circumstances or not ?

4. Sri D.S.R. Varma for the Workmen contended that the Management paid back the deducted wages for the month of April, 1981 and their grievances were fulfilled and thus there is no dispute to be adjudicated upon. On the other hand the Management contends that there is no settlement of the issue as provided for under the I.D. Act and that they made temporary adjustments fact that the full deducted wages are paid for the period in question subsequent to the conciliation proceedings indicated that the grievance is solved. Whether it is paid as a temporary measure or temporary adjustment once it is paid for the same period by deduction of wages the dispute is not there for adjudication. The Management having paid back the deducted wages, cannot say that it is only temporary measure or temporary adjustment. There is nothing like temporary measure or temporary adjustment which specify back wages for the period of strike which were deducted and paid. If they paid as a sort of gratiers amount without reference to the deducted wages for the period, it would have been a different matter. It is not so. The period of strike is specified and the amount of deducted wages for the period specified also accepted and when the same is paid for the particular period, the dispute itself is solved in its own way. So it cannot be construed that the payment is only temporary measure or temporary adjustment. It is not the case of the Management that they did not work after April, 1981 and therefore they paid it as a sort of inducement to come into the work. Now the workers are working and the management is taking work from them. Therefore when the specified point involved is only deduction of wages for the month of April, 1981 and after failure of conciliation proceedings with reference to the same said amount is paid. It is deemed that the same is paid in settlement of the said issue. So in the light of this memo filed by the workers I hold that when the factum of payment of back wages is not denied for the specified period the workers are entitled not to press the matter for adiudication. In the said circumstances the reference is terminated as not pressed.

Award is accordingly passed.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him corrected by me and pronounced in the open Court, this the 4th day of May, 1985.

Sd|- Illegible,

Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

NIL

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal.

[No. L-21011(6)|81-D.IV.(B)|D.III(B)]

का०आ० 2654:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैसर्स गवान मिका माइनिंग कम्पनी लि०, डाकघर डोमचंच जिला हजारीबाग के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2654.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Gwan Mica Mining Company Limited, P.O. Domchanch, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 1 of 1985

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to themanagement of M|s. Gwan Mica Mining Company Ltd., P.O. Domchanch, Distt. Hazaribagh (Bihar) and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri G. Gopal, Advocate.
On behalf of the workmen—Shri V. Gopal, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Mica

Dhanbad, the 9th May, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-28012/3/84-D.III (B) dated the 31st December, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Gwan Mica Mining Company, P.O. Domchanch in terminating the services of Shri Ravindra Prasad Verma, an employee of their Khirkia Mica Mine with effect from 23-9-82 without complying with the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 is legla and justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

The case of the concerned person is that he is working in Khirkia Mines of M/s. Gwan Mica Mines since 1957 in different capacity. In 1970 he passed the examination of Foreman and since then he is working as Foreman. After procuring Foreman certificate he was sometimes working as Manager of Khirkia Mica Mines under the Mines Act but he was never fullfledged Manager in as much as all administrative and policy decisions were taken by the Agent and the owners of the said mines. He was served with a notice of termination of his services on 25-9-82 intimating him that his services were no longer required with effect from 23-9-82. He made verbal representations before the Management that his services should not be terminated. He was asked to hand over the charge to Shri Balvadra Prasad on 22-10-82. He was not given one months notice or retrenchment compensation before his services were terminated. The action of the management in terminating his services was in violation of the principles of natural justice and without resorting to the rules and regulations under the Industrial Disputes Act, 1947. He was not allowed any payment untill he was forced to put his signature on receipt on 19-1-83 for full and final settlement and he had to reluctantly sign it as his services had been terminated without any payment and he was starving. He was paid gratuity, bonus and leave wages salary only. But he was not paid the retrenchment compensation and the salary for the period 22-9-82 to 25-10-82. He first applied before the LEO(C) Giridih for the settlement of his claim but he was advised by the LEO (C) Giridih to raise an industrial dispute before the ALC(C). He thereafter filed a complaint before the ALC(C), Hazaribagh on 4-1-84 for his illegal termination of his services and non-payment of his dues but, due to the adamant attitude of the employers, there was failure of conciliation and thereafter the present reference was made. It is praved that the Tribunal should hold that the termination of his services is illegal and void and that he is entitled to retrenchment compensation, notice pay and salary for the idle period and other benefits.

The case of the management is that the reference is not maintainable as the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma was working as Manager of Khirkia Mica Mines and is not a workman under Section 2(s) of the I. D Act. Shri Verma was a fullfledged Manager of Khirkia Mica Mines having all administrative and supervisory powers vested in him. He was duly served with a notice of termination of his services dated 23-9-82. He was asked to hand over charge to Shri Balvadra Prasad on 22-10-82 and all legal dues were paid to Shri Verma and accordingly Shri Verma issued a certificate declaring that he had received his full and final dues and had no claims whatsoever on the said company and that he will not claim for his service in future. Shri Verma never protested and raised any objection regarding the termination of his services or for any legal dues before the management prior to the receipt of the letter from the ALC(C) Hazaribagh dated 24-1-84 with which a complaint of Shri Verma dated 4-1-84 was enclosed. The failure of conciliation report given by the ALC(C), Hazaribagh dated 31-8-84 is misleading. The management of M/s. Gwan Mica Mines Co. Ltd. is justified in terminating the services of Shri R. P. Verma and he is not entitled to any relief or benefit under the I. D. Act.

The only point for consideration in this case is whether the termination of the services of Shri Ravindra Prasad Verma with effect from 23-9-82, without complying with the provisions of the I. D. Act, 1947 is justified.

The management has examined one witness Shri T. K. Prasad, Export Executive of M/s. Gwan Mica Mines Co. The concerned person Shri Ravindra Prasad Verma has examined himself as WW-1. Besides that the management have produced documents which have been marked Ext. M-1 to M-20. The concerned person has also produced documents which have been marked Ext. W-1 to W-8.

It will appear from the case of the concerned person that the termination of his services was bad on account of the fact that the termination of his services was a retrenchment in respect of which there was no compliance of the conditions of the provisions of Section 25F of the I. D. Act. Admittedly Shri Ravindra Prasad Verma was in employment of M/s. Gwan Mica Mining Co. and that his services were terminated with effect from 23-10-82. The main difference between the case of the concerned person and the management is whether Shri Ravindra Prasad Verma was working as Manager of Khirkia Mica Mines or not. The claim of the concerned person is based on the fact of non compliance of the conditions laid down under Section 25F of the Industrial Disputes Act. Section 25F provides that no workman employed in any industry who has been in continuous service for not less than one year under an employer shall be retrenched by that employer untill :—

(a) The workman has been given one months notice in writing indicating the reasons for retrenchment and the period of notice has expired, or the workman has been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice. Provided that no such notice shall be necessary if the retrenchment is under an agreement which specifies a date for the termination of services.

(b) The workman has been paid, at the time of retrenchment, compensation which shall be equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of 6 months ;

(c) Notice in the prescribed manner is served on the appropriate government or authority.

Retrenchment is defined under Section 2(oo) of the I. D. Act and means the termination by the employer of the services of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action but does not included :—

(a) Voluntary retirement of the workman ; or

(b) Retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract or employment between the employer and the workman concerned contain a stipulation in that behalf ; or

(c) termination of services of a workman on the ground of continued ill health.

Thus on perusal of the definition of retrenchment under Section 2(oo) and the conditions precedent to the retrenchment of workman under Section 25F of the I D. Act it has to be seen whether the concerned person is a workman as defined under Section 2(s) of the I. D. Act.

Workman under Section 2(s) of the I. D. Act means any person employed in any industry to do any skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be expressed or implied, and includes any such person who has been dismissed discharged or retrenched in connection with that dispute, but it does not include any such person who is subject to the Army Act, Air Force Act or the Navy Act or who is employed in the Police service or as an officer or

other employee of a prison or who is employed mainly in a managerial or administrative capacity, or who, being employed in supervisory capacity, draws wages exceeding 500 hundred rupees per mensem or exercises, either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, function mainly, of a managerial nature. Keeping the above definition of workman in view, now let us examine whether the work performed by the concerned person was that of a workman or he functioned mainly in a managerial or administrative capacity. MW-1 has stated that Shri Ravindra Prasad Verma was the Manager of Khirkia Mica Mines and looked after the administrative and supervision of the said mines. He has further stated that Shri Verma took disciplinary action against the workman and he was the authority to grant leave to the workmen. Shri Ravindra Prasad Verma has stated in his evidence that in 1970 he passed the examination of Foreman and since thereafter he was working as a Foreman. He has stated that he never worked as Manager in Khirkia Mica Mines. According to him he did not obtain any certificate from DGMS for Managership under the Mines Act and he did not get permit to act as Manager on the ground of health till May, 1985. He has also stated that unless certificate is given by DGMS one cannot work as Manager of Mines. In his cross-examination he has stated that he was temporarily working as a Manager when DGMS had inspected the mines after 5-2-80. It will also appear from his evidence that he has signed many papers of the Mica Mines as Manager of Khirkia Mica Mines but he has tried to explain that he was forced to sign those papers by the management which apparently appears to be unconvincing. The management has produced Ext. M-1 which is an extract of Manager's diary from 12-8-80 onwards. This diary bears the signature of the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma as Manager and shows that he was inspecting the mines and maintaining a note of his inspection in Manager's diary. Ext. M-2 dated 9-7-80 and Ext. M-3 of the same date shows that the concerned person had issued notice to the workmen Rajendra Prasad Singh and S. K. Pain as to why suitable action should not be taken against them for disobeying the written instructions as they had left the mines without sanctioned leave and as to why S. K. Pain did not join duty after the expiry of his sanctioned leave. Admittedly these notices were issued under the signature of the concerned person as Manager and shows that he was the person authorised to take disciplinary action against the workmen Ext. M-4 M-5, and M-6 are leave applications of workmen of Khirkia Mica Mines and leave was granted to them under the signature of the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma. It is clear therefore that Shri Ravindra Prasad Verma was the authority who was granting leave to the workmen of Khirkia Mica Mines. Ext M-8 is the Manager's charge report dated 22-10-79 which shows that the concerned persons Shri Ravindra Prasad Verma took over charge as Manager on 22-10-79 from the outgoing Manager Shri S. K. Guha. Shri Ravindra Prasad Verma has signed as in coming manager on Ext. M-8. Ext. M-9 is a notice in Form E-2 of temporary discontinuance of mining operation of Sheosankar Mine. It shows that a notice was given under the signature of the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma as Manager to the Director Indian Bureau of Mines, Nagpur that the working of the said mines has to be discontinued from 9-9-79 Ext M-10 is a notice in Form-I which also shows that Shri Ravindra Prasad Verma was the Manager who had given the notice and had actually signed it Ext M-20 will show that the management in their comment before the ALC(C) Hazaribagh had clearly stated that the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma was Manager in the Mica Mines and as such he was not entitled to retrenchment relief. Besides that there are documents filed and exhibited on behalf of the concerned person himself which shows that he was working as Manager in Khirkia Mica Mines Ext. W-5 is the complaint which the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma made before the ALC(C) Hazaribagh for payment of service compensation. It will appear from this petition that he was working in Khirkia Mica Mines of M/s Gwan Mica Mines Co for the last 25 years as Manager Ext. W-8 dated 5-2-80 is a letter from the Director of Mines Safety, Koderma written to Shri Ravindra Prasad Verma describing him as Manager Khirkia Mica Mines This was in connection with application of Shri Ravindra Prasad Verma for the grant of Manager's permit It no doubt shows that Shri Ravindra Prasad Verma had not been examined and declared medically fit under Metalliferous Mines Regulation-30(1)|31(1) and Shri Verma was requested to get himself medically examined. This Ext. W-8 only shows that he had not been medically fit but this does not go to show that Shri Ravindra Prasad Verma was not working as Manager of Khirkia Mica Mines. The learned Advocate appearng on behalf of the concerned person has drawn my attention to the evidence of MW 1 wherein MW-1 has stated in his evidence on recall that Shri Verma used to do the work, of accounting in the mines On the basis of this statement it is stated that Shri Verma was working as an Accountant which is, a work of clerical nature and as such he was a workman as defined under the I.D. Act. Except for this solitary evidence to show that the concerned person was working as Accountant, there is no other evidence to show that he was doing any clerical or any skilled or unskilled manual, supervisory, technical or clerical work. While considering the nature of job performed by a person the totality of the entire work has to be seen and in view of the evidence it will appear that the concerned person was actually doing all the jobs of managerial nature and his work of accounting was only incidental or formed a minor part of his multiferious activities of a manager.

On consideration of all these documents and the oral evidence adduced on behalf of the parties, it appears clear that Shri Ravindra Prasad Verma was working as Manager of Khirkia Mica Mines and was not a workman as defined under Section 2(s) of the I. D. Act.

In view of the fact that the concerned person was not a workman the termination of his services by the management will not be covered under the definition of 'retrenchment' under Section 2(oo) of the I. D. Act and as such the provision of Section 25F of the I.D. Act cannot be availed of by the concerned person. Without going into the merits of the claim of the concerned person regarding his dues, I would only hold that as the concerned person is not a workman under the I.D. Act he cannot get any relief from this Tribunal and the action of the management of M/s. Gwan Mica Mining Company in terminating his services cannot be looked into.

In view of the facts, evidence and the circumstances discussed above I hold that as the concerned person Shri Ravindra Prasad Verma was not a workman the action of the management relating to the termination of his services as a Manager cannot be looked into by this Tribunal and as such no relief can be granted to the concerned person. I further hold that this Tribunal cannot consider the case of termination of a Manager and it is not possible to give the Award either in the affirmative or in the negative.

[No. L-28012|3|84-D III(B)]
I. N. SINHA, Presiding Officer

का०आ० 2655:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 की 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन, अंकलेश्वर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 1 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2655.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, as shown in the Annexure. in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Oil & Natural Gas Commission, Ankleshwar and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO I AT BOMBAY

Present

Dr. Justice R.D. Tulpule Esqr.,
Presiding Officer

Reference No. CGIT-5 of 1983

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Oil & Natural Gas Commission, Ankleshwar.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Employer—Mr. S. R. Pai, Advocate.
For the workmen—Mr. M. B. Anchan, Advocate.

INDUSTRY : Oil fields STATE : Gujarat

Bombay, dated the 25th day of March, 1985.

AWARD

This is a reference under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act worded as follows :—

SCHEDULE

"Whether the demand of workmen for stepping up of pay of Shri T. E. Prabhakaran, Rigman now production operator from 1-4-1957 at par with his juniors is justified? If not, to what relief the workmen are entitled to?"

Heard parties. They found the terms of settlement which are settled and negotiated in my presence acceptable. The workmen was present. He was understood the terms and agrees to them voluntarily. The parties have filed the terms of settlement. I am satisfied that the settlement is genuine, bonafide and in the interest of the workmen. A copy of that settlement is filed as schedule to this award. I accept the settlement and direct award in terms of settlement.

R.D.TULPULE
PRESIDING OFFICER

[No.L-30012/2/82-DIII(B)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT BOMBAY

Ref. CGIT 5 OF 1983

BETWEEN

The management of Oil & Natural Gas Commission, Baroda.

AND

Their workmen

MAY IT PLEASE THE HON'BLE TRIBUNAL

TERMS OF SETTLEMENT

Without prejudice to the contentions of the parties, the parties have negotiated and arrived at the following settlement :—

1. The workman Shri T. E. Prabhakaran Chargeman (P) hereby withdraws his demand of his free will for stepping up his pay on par with his juniors.

2. In view of the above and with a view to maintain good Employer-Employee relations, the management of ONGC hereby agrees to pay the workman an ex-gratia amount of Rs. 3400 which the ONGC pays hereby vide cheque No. 033669 dated 16-3-85. But this would not be considered as creating a precedent in any other case.

3. The workman accepts the said amount of Rs.3400/- in full and final settlement of his claim arising out of the aforesaid demand and will not have any other claim of whatsoever nature in future against ONGC arising out of the said demand or connecting with the said demand.

4. The parties pray that the above reference be disposed of in terms of the said settlement.

Name of the workman

Name of the Employer

Witness for the Employee

Witness for the Employer

Bombay:
Dated:

New Delhi, the 25th March, 1985

का०आ० 2656:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लि० के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है ।

S.O. 2656.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division I, and their workmen.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL: (CENTRAL) AT HYDERABAD.

PRESENT:-

Sri J. Venugopala Rao,
Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 69 of 1984.

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I, P.O. Godavari Khani, Dist. Karimnagar.

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I, P.O. Godavari Khani, Dist. Karimnagar.

APPEARANCES :

Sri K. Srinivasa Murthy, Kumari G. Sudha and Sri H.K. Saigal, Advocates—for the Management
None represented—for workmen.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order Letter No.L-22012/35/83-D.III(B)/DE-II(B) dated 16-6-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Singareni Collieries Company Limited Ramagundam Division-I to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action taken by the management of M|s. Singareni Collieries Company Limited, Ramagundam Division-I in terminating the services of Shri Usikamalla Lachulu, General Mazdoor, Godavari Khani-I Incline w.e.f. 9-8-1982 is justified?

If not, to what relief, the workmen is entitled?" The reference was registered as Industrial Dispute No. 69 of 1984 and notices were issued to both the parties.

2. Notice was served to the workmen to file their claims statement on 28-11-1984. On 28-11-1984 no claims statement was filed on that day and workman called absent. Adjournments were given on 28-12-1984, 4-2-1985, 22-2-85, 8-3-1985, 29-3-1985 and finally on 18-4-1985 the workmen did not file their claims statement and were called absent on the dates mentioned. On 29-3-1985 Sarvasri K. Srinivasa Murthy, H. K. Saigal, P. V. Sidhartha and Miss G. Sudha, filed their vakalat for the Management.

Inspite of giving several adjournments the workman called absent and did not file their claims statement and the workman has not contested the case. Hence I hold that the workman is not interested to contest the case for best reasons known to himself and no relief can be granted and an Award is passed accordingly.

Given under my hand and the seal of this Tribunal this the 18th day of April, 1985.

INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence.

NIL

INDUSTRIAL TRIBUNAL
J. VENUGOPALA RAO
[No.L-22012/35/83-D.III(B)]

Dated : 23-4-85.

का० आ० 2657:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, मैसर्स सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी लि० के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है ।

S.O. 2657.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their workmen.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal

Industrial Dispute No. 4 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Singareni,
Collieries Company Limited,
Kothagudem, Khammam District. A. P.

AND

The Management of Singareni,
Collieries Company Limited,
Kothagudem, Khammam District. A. P.

APPEARANCES :

Sri K. Srinivasa Murthy, Advocate—for the Management.

None present on behalf of the Workmen.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order Lr. L-22012(113)|83-D. III(B) dt. January, 1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem and their workmen to this Tribunal for adjudication.

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem are justified in refusing grant of two extra increments to Shri Ch. Mooses, Lineman, No. 5 Incline? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

This reference was registered as Industrial Dispute No. 4 of 1984 and notices were issued to both the parties.

2. The workman sent his claims statement by 1-3-1984 by post, and posted for counter to 20-3-1984. On 20-3-1984 the Management sent counter by post by 20-3-1984 and posted for enquiry to 11-4-1984. On 11-4-1984 workmen was not ready and posted to 4-5-1984. Both parties were called absent on 4-5-84, 23-5-84, 13.6.84, 26.6.84, and on 10-7-1984 Sri K. Srinivasa Murthy offered to appear for the management. Workman was called absent on that day, and posted the matter for enquiry to 28-7-1984. On 28-7-84 both sides are not ready and adjourned to 13-8-84. On 13-8-84 and 14-9-84, 29-9-84 both parties called absent. On 29-10-1984 Sri K. Srinivasa Murthy wants to file vakalat for the Management. Workman called absent and notice was sent to the workman to be present in the court on 22-11-1984. On 22-11-1984 Sri K. Srinivasa Murthy filed vakalat for the Management and Sri D.S.R. Varma wants to file vakalat for the workmen, the matter was adjourned to 21-12-1984 for vakalat and enquiry. On 21-12-1984 Sri D.S.R. Varma for the workmen not ready and vakalat was not filed, the matter was adjourned to 30-1-1985 for counter and enquiry. On 30-1-1985 and on 12-2-1985 and 20-3-1985 workmen called absent and finally adjourned to 20-4-1985. On 20-4-1985 counsel for the management and Personnel Officer were present. Sri D.S.R. Varma who offered to file vakalat on 22-11-1984 and 21-12-1984 did not file any vakalat for the workman till this date. Workman also called absent. Inspite of giving several adjournments the workman nor their representative came forward to contest the case Hence I find that the workman is not interested in contesting his case inspite of giving several adjournments and fair and full opportunities, the workman called absent for the reasons best known to himself, the reference is terminated and the workman is not entitled to any relief.

Award is passed accordingly.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 20th day of April, 1985.

Sd|-

INDUSTRIAL TRIBUNAL

Appendix of Evidence

NIL

24-4-85.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-22012|113|83-D. III(B)]

का०आ०2658:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स सिंगरेनी कोलरीज कम्पनी, कोठागुडम डिवीजन के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है ।

S.O. 2658.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division and their workmen.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri J. Venugapala Rao, Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 21 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries,

Company Limited, Kothagudem Division,

Khammam District. (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collieries,

Company Limited, Kothagudem Division,

Khammam District. (A.P.)

APPEARANCES :

S|s. K. Srinivasa Murthy, G. Sudha and H. K. Saigal, Advocates—for the Management.

None present on behalf of the Workmen.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order Lr No. L-22012|111|83-D.III(B), dt. 21-3-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the employoyers in relation to the management of Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem Division to this Tribunal for adjudication.

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Company Limited, Kothagudem are justified in refusing supply of uniforms to Peons working at Mines especially when they are providing uniforms to those employed in the Head Office? If not, to what relief are the Peons in the Mines entitled?

This reference was registered as Industrial Dispute No. 21 of 1984 and notices were issued to both the parties.

2. Notice was given to the Workmen to file their claims statement on 12-4-1984. But the workmen did not file their claims statement on adjourned dates on 12-4-1984, 23-4-84, 30-4-84, 14-5-84, 31-5-84, 12 6 84, 25-6-84 and finally on 9-7-84 the workmen filed their claims statement. On all the above said dates the workman called absent, and subsequently the workman called absent from time to time after several adjournments i e. on 25-7-84, 4-8-84, 22-8-84, 17-9-84, 12-10-84, 6.11.84, 30.11.84, 4 1.85, 1.2.85, 13 2-85, 20-3-85 and finally on 20-4-1985 the Workman nor their representative were present. Sri D.S.R. Varma offered to file vakalat on 30-1-1984 and 4-1-1985 but he did not file any vakalat on behalf of the workmen. M|s. Srinivasa Murthy, G. Sudha & H. K. Saigal filed vakalat for the management on 30-11-1984. Inspite of giving several adjournments the workmen did not come forward and contested the case for best reasons known to themselves. Hence I find that the workmen are not interested to contest the case after having given full and fair opportunity to them. The workmen are not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 20th day of April, 1985.

Sd|-

INDUSTRIAL TRIBUNAL.

Appendix of Evidence

NIL

Dated.—23-4-85

Venugopala Rao, Industrial Tribunal

[No: L-22012(111)|83-D. III (B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 23 मई, 1985

का. आ 2659.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रेशियस केरीग कारपोरेशन (प्रा.) लिमिटेड, नं. 116, आरमेनियम स्ट्रीट, मद्रास-600001 और उसकी शाखायें, 1. मद्रास, 2 मदुराई, 3. अहमदाबाद, 4. एरनाकुलम, 5. मंगलौर, 6. तिपतुन, 7 सूरत, 8. विशाखापटनम, 9 मैसूर, 10. कोटायम, 11. तिरुचिरापाली, 12. इच्चपुरम 13. उदयपुर, 14. त्रिचूर, 15. हैदराबाद, 16. कालीकट 17. पूना सहित नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं एस-35019/(189)/85-एस एस -2]

New Delhi, the 23rd May, 1985

S.O. 2659.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Precious Carrying Corporation Private Limited No. 116, Armenian Street Madras-600001, including its branches at (1) Madras, (2) Madurai, (3) Ahmedabad, (4)Ernakulam, (5) Mangalore, (6) Tiptun, (7) Surat, (8) Visakhapatnam, (9) Mysore, (10) Kattayam, (11) Tiruchirapalli, (12) Ichchapuram, (13) Udaipur, (14) Trichur, (15) Hyderabad, (16) Calicut and (17) Poona have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(189)|85-SS. II]

का आ. 2660—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एस दयानन्द, 6549 किंग्सवे, सिकन्दराबाद, आन्ध्र प्रदेश, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(232)/85-एस.एस.-II]

S.O. 2660.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs S. Dayanand, 6549, Kingsway, Secunderabad, Andhra Pradesh, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(232)|85-SS. II]

का. आ. 2661.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स टी. वी. एनाकिलोरिम, एल-10, इनसट्रोनिक कम्पाउंड, अदोर, मद्रास-41, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019(239)/85-एस एस. II]

S.O. 2661.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs T. V. Ancillaries I-10, Instronic Compound, Adyar, Madras-41, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(239)/85-SS. II]

का. आ. 2662.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दामोदरदास राधेश्याम बूब, काटन मर्चेन्ट्स, प्लाट नं. 1, राजेन्द्रागंज, रायचुर, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019(243)/85-एस एस.-II]

S.O. 2662.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Damodardas Radheshyam Boob, Cotton Merchants, Plot No. 1 Rajendraganj Raichur, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(243)/85-SS. II]

का. आ. 2663:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रिसिमन टूलिंग्स और एसोसिएट्स 16, गजापति लाला गली, ट्रिप्लीकेन, मद्रास-5, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019(237)/85-एस एस -II]

S.O. 2663.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Precision Toolings and Accessories 16, Gjapathi Lala Street, Triplicane Madras-5, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(237)/85-SS. II]

का. आ. 2664:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स इनटेगरेटिड ट्रांसपोर्ट सर्विस, बम्बई म्युचल बिल्डिंग 6 फ्लोर, 232, एन. एस. सी. बोस रोड, मद्रास-1 और इसकी शाखायें हैं—मद्रास, मदुराई, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, विजयवाड़ा और इरनाकुलम, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019(241)/85-एस एस.-II]

S.O. 2664.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Integrated Transport Services, Bombay Mutual Building VI Floor, 232, N.S.C. Bose Road, Madras-1, including its Seven branches at Madras, Madurai, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, Vijayawda and Ernakulam, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(241)/85-SS. II]

का. आ. 2665:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोकोतिया सीमेण्ट लिमिटेड, 1-10-140/1, गुरुकृपा, अशोकनगर, हैदराबाद-500002 और इसकी फैक्ट्री-श्रीनिवासनगर, डोडापौड़ु गाँव, कोदाद तहसील, नालगोंदा कस्बा, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019(244)/85-एस एस -II]

S.O. 2665.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kakatiya Cements Limited, 1-10-140/1, Gurukrupa, Ashoknagar Hyderabad-500020 including its factory at Sreenivasanagar, Dondapadu Village, Kodad Tq. Nalgonda Dist., have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(244)|85-SS. II]

का आ 2666.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स प्रिन्ट ऐड्स, 9, टाकुद्दीन खान बहादुर गली, ट्रिप्लिकेन, मद्रास-5, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019(245)/85-एमएस.-II]

S.O. 2666.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Print Aids, 9, Taccuddinkhan Bahadur Street Triplicane, Madras-5, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(245)|85-SS. II]

का. आ. 2667.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अरूमुगा सर्जिकल काटनस, छत्रपति 626102, 133, अलांगुलाम रोड, एस. तिरुवेंकटरापुरम, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल.-35019(222)/85-एस एस.-II]

S.O. 2667.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Arumugha Surgical Cottons, Chatrapatti 626102, 133, Alangulam Road, S. Thiruvenkatapuram, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(222)|85-SS. II]

का. आ. 2668.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रत्ना ट्रांसपोर्ट, 70, कांग्रेस बिल्डिंग, 574, माउंट रोड, मद्रास-600006 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (238)/85-एस एस-II]

S.O. 2668.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rathna Transports, 70 Congress Building, 574, Mount Road, Madras-600006, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(238)|85-SS. II]

का. आ. 2669.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री प्रिया एंटरप्राइजिज, 13, पेरीयार रोड, मद्रास-600017, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019 (240)/85-एसएस.-II]

S.O. 2669.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Sree Priya Enterprises, 13, Periyar Road, Madras-600017, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be mode applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(240)|85-SS. II]

का. आ. 2670.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स निरूप साएन क्रोम लिमिटेड, रजि. कार्यालय 9, अरोरा कोलोनी, रोड नं 3, बनजारा हिल्स, हैदराबाद-34, नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019 (242)/85-एसएस.-II]

S.O. 2670.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relaion to the establishment known as Messrs Nirup Synchrome Limited, Reg. Office 9, Arora Colony Road No 3, Banjara Hills, Hydrabad-34, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(242)/85-SS. II]

का. ग्रा. 2671.—मैसर्स आईशर प्रसीजन मशीन्स लिमिटेड, प्लौट नं. 75 सैक्टर-6, फरीदाबाद (पी एन/4983) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/116/85-एस एस -4]

S.O. 2671.—Whereas Messrs Eicher Precision Machines Limited, Plot No. 75, Sector-6, Faridabad (PN/4983) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|116|85-SS. IV]

का.आ. 2672.—मैसर्स मारवेन (इंडिया) लिलमिटेड 10वां फलोर मेकर चेम्बर VI, 22, बेकबेय रिक्लेमेशन नारीमन पाईंट, बम्बई-22 (एम एच/1790) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक हकदारों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक हकदारों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/123/85-एस.एस-1]

S.O. 2672.—Whereas Messrs Naarden (India) Limited 10th Floor, Maker Chamber IV, 22, Beckbay Reclamation, Nariman Point, Bombay-22, (MH/1790), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/123/85-SS. IV]

का० आ० 2673:—मैसर्स किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड, पोस्ट बाक्स नं० 5555, माल्लेश्वरम, बैंगलौर (के एन/29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि में हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि के जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को देय रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं एस-35014/122/85-एम. एस-4]

S.O. 2673.—Whereas Messrs Kirloskar Electric Company Limited, P.B. No. 5555, Malleswaram, Bangalore (KN/29), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of pemium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/122/85-SS. IV]

का.आ. 2674.—मैसर्स असकोर्टस लिमिटेड, आटोमोटिव डिवीजन येलाहांका, बंगलौर-64 (के एन/6721) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[स. एस-35014/121/85-एस-एस-4]

S.O 2674.—Whereas Messrs Escorts Limited, Automotive Division, Yelahanka, Bangalore-64 (KN/6721), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Mescellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of pemium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in the respects.

[No. S-35014/121/85-SS. IV]

का.आ. 2675—मैसर्स आईशर गुडअर्थ लिमिटेड (पहले आइशर ट्रैक्टर इंडिया लि.), आइशर रिसर्च सैन्टर प्लोट नं. 8, सैक्टर 4, बल्लबगढ़ 121004 (हरियाणा पी. एन./4905) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा, स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा, तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बकाया प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विविध वारिस। नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारियों भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाने हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों। विविध वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा।

(संख्या एस-35014/11/85 एस एस-4)

S.O. 2675.—Whereas Messrs Eicher Goodearth Limited (Formerly Eicher Tractors India Limited), Eicher Research centre, Plot No. 8, Sector 4, Ballabgarh-121004 (Haryana) (PN/4905) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioer, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employers under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/118/85-SS-IV]

का आ 2676.—मैसर्स आईशर गुडअर्थ लिमिटेड (पुराना नाम आइशर ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड) 59, एन आई. टी. 'फरीदाबाद' 121001 (हरियाणा) पी. एन. (1358) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त रकम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीकियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उन में संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने वाली व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस या नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/119/85-एस-एस-4]

S.O. 2676.—Whereas Messrs. Eicher Goodearth Limited (Formerly Eicher Tractors India Limitd), 59 N.I.T. Faridabad-121001 (Haryana)-(PN|1358) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects

[No. S-35014|119|85-SS-IV]

का. आ. 3677.--मैसर्स उनम एयर प्रोडक्टस प्राइवेट लिमिटेड, 573, कटरा ईश्वर भवन दिल्ली-6 (डी एल/1913) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/120/85-एस-एस-4]

have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the *Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act*, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintenance such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No. S-35014|120|85-SS-IV]

का. आ. 2678.—मैसर्स मावाली टीफिन रूमज डिपार्टमेंटल स्टोरज, लालबाग रोड, बंगलौर-560027 (के एन/6554) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारियों निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसे विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम नियमों की प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसका बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में किस से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारियों की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारियों को उस दशा में संदेय होता, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारियों के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों के रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सभी सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती, तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विविध वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस. 35014/124/85-एस-एस-4]

ए. के. भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 2678.—Whereas Messrs Mavalli Tiffin Rooms Departmental Stores, Lalbagh Road, Bangalore-560027 (KN/6554) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium and responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12 Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/Legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects".

[No S-35014'124 85 SS IV]

का. भा 2679--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुपर एनेक्स 34, थामबाया रोड, वेस्ट मामबालाम, मद्रास 600033 नामक स्थापन के सबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं एस-35019 (231)/85-एस एस-2]

S O 2679 —Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Super Annexe, 34, Thambiah Road , West Mambalam, Madras-600033 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No. S-35019(231)|85 SS II]

का. भा 2680--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्यामदास एंड संस 3-3-3121, कुरमाबास्ती, सुभाष रोड, सिकंदराबाद-3 नामक स्थापन के सबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35019/(235)85-एस एस-2]

S O 2680.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shamdas and Sons 3-3-3121, Kurma Basti, Subash Road, Secunderabad-3 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

[No S-35019(235)|85-SS-II]

का. भा 2681--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स महालक्ष्मी एंड क , पैरयाम केलपालयाम, एस आर के विद्यालय पोस्ट, कोयम्बटूर-641020 नामक स्थापन के सबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं एस 35019 (228)/85-एस. एस-2]

S O 2681 —Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mahalakshmi and Co. Periayaickenpalayam, S.R.K Vidyala Post, Coimbatore-641020 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(228)|85-SS. II]

का. आ. 2682.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एलमिन एजेंसी, प्राइवेट लिमिटेड नं. 41, एन. एम. एम. रोड, अमनजीकराय, मद्रास-29 और इसकी शाखा है-विजयवाडा। नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019 (229)/85-एस. एस-2]

S.O. 2682.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Elmin Agencies Private Ltd., NoN. 41, N.M.M Road, Aminijikarai, Madras-29 including its branch at Vijaywada have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-Section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(229)|85-SS-II]

का. आ. 2683.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रवि गम इंडस्ट्रिज, ए-1/14, जी. आई. डी. सी., फेज-II वतवा, जिला अहमदाबाद। नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019 (230)/85-एस. एस-2]

S.O. 2683.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ravi Gum Industries A-/14, G.D.C. Phase-II Vatva Dist. Ahmedabad have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(230)|85-SS. II]

का. आ. 2684.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० बालासुब्रमण्यम पावरलूम फैक्ट्री 13/1, काकापालायम रोड, ईलामपिल्लाई, सेलम कस्बा। नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल-35019 (236)/85-एस. एस०-2]

S.O. 2684.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A. Bala Subramaniam Powerloom Factory 13|1, Kakapalayam Road, Eliampillai, Salem Dist. have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(236)|85-SS.II]

का. आ. 2685.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स नेसामनी टैक्स, वेलान्दवालसई 637105, ईडापपड़ी, सेलम कस्बा। नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल.-35019(234)/85-एस. एस.-2]

S.O. 2685.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Nesamani Tex, Vellandivalasai 637105, Idappadi, Salem District, have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment :

[No. S-35019(234)|85-SS-II]

का. आ. 2686.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी. पी. बी. प्रिन्टर्स, 6/48, अवानाशी रोड, कोम्बेदूर-641037 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एल. 35019(227)/85-एस. एस.-2]

S.O. 2686.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D.P.V. Printers, 6|48, Avanashi Road, Coimbatore-641037 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35019(227)|85-SS-II]

नई दिल्ली, 25 मई, 1985

का. आ. 2687.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्लेरियन इंटरप्राइजिज 111-ब, हाजरा रोड, कलकत्ता-26 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017/68/85-एस. एस -2]

New Delhi the 25th May, 1985

S.O. 2687.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the estalishment known as Messrs CLARION ENTERPRISES, 111-B, HAZARA ROAD, CALCUTTA-26 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(68)|85-SS. II]

का. आ. 2688 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुपर डुपर 18-सी, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-71 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 के उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं० एस-35017/69/85-एसएस 2]

S.O. 2688.—Whereas it appears to the Central Goernment that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Super Dooper 18-C, Park Street, Calcutta-71 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(69)|85-SS. II]

का. आ. 2689 —कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 जून, 1985 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त किए जा चुके हैं) और अध्याय 5 और 6 धारा (76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त किए जा चुके हैं) के उपबंध हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे अर्थात :

"रोहतक जिले में—

क्रम सं	राजस्व ग्राम का नाम	हद बस्त संख्या
1.	अशोदा	28
2.	साखोल	39
3.	जखोदा	41
4.	कसार	43

[सं. एस-38013/10/85-एसएस-1]

S.O. 2689.—In exercise of the powers conferred by sub-section(3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st June 1985 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force) of the said Act, shall come in force in the following areas in the State of Haryana namely —

"Sl. No.	Name of Revenue Village	Had Bast No.
1.	Ashodha	28
2.	Sarkhol	39
3.	Jakhoda	41
4.	Kasar	43

in the District of Rohtak".

[No. S-38013/10/85-SS-I]

का. आ. 2690 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सुप्रीम पेपर मिल्स लि., शांतिनिकेतन, 9वीं मंजिल, 9, कैमक स्ट्रीट कलकत्ता-17 और फैक्ट्रीज (मिल्स) रानीनगर गांव जिला नादिया में स्थित नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 के उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017 (63)/85-एस एस-2]

S.O. 2690.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Supreme Paper Mills Ltd. Shantiniketan, 9th floor, 8, Camac Street, Calcutta-17 including Factory (Mill) at village Raninagar Dist. Nadia, West Bengal have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(63)|85-SS. II]

का. आ. 2691 —केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स माहरोजन टॉ कंपनी, चटर्जी इंटरनेशनल सेंटर, 20वी मंजिल म्यूर नं. 1, 33ए, चौरंगी रोड, कलकत्ता-71 नामक स्थापन के संबंध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(64)/85-एस एस-2]

S.O. 2691.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to he establishmen known as Messrs. Nahorajan Tea Company Private Limited., Chatterjee International Centre 20th Floor, Suit No I 33-A, Chowringhee Road, Calcutta-71 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Governmennt hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(64)|85-SS. II]

का. आ. 2692.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स तामरलिप्ता कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि., पी-93, सी. आई. टी. रोड स्कीम-6 एम, दूसरी मंजिल कलकत्ता-54 और शाखा मिदनापुर पश्चिम बंगाल में स्थित नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35019(65) 85-एस एस-2]

S.O. 2692.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Tamaralipta Co-operative Spinning Mills Ltd., P-93, C.I.T. Road Scheme VI-M, (2nd Floor), Calcutta-54 including Branch at Sarat Pally P. O. & Dist Midnapore (W.B.). have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment..

[No. S-35017(65)|85-SS. II]

का. आ. 2693.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फिरेरा एसोसिएट्स 190, सेंट पाल्स रोड, एक्सटेंशन बांद्रा, बम्बई-50, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम, की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35018(8)/85-एसएस-2]

S.O. 2693.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Ferreira Associates 190 St. Paul's Road Extension Bandra Bombay-50 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(8)|SS. II]

का. आ. 2694.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पेंट रिसर्च कार्पोरेशन 295, एस. एन. रॉय रोड, कलकत्ता-38, नामक स्थापन के सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017(67)/85एसएस-2]

S.O. 2694.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Paint Research Corpn. 295, S. N. Roy Road, Calcutta-38 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable, to the said establishment;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No.S-35017(67)|85-SS. II]

का. आ. 2695.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्राफ्टसमैन 336 जयगोपाल इंडस्ट्रियल इस्टेट, भवानी शंकर क्रास रोड, दादर, बम्बई-28 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35018(7)/85-एस. एस-2]

S.O. 2695.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Crafts-man 336, Jaygopal Industrial Estate Bhawani Shankar Cross Road, Dadar, Bombay-28 have agreed that the provisions of the Employees Providen Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(7)|85-SS. II]

का. आ. 2696.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इंडियन ट्यूब प्रोडेक्टस 84-बी, फर्स्ट फ्लोर, वेबर्जी रतनजी मार्ग, दामाबन्दर मार्ग, बम्बई-9 नामक स्थापन के संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35018 (6)/85-एस एस-2]

S.O. 2696.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Indian Tube Products 84-B 1st Floor, Devji Ratansey Marg, Dana Bunder Marg, Bombay-9 have agreed that the provisions of the Employees provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35018(6)/85-SS. II]

का. आ. 2697.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स स्वाकम एंड कंपनी 13, राजाराम मोहन सारनी (रामहरस्ट स्ट्रीट), कलकत्ता-9 नामक स्थापन के संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-1 की उपधारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

[सं. एस-35017 (66)/85-एसएस-2]

S.O. 2697.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Sovachem and Co. 13, Raja Ram Mohan Saran (Amherst Street) Calcutta-9 have agreed that the provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

[No. S-35017(66)/85-SS. II]

का० आ० 2698:—मैसर्स हैण्डलूम इन्टैन्सिव डिवलपमेंट प्रोजेक्ट आवास विकास कालोनी, ए-41, लाजपतनगर, मुरादाबाद (यू पी/11055) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका

है, अधीन नहीं रह जाते हैं, तथा इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती, तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/140/85-एसएस-4]

S.O. 2698.—Whereas Messrs Handloom Intensive Development Project, Avas Vikas Colony A-41, Lajpat Nagar, Moradabad (UP|11055) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Funds Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|140|85-SS-IV]

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

का० आ० : 2699-मैसर्स हैण्डलूम इनटेन्सीव डिवलपमेंट प्रोजेक्ट, धामपुर (बिजनौर) (यू पी/16915) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दे गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/142/85-एस.एस.-]

New Delhi, the 25th May, 1985

S.O. 2699.—Whereas Messrs. Handloom Intensive Development Project, Dhampur (Bijnor) (UP|6915) (thereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would

be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affec. adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|142|85-SS-IV]

का. आ. 2700 :मैसर्स हैण्लूम इनटेन्सीव डिवलपमेंट, कारपोरेशन, इंडस्ट्रियल इस्टेट, गोरखपुर (यू पी) (यू पी/6525) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कामचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम अधीन के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यागत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक मास के के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/141/85-एस एस-IV]

S O 2700—Whereas Messrs Handloom Intensive Development Corporation, Industrial Estate, Gorakhpur, Uttar Pradesh (UP/6525) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, tranfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Group Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance, benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee / legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/141/85-SS-IV]

का.आ. 2701.—मैसर्स हैण्डलूम इनटेन्सीव डिवलपमेंट प्रोजेक्ट, पुष्पराज टाकीज के पीछे, सिविल लाइन फैजाबाद (यू.पी/11080) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 39) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियो की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का या उक्त निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं । तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह रद्द की जा सकती ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक, उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विविध वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/143/85-एस एस-4]

S.O. 2701.—Whereas Messrs Handloom Intensive Development Project, behind Pushpraj Talkies, Civil Lines, Faizabad, (UP|11080) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority o fthe employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees, than the benefits admissible under the said Scheme

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer to pay the premium etc, within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/143/85-SS-IV]

का.आ. 2702.—मैसर्स सिन्थेटिक्स इंडस्ट्रियल कारपोरेशन (ए) डिवीजन आफ लोहिया मशीन्स लिमिटेड) सी-3, पनकी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कानपुर-208022(यूपी/ 5157-ए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहित बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहित बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों तो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम-निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-45014/115/85-एसएस-4]

ए०के० भट्टाराई, अवर सचिव

S.O. 2702.—Whereas Messrs Synthetics Industrial Corporation Limited (A Division of Lohia Machines Limited), C-3, Panki Industrial Estate, Kanpur-208022 (UP/5157-A) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority o fthe employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Uttar Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/115/85-SS-IV]

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

का. आ. 2703.—मैसर्स सूजा रबड़ प्रोडक्ट्स, 45, पट्टामगलम स्ट्रीट, माइलापुतुराय-609001 (टी एन/8827) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों, संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम

के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस.-35014/134/85-एस.एस.-4]

New Delhi, the 30th May, 1985

S.O. 2703.—Whereas Messrs Suja Rubber Products, 45, Pattamangalam Street, Mayiladuturai-609001 (TN|8827) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer followed to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014/134/85-SS-IV]

का.आ. 2704.—मैसर्स प्रणान्त टैक्सटाइलज प्राइवेट लि., रंगास्वामी नगर, वेदापट्टी पोस्ट कैम्बटूर (टी एन 1178), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या

इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/135/85-एस एस-4]

S.O. 2704.—Whereas Messrs Prashanth Textiles Private Limited, Rangaswamy Nagar, Vedapatty Post, Coimbatore-641007 (TN|1178) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer followed to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|135 85-SS-IV]

का. आ. 2705.—मैसर्स कावेरी मैट्रीयल हैंडलिंग सिस्टमज, 42/6-बी, मद्रास रोड, मेलाकावेरी-612002, कुम्बाकोनम (टी एन/16326) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फ़ायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब तक उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, संस्थान के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदे बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फ़ायदों में समुचित रूप से वृद्धि की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है तो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने को युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फ़ायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और, पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फ़ायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं. एस-35014/130/85-एस एस-4]

ए. के. मुद्गलाई, अवर सचिव

S.O. 2705.—Whereas Messrs Kali Material Handling Systems 42|6-B, Madras Road, Mela Kaveri-612002, Kumbakonam (TN|16326) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premmum, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercisee of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Goernment may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premimum in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir|nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme, shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamilnadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer followed to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee|legal heirs of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claim complete in all respects.

[No. S-35014|136|85-SS-IV]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1985

का. आ. 2706 :—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद के बरारी कोक वर्कर्स जो भारत सरकार का एक उपक्रम है के नियमित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 मई 1972 से 30 सितम्बर, 1985 तक की अवधि के लिये जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छूट देती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारियों नियोजित है, एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दर्शित किए जाएंगे,

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिये वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते,

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिये यदि कोई अभिदाय पहले ही संदत्त किये जा चुके है, तो वे वापस नहीं किये जाएंगे,

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी,

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया

कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पद धारी ——

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनिमय, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेखा उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रति फलस्वरुप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रुप में पाने का हकदार हुआ है या नहीं, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हो उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा——

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह वह आवश्यक समझें, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अभियोग में कारखाने, स्थापन, कार्यालय या परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से सबंधित ऐसे लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेज, जैसे निरीक्षक या अन्य पद धारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनको परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक को उसके अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पद धारी के पास यह विश्वास करने का युक्ति युक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखा बही या अन्य दस्तावेज, की नकल करना या उससे उद्धरण लेना ।

[सं० एस–38015/12/83–एच०आई०]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छुट को भुतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छुट के लिये आवेदन देर से प्राप्त हुआ था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट को भुतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

New Delhi, the 31st May, 1985

S.O. 2706.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Bararee Coke Works, belonging to Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, a Government of India Undertaking, from the operation of the said Act for the peiod from 1st day of May, 1972 upto and inclusive of 30th day of September, 1985.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

1. The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

2. Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

3. The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded;

4. The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

5. Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and in kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/12/83-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का.आ. 2707.— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4327, तारीख 24 नवम्बर, 1984 के क्रम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम को, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की और अवधि के लिये छुट देती है।

2. उक्त छुट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसेउक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी,

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिये, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिये रखे गए थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरुप इस अधिसूचना के अधीन छुट दी जा रही है, नकद और वस्तु रुप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं , या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था, या नहीं,

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनको परीक्षा करने दे या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की उसके अभिकर्ता या सेवक को या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल करना या उसमे उद्धरण लेना ।

[सं. एस–38014/40/84–एच. आई.]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में छुट को भुतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है क्योंकि छुट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया मे समय लग गया था। किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छुट को भुतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

S.O. 2707.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 4327 dated the 24th November, 1984, the Central Government hereby exempts Hindustan Shipyard Limited, Visakhapatnam from the operation of the said Act for a further period of one year with effect from 1st April, 1984 upto and inclusive of the 31st March, 1985.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

1. The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insruance (General) Regulation, 1950 ;

2. Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars conatined in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in case and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) required the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and required any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/40/84-HI]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the applicaiton for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

का. आ. 2708.— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1443, तारीख 17.4.84 के क्रम में; (1) भारत गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड (सेंट्रल वर्क-शाप) डाकघर ऊरगांव, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, (2) भारत गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड (उरगांव डेरी), डाकघर उरगांव, कोलार स्वर्ण क्षेत्र, और (3) भारत गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड, ऊरगांव प्रिंटिंग प्रेस, डाकघर, ऊरगांव, कोलार स्वर्ण क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से 1 जलाई, 1984 से 30 जून, 1985 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छट देती है ।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :—

(1) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्रारुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थी ;

(2) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित्त प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी :

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अवधि की बात दी गई किसी विवरणी को विशिष्टियों को सत्यापन करने के प्रयोजन के लिये, या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं, या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को, जो ऐसी प्रसुविधाएं हैं, जिनके प्रतिफलस्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नही, या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नही,

निम्नलिखित कार्य करने के लिये सशक्त होगा :—

(क) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जो सब आवश्यक समझें, या

(ख) ऐसे प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक के अधिभोग में कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखे, बहियां और अन्य दस्तावेजों ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और उनको परीक्षा करने दें या वह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह आवश्यक समझे, या

(ग) प्रधान नियोजक या अव्यवहत नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना, या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे किसी रजिस्टर, लेखा बही, अन्य दस्तावेज की नकल करना या उससे उद्धरण लेना ।

[सं. एस-38014/4/84-एच. आई.]

ए० के. भट्टाराई, अवर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन

इस मामले में छूट को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट के आवेदन संबंधी प्रक्रिया में समय लग गया था । किन्तु यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

S.O. 2708.—In exercise of the powers conferred by section 87 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1443 dated 17-4-1984, the Central Government hereby exempts : (1) Bharat Gold Mines Private Limited (Central Workshop), Oorgaum Post, Kolar Gold Fields; (2) Bharat Gold Mines Private Limited (Oorgaum Diary), Oorgaum Post, Kolar Gold Fields, and (3) Bharat Gold Mines Private Limited Oorgaum Printing Press, Oorgaum Post, Kolar Gold Fields from the operation of the said Act for a further period from the 1st July, 1984 upto and inclusive of the 30th June, 1985.

2. The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

1. The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

2. Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the said Act has been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory;

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of person and payment of wages

or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been employee; or

(d) make copies of or take extracts from any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/4/84-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

नई दिल्ली, 25 मई, 1985

का. आ. 2709:—केन्द्रीय सरकार कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय की सहायक श्री डी. के. वजीरानी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के निरीक्षक श्री पी सी. वधवा को उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को वापस लेती है।

[सं. जैड-11011/2/84-उत्प्रवास-II]

इन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 1985

S.O. 2709.—The Central Government hereby withdraws authorisation given to Smt. D. K. Vazirani, Assistant from DGFASLI and Shri P. C. Wadhwa, Inspector of Employees State Insurance Corporation, under Sectioon 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983).

[File No. Z-11011/2/84-EMIG. III]

INDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

का. आ. 2710:—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो श्रम मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, के क्षेत्रीय कार्यालय हरियाणा का नाम उक्त उप-नियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

[संख्या ई० 11012/2/85-एस. एस.-I]

चित्रा चोपड़ा, निदेशक

New Delhi, the 27th May, 1985

S.O. 2710.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages [Use for Official purposes of the (Union) Rules], 1976, the Central Government hereby notifies the name of the Regional Office, Haryana of the Employees' State Insurance Corporation, an autonomous body under the Ministry of Labour, for the purposes of the said sub-rule.

[No. E-11012/2/85-SS.I]

CHITRA CHOPRA, Director.

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

का. आ. 2711:—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का. आ. 4452 दिनांक 30 नवम्बर, 1984 द्वारा कोल उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2 दिसम्बर, 1984 से छ. मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि का छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है,

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 2 जून, 1985 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. संख्या एस-11017/13/81-डी-I (ए)]

श. ह. सु. अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th May, 1985.

S.O. 2711.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour S.O. No.4452 dated the 30th November, 1984 the Coal Industry to be public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 2nd December, 1984;

And wheheas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period of six months;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section (2) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 2nd June, 1985.

[F. No. S-11017/13/81-D.I(A)]

S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1985

का. आ. 2712.—केन्द्रीय सरकार खान नियम 1955 के नियम 72 के उप नियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3(i) तारीख 14 मई 1960 में प्रकाशित भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि. 547 तारीख 4 मई 1960 को अधिक्रांत करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित सामाजिक विज्ञान, सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण में डिग्री या डिप्लोमा के संबंध में उसके स्तंभ-1 की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित संस्थाओं को उपरोक्त नियम के प्रयोजन के लिए मान्यता प्रदान करती है:—

सारणी

1	2
1. भारत में विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय	सामाजिक विज्ञानों में कोई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा जिसके अंतर्गत

1	2
	समाजशास्त्र या समाज कल्याण/सामाजिक कार्य/समाज सेवा/सामाजिक विज्ञान/तकनीकी या श्रम विधियां/कल्याण या औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंध भी हैं ।
2. श्रम निदेशालय पश्चिम बंगाल सरकार	श्रम कल्याण में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
3. भारतीय औद्योगिक संस्थान खडगपुर	औद्योगिक मनोविज्ञान और औद्योगिक संबंध में डिप्लोमा
4. (i) पी. एस. जी. समाजिक कार्य विद्यालय । कोयम्बटूर; (ii) राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान बंगलौर; और (iii) मद्रास समाजिक कार्य विद्यालय;	समाज सेवा प्रशासन में डिप्लोमा
5. काशी विद्यापीठ बनारस	अनुप्रयुक्त समाजशास्त्र मे मास्टर की डिग्री
6. श्रम कल्याण कर्मकार संस्थान (श्रम कल्याण कर्मकारों का भुतपूर्व विद्यालय) मुम्बई	श्रम कल्याण में डिप्लोमा (दो वर्षीय पाठ्यक्रम)
7. जेवियर्स श्रम संबंध संस्थान, जमशेदपुर, बिहार	औद्योगिक संबंध और कल्याण में डिप्लोमा
8. भारतीय सामाजिक व्यवस्था संस्थान पुणे	(i) सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो सैंट जेवियर महाविद्यालय रांची द्वारा प्रदान किया जाता है । (ii) समाज सेवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो सामाजिक विज्ञान संस्थान लोयोला महाविद्यालय मद्रास द्वारा प्रदान किया जाता है । (iii) समाज सेवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा जो सैंट एलोयसिस महाविद्यालय मंगलौर द्वारा प्रदान किया जाता है ।
9. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुम्बई	सामाजिक विज्ञान प्रशासन में डिप्लोमा
10. राष्ट्रीय श्रम विधि संगम के तत्वावधान में औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली ।	औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

[सं. एस.-65025/2/83-एम.I-]

एल के नारायणन, अवर सचिव

New Delhi, the 28th May, 1985

S.O. 2712 --In pursuance of clause (b) of sub-rule (2) of rule 72 of the Mines Rules, 1955, and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No.G.S.R.547 dated the 4th May, 1960, published in Part II—Section 3(i) of the Gazette of India dated the 14th May, 1960, the Central Government hereby recognises for the purpose of the above rule, the institutions mentioned in column I of the table below in respect of the degree or diploma in Social Science, Social Work or Labour Welfare mentioned in the corresponding entry in column II thereof :—

TABLE

I	2
1. Any University in India established by law.	Any degree or post graduate diploma in Social Sciences, including any degree or post graduate diploma in Sociology or Social Welfare/Work/Service/Science/Techniques or Labour Laws/Welfare or Industrial Relations and Personnel Management.
2. Labour Directorate, Government of West Bengal.	Certificate course in Labour Welfare.
3. Indian Institute of Technology, Kharagpur.	Diploma in Industrial Psychology and Industrial Relations.
4. (i) P.S.G. School of Social Work, Coimbatore. (ii) National Institute of Social Sciences, Bangalore; and (iii) Madras School of Social Work.	Diploma in Social Service Administration.
5. Kashi Vidya Pith, Banaras.	Degree or Master of Applied Sociology.
6. Institute for Labour Welfare Workers (formerly School for training of Labour Welfare Workers) Bombay.	Diploma in Labour Welfare (two year course).

7.	Xaviers Labour Relations Institute, Jamshedpur, Bihar.	Diploma in Industrial Relations and Welfare.
8.	Indian Institute of Social Order, Poona.	(i) Post-graduate diploma in Social Science, conferred at St. Xavier's College, Ranchi. (ii) Post-graduate diploma in Social Service, conferred at the Institute of Social Sciences, Loyola College, Madras. (iii) Post-graduate diploma in Social Services conferred at St. Aloysius College Mangalore.
9.	Tata Institute of Social Sciences, Bombay.	Diploma in Social Science Administration.
10.	Institute of Industrial Relations and Personnel Management, New Delhi under the auspices of National Labour Law Association.	Post-graduate Diploma in Industrial Relations and Personnel Management.

[No. S-65025/2/83-MT]
L. K. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 मई, 1985

अधिसूचना

का. आ. 2713.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33ग की उपधारा (2) के अधीन दायर किया गया आवेदन, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची-1 में उल्लिखित है श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1683 दिनांक 14 अप्रैल, 1969 में विनिर्दिष्ट श्रम-न्यायालय इलाहबाद के समक्ष लम्बित है ;

और भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या का. आ. 2029 तारीख 6 जून, 1984 और अधिसूचना संख्या 2212 तारीख 26 जून, 1984 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7 के अधीन कानपुर में एक श्रम न्यायलय गठित किया गया है जिसका न्याय-क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1948 का 14) की धारा 33 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आवेदन से संबंधित कार्यवाहियों को उक्त श्रम न्यायालय, इलाहबाद से वापस लेती है और इन्हें उक्त केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय, कानपुर को अंतरित करती है और उक्त केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय, कानपुर उन पर उसी प्रक्रम से कार्रवाई प्रारम्भ करेगा जिससे वे उन्हें अंतरित की गई है और विधि के अनुसार उनका निपटान करेंगे।

अनुसूची-1

उस मामले की सूची जो श्रम न्यायालय इलाहबाद के पास लम्बित पड़ा है और केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय कानपुर को अंतरित किया जाना है :—

क्रम सं.	श्रम न्यायालय आवेदन संख्या	विषय
1	2	3
1.	श्रम न्यायालय आवेदन संख्या 16/68	भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री आर. एन. गोविल

[सं.एस. 11020/1/84-डेस्क I (ए)]

New Delhi, the 28th May, 1985

S.O.2713.—Whereas application filed under sub-section (2) of section 33-C of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) mentioned in Schedule I hereto annexed, is pending before the Labour Court, Allahabad, specified in the Notification of the Ministry of Labour S.O. 1683 dated the 14th April, 1969;

And whereas the Government of India have constituted vide Notification S.O.No.-2029 dated the 6th June, 1984 and S.O. No.2212 dated the 26th June, 1984, a Labour Court at Kanpur under section 7 of the Industrial Disputes Act, with jurisdiction over the State of Uttar Pradesh;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33-B of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said application from the said Labour Court, Allahabad and transfer the same to the said Central Government Labour Court, Kanpur and the said Central Government Labour Court, shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose the same in accordance with the law.

SCHEDULE I

List of case pending with the Labour Court, Allahabad to be transferred to the Central Government Labour Court, Kanpur

Serial No.	Labour Court application No.	Subject
1.	LCA No.16/68	State Bank of India versus Shri R.N. Govil.

[F.No. S-11020/1/84-D.I(A)]

नई दिल्ली, 30 मई 1985

का. आ. 2714.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ग की उपधारा (2) के अधीन दायर किए गए आवेदन पत्र जो इससे उपाबद्ध

अनुसूची-1 में उल्लिखित हैं श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 458 तारीख 5 फरवरी 1963 में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय जालन्धर के समक्ष लम्बित पड़े हैं ,

और भारत सरकार ने श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 2251 तारीख 2 मई 1983 और का.आ. 3104 तारीख 25 जून 1983 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा-7 के अधीन चंडीगढ़ में एक श्रम न्यायालय गठित किया गया है जिसका न्याय क्षेत्राधिकार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर राज्यों तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के ऊपर है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आवेदनपत्रों से संबंधित कार्यवाहियों को उक्त श्रम-न्यायालय, जालन्धर से वापस लेती है और उन्हें उक्त श्रम न्यायालय, चंडीगढ़, को अंतरित करती है तथा उक्त न्यायालय चंडीगढ़ उन पर उसी प्रक्रम से कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे, जिससे वे उन्हें अंतरित की गई हैं और विधि के अनुसार उनका निपटान करेंगे ।

अनुसूची—I

क्रमांक	आवेदन संख्या	विषय
1.	92-सी-1983	श्री गोमती प्रसाद बनाम उत्तरी रेलवे
2.	108-सी-1984	श्रीमति सुन्दर देवी और अन्य बनाम उत्तरी रेलवे
3.	12-सी-1985	श्री जसराम बनाम उत्तरी रेलवे
4.	20-सी-1983(विविध)	श्री सुरिन्द्र सिंह बनाम उत्तरी रेलवे
5.	41-सी-1983(विविध)	श्री जोगा सिंह बनाम उत्तरी रेलवे
6.	108 सी से 115-सी/79 तक	श्री केवल सिंह और अन्य बनाम उत्तरी रेलवे

[सं. एस 11020/2/83-डी-1(ए)]
एस.एच.एस. अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 30th May, 1985

S.O. 2714— Whereas the applications filed under sub section (2) of section 33-C of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) mentioned in Schedule hereto annexed, are pending before the Central Government, Labour Court, Jullundhar, specified in the Notification of the Ministry of Labour No. S.O. 458 dated the 5th February, 1963;

And whereas the Government of India have constituted, vide Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour Notification No.S.O. 2251 dated the 2nd May, 1983 and S.O. No. 3104 dated the 25th June, 1983, a Labour Court at Chandigarh under section 7 of the Industrial Disputes Act with jurisidiction over the States of Punjab, Himachal Pradesh, Haryana, Jammu and Kashmir and the Union Territory of Chandigarh;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 33-B of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said applications from the said Labour Court, Jullundhar and transfers the same to the said Labour Court, Chandigarh and the said Labour Court, Chandigarh shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose the same in accordance with the Law.

SCHEDULE I

Serial No.	Application No.	Subject
1	2	3
1.	92-C-1983	Shri Gomti Parshad *versus* Northern Railway
2.	108-C-1984	Shrimati Sunder Devi and others *versus* Northern Railway
3.	12-C-1985	Shri Jas Ram *versus* Northern Railway
4.	20-C-1983 (Misc.)	Shri Surinder Singh *versus* Northern Railway
5.	41-C-1983 (Misc.)	Shri Joga Singh *versus* Northern Railway
6.	108-C to 115-C/79	Shri Kewal Singh and others *versus* Northern Railway.

[No.S.11020/2/83.D.I(A)]
S. H. S. IYER, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मई, 1985

का. आ. 2715.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, हारीयाजाम कोलियरी मैसर्ज ईस्टर्न कोलफील्डज लिमिटेड के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22-5-85 को प्राप्त हुआ था ।

New Delhi, the 27th May, 1985

S.O. 2715.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hariajam Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 23 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1). (d) of the I.D. Act., 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Hariajam Colliery of Eastern Coalfields Ltd. and their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workman—Shri D. Mukherjee, Secretary Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, Dhanbad, the 16th May, 1985

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(60)|83-D.IV(B) dated, the 8th June, 1984.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Hariajam Colliery of Eastern Coalfields Ltd., in superannuating Shri Meshar Seikh with effect from 12-7-82 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

The concerned workman Shri Meshar Seikh was originally employed in Singhpur Colliery by the erstwhile employer. The said colliery was taken over and nationalised in 1973 and thereafter it was merged with Badjna Colliery of ECL. According to the case of the workmen the concerned workman was transferred to Hariajam Colliery by the management of M|s. ECL after nationalisation. The management of Badjna Colliery had issued an identity card to the concerned workman. The said identity card was prepared on the basis of Form B Register but there was no entry regarding the date of birth of the concerned workman in the identity card issued to him. The management issued a letter dated 16|18-11-82 alleging the date of superannuation of the concerned workman as 12-7 82 but in view of late detection the concerned workman was physically superannuated with effect from 19-12-82. The concerned workman represented before the management challenging his proposed superannuation by drawing attention of the management towards Form A record maintained in the office of the Regional P.F. Commissioner and the age recorded in the school leaving certificate. As per Form A record maintained in the office of the Regional C. M. P. F. Commissioner, the actual date of birth of the concerned workman is 2-1-1932 and according to the school leaving certificate also the date of birth is 2-1-1932. The said Form A record was prepared by the erstwhile management in accordance with the entry in Form B register and a copy of the same was also handed over to the concerned workman. The management is bound to respect the date of birth as entered in Form A record and school leaving certificate. The actual date of birth of the concerned workman is 2-1-1932. The management refused to cancel the order of superannuation of the concerned workman and thereafter the union raised an industrial dispute before the ALC(C) Dhanbad demanding the reinstatement of the concerned workman with full back wages. The alternative demand made by the union for assessing the age of the concerned workman through medical examination was turned down by the management. The action of the management in superannuating the concerned workman with effect from 19-12-82 was illegal, arbitrary, unjustified and against the principle of natural justice. On the above facts it has been prayed that the Award be made in favour of the concerned workman by reinstating him with full back wages.

The case of the management is that after Singhpur Colliery was merged with Badjna Colliery of ECL after nationalisation the Form B Register of Singhpur Colliery also merged with Badjna Colliery in which the age of the concerned workman was shown as 43 years on 12-7-65. Later on a part of Badjna Colliery was merged with the adjoining Hariajam Colliery of ECL in 1981 and thereafter the concerned workman along with some other workman became the employees of Hariajam Colliery. The entries in the Form B Register in regard to the date of appointment age and other particulars were duly attested by the concerned workman and in confirmation of the same he had signed the entries in the said Col. As per the aforesaid entries the date of birth of the concerned workman was taken to be as 12-7-22 and when he attained the age of 60 years which is the age of retirement he should have been superannuated from 12-7-82. But due to lapse on the part of the office for putting up the case in time, the concerned workman could not be retired with effect from 12-7-82 and was superannuated from service with effect from 19-12-82 by an order issued on 16|18-12-82 by the Agent of Hariajam Colliery. During the course of conciliation proceeding the sponsoring union contended that the age of the concerned workman was not recoded in the records of the management in as much as the identity card issued to him after nationalisation did not indicate his age or date of birth. It was further submitted that the entries in the date of birth of the concerned workman was recorded as the identity card are made in accordance with the entries in Form B Register. The other point raised by the sponsoring union during the conciliation proceeding was that the date of birth of the concerned workman was recordd as 2-1-1932 in the C.M.P.F. records. The management had contacted the C.M.P.F. organisation and was informed that they had no such record and Form A could not be traced. The sponsoring union produced a document purported to be Form A completed at the time of his employment in 1968, before the conciliation Officer. But the said Form A was forged and fabricated as on verification it was learnt that the signature of the Officer on the said Form A was not that of the manager of the Colliery concerned in 1968. Earlier the concerned workman had made a representation before the management but he had not made any reference in respect of the entry of his age in Form A record and the date of his birth in the school leaving certificate. The workman had clearly stated in his representation that on the date of his appointment his age|date of birth was wrongly recorded as 43 years instead of 33 years by the erstwhile employer. The management rejected the representation of the concerned workman dated 24-11-82 by letter dated 17-12-82. The concerned workman and the sponsoring union have besed the case on some fabricated records and they cannot be accepted in face of the entries in Form B Register which was duly attested by the concerned workman. In the schedule of the order of reference it is wrongly stated that the concerned workman was retired from 12-7-82 in as much as the concerned workman was actually retired with effect from 19-12-82. In regard to the alternative demand of the union for determining the age of the concerned workman through medical examination the same could not be accepted as there was no doubt about the age of the concerned workman as from the entries in Form B Register. On the above plea it has been submitted on behalf of the management that the superannuation of the concerned workman with effect from 19-12-82 is justified.

The only question to be determined in this case is as to what was the age|date of birth of the concerned workman because the said date would determine the date of superannuation of the concerned workman after completing the age of 60 years.

The management have examined three witnesses and the concerned workman have examined WW-1 who is the concerned workman himself. Besides that the management has produced document which have been marked Ext. M-1 to Ext. M-9. The concerned workman also produced documents which have been marked as Ext. W-1 to W-3.

The management has superannuated the concerned workman on the basis of the entry of his age in Form B Register. Photo copy of which has been marked as Ext. M-8. The entries in Ext. M-8 show that the concerned workman Shri Meshar Seikh was aged 43 years on the date of his appoint ment dated 12th July, 1965. This Ext. M-8 is in respect of Hariajam Colliery and the concerned workman has not admittedly s'gned against the said entry. As the concerned workman has not signed Ext. M-8 it cannot be said that he had knowledge about the entry of his age in the said Form B Register. Ext. M-1 is Form B Register of Badjna Colliery. MW-1 who is working as Senior Personnel Officer of Hariajam Colliery has stated that in 1975 Singhpur was merged with Badjna Colliery and thereafter a combined Form B Register was prepared in respect of Badjna and Singhpur Colliery and Ext. M1 is the entry in the said Form B Register of Badjna and Singhpur Colliery. The relevant entry is in Sl. No. 274 which relates to Meshar Seikh. It will appear from the said entries that the age of the concerned workman was noted as 43 years on 12th July, 1965. It is stated on behalf of the management that in Col. 9 of the said entry there is the signature of the concerned workman showing that he had accepted the entries made against his name. The concerned workman however has denied his alleged s gnature in Col. 9. This Tribunal is not of course hand writing expert but on a casual perusal of the signature in Col. No. 9 against the name of the concerned workman with his admitted signature on Ext. M-4, Ext. W-2 and his signature on his deposition (WW-1's deposition) it will appear that the signature made in Col. No. 9 against his name in Ext. M-1 is not similar to the admitted signatures of the concerned workman. The entry of age of the concerned workman n Ext. M-1 appears to be somewhat doubtful in view of the fact that the said age was not mentioned in the identity card of the concerned workman which is marked as Ext. W-1. It will appear from the evidence of MW-1 that the identity card has col. regarding the names, father's name Form B No. C.M.P.F. No., home address date of employment and the date of his birth and these particulars are filled up in the identity card. He has also stated that in 1975 identity cards were issued to the workmen of Badjna Colliery but all particulars mentioned in Form B Register were not included in the identity card. He has further stated that the identity card particulars are filled up on the information given by the workmen. According to him the particulars in the identity card are filled up on the information given by the workmen, but the said statement does not appear to be correct as entries in the identity card are to be made in accordance with the entry in the identity card register and the identity card register is maintained on the basis of entries made in Form B Register. He has further stated that Form A is filled up by the office of the Colliery when a workman applies for being a member of the C.M.P.F. He does not know if a copy of the said declaration is also handed over to the workman and another copy sent to the office of the C.M.P.F. The concerned workman WW-1 has stated that he had filled up Form A when he had applied for being a member of C.M.P.F. and that the particulars in Form A were filled up in accordance with the particulars in Form B Register. The workman has produced the photo copy of Form A which is marked Ext. W-2 and he has stated that it contains his signature and the signature of the then Manager Shri Banerjee. The management has not called for the Register from the C.M.P.F. office to falsify the entries in Ext. W-2 and it appears that the age of the concerned workman was recorded as 2nd January, 1932 in Form A of C.M.P.F. which is marked Ext. W-2 in this case.

MW-3 Shri K. K. Singh, Senior Personnel Officer has stated that incline No. 27 of Badjna Colliery was transferred to Hariajam Colliery on 4-5-81 and all the woorkmen of 27 incline were also transferred to Hariajam Colliery and at that time L.P.C. was issued to all the workmen who were transferred to Hariajam Colliery. MW-3 has proved the L.P.C. of the concerned workman which was issued at that time and has been marked Ext. M-9. He has stated that it was on the basis of Ext. M-9 that the entries were made in Form B Register in respect of Hariajam Coolliery (it refers to the entries of the concerned workman in Ext. M-8). In this Ext. M-9 the age of the concerned workman is stated to be 43 years. MW-2 has stated that the entries in Form B register Ext. M-8 were filled up in accordance with the entry made in the L.P.C. and as such no signature of the concerned workman is taken on Form B register. He has admitted that Ext. M-8 does not contain the signature of the concerned workman. He has stated that the concerned workman was retired on the basis of Ext. M-8. The case of the concerned workman is that in Form B Register of the erstwhile manager the date of birth of the concerned workman was noted as 2-1-1932 and that he had signed against the said entry. The management has not produced the said Form B Register of Singhpur Colliery where the date of birth of the concerned workman was first entered in Form B Register. MW-2 has stated that he does not know if the concerned workman had signed in Form B Register of Singhpur Colliery in which his age was entered as 2-1-1932. It has been stated on behalf of the management that the said register is not available.

In this connection I would refer to one more docoument namely Ext. W-3 which is school leaving certificate of the concerned workman. It will appear from this school leaving certificate that his date of birth was 17-1-1932. It is stated in the W.S. of the concerned workman that his age was recorded as 2-1-1932 in the school leaving certificate which has been falsified by the production of the school leaving certificate by him. It will further appear from the evidence of WW-1 that he had produced the school leaving certificate in proof of his age at the time of his appointment and on the said basis his date of birth was noted as 2-1-1932. If the date of birth of the concerned workman had been noted on the basis of the school leaving certificate Ext. W-3 the date of birth of the concerned workman would have been noted as 17-1-1932 in Form B Register of the erstwhile management of Singhpur Colliery. The assertion of the concerned workman that his date of birth was recorded in Form B register by Singhpur colliery as 2-1-1932 on the basis of school leaving certificate therefore does not appear to be convincing.

Ext. M-4 dated 22-11-82 is a letter from the concerned worokman to the Agent of the Colliery which was written after he had received the letter Ext. M-7 dated 16|18-11-82 by which his services were terminated on superannuation. It is stated by the concerned workman that on the date of his appointment his age|date of birth was wrongly recorded as 43 years instead of 33 years by the erstwhile employer. On the basis of this statement in the letter it has been submitted on behalf of the management that the concerned workman admitted that his age was recorded as 43 years wrongly and that it should be 33 years. In this letter Ext. M-4 it was prayed that the concerned workman be examined by the Medical Board before the date of his retirement. But the management by the letter Ext. M-3 dated 10|11-12-82 rejected the prayer of the assessment to age by the Medical Board.

According to the management the concerned workman was superannuated in accordance with the age|date of birth recorded in Ext. M-8 which is not signed by the concerned workman. It will also appear that the entries in Ext. M-8 were made on the basis of L.P.C. Ext. M-9 which also does not Contain the signature of the concerned workman. Admittedly, The identity card Ext. W-1 which had been given by the management to the concerned workman does not bear the age or date of birth of the concerned workman. I have already discussed that the signature of the concerned workman on Ext. M-1 appears to be of a very doubtful nature. Moreover the date of birth noted in Form A in Ext. W-2 of the concerned workman is 2-1-1932. Thus on consideration of the entire evidence regarding the age|date of birth of the concerned workman it is difficult to hold with the management that the date of birth of the concerned workman was 12-7-1922. In the circumstances of the case, I think the best course is to refer the concerned workman to the Medical Board for the assessment of age due to the difference of age|date of birth of the concerned workman entered in Form B Register, Form A and School leaving certificate.

The action of the management of Harjajam Colliery of M/s. E.C.L. in superannuating the concerned workman with effect from 19-12-82 is not justified in view of the uncertainty of the age/date of birth of the concerned workman. The concerned workman is therefore reinstated in his job with effect from 19-12-82. The management is directed to refer the concerned workman to the Medical Board for the determination of his age and on the basis of the said assessment of age by the Medical Board the concerned workman should be superannuated on completion of 60 years. The concerned workman will get all the back wages and other benefits for the period in accordance with the assessment of age by the Medical Board.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer
[F. L-24012 (60)/83-D. IV (B)]

नई दिल्ली, 28 मई, 1985

का. आ. 2716.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम चण्डीगढ़ के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चण्डीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 22 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 28th May, 1985

S.O. 2716.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Regional Office, Chandigarh and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd May, 1985.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH

Case No. I.D. 14/84

PARTIES :

Employers in relation to the management of Food Corporation of India—Punjab Region, Chandigarh

AND

Their Workman : Pawan Kumar Singla

APPEARANCES :

For the Employers : Shri Mangu Ram.

For the Workman : Petitioner in person.

INDUSTRY : Food Corporation of India STATE : Punjab

AWARD

Dated the 17th of May, 1985

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the power conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act, per their Order No. L-42012(41)/83-D.II(B)/D.V. dated the 27th April, 1984 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of the Food Corporation of India are justified in reverting Shri Pawan Kumar Singla, Head watchman to the post of Watchman ? If not, to what relief Shri Singla is entitled to and from what date ?"

2. Petitioner workman was a Class IV employee of the Respdt. Corporation at their Sangrur Depot and was promoted as Head Watchman vide Regional Office Order No. Estt. 2/(4)/82-PB/E-III dated 8-10-1982. However, under the impunged order dated 6-11-82 he was reverted to his original post of a Watchman without any prior notice. He, thereupon, agitated against the same on the plea that it was violative of the principles of natural justice and, as such, void-ab-initio. The petitioner's apprehension was that he was reverted in view of an intervening circumstance relating to the receipt of 94 Watchmen on transfer from Haryana Region in May, 1981 who appear to have been placed senior to him even without hearing him. It was further averred that the petitioner was the General Secretary of Class IV Employees Union of the FCI which was a Regd. Body; and thus he was deeply involved in the Trade Union activities to the discomfiture of the Management who retaliated by reverting him without any justifiable reason.

3. Petitioner's demand for the appropriate relief did not evoke any satisfactory response from the Management despite the intervention of the ALC(C) at the Conciliation stage and hence the Reference.

4. Resisting the proceedings, the Management pleaded that the petitioner's promotion was purely on ad hoc basis and temporary basis without any prejudice to the claim of his seniors. Moreover under the relevant order itself it had been categoroically emphasised that he was liable to be reverted to his original post even without any notice. Elucidating their version, the Management added that there was some clerical error in the sense that the petitioner's date of selection was assumed to be 17-9-1971 even though as a matter of fact it was 22-5-72 and, that according to the relevant provisions of the FCI Staff Regulation 1971, one's date of selection was the sole critarian for fixing up the seniority. It was explained that they had another employee carrying the petitioner's name and later on it transpired that either due to oversight or inadvertance there was a mix up between the two resulting in the erroneous allotment of a higher seniority to the petitioner; but as soon as the mistake was detected they lost no time in correcting the petitioner's seniority which necessitated his reversion.

5. On the point of fact, receipt of 94 employees in the petitioner's category on transfer from Haryana was not denied even though, for the obvious reason, it was emphatically refuted that his trade union activities had weighed with them in passing the impunged order of reversion.

6. Keeping in view the comprehensive nature of the terms of reference, the parties were straightaway called upon to adduce evidence in support of their respective versions without going through the drill of framing formal issues. Thus the petitioner examined himself and produced a number of documents whose authenticity was not challenged from the opposite side; whereas the Management produced their Asstt. Manager (I.R.) Shri Mangu Ram.

7. On behalf of the Management my attention was drawn towards the promotion order Ex. W6 dated 8-10-1982 to high light the rider that the promotion was granted to a number of Watchmen, including the petitioner, to the post of Head Watchmen on purely ad hoc basis. Other conditions incorporated in the order were also projected for the proposition that the arrangement was without prejudice to the regular avenues of promotion and rights of the other employees, and that it could be withdrawn at any time without any notice. It was, therefore, argued that since the very foundation of the promotion was in the nature of a make shift arrangement, its withdrawal did not infringe any principle of natural justice, much-less any vested right of the petitioner. In the same sequence it was submitted that otherwise also the Order of reversion was fully justified because the petitioner had been granted promotion on an erroneous assumption of a higher seniority.

8. On a careful scrutiny of the entire available data and on hearing the parties I am not inclined to sustain the impunged reversion despite the stipulation contained in the relevant order of promotion Ex. W6 that it could be withdrawn at any stage without any prior notice to the concerned workman and that it was purely a make shift arrangement on ad hoc basis, without prejudice to the regular avenues of promotion or seniority rights of the other employees. The pertinent point is that the impunged reversion was not as innocuous a matter as was being made out by the Management. On the other hand it contained something more than meets the eye.

9. To be precise, the Management proceeded on the specific plea that the petitioner had a lower seniority in view of his selection date being 22-5-72 but due to some clerical mistake or oversight he was believed to have been selected on 17-9-1971 and fixed up at a higher seniority giving rise to the promotion; but as soon as the mistake came to their notice they rectified it and as a necessary consequence thereof withdrew the promotion.

10. To put it in other words, they projected a different date of his selection, which was the decisive factor for fixing up seniority and according promotions. Against such backdrop, in my considered opinion, they were required to show to this Tribunal as to on which particular date the petitioner was selected; more so when he was vehemently contesting the proposition. But significantly enough no evidence; good, bad or indifferent; was adduced by them to support the plea. And since it was a matter of record therefore they could, atleast produce a copy of the order of his selection, if not the Service Book; but shorn of doing so they did not even tender any explanation for the lapse.

11. In a situation like this where an abrupt reversion is ordered on a particular ground pertaining to the realms of fact and the Authority doing so fails to substantiate the same as action, would certainly raise many a judicial eye brows, if no prior notice is given to the effected employee.

12. Accordingly, on quashing the impunged order of reversion I return my Award in favour of the petitioner with a direction to the Management to restore the arrangement existing prior to 6-11-1982 in the context of petitioner's promoion. However, they may, if so advised, take appropriate steps to re-examine the issue on the basis of record in accordance to the procedure established by law and then pass any appropriate legal orders.

Chandigarh.
17-5-1985.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012(41)/83-D. II(B)/D. IV(B)/D. V]

का. आ. 2717.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम, हैदराबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पचाट को प्रकाशित करता है जो केन्द्रीय सरकार को 23 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2717.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Hyderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd May, 1985.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri J. Venugopala Rao, Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 65 of 1984

BETWEEN

The Workmen of Food Corporation of India, Kurnool.

AND

The Management of Food Corporation of India, Kurnool.

APPEARANCES :

None present—for the Workmen and Management.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-42012(4)/83-D.IV(B)/D.V dated 12-6-1984 referred the following dispute under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workmen and the Management of Food Corporation of India, Kurnool to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Food Corporation of India is justified in not considering Shri M. Raja Vali Baig, Ex-Watchman for appointment along with the Employment Exchange sponsored candidates? If not, to what relief the workman is entitled?"

This reference was registered as Industrial Dispute No. 65 of 1984 and notices were issued to both the parties.

2. Notice was issued to the Workman to file his claims statement on 28-11-1984. On 28-11-1984 the workman called absent and no claims statement was filed. An adjournment was given to 19-12-1984 for filing claims statement. Subsequently on 19-12-1984, 10-1-1985, 28.1.1985, 8.2.1985, 27.2.1985, 15.3.1985 and 10.4.1985 the workman was called absent and no claims statement was filed. But on 25-4-1985 (Camp at Kurnool) Sri Miskin Iqbal present at the Camp Court, Kurnool and represented that the employee got job alternatively and wants to get written instructions for the same to report not pressed". It was adjourned to 10-5-1985. On 10-5-1985 workman called absent and no representation. Since several adjournments were given to the workman to file his claims Statement, he did not choose to do so for the best reasons known to himself. Hence I find that the workman is not interested to context the case inspite of giving several adjournments and opporunities, this reference is terminated, and the workman is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 10th day of May, 1985.

Appendix of Evidence.

NIL

Dated : 18-5-1985.

J. VENUGOPALA RAO, Industrial Tribunal

[No. L-42012(4)/83-D.IV(B)/D.V]

का. आ. 2718.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम बम्बई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2 बम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2718.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2|4 of 1985

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Food Corporation of India.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers : 1. Shri J. D. Srivastava, Dy M (L)

2. Shri K. Narayanan, AM(IR).

For the Workmen No appearance.

INDUSTRY : Food Corporation STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 9th May, 1985

AWARD

By their order No. L-42011(16)|83-D.II(B)|D.IV(B)|D.V dated 1-2-1985|25-3-1985 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act :—

"Whether the proposal of the management of FCI, Bombay to change the timings of working of the Distt. Office, Manmad from 0830 hours to 1600 hours instead of the existing timings from 0915 hours to 1645 hours is justified ?"

2. The reference was in fact made in the month of February, 1985 but when it was noticed that timing stated was wrong rectification was made by the order dated 25-3-1985 and the above reference is the rectified order of reference.

3. By order dated 11-1-1983 passed by the Senior Regional Manager, Food Corporation of India a notice of change under Section 9A of the Industrial Disputes Act was issued whereby the change was proposed to be brought into effect from 1-2-1983 making the changes in the working hours of the staff of the District office of the Food Corporation of India at Manmad which before the chance stood at 9.15 hours to 16.45 hours with lunch break from 12.30 hours to 13.30 hours to 8.30 hours to 16.00 hours lunch break remaining the same.

4. Although the dispute seems to have been raised by the FCIE Association, except the request for making the change in the order of reference in harmony with the notice of change issued by the management by their say dated 11-3-1986 which request could not have been granted by this Tribunal and therefore stood rejected by order dated 11-3-1985, the Association never participated in the proceeding and allowed the matter go uncontested.

5. Against this by their written statement filed by the management it is contended that the timing of the departmental labour is from 8.30 A.M. to 5.30 P.M. with one hour lunch break between 12.30 P.M. to 1.30 P.M. whereas the timing of the staff who are deployed to supervise the work of these labourers was from 9.15 A.M. to 4.45 P.M. with one hour lunch break. Because of this difference in time there was an over-all loss of man-power every day and therefore in order to synchronise the timing of labourers and staff the proposed change was effected. It is also stated that because of the old timing damurrage was required to be paid if there was detention of wagon to be unloaded to avoid which and to maintain it at the minimum level the change became necessary. It is also stated that the working hours have remained the same and that the change will increase productivity of the labourers and that if the staff is required to work after 4 P.M. they can easily earn overtime.

6. Since the reference is allowed to go uncontested against that the management has justified the change whereby the reason for effecting the same has been substantiated, the objection raised carries no force and since the change is to result in efficiency and harmony of the working of labourers and the supervising staff, I further hold that the proposed change is justified.

Award accordingly.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-42011(16)|83-D.II(B)|D.III(B)|D.V]

R. K. GUPTA, Desk Officer.

नई दिल्ली, 29 मई, 1985

का० आ० 2719 —उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 13) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय मद्रास में सहायक श्री सुन्दर लाल को, उत्प्रवास संरक्षी द्वारा उत्प्रवास अनुमति देने को स्वीकृति देने और उत्प्रवास अनुमति प्रक्रिया के निलम्बन के आदेश पास करने के बाद, जैसा भी स्थिति हो, पासपोर्टों के पृष्ठांकनों पर उत्प्रवासी संरक्षी मद्रास की ओर से हस्ताक्षर करने का अधिकार तत्काल प्रभाव से प्रदान करती है।

[संख्या ए/22012/2/ 84 उत्प्रवास-II]

इन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 29th May, 1985

S.O. 2719.—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby authorises Shri Sunder Lal, Assistant of the Office of the Protector of Emigrants, Madras to sign the endorsements on passports on behalf of the Protector of Emigrants, Madras after the Protector of Emigrant has approved the grant of Emigration Clearance, on passed orders for Suspensions of procedure of Emigration Clearance, as the case may be, with immediate effect.

[No. A-22012|3|84-EMIG.II]

INDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 मई, 1985

का० आ० 2720.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम, बंबई के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं. 1 बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23 मई, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 30th May, 1985

S.O. 2720.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1,

Bombay as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Life Insurance Corporation of India, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 23rd May, 1985.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-4 of 1984

PRESENT :

Dr. Justice R. D. Tulpule Esqr., Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to Life Insurance Corporation of India, Bombay-21.

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the employer.—Mr. P. R. Namjoshi, Advocate.

For the workmen.—Mr. M. P. More, Advocate.

INDUSTRY : Insurance STATE : Maharashtra

Bombay, the 11th day of April, 1985

AWARD

This is a reference under Section 10 sub-section 1(d) of the Industrial Disputes Act, and is worded as under:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Life Insurance Corporation of India at Bombay in not revising the daily rates (fixed in 1976) being paid to the Casual labours deployed by them for short duration is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

2. The wording of the reference itself suggests and proceeds on the footing that the daily wages payable to casual labour deployed by the Life Insurance Corporation for short duration have not been revised since they were fixed in 1976. The only question which the terms of the reference suggests requiring adjudication is whether this action is justified. The second circumstance which may be noticed is that the term casual labour has not been defined.

3. The parties have filed their statement of claim and written statement and also filed certain documents. Evidence was also led to show the practice and procedure for payment relating to casual labour in other similar industries in the region. At the end of the arguments and evidence, a consensus had emerged amongst the parties that the Life Insurance Corporation should pay the same wage as is paid by other similar organisations in the industry in the region, namely, nationalised banks and the Reserve Bank, where it is paid to such casual labour for short duration at the rate of 1/30th of gross pay of a workman in the same category at the minimum of the scale applicable to employees employed in the organisation on a regular basis. There was however, a contention raised on behalf of the union as to from what date effect should be given to this consensus. I would presently deal with that aspect of the matter, after briefly setting out the contentions of the parties.

4. For the workmen, the Western Zone Insurance Employees Association filed its statement of claim through its General Secretary. The statement of claim deals with many things which really are not necessary and relevant to the controversy referred. It points out that the Life Insurance Corporation of India has passed regulations called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960 which embodied the terms and conditions of service of the employees employed by the Corporation. The Regulations have not been produced by either parties to the case, and it is not clear whether the regulations themselves defined what it meant by 'casual labour'. On the other hand, the regulations apply to whole time employees of the Corporation, and permits a Managing Director, Executive Director (Personnel), a Zonal Manager or a Divisional Manager to "employ staff in classes III and IV on a temporary basis subject to such general or special directions as may be issued by the Chairman from time to time."

5. It then says that the Corporation has started employing casually at the corporation offices, calling them as casual labour, for shorter periods. They were engaged either for a few hours of a day, or for a day or engaged every day. They were engaged on an ad-hoc basis, their remuneration being monthly or hourly. Most of this employment was in class-IV category, such as sweepers, hamals, scavengers, watchmen, liftmen or watchman. Circulars and directions were issued from time to time which govern the wages payable to these workmen for the part time employees. The statement itself goes to admit that their wages were revised from Rs. 65/- to Rs. 75/- per month per day's work in June, 1983.

6. According to the Association the reference covers part-time employees employed on a permanent basis, *badli* employees engaged during leave vacancies and also persons who were not in the *badli* panels for temporary employment. According to the Association, all these persons are called casual labour by the Corporation. As I shall presently point out, the Corporation has not specified what is understood by it by 'Casual Labour' Their salary was initially, according to the Association, Rs. 50 to Rs 60 per month per hour's work each day. The daily rate sometimes came to Rs. 9 or Rs. 8. As pointed out earlier, they belong to the categories of sweepers, hamals, scavengers, watchmen liftmen or watermen. The contention of the Association is that differentiation of these workmen and payment of different scales and different wages to them is discriminatory and unfair. That the directions were to the effect that nobody should be allowed to work for more than 85 days in a year, the idea being that they should not be able to claim any right to absorption. The relief which was sought by the Association has been in para 36, which almost claims that they should be treated on par with the regular employees. It seeks that every allowance which is payable and

being paid to the permanent workman and every benefit as claimed by the Association, should be paid to such workmen. According to it, this is being done by the nationalised banks and should be done by the Life Insurance Corporation. They claim that this relief should be granted retrospectively from 1976. I may mention in this context that in para 17, the Association has clearly stated that it was only in July, 1982 that this question was taken by it with the Corporation. Conciliation proceedings were then taken up, ending in failure report in February, 1983.

7. Annexure-D produced alongwith the statement, however, indicates what was understood when the reference was made by the term 'casual labour'. That is the letter addressed to the union and the LIC, communicating the Government's decision to make the present reference. After the words casual labourers, the words "(temporary and part-time) and *badli* workers" were used. It would have been better if this clarification had itself appeared in the terms of reference.

8. The written statement of the Corporation has classified the casual labour into three categories. The first category is persons who are entrusted with some kind of responsible work, though temporarily casually against a permanent incumbent's absence. The other casually engaged workmen who are given routine nature of work such as watchman, and the third is the category which is engaged for an hour or so every day to perform such functions as sweeping floors etc. Such persons are not given the benefits which are given to the wholetime salaried employees, "but at the minimum of the scale of the post to which such temporary employment is made." In para 6 it sets out the revision made from time to time, that is, in 1978, 79, 81 and 83 lifting their wage from Rs. 30 to Rs. 75.

9. Directions contained in circular letters issued by the Corporation in this connection are produced. On behalf of the Corporation the union produced a chart showing what was paid to such workmen in nationalised banks and Reserve Bank of India, alongwith its list dated 4th January, 1985. That goes to show that the wages paid are much higher in Reserve Bank and some of the nationalised banks. This can be seen from the table showing wages paid to part-time workmen (sub-ordinate class-IV staff) on page 2 of the same chart what is paid to the workmen in the LIC is shown.

10. In view of what I have stated above, and in view of the consensus which emerged, it seems to me clear on the basis of the evidence which was led showing what is paid in comparable service industries, like Reserve Bank, nationalised banks, General Insurance Company, that such employees when engaged on a casual basis by the LIC should be paid gross wage then payable at the minimum to similar employee in the same category engaged on a whole-time basis by the LIC. An award will have to be made accordingly.

11. As regards retrospective effect and claim made by the Association in that behalf, it is quite clear that the terms of reference do not specifically say or require the Tribunal to decide from what date the workmen are entitled to the relief. It says merely, that if the LIC was not justified, "to what relief are the workmen entitled to". It was the intention to get an adjudication from the Tribunal as to the date from which in case of relief, such relief should be granted, the words 'from what date' would have been added. It is difficult to think that in the terms of the reference, the retrospective aspect of the matter is included. The reason probably for not including this aspect was the difficulty in getting the details of these workmen who may have been engaged from time to time since 1976 to get the benefit thereon, and he circumstance that the demand itself was raised for the first time in 1982. Ordinarily, an award would operate from the date of reference, which I think would be appropriate and proper in this case. I do not think that I would be justified in back-dating the award, as the terms of the reference do not require me to consider that aspect of the matter specifically. I also do not think that retrospectivity from 1976 is impliedly contemplated, though the first part of the reference referred to the circumstance that the daily rates of wages of casual labour have not been received. I have already pointed out that according to the Corporation, there has been some revision from 1978. Similarly, the Association has also admitted that the rates have been revised from Rs. 65|- to Rs. 75|- in 1983. In the circumstances, the award will have to be made as follows.

12. The Life Insurance Corporation is not justified in not adequately revising the daily rates of wages paid to the casual labour. The LIC should from the date of this reference pay to those workmen who are engaged as casual labour at the rate of 1|30th of the gross salary which is paid to a regular employee engaged as whole time employee Life Insurance Corporation at the minimum of the scale applicable to them. This should come into force from 18th of January, 1983, the date of the reference.

R. D. TULPULE, Presiding Officer.

[No. L-17011(2)|83-D.IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110064, 1985